राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3   सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का तैंतीसवां दिवस   संख्या 14

मंगलवार,

04 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा उप खण्ड में महिला पुलिस थाने की स्थापना

257. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उप खण्ड निम्बाहेड़ा में महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री जवाहरसिंह बेढ़म): जिला चित्तौड़गढ़ के उप खण्ड निम्बाहेड़ा में महिला पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महिला पुलिस थाना जिला स्तर पर खोला जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ में महिला पुलिस थाना सृजित किये जाने की स्वीकृति दिनांक 05.06.1999 को जारी की गयी। जारी स्वीकृति के क्रम में महिला पुलिस थाना दिनांक 11.10.1999 से संचालित किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा और मंत्री जी की तारीफ भी करूंगा, कल आपने बहुत अच्छा...

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, तारीफ भी करने दें, बहुत अच्छा बाले कल ये।

श्री अध्यक्ष: वह बाद में। अभी तो पूरक प्रश्न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): तारीफ करूंगा, तभी तो खोलेंगे ये।

श्री अध्यक्ष: इतनी देर में तो हो जाता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निम्बाहेड़ा आज के 40 साल पहले जिला हैडक्वॉर्टर रहा है। फिर बाद में चित्तौड़गढ़ जिला हैडक्वॉर्टर बन गया। निम्बाहेड़ा में अभी जिला चिकित्सालय भी है। निम्बाहेड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय अभी-अभी खोला है और कई जिला स्तरीय

संस्थाएं हैं वहां पर। वहां पर सीमेंट का हब भी है। सीमेंट का हब होने की वजह से बाहर की महिलाएं काफी काम करती हैं और महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो वह संख्या भी मैं लेकर आया हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह निवेदन है कि हमारा जिला तो चला गया, कोई बात नहीं, कम से कम जिला महिला थाना आप खोल देंगे तो उन महिलाओं को, क्योंकि जिस तरह विजय नगर में घटना हुई, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में जिस तरह से हो रही हैं, जितने ज्यादा महिला थाने होंगे, निश्चित रूप से वे महिलाएं, जो अपनी बात नहीं बताती हैं, छिपाती रहती हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, अगर एसडीओ हैडक्वॉर्टर पर इस तरह के थाने होंगे तो इस तरह के अपराधों की संख्या कम होगी। उसकी शुरुआत निम्बाहेड़ा से करें। मेरा यह निवेदन है मंत्री जी से, क्या आप आप इसका विचार रखते हैं?

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक सरकार ने जितने भी पुलिस जिले हैं, उन पर जिला मुख्यालय पर थाना खोलने का निर्णय किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार जब भी जिले के अलावा दूसरी जगह थाना खोलने का विचार रखेगी तो वहां का परीक्षण कराकर निम्बाहेड़ा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: परीक्षण कराकर सबसे पहले कहीं खोलें तो निम्बाहेड़ा खोलना, अगर एक भी खोलें तो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): चलो धन्यवाद, साहब, मंत्री जी का भी धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर में पुल का निर्माण

258. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2024-25 में हरजी- पचानवा, कवराड़ा, तख्तगढ़ व पादरली पुल निर्माण की घोषणा हुई थी? यदि हां तो उक्त का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त पुलियाओं की डीपीआर में राशि अधिक होने के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है? यदि हां तो सरकार उक्त की बजट स्वीकृति कब तक करने का विचार रखती है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में हरजी-पचानवा नदी पर पुल, पादरली-तखतगढ़ पुल, कवराड़ा नदी पर पुल की घोषणा दिनांक 10.07.2024 को राशि रु. 19.00 करोड़ की गयी। उक्त कार्य की कन्सल्टेंट द्वारा डीपीआर राशि रु. 34.65 करोड़ प्रस्तुत की गयी है, जिसकी संशोधित राशि रु. 34.65 करोड़ की सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 10.02.2025 को जारी की जाकर निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य को 15 माह में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

(2) उक्त कार्यों की संशोधित सैद्धान्तिक सहमति राशि रु. 34.65 करोड़ की दिनांक 10.02.2025 को जारी कर दी गयी।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, मेरा एक विशेष निवेदन है कि भावरानी से रोजियों की ढाणी का एक 6 किलोमीटर का बहुत ही अत्यावश्यक रोड है, उसकी स्वीकृति की आप अनुशंसा करें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी कि आपने भावरानी से राजियों की ढाणी तक सड़क निर्माण की जो बात रखी है, इसका परीक्षण करवाकर उचित निर्णय करेंगे।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न..।

आर.बी.एम. चिकित्सालय, भरतपुर का निर्माण कार्य

259. डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर के आर.बी.एम चिकित्सालय के द्वितीय फेज का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करने वाले संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो क्या एवं कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: बिना नाम पुकारे ही? चलो।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.बी.एम. अस्पताल, भरतपुर में बजट वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में चार विभाग- न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी एवं वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में 6 विभाग- एंडोक्रोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑंकोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं प्रारम्भ करने की घोषणाएं की गयी थीं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न है? आपने प्रश्न पूछा है न?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): नहीं, मैं पूरक प्रश्न तो बाद में पूछूंगा सर।

श्री अध्यक्ष: पहले तो प्रश्न जो पूछा है, आपने उत्तर भेजा है, वही लाइनें पढ़नी हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): चलिये, चलिये, उत्तर आ गया है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं पढ़ा है वह। ज्यादा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक्सपैंशन ऑन रेनोवेशन जो है, उनका जो वर्क्स जो है, शेड्यूल जो था, वह कम्प्लीट करना था 30.06.2025 को और इसको शुरू किया था, निर्माण शुरू किया था 17.12.2021 में। फाइनेंशियल स्वीकृति...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसमें जो लिखा है, ''आर.बी.एम. चिकित्सालय के द्वितीय फेज का निर्माण कार्य 30 जून'', फिर ''जी हां'', वह जो प्रश्न का उत्तर आपने भेजा है न

इनको, पहले वह पढ़ लीजिये। फिर पूरक प्रश्न में आप यह सारा उत्तर दे देना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उत्तर तो इनको आ गया है साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कहां कह रहे हैं?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) आर.बी.एम. चिकित्सालय के द्वितीय फेज का निर्माण कार्य 30 जून, 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। संवेदक के साथ कार्यकारी एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने पर संवेदक के विरुद्ध शास्ति/पैनल्टी आरोपित कर शेष राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। संवेदक पर निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यकारी एजेंसी के परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. नि. इकाई भरतपुर द्वारा राशि रुपये 30.00 लाख की अन्तरिम शास्ति आरोपित की गयी है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): कोई बात नहीं, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं माननीय मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न में तो आप दीजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि उक्त निर्माण कार्य कब तक टैंडर की शर्तों में पूरा होना था?

दूसरा, यह जो निर्माण कार्य किया गया है, क्या यह टैंडर की शर्तों एवं एमसीआई के मापदण्डों के अनुरूप किया गया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या उक्त अस्पताल में जो दस सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गयी थी, उक्त भवन उपरोक्त सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त होगा? ये उपरोक्त सभी सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी?

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही जवाब दे रहा था। मैं दुबारा इसको रिपीट कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, अब दे दीजिये इनको।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं दुबारा रिपीट करता हूं, यह जो एक्सपैंशन का कार्यक्रम था अस्पताल का, इसको कम्प्लीट होना था 30.06.2025 को। इसका निर्माण शुरू हुआ था 17.12.2021 को। फाइनेंशियल स्वीकृति इसकी 154.62 करोड़ दी गयी थी। M/s Unique Engiventures Consortium Ltd. ग्रेटर नोएडा में है। इन्होंने कार्य शुरू किया 27.12.2021 को। वर्क कम्प्लीट होना था, शर्तों के अनुसार जो एग्रीमेंट है, उसके अनुसार कम्प्लीट होना था 26.06.2023 को। जो अभी लेटेस्ट हमने मालूम किया है, M/s Unique Engiventures Consortium Ltd. कह रहे हैं कि यह कार्य 30.06.2025 तक कम्प्लीट कर देंगे। इनको जो हमने पैसे का डिस्बर्समेंट किया है, वह 123.20 करोड़ का किया है, जो कि 154.62 करोड़ का पूरा टैंडर इसका हुआ था।

आर.एस.आर.डी.सी. इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है और देरी की वजह से इनके ऊपर 30

लाख रुपये की पैनल्टी ऑलरेडी इम्पोज कर दी गयी है 28.02.2025 को। इसके अन्दर आर.एस.आर.डी.सी. जो है, इन्होंने 133.96 करोड़ का डिस्बर्समेंट कर दिया है। उसमें से 123.20 करोड़ दे चुके हैं। अभी वर्क कम्प्लीट हुआ नहीं है। इसके बाद एक कमेटी बैठेगी और वह डिसाइड करेगी कि आगे और क्या इसमें पैनल्टी हमें इम्पोज करनी है। अब जो आपने सूपर स्पेशियलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में प्रश्न किया था, यह जो भवन बन रहा है, यह तो एक्चुअली कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहां फुटफॉल मरीजों का बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मरीजों को वो ले पाये। आपने जो सुपर स्पेशियलिटी का प्रश्न पूछा था, उसके अन्दर न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी, इन चार सुपर स्पेशियलिटीज में से नेफ्रोलॉजी नहीं चल रही थी काफी समय से। न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी चल रही थी।

MKD/RTM/04.03.2025/11:10/1b

उसके बाद पिछली सरकार ने एंडोक्रिनोलॉजी, गेस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑकोलॉजी, ऑकोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी 6 सुपर स्पेशलिटी एनाउंस की, जिसके अन्दर कुछ भी काम नहीं हुआ। आपकी अभी जो हैं, 11 सुपर स्पेशलिटी सैंक्शंड हैं, जिसमें एक्चुअली चल 3 ही रही हैं। 27 पोस्टों के खिलाफ खाली 3 पोस्ट भरी हैं। अभी भवन का निर्माण कम्प्लीट होने वाला है, जून महीना दूर नहीं है। आगे पैनल्टीज भी इम्पोज करनी पड़ेगी, करेंगे। आपकी ये भरतपुर की जो स्पेशलिटीज हैं, इन 37 पदों को, ये जितनी भी सैंक्शंड हैं, इन सबको हम चालू कर देंगे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सम्भाग का सबसे बड़ा अस्पताल है तो वहां पद भी खाली पड़े हैं, आपने स्वयं बताया है। इस अस्पताल को अन्य सम्भागों के अस्पताल की तरह प्राथमिकता देकर इन सेवाओं को शुरू करने का जल्दी से आश्वासन दें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के अन्दर यह बहुत बड़ा काम हो रहा है। माननीय सदस्य, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका जून महीना तो आ गया।

जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जायेगा तो फिर स्पेशलिटीज वहां पर शुरू करने की हमारे पास फैसिलिटीज होंगी, बैड्स भी होंगे। आपने खुद लिखा है कि फुटफॉल बहुत ज्यादा है, भवन कम्प्लीट होने के बाद इक्यूपमेंट मूव करके इन सबको हम जून के पश्चात चालू कर देंगे, यह आपको आश्वासन देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त आवेदन

260. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल पर अघोषित रोक लगाई हुई है? यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में कितने नए नाम जोड़े गए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पोर्टल को पुनः खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विगत तीन वर्षों में अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदन स्वीकार व कितने आवेदन निरस्त किए गए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सर्वे कराकर खाद्य सुरक्षा में अपात्र परिवारों के नाम हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र परिवारों के नाम जोडने हेतु दिनांक 26 जनवरी, 2025 से पोर्टल प्रारम्भ किया जा चुका है। इस संबंध में जारी पत्र दिनांक 23.01.2025 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विगत तीन वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना में 6,16,054 आवेदन स्वीकृत कर 23,26,811 नाम जोडे गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या-01 में समाहित है।

(3) विगत तीन वर्षों में अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने हेतु 5,512 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,736 आवेदन स्वीकार व 96 आवेदन निरस्त किए गए।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा पृथक से सर्वे न कराया जाकर- 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों की ई-केवाइसी करायी जा रही है।

2. माह नवम्बर, 2024 से 31 मार्च, 2025 माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के अनुसार गिवअप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 के अनुसार ऐसे परिवार, जिनमें- 1. कोई आयकर दाता हो, 2. कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, 3. एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, एवं 4. किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है, को स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उनसे होने वाले रिक्त स्थान के विरूद्ध वास्तविक जरूरतमन्द परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

पहला, आपने खंड 3 में जवाब दिया है कि विगत तीन वर्षों में अजमेर में 5 हजार 512 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 1 हजार 736 आवेदन स्वीकार हुए और 96 आवेदनों को आपने निरस्त कर दिया तो शेष रहे 3 हजार 680 आवेदनों को कब तक स्वीकार कर खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जायेगा? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कितने लाभार्थियों के द्वारा ई-केवाइसी अभी तक कराई जा चुकी है? कितने लाभार्थी ऐसे हैं, जिनके ई-केवाइसी होना शेष है? गिवअप अभियान में कितने लाभार्थियों द्वारा स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाये गये? उनके द्वारा किये गये रिक्त स्थान के विरूद्ध आपने कितने वास्तविक जरूररतमंद परिवारों को अब तक इस योजना से जोड़ दिया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अजमेर से आने वाली सदस्या को बताना चाहूंगा कि इनका पहला प्रश्न कि जो आवेदन लम्बित हैं, उनको कब तक जोड़ दिया जायेगा, इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं हो और साथ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत जो सीलिंग है, 4 करोड़ 46 लाख, वह भी ब्रेक नहीं हो, उन दोनों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया है और 26 जनवरी से जो पोर्टल खोला गया, कल 3 मार्च तक 8 लाख 91 हजार 408 नये नाम जोड़ दिये गये हैं।

उसमें आपके अजमेर जिले के 29 हजार 695 नाम जोड़े गये। अजमेर शहर से 2644 नाम जोड़े गये हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार बनने के बाद 12 लाख 95 हजार नाम भी जोड़े गये थे, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में 21 लाख 87 हजार नाम जोड़े गये हैं।

दूसरा प्रश्न, आपका कि ई-केवाइसी के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ई-केवाइसी पूरे भारत में सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जो लाभ ले रहे हैं, ई-केवाइसी करवाना जरूरी है। इसकी प्रारम्भिक तारीख 15 अगस्त तक थी, फिर लगातार राजस्थान सरकार बढ़ाती गई। हमारी आखिर 31 दिसम्बर तक थी, पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश किया कि हमें कुछ समय और देना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति करा सके। इस बार 31 मार्च आखिरी तारीख है। 31 मार्च तक जो ईकेवाइसी नहीं करवायेंगे, वह स्वयं ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जायेंगे।

इसमें 4 करोड़ 39 लाख 85 हजार आज की डेट में, जो हमारे पास लाभार्थियों की संख्या है। उसमें से लगभग 3 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाइसी करवाया है। उसमें हमने दो कैटेगीरी को इसमें माफ किया है, एक तो शून्य से दस साल, जिनके अंगूठा नहीं आता है, आइरिश मशीन पर उनको हमने एक्जेम्पट किया और 70 साल से ऊपर वालों को एक्जेम्पट किया है। लगभग 40 लाख के आसपास यह संख्या रहेगी, जो हो सकती है। इस खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाइसी नहीं करवायेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बाहर होंगे। मैं आश्वस्त

करना चाहूंगा समस्त सदस्यों कि एक भी व्यक्ति अगले चार माह में..

श्री अध्यक्ष: आप तो जो पूछा है, उसका उत्तर दीजिये, बाकी बातें तो ठीक हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिम्पल का सवाल पूछा है कि जो शेष रहे। मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं कि आपने बताया कि इतने लाख लोगों को हमने जोड़ दिया। मैं पूरे राजस्थान की चर्चा नहीं कर रही हूं। जिन्होंने सिर्फ आवेदन किया, जो 5 हजार 512 लोगों आवेदन किया उनमें से जो 3 हजार 680 लोग बच गये, जिनके आवेदन आपने स्वीकार कर लिये, लेकिन उनको जोड़ा नहीं, उनकी बात कर रही हूं, 3 हजार 680 लोगों को आप कब तक जोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष: इनका मूल प्रश्न यही है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय विधायकगण को मैं बताना चाहूंगा कि 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' के तहत जिनका आवेदन पहले आयेगा, वह हो रहा है। वह संख्या लगातार चल रही है, फॉर्म जांच भी हो रहे हैं। वे जांच हो रहे हैं, वे हो जायेंगे इन दो महीने में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपने खुद ने स्वीकार किया है कि 5 हजार 512 आवेदन प्राप्त हुए, बाकी आवेदनों को निस्तारण आप कब तक करेंगे?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं यही तो, उनकी जांच हो रही है। उनकी जांच प्रक्रिया से गुजरकर हर व्यक्ति को।

श्री अध्यक्ष: कब तक? आप तारीख बताएं? कब तक?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं कह रहा हूं अगले दो-तीन महीने में कोई भी राजस्थान में नहीं रहेगा तो अजमेर में कैसे रहेगा। आप भी विधान सभा के अध्यक्ष हों, कैसे रह सकते हो, बताओ आप।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आपने यह तो अच्छा सुझाव है और अच्छी घोषणा है, मुख्य मंत्री जी की नाम जोड़ने की, पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि 26 जनवरी से आपका पोर्टल चल रहा है और 26 जनवरी से अब तक आप लोगों ने 8 लाख लोगों के नाम जोड़ दिये। अभी आपने सैप्लीमेंट्री में कहा और जब 26 लाख लोगों के नाम जोड़ दिये तो एक तरफ आप आंसर दे रहे हो कि पिछले 3 वर्षों में 6 लाख 16 हजार आवेदन ही स्वीकृत किये हैं। यह एक तो डिफरेंस आ रहा है। दूसरा जब 3 वर्षों में 5512 आवेदन लम्बित हैं और आप उनसे ज्यादा पिछले 1 महीने में जोड़ चुके हो तो क्या यह 1736 नये पोर्टल खुलने के बाद आपने स्वीकृत किये हैं? या पहले के ही स्वीकृत हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न डिफरेंस का पूछा है। डिफरेंस इसलिए कि आवेदन लम्बित है, वो तो है ही, पर जो बचे हैं, उनके नाम स्वत: ही जुड़ रहे हैं, वो फार्म करते ही उस आधार

कार्ड में और जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके नाम जुड़ रहे हैं। इसलिए वह संख्या अलग आ रही है। इसलिए लम्बित और उस चीज में अन्तर आ रहा है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, यह नहीं बताया। ये 5512 में से जो 1736 आवेदन आपने स्वीकार किये हैं, ये नये स्वीकार किये हैं या पिछले तीन वर्षों के हैं?

श्री अध्यक्षः मिलाकर किये हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने जो प्रश्न तीन का पूछा है, उसका उत्तर आपको दे दूंगा। आपको सारा डिटेल में दे दूंगा। आपको बिलकुल।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, माननीय गोपीचन्द मीणा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड ब का है, सिम्पल सा है। माननीय सदस्य ने पूछा, कब तक बचाओगे?

जहाजपुर के मन्दिरों का विकास

261.श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कौन-कौनसे मन्दिर पंजीकृत हैं? विगत पांच वर्षों में उक्त मन्दिरों का आय-व्यय तथा विकास हेतु व्यय का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मन्दिर बलदेव जी महाराज, शक्करगढ व बृजनन्दन मन्दिर, जहाजपुर का जीर्णोद्धार, चहुंमुखी विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित 5 राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिर हैं। मंदिरों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विगत 5 वर्षो में उक्त मंदिरों का आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। मंदिरों के विकास हेतु व्यय का विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न हैं।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय मंदिर बलदेव जी महाराज, शक्करगढ व बृजनन्दन मंदिर, जहाजपुर में जीर्णोद्धार व चहुंमुखी विकास हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

Bhs/Rtm/04.03.25/11.20/1c

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उत्तर आ गया मेरा। मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री एवं उप मुख्य मंत्री महोदया को मैं मेरे भीलवाड़ा जिले में और जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में देवस्थान ...।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछना है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): इसका बजट दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछना है, बाकी बातें भाषण में कह देना।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): मेरा पहला पूरक प्रश्न है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग ने प्रबन्धित एवं आत्मनिर्भर पांच राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु मैंने प्रस्ताव दे रखे हैं उनकी स्वीकृति प्रदान करावें।

दूसरा प्रश्न साथ ही है मेरा कि जिस तरह वक्फ बोर्ड में राजस्थान में पूरे देश में अधिकारी/कर्मचारी देवस्थान विभाग ने लगा रखे हैं, इसी तरह मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से कि देवस्थान विभाग में भी हर जिले में कर्मचारी/अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि हमारे मन्दिरों की देख-रेख हो सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह मांग करने का नहीं है, यह प्रश्न पूछें कि क्या सरकार करेगी।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): हां, करने की इच्छा रखते हो क्या? नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: हां, यह पूछो, मांग तो इसमें नहीं होती। माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग के प्रबन्धित व नियंत्रित मन्दिर बलदेव राम जी महाराज, शक्करगढ़ व बृजनन्दन मन्दिर सहित गणेश जी, मंशापूर्ण जी, मन्दिर श्री शान्तेश्वर जी, मन्दिर श्री राजराजेश्वर जी के जीर्णोद्धार, विकास और उन्हें विकसित करने की मांग माननीय सदस्य ने की है, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस वर्ष जो बजट घोषणा हुई है, राजस्थान के देवस्थान विभाग के प्रबन्धित और नियंत्रित मन्दिर 593 हैं, जिनमें 552 राजस्थान में हैं और 41 मन्दिर अन्य प्रदेशों में हैं। इन सभी तरह के मन्दिरों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 161 करोड़ रुपये की घोषणा की है और माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के पांचों मन्दिर हैं उनको हम इस प्लान में जोड़ कर उनके विकास के लिए हम काम करेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है कि हर जिला स्तर पर देवस्थान विभाग का कर्मचारी लगाने की जो व्यवस्था की इन्होंने मांग की है तो माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे देवस्थान विभाग के पूरे राजस्थान में 12 एडिश्नल कमिश्नर हैं विभिन्न जगहों पर और उनके अधीन सारी जगह व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी नया कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। यह माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): धन्यवाद, सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समरजीत सिंह। माननीय मंत्री जी।

भीनमाल बागोड़ा सड़क का नवीनीकरण कार्य

262. श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल बागोड़ा सड़क का निर्माण वन क्षेत्र के मध्य में हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर सरकार द्वारा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में नवीनीकरण का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) भीनमाल-बागोड़ा सड़क भीनमाल के पास वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र वनखण्ड-जोड जुंजाणी के खसरा नं. 08 रकबा 5.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 10 रकबा 8.50 हैक्टेयर व खसरा नं.1992 रकबा 2.27 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क, वन विभाग के नाम अमलदरामद होने से पूर्व का निर्माण किया हुआ है। यह तीनों खसरे वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है।

(2) उक्त सड़क का नवीनीकरण कार्य आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में है। बिना सक्षम अनुमति के अभाव में नवीनीकरण कार्य अनुमत नहीं है।

(3) उक्त सड़क के नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति/वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु कोई प्रस्ताव (परिवेश पोर्टल पर) विभाग को प्राप्त नही हुआ है, यदि उक्त सडक के संबंध में परिवेश पोर्टल पर कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): जवाब तो आ गया है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया है कह रहे हैं, विराजें। प्रश्न पूछिये।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से बागोड़ा सड़क निर्माण के लिए 55 करोड़ पी.डब्ल्यू.डी. ने जारी किये हैं उस सड़क के नवीनीकरण के मामले में मैंने यह प्रश्न उठाया है जो वन विभाग द्वारा रोका गया है। वन विभाग ने कहा है कि यह जो भी सम्बन्धित जमीन है गैर मुमकिन सड़क वन विभाग के नाम अमलदरामद है। पूर्व में आजादी के बाद से यह स्टेट हाईवे है, आजादी के बाद से यह सड़क चल रही है और बाड़मेर को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क है। पूर्व में भी पहले सैटलमेंट के समय से ओर 1978 में यह म्युटेशन भी पी.डब्ल्यू.डी. के नाम भरा गया। रीसैटलमेंट में यह आपके वन विभाग के नाम से हुआ है। मेरा तो यह कहना है कि यह तीन विभागों के बीच में फंस गयी सड़क। 55 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने पास किये। अब हम किसके पास जायें? पी.डब्ल्यू.डी. के पास जाते हैं तो कहते हैं कि वन विभाग ने रोक दिया। वन विभाग कहता है कि सड़क हमारी है, हम जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, पता करते हैं तो ये पहले सैटलमेंट में और आजादी के बाद से यह सड़क चल रही है तो अब आपका संरक्षण चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि

इन तीन विभागों के कुछ तो जैसे आज सरकार में ...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सरकार में काम की सहूलियत ईजी करने का जो नारा चल रहा है, अब आप तीनों विभागों को तय करके कि किस तरह से किया जाये हमें तो यह सड़क चाहिये जो वर्षों से चली आ रही है और आजादी के बाद से चली आ रही है और मुख्य सड़क है। इसके लिए मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सड़क का उल्लेख किया पांच किलोमीटर की लम्बाई की यह सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसकी जो यूज़र एजेंसी है वह पी.डब्ल्यू.डी. विभाग है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, जो परिवेश पोर्टल है उस पर विधिवत रूप से आवेदन करे, परीक्षण कराने के बाद एन.ओ.सी. देने का काम वन विभाग करेगा। वन विभाग किसी सड़क को, किसी निर्माण कार्य को रोकता नहीं है लेकिन एन.ओ.सी. देने का काम लेकिन एक मिथक बना हुआ है। यदि परिवेश पोर्टल पर विधिवत आवेदन करेगा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग तो परीक्षण कराने के बाद इस सड़क के लिए एन.ओ.सी. देने का काम वन विभाग करेगा। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका यही संरक्षण चाहूंगा कि जनता तो इस चीज के लिए जायेगी नहीं। यह तो विभागों को ही आपस में तालमेल बैठा कर काम करना है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रालय भी है, रेवेन्यु विभाग भी है, जो भी त्रुटियां हैं वो दूर करें, क्योंकि वर्षों से इस पर पैसा लगता आया है। 2012 में भी इसकी चौड़ाई हुई है। यह पहली बार ही किसी वन विभाग के अधिकारी ने इसको रोका है और मौके पर तो सड़क है उसको तो कहीं ले जा नहीं सकते आप। उसी को रिन्यु करना है तो मैंने कहा कि इसको ईजी करें और इस सड़क को जल्द से जल्द बनायें ताकि लोगों को फायदा मिले।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को फिर अवगत करा रहा हूं कि ...।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): वन विभाग भी पी.डब्ल्यू.डी. से इसकी रिक्वेस्ट करे।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): एक प्रक्रिया है, आपके जो भी एक्स.ई.एन. इस काम को देख रहे हैं आप उनको आदेशित करें और वो परिवेश पोर्टल पर इस फाइल को अपलोड करें, वन विभाग की तरफ से एन.ओ.सी. देने का काम मेरा विभाग करेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करो सरकार को कि सामंजस्य बैठायें तीनों विभागों का।

श्री अध्यक्षः मैं कर रहा हूं। मेरा इसमें एक सुझाव है कि माननीय सदस्य, आप वहां के जिलाधीश महोदय से चर्चा करें वो दोनों-तीनों विभागों को बुलायें। जहां वन विभाग की जरूरत होगी, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो एन.ओ.सी. दे देंगे। इतना ही है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो सरकार को निर्देश दो, साहब, सरकार व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्षः वहां का कलेक्टर सरकार ही है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष जी। नेता प्रतिपक्ष, आप बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप बार-बार मत उठा करो। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सक्षम हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुनो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मैं सक्षम हूं जवाब देने में। आप इस तरह से नहीं बोलोगे बार-बार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आप ही से कहा है कि आप सरकार को निर्देशित करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपको किसने कहा? बैठिये। यानी यह कंपीटिशन थोड़े हो रहा है।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): मैंने इसीलिये निवेदन किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपका संरक्षण चाहिये कि तीनों विभागों का तालमेल हो तो यह सड़क जल्दी से जल्दी बन जाये।

श्री अध्यक्षः मैंने कह दिया। मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय प्रधान मंत्री जी ने पारदर्शिता रहे, संवेदनशीलता रहे, इसी के लिए परिवेश पोर्टल का गठन किया है। परिवेश पोर्टल का दूसरा गठन भी हो चुका है और एक प्रक्रिया है, इसमें न जिलाधीश महोदय की आवश्यकता है न किसी और के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, जो यूजर एजेंसी सड़क बना रही है वो विधिवत परिवेश पोर्टल पर आवेदन करे, परीक्षण करने के बाद जो-जो कागज वो मांगे वो अपलोड करे, माननीय विधायक महोदय, निश्चित रूप से उस पर एन.ओ.सी. दी जावेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। माननीय यूनुस खान।

डीडवाना जिला मुख्यालय में मिनी सचिवालय की स्थापना

263. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की गई है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो कब तक चिन्हित की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला मुख्यालय डीडवाना में कितने जिला स्तरीय कार्यालयों का संचालन किया जाना शेष है? उक्त कार्यालयों का संचालन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज

पर रखें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): (1) जी हां। नवगठित जिलों के संबंध में अंतिम निर्णय हो जाने के फलस्वरूप सरकार डीडवाना - कुचामन जिले की आम जनता को राहत देने के लिए जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय अथवा कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करवाये जाने का विचार रखती है।

इसके लिए जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन द्वारा उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाये गये हैं। आवंटन किये जाने के उपरांत मिनी सचिवालय अथवा कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण की कार्ययोजना प्रारंभ की जावेगी।

(2) जी हां, डीडवाना जिले में जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है।

जिला कलक्टर, नागौर द्वारा मौजा मण्डाबासनी के खसरा नंबर 1496/1487 रकबा 19.02 हैक्टेयर गै.मु.गोचर में से 08.00 हैक्टयेर भूमि राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाये गये हैं। आवंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में 26 जिला स्तरीय कार्यालय स्वीकृत नहीं होने के कारण संचालन किया जाना शेष है। बाकी सबका हो रहा है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर अवलोकनीय है। उक्त कार्यालयों का संचालन संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति उपरान्त किया जायेगा।

Kas/rtm/04.03.2025/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा डीडवाना जिला बरकरार रखा। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्रद्धेय भैरोंसिंह जी शेखावत के समय यह शुरू हुआ और वसुन्धरा जी के द्वारा यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। आज हमारे डीडवाना में करीब-करीब सब कार्यालयों के भूमि-भवन हैं। मिनी सचिवालय का प्रोसीजर 2017 में शुरू हुआ था, उस पत्रावली में जो गोचर की जमीन है, उसके बदले हमने वन विभाग की जमीन ली और वन विभाग को एक पंचायत की जमीन दे दी, वह प्रक्रिया भी पूरी हो गई, उस जमीन का केवल नामांतरण नहीं हुआ, सरकार बदल गई और बायस्ड होकर भू-माफियाओं को फायदा देने के लिये हमारा जो उस समय पैसा स्वीकृत था..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे जी की सरकार में मिनी सचिवालय की बाकायदा फाइल चली थी, जिसकी प्रतिलिपि मैं माननीय मंत्री महोदय को बाद में मुहैया करा दूंगा, क्या सरकार उस भूमि पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है?

दूसरा, चूंकि यह जिला बनने से पहले जिला कलेक्टर नागौर ने चिट्ठी भेजी है और उसने यह जमीन भेजी है, आप क्या उसकी जांच करायेंगे? क्योंकि वह पैसा एक तरह से फिजूल में ऐसी जगह खर्च कर दिया गया, जहां शराब की दुकानें खुली हुई हैं, शहर से 7 किलोमीटर दूर है। क्या सरकार उसकी जांच करवायेगी और जो पहले माननीय वसुन्धरा जी के शासन में मिनी सचिवालय की पत्रावली लगभग फाइनल स्टेज पर आ गई थी और 28 करोड़ रुपये सेंक्शन भी हो गये, उसकी प्रथम किश्त 6 करोड़ 51 लाख रुपये आ भी गई, क्या उसकी जांच करवा कर उस जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है कि पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार ने एक जमीन का आइडेंटिफिकेशन किया था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसके लिये फंड भी स्वीकृत किया था और काफी आगे की स्टेज तक वह पहुंच गया था। हम आपसे पूरे कागज लेकर इसका पूरा परीक्षण करायेंगे। चूंकि वर्तमान सरकार ने भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है, यदि यह सूटेबल नहीं है और आपको लगता है कि जो पहले जमीन आइडेंटिफाई की थी, वो ज्यादा सूटेबल है, तो उसमें से जो भी जनहित में होगा, वह निर्णय लेंगे और जनहित में और आपसे सलाह लेकर जो जनता के हित में होगा, वो जमीन आइडेंटिफाई करके कलेक्ट्रेट भी स्थापित करेंगे और मिनी सचिवालय भी स्थापित करेंगे। तब तक 2023 में जो नोटिफिकेशन हुआ, उसका अस्थाई रूप से कार्यालय डीडवाना में चल रहा है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमारे पास इसके अलावा भी राज्य सरकार की 580 बीघा जमीन और है, तीन जगह जमीन पड़ी है, जनहित में जो हो...।

श्री अध्यक्षः आपसे राय करके ही करेंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): बस, मैं एक निवेदन कर दूं, क्या सरकार कमेटी बनाकर उनका परीक्षण करवाना चाहेगी?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जिला कलेक्टर से लगाकर सरकार के सभी अधिकारी सक्षम हैं। जनहित में जो भी होगा और जिन जनप्रतिनिधियों की सलाह लेना आवश्यक होगा, उनकी सलाह जरूर लेंगे, लेकिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसका परीक्षण करके जनहित में जो भी निर्णय होगा, वह जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री बालमुकुन्दाचार्य।

हवामहल क्षेत्र में पर्यटक सहायता केन्द्र

264. श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सही है कि विधान सभा क्षेत्र हवामहल में पर्यटक सहायता केन्द्र नहीं होने के कारण पर्यटकों को समस्या होती है? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा हेतु

पर्यटक सहायता तथा सुविधा केन्द्र का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

पर्यटन मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): जी नहीं। विभाग द्वारा पर्यटन भवन स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर एवं हवामहल विधान सभा क्षेत्र में जन्तर-मन्तर एवं जलमहल की पाल पर स्थित पर्यटक सहायता बल बूथों के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विधान सभा क्षेत्र हवामहल में पृथक से पर्यटक सहायता तथा सुविधा केन्द्र निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर नवीन कार्यालय खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में देशी-विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं और उनके लिये पर्यटन स्थलों में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था नहीं है तथा लपके उन्हें परेशान करते हैं। इसलिए क्या पर्यटन स्थलों पर सरकार पुरुष एवं महिला गार्ड लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्तमान में कहां-कहां पर गार्ड हैं और अब कहां-कहां लगाने का विचार रखती है?

इसके अलावा, जलमहल चौपाटी में सामान बेचने वाले लोगों को आईडी कार्ड दिये जाने चाहिये और उन्हें ही वहां पर बैठने की व्यवस्था देनी चाहिये, क्योंकि वहां पर असामाजिक तत्व सामान बेचने के बहाने देशी-विदेशी पर्यटकों को, खास कर महिला पर्यटकों को परेशान करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसके साथ वहां पर स्मैक वगैरह का अवैध कारोबार भी करते हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या असामाजिक तत्वों को रोकने के लिये कोई गार्ड या कोई अन्य व्यवस्था की जा रही है? इसके साथ ही एक और मुद्दा यह है कि यहां पर पर्यटक आते हैं तो उनकी राजस्थानी वेशभूषा पहन कर फोटो खिचवाने की इच्छा होती है, परंतु शिकायतें यह आ रही हैं कि कपड़े पहनाने वाले पुरुष होते हैं और पहने वाली महिलाएं होती हैं और उसकी वजह से कई बार वहां पर छेड़छाड़ की शिकायतें हो रही हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): प्रश्न यही है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करने की मंशा है या नहीं? वहां पर जो गार्ड लगे हैं, वो निगरानी करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी अनगिनत शिकायतें हैं।

श्री अध्यक्षः करते हैं या नहीं करते, इसका उत्तर आने दीजिए।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सारे प्रश्न

एक साथ पूछ लिये।

श्री अध्यक्ष: हां, दो ही प्रश्न पूछने होते हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): यह एक गंभीर विषय है और 2024-25 में सिर्फ वर्ल्ड सिटी के विकास के लिये सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी दिया है। यहां हमारे बहुत सारे ट्यूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनका विकास करना, जिनको और अच्छा बनाना हमारे लिये प्राथमिकता है। अभी आपने प्रश्न पूछा कि जयपुर में पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु पर्यटक सहायता बल बूथ कहां-कहां हैं? ये हैं जंतर-मंतर में, जल महल में, आमेर में, अलबर्ट हॉल में और हवामहल में। इन पर समय-समय पर कार्यवाही होती है। पर्यटक सहायता बल पर्यटकों की सहायता के लिये ही गठित है। टीएएफ द्वारा राजस्थान में वर्ष 2022 में 236 शिकायतों पर, वर्ष 2023 में 311 शिकायतों एवं 2024 में 541 शिकायतों पर कार्यवाही की गई। गत वर्ष जयपुर में 170 लपकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिये पुलिस विभाग के साथ-साथ पर्यटन विभाग भी पूरा ध्यान रखता है। दिसम्बर, 2024 में पर्यटक सहायता बल के कर्मचारियों की संख्या 139 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि क्या सरकार वहां पर सहायता केन्द्र के साथ-साथ बोर्ड लगाने की मंशा रखती है, ताकि बोर्ड के माध्यम से वहां शिकायत दर्ज की जा सके। उसमें फोन नंबर एवं सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धी जानकारी हो, ताकि शिकायतें मौक़े पर हाथों हाथ की जा सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी ही ट्यूरिजम विभाग एक फोन एप भी शुरू करने वाला है। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आप अपने फोन पर ही उस एप को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें यह भी होगा, नियरस्ट पुलिस स्टेशन, नियरस्ट हॉस्पिटल, कहां से आपको टैक्सी मिलेगी, कहां से आपको क्या सहायता मिल सकती है, कहां जाना है, बहुत कुछ होगा। बहुत अच्छा फोन एप डवलप होने वाला है। राजस्थान में जो भी पर्यटक आयेगा, उसको यह सुविधा मिलेगी, लेकिन अभी जो आपने मुझे पूछा, तो मैं बताना चाहूंगी, चौड़ा रास्ता स्थित पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन का जीर्णोद्धार करवा कर 2015 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा साढ़े पांच करोड़ की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया गया था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर ट्यूरिस्ट फैसेलिटी सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके अंतर्गत स्वागत एवं प्रतीक्षा कक्ष, ए.टी.एम., फोरेन करेंसी एक्सचेंज, साइबर कैफे, ट्यूरिस्ट ब्यूरो ऑफिस एवं जन सुविधाओं का प्रावधान था। इसके प्रयोग पर निरंतर विचार-विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही इस केन्द्र को चालू करने का निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर के चिकित्सालयों में कार्यरत अस्थाई कार्मिक

265. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला उदयपुर के राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न व्यक्तियों को निजी कम्पनी के माध्यम से विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व किस-किस एजेंसी के माध्यम से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्मिकों की आर. एल. एस. डी. सी. के माध्यम से स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर से संबद्ध चिकित्सालयों में प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिको का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न व्यक्तियों को प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) दिनांक 19/02/2025 को घोषित बजट घोषणा के बिंदु संख्या 97 की सारणी के क्रम संख्या 5 अनुसार प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किये जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किये जाने की घोषण की गई है । जिसके संबंध में कार्मिक विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो प्लेसमेंट ऐजेंसी से संविदा पर हायर किये जाने वाले उदयपुर जिले में मेडिकल कॉलेजेज और हॉस्पिटल में कौन-कौनसी प्लेसमेंट ऐजेंसीज ने कितने लोगों को हायर किया है, वो डिटेल मैंने माननीय सदस्य को भेज दी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि राजस्थान लोजेस्टिक्स एवं स्किल डवलपमेंट कारपोरेशन के बारे में पूछा है। अभी बजट अलाउंसमेंट में हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पाइंट नंबर 97 तारीख 19.2.2025 सीरियल नंबर 5 पर यह घोषणा की थी कि अब प्लेसमेंट ऐजेंसीज के जरिये संविदा पर किसी को नहीं लिया जायेगा।

Msk/rtm/04.03.25/1140/1e

और Rajasthan Logistic and Skill Development कॉर्पोरेशन, वे आपके प्लेसमेंट आफ स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, कम्प्यूटर ऑपरेटर, हैल्पर, असिसटेंट, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, जितने भी जो संविदा पर हैं, वे डायरेक्टली हायरिंग करेंगे और अभी प्रोसेस

अंडर-वे है, डीओपी के पास गया हुआ है, जैसे ही डिओपी क्लीयर करेगा तो डायरेक्टली यहां से हायरिंग होगी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं, पर संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ जिसका न्यूनतम वेतन 9334 रुपये मासिक है, इसके अन्दर काम करने वाले वार्ड बॉय की योग्यता साक्षर होती है और नर्सिंग अधिकारी की योग्यता 12वीं के पश्चात तीन वर्ष छह माह की डिग्री होती है। मगर इन दोनों को एक समान ही वेतन मिल रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये ट्रेनिंगशुदा, तीन वर्ष छह माह की डिग्री लेकर, जो डिप्लोमा कर रखे हैं, उनको 26 हजार 500 रुपये देने का विचार रखते हैं। रखते हैं तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: एक ही पूछिए। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप जिनका संविदा का जिक्र कर रहे हैं, वे सब फोर्थ-क्लास एम्प्लॉइज हैं, इनका 60 परसेंट केन्द्र सरकार देती है, इनकी 40 परसेंट तनख्वाह हम वहन करते हैं। अभी इनको जो मिल रहा है, 2024-25 में जो 15.02.25 को तय किया गया था, इनकी सैलेरी 7830 थी, उसमें 999 ईपीएफ/ईएसआई के कट गये, शेष बचे 6831, ईपीएफ 888, 222 ईएस, 1609, जीएसटी मिलाकर ये 10661 हो गये। मानते हैं कि इनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हमारी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रपोजल भेजा है कि इनको नेट 10661 मिलता है, उसको बढ़ाकर 13601 कर दिया जाये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हो गया, दो हो गये, विराजें। आप तो सभापति हैं। श्री जब्बर सिंह खांखला।

आसीन्द नगरपालिका में नवीन उचित मूल्य की दुकानें

266. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राशन डीलरों को कमीशन के स्थान पर मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका, आसीन्द व ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी, नहीं। वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों को मानदेय दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उचित मूल्य दुकानदार को आवंटित मात्रा के विरुद्ध उसके द्वारा वितरित मात्रा के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है।

(2) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पूरक प्रश्न हैं। क्या सरकार राशन डीलरों के मानदेय के लिए भविष्य में कोई योजना बनाकर प्रस्ताव लेने का का विचार रखती है, जिसमें डीलरों का मानदेय कम से कम तीस हजार रुपये प्रतिमाह हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी तो वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सबका साथ, सबका विकास की धारणा पर चलते हुए इस बार बजट 2025-25 के बिन्दु संख्या 97 के क्रम 4 में राशन डीलरों के कमीशन में 10 परसेंट वृद्धि की गयी है। उन्हें पहले जो 137 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था, अब उन्हें 150 रुपये 70 पैसे क्विंटल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य हो गया?

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि नगरपालिका आसीन्द के कुछ वार्ड शहर से बाहर हैं। भैरूखेड़ा, आमलीखेड़ा, राजपुरा की झोपड़िया, अर्जुनपुरा की झोपड़िया, गोविन्दपुरा, चमनपुरा। ये वार्ड शहर से तीन से चार किलोमीटर की दूरी हैं। यहां कुछ वार्डों में, जैसे कि भैरूखेड़ा और गोविन्दपुरा में मापदण्डों में शिथिलता बरतते हुए इन वार्डों में नवीन दुकानें खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी इनकी विधान सभा से सात नयी उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्ताव आये हुए हैं, उसमें अगर आपको कोई भी लगता है तो उसमें हम जरूर देखेंगे। उसकी जांच कराकर, जहां उचित लगेगा, जहां आम जन को राहत प्रदान हो सके, वहां जरूर अवश्य खोला जायेगा।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह शेखावत।

बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सालय

267. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किस-किस श्रेणी के पशु चिकित्सालय स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में किस-किस संवर्ग के, कितने-कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद कब से रिक्त है? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कौन-कौनसे पशु चिकित्सालय भवन विहीन है? क्या सरकार उक्त भवनों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो

क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की रिक्ति का वर्षवार/दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत राजकीय भवन विहीन पशु चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ कर बात करें। प्रश्न काल है। बाद में या पास में बैठ जायें। खड़े होकर नहीं। कल इतनी व्यवस्थाएं दे दीं, फिर भी। माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): मेरा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि मेरे यहां पर पूरे जिले में सर्वाधिक गोशालाएं हैं, जिनमें 10 हजार से अधिक गोवंश है। इसके साथ ही वहां किसान डेयरी एक उद्योग के रूप में करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अच्छी नस्ल की वहां गाय और भैंस हैं और लोग डेयरी का कार्य करते हैं। इसे देखते हुए मैं मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि वहां बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखते हैं, क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिये कि इनके क्षेत्र में पशुओं की संख्या है, गोवंश की संख्या ज्यादा है। वैसे इनके क्षेत्र में चिकित्सालय खुले हुए हैं। पूरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र में ब्लॉट वेटेनरी चिकित्सालय 1 है, प्रथम श्रेणी के 2 रामपुर व नारायणपुर में है। पशु चिकित्सालय 10 हैं। पशु चिकित्सा उप केन्द्र 44 हैं। इनकी टोटल ग्राम पंचायतें शहर सहित 57 हैं, सब में पशु चिकित्सालय हैं। एक भी चिकित्साविहीन संस्था नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो मांग की है कि पॉली क्लीनिक की, जहां भी ये खोलना चाहते हैं, एक बार वे प्रस्ताव बनाकर भेजें। निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर आवश्यकता होगी तो खोलेंगे।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी से है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, दो प्रश्न हो गये।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): एक ही था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 57 में से 41 भवन में चल रहे हैं, इनके लिए आप जल्दी से कब तक भवन बनाने का विचार रखते हैं?

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि उप खण्ड नारायणपुर का जो पशु चिकित्सालय उप केन्द्र राजपुरा है, उसमें दो साल से एलएसए और

पशु परिचर, दोनों पद खाली हैं और दो साल से बंद पड़ा है, उस पर शीघ्र लगाने की व्यवस्था करें।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर विधान सभा क्षेत्र में टोटल 4 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, 5 पशुधन निरीक्षक के पद रिक्त हैं। निश्चित रूप से ये जो रिक्त पद हैं, उन्हें भी हम आवश्यकतानुसार भरेंगे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपने आशंका व्यक्त की है कि यहां बहुत सारी भवन रहित चिकित्सा संस्थाएं चल रही हैं।

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि बानसूर में कुल 16 संस्थाएं राजकीय भवन में संचालित हैं और 29 संस्थाएं ऐसी हैं, जो या तो ग्राम पंचायत के भवन में संचालित है, किराये के भवन में है या अन्य जगह वह संचालित है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि इसमें दो संस्थाओं ज्ञानपुर व तुराणा में भवन स्वीकृत है, लेकिन भूमि विवाद के कारण काम रुका हुआ है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भवन बनाने के लिए बजट घोषणा की थी, जिसमें 3 पशु चिकित्सालय व 6 उप केन्द्रों के भवन की स्वीकृति हमने जारी कर दी है। शीघ्र ही उन भवनों के टेण्डर होंगे और भवन बनेंगे। बाकी जो भवन रहित हैं, 41 में से 11 की स्वीकृति जारी हो गयी, शेष रहे वैकल्पिक व्यवस्था, ग्राम पंचायतों के किराया भवन, अन्य भवनों में चिकित्सा संस्थाओं के पट्टे बनने पर उनको चरणबद्ध तरीके से हम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार भवन स्वीकृत करेंगे।

mdp/rtm/04.03.25/11:50/1f

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री डूंगरराम गेदर।

श्रीगंगानगर जिले में संचालित औद्योगिमक इकाइयां

268. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा कितनी औद्योगिक इकाइयों को किस-किस श्रेणी (लाल, नारंगी व हरी) में रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में लाल श्रेणी वाली औद्योगिक इकाइयों को कब-कब व क्या-क्या नोटिस जारी किए गए? सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन रिलायंस बायो एनर्जी गैस प्लांट को किस श्रेणी का लाइसेंस जारी किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री संजय शर्मा): (1) श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा कुल 1113 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 21

औद्योगिक इकाइयां लाल श्रेणी, 689 औद्योगिक इकाइयां नांरगी श्रेणी और 403 औद्योगिक इकाइयां हरी श्रेणी में वर्गीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) श्रीगंगानगर जिले में लाल श्रेणी में वर्गीकृत औद्योगिक इकाइयों में निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करने पर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रावधानों/पर्यावरण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही करवाई गई है।

उक्त औद्योगिक इकाईयों को जारी किए गए नोटिसों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) सूरतगढ नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम 37 पीएनबी, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर में इकाई मैसर्स रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण हेतु जारी आदेश दिनांक 02-06-2020 के अनुसार हरी श्रेणी में वर्गीकृत है।

उक्त इकाई को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा दिनांक 04.06.2024 को स्थापना सम्मति जारी की गयी। इकाई को जारी स्थापना सम्मति की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न हैं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे मिल गया है। मुझे पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं?

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): उत्तर प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मेरा पूरक प्रश्न यह है कि आपने उत्तर दिया है कि श्री गंगानगर जिले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 21 औद्योगिक इकाइयों को लाल श्रेणी में इंगित किया है। इसमें श्री गंगानगर शुगर मिल की 2 यूनिट, सूरतगढ़ थर्मल पावर की सारी यूनिट, बांगड़ सीमेंट, श्री सीमेंट, जालन्धर की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त नहरों में आ रहा पानी, इनकी वजह से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा किडनी फेल बीमारी के मरीज आ रहे हैं। दमा, खांसी, सांस की बीमारी, टी.बी. आदि गंभीर बीमारियां बुरी तरह से फैल रही हैं। सरकार इनको रोकने के लिए क्या प्रबंध कर रही है स्पष्ट रूप से बताइए?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है और मैंने उत्तर में भी कहा है कि जो आपने माना कि जो औद्योगिक इकाइयों का आपने नाम लिया, वह रेड श्रेणी में हैं। रेड श्रेणी में हम मानते हैं मोस्ट पोल्यूटेड, लेकिन फिर भी समय-समय पर विभाग द्वारा उनको ताइद किया जाता है और समय-समय पर उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जांच भी की जाती है, जिससे प्रदूषण को हम रोक सके। आने वाले समय में आप जो भी सुझाव देंगे, विभाग के द्वारा मैं आश्वस्त करता हूं कि उन पर अमल किया जायेगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): जो बीमारियां फैल रही हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): बीमारियों को रोकने का काम, माननीय अध्यक्ष महोदय,...।

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुन लीजिए पहले आप। दूसरा प्रश्न है ये बीमारियों वाला।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): दूसरा नहीं है पहला ही है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): प्रदूषण विभाग का काम प्रदूषण को रोकने का है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के इलाज का काम माननीय चिकित्सा मंत्री जी द्वारा है। एक मिनट, माननीय सदस्य, मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में उस प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोकें, विभाग उस पर संवेदनशील होकर काम करेगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): आपने जवाब में यह कहा है कि लाल श्रेणी की इकाइयों को आपने नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया। ये जवाब आये हुए डेढ़ साल और दो साल हो गये। इसके बावजूद भी आज मुझे जो उत्तर मिला है, उसके अन्दर भी उन्हीं इकाइयों को, 21 इकाइयों को आप लाल श्रेणी में मानते हैं। डेढ़ साल पहले भी वह लाल श्रेणी थी, आपने जवाब मांग लिया। वापस संतोषजनक जवाब कैसे आया? या तो परिशिष्ट अ जो आपने जवाब दिया, वह सही नहीं है या फिर परिशिष्ट ब जो आपने दिया वह सही नहीं है। आप इसको स्पष्ट कीजिए की ये 'अ' सही है या 'ब' सही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भी औद्योगिक इकाई के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है या जांच के दौरान उसके अन्दर नियमों की अवहेलना प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा विधि सम्मत नोटिस दिया जाता है। उसको उस कमी को दूर करने का समय दिया जाता है और यदि उस समय सीमा के अन्दर वह उसको दूर नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जैसा कि आप मान रहे हैं कि नोटिस दिया गया और नोटिस के अन्दर लिखा भी जाता है कि आपके अन्दर ये-ये कमियां पायी गयीं, 15 दिन के अन्दर आप उस कमी को दूर करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिसके अंतर्गत हम बिजली कनेक्शन काटने का और इकाई को बंद करने का काम भी करते हैं। एक बार हम उन इकाइयों की दोबारा जांच कर लेंगे, यदि उसमें कमियां पायी गयी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): 01/01/2024 का जवाब है। सवा साल हो गये।

श्री अध्यक्ष: आपके दो प्रश्न हो गये। अब नहीं। कालीचरण जी। विषय तो गंभीर है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप देखिए आपने जो परिशिष्ट ब पर दिया है, पतंजलि का है। आपने नोटिस दिया और जवाब आ गया, आप संतुष्ट है और उसके बाद फिर लाल श्रेणी में क्यों मान रहे हैं। एक ही बात तो होगी या तो लाल में रहेगी या नहीं रहेगी या

फैक्टरी बंद रहेगी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाल श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि उन औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जाए। उनको ताइद किया जाता है कि नियमानुसार वे अपने मापकों में चेंज करें। आपको पतंजलि या रिलायंस से चिढ़ क्या है, ये बता दीजिए आप।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पतंजलि को बचाने का ठेका ले रखा है क्या?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): बचाने का ठेका ..(व्यवधान)... नहीं ले रखा, नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियमानुसार चलवाइए ..(व्यवधान)... नियमों से चलाओ।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न पूछ लिया है। आप बैठिए। आपस की बात यहां नहीं।

जयपुर सेन्ट्रल जेल का अन्यत्र स्थानान्तरण

269. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सेन्ट्रल जेल घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जेल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है।

वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जयपुर को घनी आबादी क्षेत्र से स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं बाहर भेज दूंगा। प्रश्नकाल के दौरान सभी सदस्य अपनी-अपनी जगह पर बैठेंगे, मंत्री भी और आप भी। अति-आवश्यक हो तो कोई मंत्री के पास आकर बैठे। देख रहा हूं कोई वहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है। प्रश्नकाल में भी हम गंभीरता नहीं बरत सकते? एक घंटे इंतजार कर लीजिए। आपके सदस्य भी बैठे हैं। जीरो आवर तक तो कम से कम आप सहयोग कीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान जयपुर सेन्ट्रल जेल में कितने कैदी रखने की केपेसिटी है और कितने कैदी रखे हुए हैं? माननीय उच्च न्यायालय ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी बार राज्य सरकार को सघन आबादी क्षेत्र से जेल शिफ्ट किये जाने के लिए कब-कब निर्देश दिए? पहला क्वेश्चन, दूसरा मेरा है।

श्री अध्यक्षः दो ही हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने उत्तर में कहा कि जयपुर शहर की सेन्ट्रल जेल को शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में भूमि चिन्हीकरण का काम चल रहा है। पिछले दस साल में कम से कम हर सेशन में यह प्रश्न आता है और जवाब मिलता है कि मामला प्रक्रियाधीन है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जे.डी.ए. ने चाकसू तहसील के गांव तितरिया में 170 बीघा जमीन इसके लिए आपको बतायी है तो क्या आप वहां पर इस जेल को स्थानांतरित करेंगे? करेंगे तो कब तक करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो जयपुर में केन्द्रीय कारागृह है, उसकी बंदी क्षमता क्या है? इस जेल की बंदी क्षमता है 1173 और निरुद्ध बंदियों की संख्या है 1751, यहां ज्यादा बंदी होते हैं तो उनको दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है।

दूसरा आपका प्रश्न है कि कब-कब सम्माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। यह मैं निर्देशों की जानकारी करके आपको जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन हमने जो कार्यवाही की है, यहां जो बजट घोषणा 2022-23 हुई, उसमें भी बिंदु आया था। जो 25 केन्द्रीय जिला कारागृह हैं, उनके अंतर्गत जयपुर को भी शामिल किया गया है, बाहर शिफ्ट करने के लिए। हमारे द्वारा, विभाग के द्वारा जिला कलक्टर को पत्र लिखा गया है कि जमीन का चिन्हीकरण करें। सम्माननीय सदस्य द्वारा जो जमीन बतायी गयी है कि जे.डी.ए. देने को तैयार है, हमारा विभाग कोर्डिनेशन करके यदि उपयुक्त जगह होगी तो उसमें शिफ्टिंग करने की हम कार्यवाही जरूर शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। ये जेल अभी यहां पर है, क्योंकि जयपुर में ज्वैलरी का बहुत जबरदस्त काम है। दो लाख लोग इसमें काम करते हैं। मजदूरी मिलती है। यदि वहां ज्वैलरी का हब बना दिया जाए और वहां गद्दियां ऑक्शन करें ज्वैलर्स को तो आपको उतना पैसा मिलेगा जिससे वह जेल भी बन जाएगी और यहां कामर्शिलय कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसके बारे में गंभीरता से विचार करें, क्योंकि न्यायालय ने 2016 में और अभी दो बार आपको इस बात के लिए निर्देशित कर दिया, उसके बाद भी मामला प्रक्रियाधीन है, कह कर हम इतिश्री कर लेते हैं। इस बारे में गंभीरता से विचार करके जेल को स्थानांतरित करने की बात करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, हमें नवीन कारागृह निर्माण हेतु 1 लाख 30 हजार वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। पैसा कितना भी लगे, सुविधाएं

डवलप करने केलिए सरकार कृत संकल्पित है। जैसे ही जगह चिन्हीकरण हो जायेगा, चिन्हिकरण होने के बाद आपकी जेल की शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

समदड़ी पंचायत समिति मुख्यालय में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय की स्थापना

270. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश की सभी नवीन पंचायत समिति मुख्यालयों पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय खोल दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला बालोतरा की नवीन पंचायत समिति मुख्यालयों पर उक्त कार्यालय खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो समदडी पंचायत समिति मुख्यालय पर कब तक उक्त कार्यालय खोल दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी नहीं। प्रदेश की 11 पंचायत समिति मुख्यालयों पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोला जाना शेष है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बालोतरा जिले की समदडी व पाटौदी पंचायत समिति मुख्यालयों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोला जाना शेष है। समदडी पंचायत समिति मुख्यालय पर बाल विकास परियोजना कार्यालय खोला जाना संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): उत्तर आ गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उप मुख्य मंत्री जी को मेरे समदड़ी में सी.डी.पी.ओ. ऑफिस नहीं है, इसको खोलने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछ लें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): पूछ लिया साहब, यही प्रश्न पूछा है।

Ans/rtm 12.00 1g 04.03.2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बाल विकास परियोजना कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र की आवश्यकता व संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाता है। मैं इसका परीक्षण करवा लेती हूं। परीक्षण करवाकर एवं परीक्षण उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2025 को शुभारंभ

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त।

मुझे माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दूं, दो जानकारियां देनी हैं।

एक, हमारे यहां कांस्टिट्यूशन क्लब हम सबने तैयार किया है। बहुत आग्रह था कि इसका शुभारम्भ किया जाए। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 08 मार्च को दोपहर 11.00 बजे इसका शुभारम्भ लोक सभा स्पीकर माननीय ओम जी बिरला करने वाले हैं। आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि उसमें पधारें। साथ ही, जो विधायक महोदय अभी सदस्य नहीं बन पाए हैं, उनसे आग्रह है कि तब तक वह उसके सदस्य बन जाएं। यह आपका ही क्लब है और अपन सबको उसका सदस्य बनकर, अच्छे रूप से इसकी सुविधाओं का लाभ लेना है, यह आपको जानकारी देनी थी। ...(व्यवधान)... मेरे से पूछ लेना। जो कुछ अलग से पूछना है, मेरे से पूछ लेना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लंच तो दिलाएंगे?

श्री अध्यक्ष: लंच होगा। कोई कमी नहीं होगी, लंच बढ़िया होगा, स्वादिष्ट होगा और आपकी रुचि पूर्वक होगा। ...(व्यवधान)... बैठिये, सब खड़े हो गये। मैं खड़ा हूं अभी तो, बैठो। मैं अनुमति दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने आपकी परमीशन ली है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि दिन में लंच वगैरह होगा, उसके बाद शाम को क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: जब यह प्रारम्भ हो जाएगा, उसमें जो कुछ उपलब्ध सुविधाएं हैं, उसका यथा नियमानुसार हम उसका उपयोग कर सकेंगे।

मुझे दूसरी सूचना यह देनी है कि हम सब समझदार है, बार-बार मैं आप जैसे समझदार लोगों को कोई निर्देश दूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम सब पता है कि जब प्रश्न काल होता है तो कम से कम प्रश्न काल में तो अपनी सीटों पर बैठें। मैं देख रहा हूं कि प्रश्न काल में ही कुछ सदस्य इधर के कुछ उधर के घूम रहे हैं।

मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा कि अपनी बात 11 बजे पहले करके आ जाओ। कम से कम 11 से 12 तो अपना सारा कंसन्ट्रेशन सदन में दे और यहां तक सम्भव है कि जीरो आवर तक दें तो अच्छा रहेगा। हम सब पालन करेंगे, कल मैंने जो कुछ कहा है। इसको आदर्श विधान सभा बनाने के लिए हम सब प्रयत्नशील है। मैं कोशिश कर रहा हूं और आप सब भी सहयोग करेंगे।

सदन के अंदर बोलते समय जो मैंने कल कहा था लेकिन मेरे निर्देश के बावजूद कोई शब्द ऐसे निकले, आपके तकिया कलाम में होंगे, वह जरा इस हाउस के बाहर करें। वरिष्ठ लोग हैं इसलिए मैं उनका कोई नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने एक्सपंज कर दिये हैं। लेकिन हम सब बोलते समय सावधानी बरतें। एक दूसरे का सम्मान भी रखे, अपनी बात भी कहे उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सबको अवसर दे रहा हूं, फिर भी ऐसे शब्द निकलते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। हम सब समझदार हैं, इस प्रकार का नहीं करें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के पास विधायक जाकर बैठे हैं, उससे न्यूसेंस क्रियेट होती है, उसके बारे में आपने निर्देश दिये हैं, वह उचित

है। लेकिन मेरे पास यदि कोई आता है या मैं किसी के पास जाता हूं तो मेरे पास ट्रांसफर का काम नहीं है, मेरे पास सारा इस हाउस के संचालन को लेकर ही है, इसलिए मुझे थोड़ा उससे अपवाद माना जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः पूरे सात घंटे चलता है, वही एक घंटा मिलता है, यह सम्भव नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसको और कोई बात मेरे से पूछनी है अकेले में चैम्बर में आकर पूछे ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, यहां नहीं। बैठे-बैठे नहीं। चैम्बर में आकर पूछे। हम लोग कोई अनुशासन भी बनाये रखे।

एक बात जो आप बार-बार कह रहे हो ना, जब भाषण होते हैं हम बीच में एक दूसरे पर छोटी-मोटी कटाक्ष करते हैं, टोटिंग करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, वहां तक सम्भव है। लेकिन एक सदस्य कोई एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा लेकिन एक ही भाषण में या दो-तीन के भाषण में हम बार-बार करेंगे, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी चाहे दोनों पक्षों में से, यह उचित नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में फाइनेंस कम्पनियों की कार्यशैली से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

2. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में फसल का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री मुकेश भाकर, सदस्य की ओर से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का स्थायी रजिस्ट्रेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से डिग्गी अनुदान योजना में आवेदन की अवधि न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर बसी आबादी के पट्टे नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर ज़िले में संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से गौ माता को राज्य पशु का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

8. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राजसमन्द में खनन माफियाओं द्वारा वन अधिकारियों पर किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से रतनगढ़ बस स्टैण्ड पर कार्मिकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर

विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में चने की फसल में रोग लगने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री घनश्याम एवं 06 अन्य सदस्यों की ओर से सांगानेर में भूमाफियाओं द्वारा युवक की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की ओर से एम.बी.सी. आरक्षण को नवीं अनूसूची में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से सूरत के शिवशक्ति टैक्सटाईल मार्केट अग्निकाण्ड से प्रभावित प्रवासी राजस्थानियों को आवश्यक सहायता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री विकास चौधरी, श्री घनश्याम, डा. ऋतु बनावत एवं श्री रफीक खान को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री राम सहाय वर्मा (रेगर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की सिवायचक तथा गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

2. श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से सवाई माधोपुर ज़िले में अवैध खनन पर रोक लगाये जाने के संबंध में।

3. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से भादरा में पृथक् उपनिवेशन तहसील का सृजन तथा चकबन्दी एवं किलाबन्दी कार्य करवाये जाने के संबंध में।

4. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना से वंचित ग्राम एवं ढाणियों को जोड़ने के संबंध में।

5. श्री उदयलाल डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायतों तथा ग्रामों को टी.एस.पी. क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

6. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के टैन्ट व्यवसायी की संदेहास्पद मृत्यु की जांच के संबंध में।

7. श्री सुखवंत सिंह, सदस्य की ओर से रामगढ़ में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाने के संबंध में।

8. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से पटवारी भर्ती, 2025 में नियमानुसार आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

9. श्री दीन दयाल, सदस्य की ओर से दौसा शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था के संबंध में।

10. श्री रामावतार बैरवा, सदस्य की ओर से चाकसू में आयुष चिकित्सा महाविद्यालय के

भवन निर्माण के संबंध में।

11. श्री सोहन लाल नायक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में क्षतिग्रस्त नहरों तथा खालों के पुनर्निर्माण के संबंध में।

12. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में।

13.श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के संबंध में।

14. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।

15. भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बांधों को रामजल सेतु लिंक परियोजना से जोड़ने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

VPS-RTM-04.03.2025-12.10-1h

पर्ची

आज दिनांक 04.03.2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 40 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री अरूण चौधरी	फाल्गुणी मेला, खाटू श्याम बाबा मन्दिर में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।
2.	श्री हरलाल सहारण	चूरू जिला मुख्यालय की नगर परिषद सीमा में आने वाले पार्कों की स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री लालाराम बैरवा	शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में बनेड़ा के कतिपय गांवों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4.	श्री चेतन पटेल कोलाना	चम्बल फर्टिलाइजर गढ़ेपान में गैस लीकेज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम समिति के प्रतिवेदन के सम्यक् वितरण के अभाव में सदस्यगण को संशोधन प्रस्तुत करने के अवसर की अनुपलब्धता

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्षजी, 27 तारीख को यहां पर नियम समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत

किया गया और प्रक्रिया के नियम 248 के अन्दर जब यह प्रावधान है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय, जब यह जीरो ऑवर हो जाये, उसके बाद आप रखना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट की बात है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप दस मिनट बाद कर देना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं दो मिनट में बोल लूंगा तो क्या दिक्कत है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसी को बैठाकर, बीच में दो मिनट बोलना ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे शुरू होने से पहले, यही समय होता है इसलिए मैं नियमों के तहत ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कोई भी विषय लाना हो तो जीरो ऑवर के बाद लाएं ताकि मैं अनुमति भी दे सकूं। जीरो ऑवर के बाद करवा देंगे आपका।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, यह तो व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो हमेशा इसके बाद ही आता है। हमेशा आता है। कल भी आप लेकर आये थे। इसी टाइम तो लेकर आये थे। आप जीरो ऑवर के बाद लाये थे क्या कल?

श्री अध्यक्षः नहीं, वह तो आवश्यक था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तो यह भी आवश्यक ही है, साहब।

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न काल के बाद ही होता है विशेषाधिकार का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतनी टाइम में तो मैं बोल ही जाता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 248 में यह प्रावधान है कि- 'समिति की सिफारिशें मेज पर रखी जायेंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जायें उससे आरम्भ होकर सात दिनों की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह प्रतिवेदन जो है, वह सदस्यों को वितरित ही नहीं किया गया और जब वितरित ही नहीं किया गया तो सदस्यों को जानकारी ही नहीं है तो किस नियम के तहत वे संशोधन लेकर आएंगे? इसीलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि प्रक्रिया नियम और संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अंतर्गत जो विरचित किये गये हैं, इस प्रकार यह संविधान तथा प्रक्रिया के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए माननीय सदस्यों के नियम समिति के प्रतिवेदन में संशोधन प्रस्तुत किये जाने के अधिकारों को कर्टेल करने का प्रयास किया गया है, यह अनुचित है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आज ही इसका सर्कुलेशन किया जाये, इसको सर्कुलेट किया जाये और उसके सात दिन के बाद में आप इसके प्रतिवेदन में संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में आसन से यह व्यवस्था दे दी गयी थी कि सारे प्रगति प्रतिवेदन, सारी वार्षिक रिपोर्ट, वे सारे के सारे ऑनलाइन उपलब्ध हैं और फिजिकली वितरण नहीं किया जायेगा। यह आसन से

व्यवस्था दी जा चुकी है। आप ऑनलाइन सर्च करिये और बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस बार आसन से यह व्यवस्था है कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उनको बोल दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आप बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा ऐसा निवेदन है कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष का यह आरोप कि संविधान के किसी आर्टिकल का या अनुसूची का या विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया का कोई उल्लंघन हो रहा है, यह आरोप तो बिलकुल गलत है।

दूसरा, जहां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत होना और प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का, संशोधन करने का अवसर देना, यह विधान सभा सचिवालय का काम है। जैसा भी आप आदेश देंगे, हम उसकी पालना करेंगे लेकिन आपका आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अब मैं व्यवस्था दे दूं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए। यह अपनी बात को विधान सभा सचिवालय पर डाल कर बैठ गये। बात यह नहीं है। यह आरोप नहीं है। मैं जो तथ्य रख रहा हूं, गलत है तो आप बता दीजिए, सबसे पहली बात।

दूसरी नम्बर की बात, आपने यह कहा है कि यह विधान सभा अबकी बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगी। तो यह क्या बात हुई कि ऑनलाइन इस पर देख लेंगे और आप यह बता दो कि कहां है यह प्रतिवेदन?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। हो गया, आप उनसे मत पूछिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऑनलाइन आप देखकर बता दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री इतने दिन हाउस चलने के बाद भी वे बच्चे लगे हुए हैं, उनसे ही इसको खुलवाकर चलवा रहे हैं। आपको तो जानकारी आयी नहीं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय, विराजिये। ...(व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य: शेम।

श्री अध्यक्ष: अब न तो शेम की बात है और न कोई नियमों की बात है। मतलब, कोई बात हो तो शेम करें। क्या तमाशा है यह?

मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट है कि अपने सदन के अन्दर नियम समिति की रिपोर्ट रखी गयी और वह ऑनलाइन हो गयी। सात दिन के अन्दर किसी का कोई मेरे पास एक का भी नहीं आया। हमने दोनों व्यवस्थाएं इसीलिए दी थीं कि जो लोग नहीं समझ पाते, उसको कोई आये तो तब तक आ जाये। यह जब आ गया तो मेरे पास आ जाते या सचिवालय को देते। अतः यह नियम समिति की रिपोर्ट नियमानुसार स्वीकृत की गयी है। आगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य से आप पूछ लें, एक भी सदस्य के पास आयी हो तो रिपोर्ट, एक भी सदस्य ने देखी हो तो, आप

पूछ लो। यह सारे बैठे हैं, सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य बैठे हैं।

श्री अध्यक्षः बैठिये। अगला, श्री विकास चौधरी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्षः आप बोलिये। श्री विकास चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अजमेर में चने की फसल में रोग लगने से उत्पन्न स्थिति

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपका अजमेर जिले से ऐसे ही प्रेम बना रहे।

श्री अध्यक्षः मेरा तो सभी से प्रेम है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गम्भीर विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। रबी की फसल, चने की जो खड़ी फसल है उसमें उकठा रोग लगने से पूरे अजमेर जिले के, विशेष तौर से अराई, बोराड़ा, सरवाड़, मालपुरा, दूदू के क्षेत्र में इस रोग से जब दस-पन्द्रह दिन बाद फसल कटनी है, यह रोग पूरी फसल को खराब कर चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेष गिरदावरी के आदेश शीघ्र से शीघ्र आप दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2024 में अतिवृष्टि के कारण पूरी फसल खराब हो चुकी है। आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। रबी की फसल भी इस उकठा रोग के कारण लगभग-लगभग खराब हो चुकी है। किसान यह कह रहे हैं कि हमारी अतिवृष्टि के कारण पहले खरीफ की फसल खराब हो गयी और अब उकठा रोग के कारण रबी की फसल खराब हो गयी, तो इन दोनों फसलों के खराब होने से किसानों का राम तो रूठ गया लेकिन मुख्य मंत्रीजी के बारबार संबोधन में यह कहते हुए वे नजर आते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि किसानों की गिरदावरी अतिशीघ्र करें और उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा रैंडम प्रक्रिया द्वारा क्रॉप की कटिंग हो और क्रॉप की कटिंग जब हो वह किसानों के सामने हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज से यह आशा है कि राज तुरंत गिरदावरी कराये और इस रैंडम प्रक्रिया में क्रॉप कटिंग किसानों के सामने करके किसानों से चना फसल 1,327 प्रीमियम राशि बीमा कम्पनियां लेती हैं और लगभग 14,163 क्लेम राशि पर बीघा यह बीमा कम्पनियां देती हैं लेकिन बीमा कम्पनियां अपनी हठधर्मिता निभा रही हैं। किसानों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करता हूं कि शीघ्र किसानों को राहत दें, नहीं तो पूरे अजमेर जिले के किसान एक आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं।

आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम।

सांगानेर में भू-माफियाओं द्वारा युवक की हत्या

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के तहत आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक गम्भीर मुद्दा लाना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में एक दलित युवक की 28.11.2024 को निर्मम हत्या कर दी गयी और उस युवक को मार कर सड़क पर पटक दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक पुलिस उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष मुख्य मंत्रीजी के पास मिलने गया तो उनको मिलने का मौका भी नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में लगातार भू-माफियाओं द्वारा जयपुर शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं इनमें राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को मिला हुआ है और जो भू-माफिया हैं, जिनका जयपुर शहर में आये दिन आतंक है, कहीं मकानों पर कब्जा करना, कहीं जमीनों पर कब्जा करना, यह इस प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि ऐसे दलित लोगों की मदद अगर आपके अध्यक्ष होते हुए भी नहीं हो पाएगी तो फिर इस प्रदेश में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर मुद्दे पर गृह मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हाउस में बैठे हैं तो उनको यह बताना चाहिए और यह वक्तव्य देना चाहिए कि हम अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा करेंगे और उनकी मदद करेंगे। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि इन लोगों की मदद की जाये और दलितों को इस भारतीय जनता पार्टी के राज में बचाया जाये।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत।

एम.बी.सी. आरक्षण का संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलन

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.बी.सी. समाज में पांच जातियां हैं- गुर्जर, रेबारी, गाडिया लोहरा, बंजारा और राइका को कुल पांच प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया गया।

ssy/rtm/04.03.2025/12.20/1j

मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान की 5 से 7 परसेंट जनसंख्या एमबीसी समाज से आती है। उन्होंने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया। ट्रेनें रोकीं, कई लोग शहीद हुए और नेशनल हाईवे तक जाम किये। लंबे संघर्ष के बाद उनको यह 5 प्रतिशत आरक्षण मिला। लेकिन 2 बार राजस्थान विधान सभा से प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया, फिर भी केन्द्र की 9वीं

अनुसूची में यह आरक्षण नहीं जोड़े जाने के कारण सदैव समाज के लोगों को यह आशंका बनी रहती है कि हमारा आरक्षण खत्म हो जायेगा।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मेरा निवेदन है कि डबल इंजन की सरकार हमारे साथ है। पूरा एमबीसी समाज सरकार से यह उम्मीद कर रहा है कि उनको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाये और इस आशंका को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाये। पूर्व में भी 4 बार राज्य सरकार ने एमबीसी समाज को आरक्षण दिया और 3 बार उनका यह आरक्षण रिजेक्ट हुआ। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि एमबीसी समाज को आरक्षण के लिए 9वीं अनुसूची में सरकार का, विधान सभा का प्रस्ताव जाये जिससे कि उनकी आशंका को समाप्त किया जा सके।

मेरा यह भी कहना है कि जो शहीद हुए, उनमें से एक व्यक्ति रूपनारायण गुर्जर, उसके आश्रित को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उस पर भी सरकार विचार करे।

साथ ही यह आरक्षण रोस्टर के माध्यम से दिया जाये। 2020 में जो समीक्षा की गई थी आंदोलन के बाद, उसमें कहा गया था कि 372 नियुक्तियां दी जायेंगी। उन पर भी सरकार विचार करके नियुक्तियां प्रदान करे।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि एमबीसी समाज से 10 सदस्य सदन में भी उपस्थित हैं और उन सबकी मनोभावना भी यही है कि एमबीसी समाज के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़कर सदैव के लिए हर तरह की आशंका से समाज को मुक्त किया जाये। उनको इस डर से मुक्त किया जाये कि उनका आरक्षण निरस्त हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। श्री रफीक खान।

सूरत के टैक्सटाईल मार्केट अग्निकाण्ड से प्रभावित

प्रवासी राजस्थानियों को सहायता

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, राजस्थान के बहुत से व्यापारी पूरे देश में अलग-अलग जाकर व्यापार करते हैं। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर सूरत में 26 तारीख को शिवशक्ति टैक्सटाइल मार्केट में आग लगी, हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान व्यापारियों का हो गया। उनकी सारी नकदी जल गयी। माल जल गया। वह बिलकुल सड़क पर आ गये, उनके पास में कुछ भी नहीं है।

अभी तक हमारे यहां से कोई रिप्रजेंटेशन सरकार का गया नहीं है। हमने सुध नहीं ली है। व्यापारी सड़कों पर हैं। एक खास बात और है कि वहां एक एसोसिएशन है राजस्थान के व्यापारियों की, निर्मल जैन उसके अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैं धन्यवाद दूंगा निर्मल जैन को कि उन्होंने अपने एक दूसरे मार्केट में ऐसे 400 राजस्थानियों को जगह दी है ताकि वह फिर से अपना काम शुरू कर सकें।

मैं, सारे व्यापारियों की तरफ से मुख्य मंत्री जी से गुहार करना चाहता हूं कि उनकी सुध लें और उनके यहां एक डेलीगेशन राजस्थान से जाये। उसमें सत्ता पक्ष के साथियों के साथ

विपक्ष के साथी भी जायें। जैसे हमारे रविन्द्र जी हैं, वह शायद उसी एरिये से आने वाले हैं, ऐसे किसी साथी को जिनका एरिया बनता है, उनको साथ लेकर जायें। प्रतिपक्ष के व्यक्तियों को साथ लेकर जायें। वहां के व्यापारियों से बात करें। क्या उनको हम कंपनसेशन दे सकते हैं? कोई फाइनेंसियल एड दे सकते हैं? कोई लोन दे सकते हैं? कैसे उनका व्यापार वापस से शुरू हो, इस पर संज्ञान लिया जाये और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाये। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: 295 । हां। जवाब दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही गंभीर है और मानवता से जुड़ा हुआ भी है। हमारे राजस्थान के अनेक जिलों के व्यापारी सूरत में एक स्पेसिफिक मार्केट है जिसमें व्यापार करते हैं, जिसका रफीक भाई ने जिक्र किया। बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, बहुत भारी नुकसान भी हुआ।

लेकिन जिस दिन अग्निकांड हुआ, उसके घंटे, 2 घंटे बाद में ज्यों ही हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत ही गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की और यह कहा कि हमारे राजस्थानियों को अग्निकांड से जो नुकसान हुआ है, मन में जो पीड़ा हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वह संपूर्ण भरपाई तो शायद हो पाये नहीं, लेकिन उनकी तुरंत सहायता होनी चाहिए। उस सम्बन्ध में वह पूरे प्रयत्नशील हैं। सरकार भी बार-बार उनके संपर्क में है। जितना राजस्थान सरकार की ओर से उनका सहयोग करने की आवश्यकता होगी, राजस्थान सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला, 295 । श्री रामसहाय वर्मा। हो गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट। एक लाइन।

श्री अध्यक्ष: स्थगन में हो जाता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इनके नॉलेज में डाल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थगन में दोबारा नहीं। स्थगन में आपको बोलने की अनुमति दे दी भई। आपको जो बोलना था, आपको अनुमति दे दी।

श्री रामसहाय वर्मा।

निवाई की सिवायचक तथा गोचर भूमि से अतिक्रमण की बेदखली

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई तथा पीपलू में अवैध अतिक्रमण कर अवैध कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना पड़ता है।

उक्त स्थान की सिवाय चक जमीनें तथा गोचर भूमि पर अतिक्रमण से बारिश के दौरान नदी, नालों में पानी के निकास में परेशानी होती है, जिससे स्थानीय निवासियों के घरों में

पानी भर जाता है। अतः निवाई तथा पीपलू की सिवाय चक जमीनें तथा गोचर भूमि की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराये जाकर स्थानीय निवासियों को राहत देने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती इन्द्रा। श्रीमती इन्द्रा। (अनुपस्थित)

श्री संजीव कुमार।

भादरा में पृथक् उपनिवेशन तहसील का सृजन तथा चकबंदी एवं किलाबंदी कार्य

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि तहसील भादरा में चकबंदी/मुरब्बाबंदी/किलाबंदी का कार्य वेप्कोस लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। परन्तु वेप्कोस कम्पनी द्वारा उपरोक्त कार्य में भारी गलतियां की गयी है, जिससे कंपनी द्वारा किये गये कार्य को मौके पर लागू करवाया जाना संभव नहीं है।

महोदय, उक्त कम्पनी द्वारा पूर्व में वर्ष 2007-08 में भी चकबंदी/मुरब्बाबंदी/किलाबंदी का कार्य किया गया था, परन्तु उस समय भी कंपनी द्वारा भारी त्रुटियां व अनियमितताएं किये जाने के कारण उक्त कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, जिससे यह कार्य अपूर्ण रह गया था।

महोदय, पिछली भाजपा सरकार ने विधान सभा के बजट में तहसील भादरा को उपनिवेशन तहसील घोषित किया था परन्तु उप निवेशन विभाग में पटवारी व भू- अभिलेख निरीक्षक के पद रिक्त होने व स्टॉफ के अभाव के कारण उक्त कार्य विभाग द्वारा नही करवाया जा सका।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राज्य सरकार द्वारा तहसील भादरा में चकबंदी/ मुरब्बाबंदी/किलाबंदी का कार्य पुनः उसी वेप्कोस लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट कर कंपनी को कार्य सौंप दिया, परन्तु इस बार भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर भारी अनियमितताएं की गयी हैं। जो कि उपनिवेशन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जांच में कंपनी के उक्त कार्यों में भारी त्रुटियां होने से मौक़े पर लागू नहीं करवाया जा सकता। उप निवेशन विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त जांच में यह पाया गया है कि मौके पर लगाये गये पत्थरों एवं कंपनी द्वारा प्रदत्त कोर्डिनेट्स ब्लॉक में 1 से 3 बीघा तक रकबा कम पाया गया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा तैयार चक वाइज जमा बंदी का कुल रकबा सी.सी.ए. चक प्लान से भी मेल नहीं खाता है।

अतः आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र भादरा, जिला हनुमानगढ़ में अलग से उपनिवेशन तहसील सृजित कर चकबंदी/मुरब्बाबंदी एवं किलाबंदी का कार्य उपनिवेशन विभाग द्वारा पूर्ण करवाये जाने के आदेश प्रदान कर अनुगृहीत करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना से वंचित ग्राम एवं ढाणियां

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत देवानिया-नाथड़ाऊ परियोजना का कार्य चल रहा है। इस परियोजना में पाइप लाइन का सर्वे वर्ष 2019 में किया गया था, जिसमें शेरगढ विधान सभा क्षेत्र के कुछ राजस्व गांव एवं ढाणियां सर्वे से वंचित रह गये हैं। वंचित रहे राजस्व गांव एवं ढाणियों को इस परियोजना में जोड़ा जाए।

देवानिया-नाथड़ाऊ परियोजना में कुल 5,000 किलोमीटर पाइप लाइन थी जो कि अभी रिवीजन सर्वे में 6,800 किलोमीटर हो गई है तथा परियोजना की राशि 262.19 करोड़ से 290 करोड़ हो गई है। जिसकी डिविएशन स्टेटमेंट पत्रावली अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त डिविएशन स्टेटमेंट पत्रावलि गत एक वर्ष से स्वीकृति हेतु जयपुर मुख्यालय स्तर पर लंबित है। इस स्वीकृति के अभाव में कार्य पूर्ण न होने से योजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित राजस्व ग्राम एवं ढाणियों को जोड़ने हेतु लंबित डिविएशन स्टेटमेंट पत्रावलि की स्वीकृति जारी करवाकर शेरगढ़ वासियों को पेयजल संकट से राहत प्रदान करावें।

spp/rtm/04.03.2025/12.30/1k

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल डांगी।

वल्लभनगर की पंचायतों तथा ग्रामों को टी.एस.पी. क्षेत्र में सम्मिलन

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति भीण्डर व वल्लभनगर की 52 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतें ही टी.एस.पी. जनजाति क्षेत्र में आती हैं। जबकि पंचायत समिति वल्लभनगर व भीण्डर की ग्राम पंचायत, बाठरड़ाकला, बग्गड़, अमरपुरा खालसा, कुंथवास, सवना, सिंहाड़, पाणुन्द, मोतीदा, लुणदा, सांरगपुरा कानोड़, आकोला, वाणियातलाई, अमरपुरा जागीर पंचायतें हैं। इसके अलावा भी लगभग 50 राजस्व ग्राम ऐसे हैं जो टी.एस.पी के मापदण्ड पूरे करते हैं, किन्तु यह गांव टी.एस.पी. में सम्मलित नहीं हैं।

इस कारण यहां के लोगों को जनजातीय योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीएसपी का लाभ नहीं मिलने से इन पंचायतों के विकास में कमी आई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय जनजाति विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति वल्लभनगर व भीण्डर की इन पंचायतों को टीएसपी में सम्मिलित करवाने हेतु नवीन सर्वे का कार्य करवाकर उचित कार्यवाही करावें। बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन के टैण्ट व्यवसायी की संदेहास्पद मृत्यु

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि श्रवण सिंह उर्फ सवाई सिंह जोजावर में टैण्ट का व्यवसाय करता था, महावीर सिंह भाटी भी टैण्ट व्यवसायी था। महावीर ने अपने टैण्ट व्यवसाय को 11 माह के लिए श्रवण सिंह को दिया था। 8-9 माह तक काम करता रहा। उसके बाद दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ बताते हैं। दिनाक 09/02/2023 को लोगों ने श्रवण सिंह को आखिर बार टैण्ट के गोदाम पर जाते हुए देखा बताते हैं। मगर उसके बाद वो कहीं नहीं दिखाई दिया।

महावीर सिंह दिनांक 10/09/2023 को श्रवण सिंह के घर गया और श्रवण सिंह की पत्नी को कहा कि थाने चलो, थानेदार मेरे मिलने वाला है, मैं कार्यवाही करवाता हूं, लेकिन श्रवण सिंह की पत्नी ने उसके साथ जाने से मना किया। श्रवण सिंह की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को तूने ही छुपा रखा है। तब महावीर सिंह ने श्रवण सिंह की माता को साथ लेकर सिरयारी थाने गया और मां को बाहर बैठाकर अंदर जाकर थानेदार से मिलकर MPR 08/2023 दिनांक 10/12/2023 दर्ज कराई। उसके बाद महावीर सिंह ने मृतक को ढूंढने के लिये किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया।

क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 तारीख से लगातार ढूंढा और ग्रामवासियों को उसकी मोटर साइकिल जोजावर से 40-45 किलोमीटर दूर सातपालिया से 4 किमी. दूर जंगल में पहाड़ों के बीच मिली तथा लगभग 1 किमी दूर पहाड़ों में पेड़ से लटकी हुई क्षत-विक्षत लाश मिली, जिसके दोनों घुटने जमीन पर टिके हुए थे और गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिससे यह आत्महत्या नहीं अपितु मर्डर लगता है। इतने लंबे समय बाद भी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।

महोदय जी यह सीधा-सीधा हत्या को आत्महत्या दिखाया जाना प्रतीत हो रहा है। अतः मैं इस पूरे प्रकरण की जांच की पत्रावली पुलिस मुख्यालय मंगवाकर किसी ईमानदार अधिकारी के माध्यम से जांच करवायी जाये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आशा करता हूं कि आप द्वारा अतिशीघ्र न्याय प्रदान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखवन्त सिंह। (अनुपस्थित) श्री पितराम सिंह काला।

पटवारी भर्ती 2025 में नियमानुसार आरक्षण प्रदायगी

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में ST को 12% आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मिलीं 175 सीटें, SC को 16% आरक्षण के आधार पर 277 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मिलीं 229 सीटें, OBC को 21% आरक्षण के आधार पर 364 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मिलीं 303 सीटें, जबकि सरकार द्वारा MBC को 5% आरक्षण के आधार पर 87 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मिलीं 165 सीटें तथा EWS को 10% आरक्षण के आधार पर 173 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मिलीं

405 सीटें।

मान्यवर, सरकार द्वारा एस.सी., एस.टी. एवं ओबीसी वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है। मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में एस.सी., एस.टी. एवं ओबीसी वर्ग को आरक्षण के हिसाब से पदों की स्वीकृति दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री दीन दयाल।

दौसा शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था

श्री दीन दयाल (दौसा): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और नियम् 295 के तहत दौसा शहर में बेहाल सफाई व्यवस्था को सुदृढ करवाकर नियमित सफाई करवाये जाने हेतु निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दौसा के नगर परिषद् क्षेत्र दौसा में वर्तमान में 55 वार्ड हैं। दौसा नगर परिषद में सफाई व्यवस्था बड़ी बेहाल स्थिति में है। नियमित मॉनिटरिंग के अभाव में जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े रहते हैं जिस कारण गन्दगी और दुर्गन्ध का तो वातावरण रहता ही है साथ ही संक्रामक बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा जमीनी स्तर पर कचरा निस्तारण कार्य कराया जाना चाहिये। साथ ही संवेदक की लापरवाही पर उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

दौसा नगर परिषद् में पर्याप्त कचरापात्र व पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव है जिस कारण शहर के अन्दर की कॉलोनियों में, मौहल्लों में कचरे का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है। नगर परिषद् दौसा में कचरा निस्तारण के व्यापक एवं व्यवस्थित व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि प्राथमिकता से बजट स्वीकृत कर सभी वार्डो में सफाई के लिए पर्याप्त संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

अतः मेरा निवेदन है कि उपर्युक्त लोकहित के विषय को ध्यान में रखते हुए इस ओर मैं माननीय स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामावतार बैरवा। (अनुपस्थित) श्री सोहनलाल नायक।

रायसिंहनगर में क्षतिग्रस्त नहरों तथा खालों का पुनर्निर्माण

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत में सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में गंग कैनाल के सिंचाई खालों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। किसान सिंचाई के पानी के अभाव में बरबाद हो रहे हैं। सिंचाई विभाग विगत दो सालों से सी.ए.डी. में खालों का निर्माण नहीं कर रहा है तथा गंग कैनाल क्षेत्र की समस्त खालें जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा में नहरों और खालों का निर्माण कार्य हेतु सरकार बजट उपलब्ध कराये, जिससे जीर्ण-शीर्ण नहरों एवं खालों का निर्माण हो सके तथा किसानों को उनके हक

का पानी पूर्ण रूप से मिल सके तथा विगत दो सालों से सी.ए.डी. विभाग द्वारा खालों का निर्माण नहीं करवाया गया है जिससे उन जीर्ण-शीर्ण खालों का निर्माण हो सके।

श्री अध्यक्षः श्री अशोक कुमार कोठारी।

प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों पर प्रतिबन्ध

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत राजस्थान में हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा FSSAI एवं FDA ही अधिकृत खाद्य सर्टिफाइड संस्थाएं हैं। वर्तमान में इनके मानक के अलावा शाकाहारी व अन्य उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाकर उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन भारत में 3 निजी एजेंसियों द्वारा दिये जाते हैं- यह एजेंसियां हैं जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र और हलाले सर्टिफिकेशन इण्डिया। जिसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त मुस्लिम आतंकवादियों के संरक्षण में मदद कर रही है।

हलाल सर्टिफिकेशन एक समानान्तर अर्थव्यवस्था को जन्म दे रहा है, क्योंकि उक्त सर्टिफिकेशन में एक शर्त यह भी है कि इसको इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ही तैयार करता है। इससे हिन्दू समाज की वह जातियों, जिनका पुश्तैनी मांसाहार का कार्य है, उक्त सर्टिफिकेट के कारण बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर ऐसे सर्टिफिकेट के उत्पादों की बिक्री बंद नहीं की गई तो कल अन्य धर्म के धर्मावलम्बी भी अपने धर्म विशेष के नाम से उत्पादों की बिक्री पर जोर देंगे जो कि समाज में वैमनस्यता पैदा करेगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांसाहार के अलावा उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट के अन्य खाद्य सामग्रियों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में विक्रय की जा रही ऐसी सामग्रियों जो मांसाहार की श्रेणी में नहीं आती, उनको हलाल सर्टिफाइड के नाम से बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाये। धन्यवाद।

jyg/rtm/04.03.25/12.40/1l

श्री अध्यक्षः श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर में सड़कों का नवीनीकरण

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में निम्न मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य हेतु निवेदन है। आकोली से रामबोटकी, दीगांव से नारणावास, सुमेरगढ़ खेड़ा से देवाड़ा,

भंवरानी से रोजीयों की ढाणी से रायथल, सापणी से बोकडा, कवराडा से भूति, हरजी से वल्डिया महादेव, उखरड़ा से चांदराई, खोड़ा मोमाजी से कुआडा से थांवला, सुगालिया-अमृतियां वेरा से कालोपादर से बाला, राजनवाड़ी से धवला, ओडवाड़ा से बालवाडा तक की सड़को का निर्माण करावें।

इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र आहोर की पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क छीपरवाड़ा से वाया मेडाउपरला-मायलावास बारलावास भेटाला नागणी दीगांव-डुडसी गांव से डुडसी प्याऊ, चांदराई से पांचोटा-तरवाड़ा-मुलेवा-किशनगढ़-निम्बला, तखतगढ़ (पाली) से पादरली-नारवणा से कवराडा, मायलावास से कटकेश्वर महादेव मंदिर, देबावास से ओडवाडा-रायथल, रोड़ला से भूति-कंवला, कवराड़ा से वलदरा-रुडमाल की ढाणी-मालगढ़-नोरवा, चुंडा से किशनगढ़, सुगालिया बालोतान से सेदरिया-पावटा, पांचोटा-नागणेशी-शंखवाली तक की सड़कों का नवीनीकरण एवं चौडाईकरण करवाने का श्रम करावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर जनहित में उक्त सड़कों का नवीनीकरण एवं चौडाईकरण करवाया जावें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना में विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के अन्तर्गत वर्तमान में 132 अकलेरा, मनोहर थाना केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में उर्जा प्रसारण एवं वितरण की स्थिति अत्यंत दयनीय है। गांव के लोगों के बहुत फोन आते हैं। लम्बे समय से क्षेत्र में मेंटिनेंस का कार्य भी नहीं हुआ है। 11 केवी लाइन जो कई गांवों जैसे समरोल, बिन्दायका, गुराड़ी देवली बटूखेड़ी, भूलनखेड़ी के अन्दर से लाइन गुजर रही है, उस लाइन को गांव से बाहर की जावे। 132 केवी कोलुखेड़ी कलां या समरोल में नया खोला जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि लोड अधिक होने की वजह से बार-बार ट्रिपिंग होती है व नया 33 केवी जीएसएस टोडरी जग्गनाथ, मनपसर, गेहुखेड़ी, तुरकाड़िया सरखण्डिया में खोलने से क्षेत्र में काफी समस्या का समाधान होगा। कई जगह हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जहां पर 3 फेज एग्रीकल्चर कनेक्शन होने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा सिंगल तार पर ही विद्युत सप्लाई की जा रही है और कभी भी हादसा हो सकता है। क्षेत्र में बिजली से काफी मौतें हुई हैं, उनको मुआवजा दिया जाये। कोई अनहोनी घटना ना हो सके इसके लिए स्थायी समाधान किया जाये। मैंने कई बार उच्च अधिकारियो को अवगत करवाया है कि बिजली की बहुत विकट समस्या है उसका समाधान किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कालीसिंध सुपर थर्मल प्लांट की इकाई बार-बार खराब होने की वजह से क्षेत्र विद्युत व्यवस्था बिगड़

जाती है। 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन कोलूखेड़ी कलॉ या समरोल में स्वीकृत किया जाये ताकि क्षेत्र के लोगो को काफी ज्यादा फायदा हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई के बांधों का रामजल सेतु लिंक परियोजना से जोड़ा जाना

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई पानी के क्षेत्र में डार्क जोन में आता है। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के रेहडिया बांध, गुढाकटला बांध, धपावन बांध, बडियाल खुर्द बांध, पूछडी बांध, घाटीदीपपुरा बांध, अमन सागर बांध है जिन्हें PKC-ERCP रामजल सेतु लिंक परियोजना में जोड़ने को लेकर लम्बे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा बार-बार मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र का एक भी बांध नहीं जोड़ा गया है। यदि सरकार द्वारा PKC-ERCP रामजल सेतु लिंक परियोजना से उक्त बांधों को जोड़ा जाता है तो आमजन को पीने का पानी एवं सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित रेहडिया बांध, गुढाकटला बांध, धपावन बांध, बडियाल खुर्द बांध, पूछडी बांध, घाटीदीपपुरा बांध, अमन सागर बांध है जिन्हें PKC-ERCP रामजल सेतु लिंक परियोजना से जोडा जाये ताकि आमजन को पीने का पानी एवं सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पर्ची।

श्री अरूण चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खाटूश्याम बाबा मंदिर में अव्यवस्था

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): बोलो श्याम प्यारे की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा श्याम सबकी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अभी फाल्गुन के महीने में दिनांक 28 फरवरी से 11 मार्च के बीच में बाबा श्याम का दरबार सज़ा है और एक विशाल मेला भरा हुआ है। मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार कुम्भ की व्यवस्था हुई, उसी भांति इस बाबा श्याम दरबार की भी व्यवस्था हो। अभी हाल ही में वहां के व्यापारियों ने व्यापार बंद करके विरोध जताया था। मेरी यह भावना है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी कुछ श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए गये थे लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ अव्यस्थाएं थीं, मैं यह मांग करता हूं कि उन अव्यवस्थाओं को दूर कर किस प्रकार सुलभ और जल्दी दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था सरकार कराये। माननीय गृह मंत्रीजी विराजे हैं, आपसे मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि यह बाबा श्याम का यह दरबार है और जिस प्रकार हमारे देश में पधारो म्हारे देश की तर्ज पर पधारो म्हारे खाटू बाबा रे दरबार की भावना

सभी लेकर आयें और दर्शन करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री हरलाल सहारण। ...(व्यवधान)... इस पर कोई चर्चा नहीं होती।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा की बात नहीं है, मैंने कल भी मामला उठाया था, सरकार से जवाब दिलवाओ इस पर।

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान)... श्री हरलाल सहारण। ...(व्यवधान)... सरकार इस पर जवाब देना चाहे तो मना थोड़े है। ...(व्यवधान)... श्री हरलाल सहारण।

चूरू नगर परिषद् क्षेत्र के पार्क

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पहला सुख नीरोगी काया, मतलब संसार में सबसे पहले सुख नीरोगी काया ही है। शरीर यदि स्वस्थ रहेगा, नीरोग रहेगा तो हम अपने जीवन में बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आज का वातावरण पहले की तरह नहीं रहा, दूषित हो चुका है। लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं हो पाती, लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, खानपान में हो रहा बदलाव लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही समाज अपने घरों तक सीमित रह गया है, इस कारण बच्चों एवं बुजुर्गों को स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक समस्याएं हो रही हैं। बच्चों को खेलकूद के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिलता तो उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक स्वास्थ्य के ठीक रहने का व्यापक महत्व है परंतु लोगों को व्यायाम करने के लिए कोई उचित जगह नहीं मिल पाती। इन सभी का संगम आज पार्कों में मिलता है, पार्कों का निर्माण करने के लिए समाज के अन्दर जागरूकता आयी है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। सार्वजनिक पार्कों का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू में नगर परिषद् क्षेत्र में लगभग 24 पार्क हैं, जिनमें से 6 विकसित पार्क हैं, शेष अविकसित हैं, जिसके कारण सोसायटी में निवास करने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए और बच्चों को खेलकूद के लिए उचित स्थान नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इन पार्कों में चारदीवारी, फुटपाथ, बच्चों के झूले, ओपन जिम लगाने की महती आवश्यकता है। एक पार्क को विकसित करने के लिए करीबन 30 लाख रुपये व्यय होते हैं। इसी प्रकार चूरू शहर में 24 पार्कों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनको विकसित करने के लिए करीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपये की आवश्यकता है।

MLS/RTM/04.03.2025/12:50/1m

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में नगर परिषद में ड्रेनेज सीवरेज के नवीन एसटीपी से जल के पुनरुपयोग के लिए स्वीकृत ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जौहरी सागर में पम्पिंग स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु पाइप लाइन डालने के लिए कार्यादेश जारी हुए लगभग एक साल हो चुका है। अभी तक यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। लगभग 2 माह में वर्षा ऋतु आ रही है। मेरे चूरू की पानी के भराव क्षेत्र के रूप में पहचान बनी हुई है। अगर उक्त समय में कार्य नहीं हुआ तो लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लालाराम बैरवा।

बनेड़ा (शाहपुरा) के कतिपय गांवों का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, बनेड़ा में कई ऐसे गांव, मजरे, ढाणियां हैं, जो वर्षों पहले बसे हुए थे और बसे हुए हैं, जो गांव आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, जिनके कारण आमजन को अपने मकान का पट्टा बनाने में समस्या आती है तथा केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वे वंचित रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आदि।

ऐसे गांव जो चरागाह भूमि पर बसे हुए हैं या अन्य कारणों से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे गांवों की भूमि को चरागाह से बिलानाम में परिवर्तित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कृपा कराएं, जिससे आमजन को राहत मिल सके तथा माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना के अनुसार सभी सरकारी योजनाओं का आमजन को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल कोलाना।

गढ़ेपान स्थित चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से गैस रिसाव

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कोटा जिले में गढ़ेपान गांव के पास चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कम्पनी है, सीएफसीएल इसको कहते हैं, इस फैक्टरी में यूरिया बनाया जाता है और इस दौरान समय-समय पर चिमनी से अमोनिया गैस रिलीज होती है। 15 फरवरी, 2025 को सुबह साढ़े 5 बजे से ही हवा में स्मेल आ रही थी और इसी फैक्टरी के पास में 500 मीटर की दूरी पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें करीब 200 छात्राएं पढ़ती हैं। अचानक उनकी एकदम से तबीयत बिगड़ने लगती है, बच्चियां बेहोश होने लगती हैं, उनका दम घुटने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालात इस क़दर बन जाते हैं कि गांव वालों को फैक्टरी में फोन करके बोलना पड़ता है कि बच्चियां बेहोश हो रही हैं, इस फैक्टरी से जो गैस रिलीज हो रही है, इसे बन्द करेंगे या मरने का इन्तजार करेंगे। 15 बच्चियों सहित 18 अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें कोटा भेजना पडा। डॉक्टर्स की 48 आवर्स की कड़ी निगरानी में ये

मरीज वहां पर भर्ती रहे। दो बच्चियां सीएफसीएल की डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार के बाद जब डिस्चार्ज हुईं तो रात को फिर दोबारा तबीयत बिगड़ी और फिर से उन्हें कोटा रैफर करना पडा।

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो गनीमत रही कि यह हादसा रात के समय नहीं हुआ, नहीं तो उस गांव के सोते हुए लोग सोते के सोते ही रह जाते। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि, what are the roles of detectors, sensors and alarms? क्या कारण रहा कि इन 18 लोगों की तबीयत बिगड़ी? प्रदूषण मण्डल, वह फैक्टरी बॉयलर विभाग नहीं मान रहा कि गैस लीक हुई है। दोनों ही विभागों की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक साइट पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, अब यह सोचने का विषय है कि, there are only two possibilities - either gas has been released or it has been leaked. ये दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मैं ऐसा समझता हूं और, it seems very clear that facts are being hidden. Hon'ble Speaker Sir, हमें आपका संरक्षण चाहिये। हम किस चीज का इन्तजार कर रहे हैं कि भोपाल गैस काण्ड जैसा एक और काण्ड हमारे प्रदेश में भी हो? हमें इस पर विचार करना चाहिये। इससे पहले भी वहां के क्षेत्रीय किसानों ने, जो उनकी फसलें नष्ट हुईं उस अमोनिया गैस के कारण, 250 बीघा भूमि पर किसानों की फसलें नष्ट हो गईं उस अमोनिया गैस के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, यह आपसे और हमसे छिपा नहीं है कि कौन-सी पार्टी की सरकार कॉरपोरेट सैक्टर को सबसे ज्यादा संरक्षण देती है, इसलिए हम आपसे विशेष संरक्षण का निवेदन करते हैं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank You Sir.

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, जो पर्ची लग रही है या स्थगन लग रहा है, कम से कम उनके मंत्री तो रहें। न अधिकारी हैं, न मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: यह नोट करें। सम्बन्धित मंत्री सदन में उपस्थित रहें।

श्री केसाराम चौधरी। ध्यानाकर्षण।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पुराने ट्रैक्टर पर टैक्स में कटौती एवं प्रतिमाह पैनल्टी माफी

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियम 131 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: बस आपको तो ध्यान आकर्षित करना है। मंत्री जी बोलेंगे, फिर आपको उस पर जो बोलना है, आप बोलिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि नये ट्रैक्टर, जो कि राज्य में खरीद के पश्चात अथवा अन्य राज्यों से खरीदकर लाये जाते है, के प्रथम पंजीयन पर राज्य

में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 22.12.2022 को अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में संशोधन कर फीस रुपये 600/- निर्धारित की गयी है।

पुराने ट्रैक्टर जो कि प्रथम पंजीयन से 15 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण करवाते हैं, तो ऐसे ट्रैक्टरों पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 22.12.2022 को अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में संशोधन कर नवीनीकरण फीस रुपये 5000/- निर्धारित की गयी है। यदि वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण विलम्ब से होता है तो ऐसे ट्रैक्टरों पर रुपये 500/- प्रतिमाह शास्ति ली जाती है। ये दरें दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी हैं।

राज्य में कृषि उपयोग हेतु ट्रैक्टरों पर मोटरवाहन कर/एकबारीय कर देय नहीं है। ऐसे वाहनों पर प्रथम पंजीयन अथवा पंजीयन नवीनीकरण के समय राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-डी के तहत दिनांक 11.01.2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के अन्तर्गत रुपये 1500/- ग्रीन टैक्स लिया जाता है।

इस प्रकार राज्य में प्रथम बार पंजीयन के समय ट्रैक्टर स्वामी को कुल राशि 2100/- रुपये तथा समय से पंजीयन का नवीनीकरण कराने पर कुल राशि 6500/- रुपये देय होती है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, नया ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस पर टैक्स है मात्र 600 रुपये और वह ट्रैक्टर पुराना हो जाता है। उस पर प्रदूषण टैक्स के रूप में भी 1500 रुपये जोड़कर मात्र 2100 रुपये में नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। खरीदते समय टैक्स लगता है। जब वह ट्रैक्टर 15 साल पुराना हो जाता है और कोई गरीब आदमी नया ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता, वह पुराना ट्रैक्टर ही खरीदकर अपना काम चलाना चाहता है तो उस पर टैक्स है 5000 रुपये, मतलब नये ट्रैक्टर से 8 गुना ज्यादा।

उसमें 1500 रुपये ग्रीन टैक्स के रूप में लिये जाते हैं। इस प्रकार 6500 रुपये पुराने ट्रैक्टर पर टैक्स के रूप में हैं। 6500 रुपये के बाद में अगर वह ट्रैक्टर 15 साल तक रिन्यू नहीं कराता है तो 15 साल के 500 रुपये के हिसाब से उस ट्रैक्टर की नया लें, उतनी कीमत हो जाती हैं। इसलिए मेहरबानी करके मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह काश्तकार का पुराना ट्रैक्टर, काश्तकार कोई अपना ट्रैक्टर प्रदूषण फैलाने के लिए नहीं करता, वह प्रदूषण को मिटाने के लिए खेती बोता है और ग्रीनरी पैदा करता है, इसलिए 1500 रुपये का जो यह ग्रीन टैक्स लगाया जाता है, यह माफ किया जाये। इसके अलावा जो 500 रुपये प्रतिमाह पैनल्टी लगायी जाती है, आप टैक्स पर ही 8 गुना भत्ता ले रहे हैं नये ट्रैक्टर से और नये ट्रैक्टर से 8 गुना ज्यादा पंजीयन शुल्क ले रहे हैं तो अपको चाहिये कि उसका पंजीयन शुल्क भी कम करें और ग्रीन टैक्स भी माफ करें। 500 रुपये की पर मंथ जो पैनल्टी ली जाती है, उसे भी माफ करने की मेहरबानी करें। गरीब किसान पुराना ट्रैक्टर लेकर अपना गुजारा करता

है।

मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में, मुझे मालूम है कि यह केन्द्र सरकार का विषय है, मगर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केन्द्र सरकार से यह निवेदन करें कि राजस्थान के गरीब किसान इस बात को सहन नहीं कर सकते, उनको बहुत पीड़ा होती है।

MKD/RTM/04.03.2025/13:00/1n

आप अपने पंजीयन कार्यालय से पता कराये कि वहां पर पुराने ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन, लोग देखते हैं कि इतने पैसे तो ट्रैक्टर के लगते नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वही बात रिपीट हो रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूं। पंजीयन कार्यालय से आंकड़े मंगवाये।

श्री अध्यक्ष: विराजो तो सही।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कि कितने पुराने ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनके भी आंकड़े मंगवायें, ताकि आपको सही ज्ञान हो सके।

श्री अध्यक्ष: वही बात हो रही है, विराजो तो सही। माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पेनल्टी जो लगाई है, वह समय पर वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए ही तो है। वैसे कोई फीस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, अगर तय समय पर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं है, न उसके लिए कोई शुल्क है। आप ग्रीन शुल्क की बात कह रहे हो, यह हमारा टैक्स, यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए है, हर वाहन से लिया जाता है, लेकिन किसानों पर इसका इतना भार नहीं है। इसलिए अगर केन्द्र सरकार से 500 रुपये में, कोई जो भी वहां से दिशा निर्देश होगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तीन गुना टैक्स लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, भाई। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। अब विराजो। माननीय सदस्य, मंत्री जी ने कह दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वित्त मंत्री जी भी यहीं पर मौजूद हैं, आप इसमें छूट करवा दो।

व्यवस्था

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की उत्तर प्राप्ति तीन दिवस में अनिवार्य तथा सुसंगत विभाग को प्रेषण सरकार का अंदरूनी मामला

श्री अध्यक्ष: ये यही हैं। आपकी बात हो जायेगी। मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कुछ व्यवस्थाएं सरकार के ध्यान में लानी हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस दिन लगता है, तीन दिन के अन्दर उसका उत्तर सदन में आना चाहिए। प्राय: पाया गया है कि अधिकांश ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव के वहां पर उत्तर नहीं आते और उत्तर यदि नहीं आता तो सरकार किसी भी, सदन या अध्यक्ष किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

हमने जब कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, बार-बार यह कहा जाता रहा कि समय कम होने के कारण उत्तर देने में असमर्थ हैं। यह बात स्वीकार नहीं है। लेकिन जब कहा गया तो उसका उत्तर अभी आया है, चर्चा होगी। भविष्य में सरकार को भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य लगाये, कोशिश करें कि तीन दिन में आ जाये। यदि नहीं आता है तो जिस दिन लगता है, उसी दिन रात को पहले भी 12 घंटे में उत्तर आता रहा है।

इसलिए कोई भी विभाग पर्टिकुलरली रेवेन्यू विभाग यह कहता है, मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा होती है, मेरा प्रस्ताव है, इतने अल्प समय में उक्त प्रस्ताव का जवाब तैयार किया जाना सम्भव नहीं है, यह उत्तर है। 5 फरवरी को यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है। यदि कोई प्रस्ताव उस विभाग का नहीं है तो वह अपना जो सम्बन्धित विभाग है, उसको ऑटोमैटिक भेज दे। एक महीने के बाद दूसरे विभाग को भेजा जाता है। यह भी उस विभाग की सुस्ती आती है।

अतः विभाग उसमें सुस्ती न करे। दूसरे विभाग को सही समय पर भेज दे और वह उत्तर तैयार करके यहां पर हाउस में जमा करा दे। ऐसा मेरा सबसे आग्रह है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आये। माननीय, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का हम पूरा पालन करेंगे। इस प्रश्न में, नम्बर 2 में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसमें देरी हुई, उसका थोड़ा वाजिब कारण है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना काम था। हमारे उद्योग विभाग का अपना काम था। यह विषय सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होने के बाद सरकार के संज्ञान में है और सरकार ने जब इस सम्बन्ध में कानून बनाने का हाउस में हो गया तो ऐसी स्थिति में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तुरन्त का कोई विषय नहीं है। यह विषय 15 सालों से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी बता देंगे उसका।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हरि मोहन जी, मेरी बात सुन लो। आपको कोई मैं जवाब नहीं दे रहा। आपको सुनना तो पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: मैं करूंगा, यह मैंने उठाया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्योंकि यह विषय आज से नहीं, 2010 में अराफात में लीज हुई थी, फिर 2017 में कंवर्ट हुआ, 2017 से विभिन्न न्यायालय में यह प्रकरण गया है। इसलिए, यह ध्यानाकर्षण की श्रेणी में मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि इसमें कोई दुरुपयोग वाला विषय ही नहीं है।

फिर भी, विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय मंत्री जी देंगे और आपने जो व्यवस्था दी है, मेरा उस व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन है कि आपकी व्यवस्था को हम मानेंगे। इसमें पत्र

लिखने का कारण था। वह यही था, क्योंकि हाउस में लॉ बनाने के लिए ऑलरेडी ले हो चुका है, इसलिए मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: मेरा इसमें स्पष्ट है कि यह 5 फरवरी को लगा और 6 फरवरी को उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद विभाग द्वारा 4 मार्च को यह कहा जाता है, एक माह पश्चात, अल्प समय के आधार पर जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी व्यवस्था पूरी हो जाए। जिस भी विभाग को कोई आपत्ति है, कोई कठिनाई है, कोई है तो समय पर सचिवालय को आकर दे दे, नहीं तो सचिवालय स्वतंत्र होगा कोई भी प्रस्ताव लगाने के लिए। यह समय कम होने की बात स्वीकार नहीं की जायेगी।

विभागों में होती है, कई बार दो विभागों को चला जाता है, आपने जो कहा, कई बार कोई कोर्ट का है, लेकिन 5 फरवरी के बाद और आज तक उसके बारे में न कहा जाए, लगने के बाद पूर्व रात्रि को कहा जाए कि साहब समय कम है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को..।

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान आकर्षित कर दें। हो गया, आप तो केवल दो लाइनें बोलो कि ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक निवेदन, वैसे तो जो आप आदेश देंगे, उसकी अनुपालना करूंगा।

श्री अध्यक्ष: जो परम्परा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लेकिन 131 के प्रावधान 3(2) में लिखा हुआ है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, वह स्वयं अपने उस प्रस्ताव का वाचन करेगा। आप उसको देख लें, फिर मुझे अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: आपको भी देंगे अनुमति। पहले उत्तर आ जाए, फिर आप भी बोलना, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सर, नहीं-नहीं, यह नहीं है। मेरा निवेदन दूसरा है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया, उसका पहले मैं वाचन करूंगा। आप पढ़ लो। अगर नियम में है तो आप दें, नियम में नहीं है तो मत दें। आप पढ़ लें। संसदीय कार्य मंत्री जी, पढ़ लें, फिर बोलें। पहले भी आप..।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, एक मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुझे आसन ने अनुमति दी है। आप परमीशन दें तो। आप कहेंगे तो कितनी ही बार पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लेंगे। आपके कहने से पढ़ने में कोई दुविधा नहीं है और सब्जेक्ट टू करेक्शन हमेशा होता है। कोई विद्वान नहीं होता है, कोई हमेशा सर्वगुणी नहीं होता है, रोज सीखते हैं। आसन की व्यवस्था और नियमों के अनुसार आप ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करेंगे, विभाग या मंत्री इसका

जवाब देंगे। उसके बाद आपको जो जानकारी चाहिए, सप्लीमेंटरी चाहिए, तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए, वह सब आपको मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्षः अब हो गया, व्यवस्था दे दी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपकी व्यवस्था सर माथे पर।

श्री अध्यक्षः तो हो गई, फिर खत्म। ये मैं पढ़ चुका हूं। मेरे पास है। समय क्यों खराब करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरा निवेदन तो सुनो। साहब, इसमें लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्षः हां, मैंने इसको पढ़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पढ़ लिया ना, आपने।

श्री अध्यक्षः अब पढ़ने के बाद बैठिये। मैंने पढ़ लिया। माननीय सदस्य, मैंने पढ़ लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): तो मैं सही कह रहा हूं ना। मैं सही कह रहा हूं, ये तो मानते हो ना आप।

श्री अध्यक्षः अरे हां, आप विराजो। अभी तक कि, साधारणतया सदन, विराजो तो सही, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप हमारे भीष्म पितामह हैं। सदन में मेरे कार्यकाल से नहीं, पुराने कार्यकाल से व्यवस्था रही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आकर्षित करते हैं। वह लगता है और मैंने पुराने माननीय अध्यक्ष की भी व्यवस्थाएं पढ़ी हैं। सदस्य ध्यान आकर्षित करता है। उसके बाद मंत्री उस पर अपना जवाब देता है। फिर सदस्य, जो भी उसमें उसको पूछना है, करना है, बोलना है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके बाद फिर मंत्री यदि कोई उसमें से बात कहना चाहता है, वह भी कह सकता है। इसलिए, इसको पढ़ने के समय की तुलना में केवल ध्यानाकर्षण ही पर्याप्त है। हमारे मंत्री भी समझदार हैं। आप भी समझदार हैं।

अतः इसमें समय लगने की तुलना में आप केवल ध्यान आकर्षित कर दें, नहीं तो अपना समय अभी।

इसमें एक व्यवस्था और देनी थी। आज भोजनकाल, चूंकि शिक्षा और वह भी उच्च शिक्षा, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होनी है। अतः भोजन अवकाश को निरस्त किया जाता है और जिसको भोजन करना हो, एकदम से नहीं जाएं, धीरे-धीरे जाएं। आप ध्यान आकर्षित कर लो, अब व्यवस्था हो गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने व्यवस्था दे दी, वह सर माथे पर।

श्री अध्यक्षः तो बस अब आकर्षित कर दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं..।

श्री अध्यक्षः फिर लेकिन नहीं होता।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपकी व्यवस्था सर माथे पर, वही करूंगा। हां सर, वहीं करूंगा। सर, वही करूंगा, जो आपने फरमाया है, लेकिन जो नियमों में है तो परम्परा तो जब होती है सर, जब नियमों में नहीं हो।

श्री अध्यक्षः किसी भी नियम को स्थगित करने का अधिकार है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक लीज भूमि का दुरुपयोग

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक लीज भूमि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने हरिमोहन शर्मा जी को, हमारा वरिष्ठ सदस्य घोषित कर ही दिया है। वे तीन बार इस सदन में रह चुके हैं। एक बार मंत्री भी रह चुके हैं और नियम 131 के अन्तर्गत उन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया है।

Bhs/Rtm/04.03.25/13.10/10

और जो पीड़ा दिखायी दे रही है यह हमारी ही सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि इसका जवाब दिया जा सके। यह बात पूरे सदन को जाहिर हो जायेगी थोड़ी देर बाद में।

मैं इन्हीं के शब्दों में रिपीट कर रहा हूं जो हरिमोहन जी ने लिखा है कि मैं गम्भीर लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि राज्य सरकार का तुरन्त हस्तक्षेप करना अपेक्षित है। इससे पहले कि मैं इसकी विस्तृत डिटेल में जाऊं मैं सदन को थोड़ा सा बेकग्राउंड देना चाहता हूं कि यह 227 एकड़ भूमि है कोटा में जो तकरीबन 1960 के दशक से जे.के. ग्रुप के पास थी उसके बाद वो बी.एफ.आई.आर. में गये, Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). जहां पर उनको रुग्ण इकाई घोषित कर दिया, उनको सिक यूनिट घोषित कर दिया गया और उसके बाद मैसर्स अराफात पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को यह जमीन दे दी गयी। मैसर्स अराफात पेट्रो केमिकल्प प्राइवेट लिमिटेड भी थोड़े समय के बाद में बी.एफ.आई.आर. में गया, Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), और वहां पर कुछ शर्तें रखी गईं लेकिन इससे पहले कि मैं इन शर्तों पर आऊं मैं वापस हरिमोहन जी ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने अपने शब्दों में लिखा है कि नियमों के विपरीत लीज भूमि का किस्म परिवर्तन कर दुरुपयोग करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने लीज भूमि का किस्म परिवर्तन आदेश निरस्त किया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): उच्चतम न्यायालय है, उच्च नहीं है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। यह भूमि का किस्म परिवर्तन किसने किया? यह इन्हीं की सरकार ने किया और 5 जुलाई, 2019 को भूखण्डों के उप विभाजन और भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति इन्हीं के समय दी गई और यहां खत्म नहीं होता, हरिमोहन जी किसलिये हमारी सरकार से अपेक्षा रखते हैं वो अब जाहिर होता है कि इन्हीं की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गई कि इसको निरस्त भी किया जाये। इन्हीं की सरकार ने भू उप खण्ड को विभाजन की अनुमति

दी और इन्हीं की सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट गई कि इसको निरस्त किया जाये और फिर 20 अप्रैल, 2023 को जिसमें रीको द्वारा उप विभाजन की कार्यवाही को अवैध करार दिया गया और राज्य सरकार को उस समय 2023 में इन्हीं की सरकार थी, राज्य सरकार को लोक हित में पुन: विचार करने के लिए अभिमत दिया गया।

अब टेक्निकल इश्यूज पर मैं आता हूं। इन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विधि विशेषज्ञ की राय के बाद भी 227 एकड़ भूमि को सरकार अपने कब्जे में नहीं ले रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ना चाहता हूं। पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर उसका अनुवाद कर दूंगा। अपने निर्णय में पैरा 108 में उन्होंने लिखा है - "We may summarize our overall conclusion in the following points:

(i)There has been an uninterrupted and subsisting relationship of lessor and lessee between the state Government and either J.K. Group or Respondent No. 1 (Arafat Group);

(ii) In the context of Large Industrial Area (LIA), Kota, from the first lease deed executed in 1967, till date, the State Government has maintained the position of lessor."

इसका मैं हिन्दी में अनुवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना नतीजा और जो निष्कर्ष निकाला उसको संक्षेप में लिखा कि 1967 से आज की तारीख तक यानी 2023 तक जब यह निर्णय हुआ, तब तक मालिकाना अधिकार राज्य सरकार का है और मालिक ही किराये पर अपनी प्रोपर्टी दे रहा है वह तय हो गया कि मालिक हम हैं लेकिन हमने किराये पर दे दी है। तो जब किराये पर दी हुई है तो सरकार के अपने कब्जे में लेने की बात नहीं होती। अब मैं और आता हूं, इन्होंने लिखा कि समझौते के अनुसार मजदूरों के हितों की रक्षा भी नहीं कर पा रही सरकार। यह भूमि अराफात पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे में चल रही है जिससे राज्य को नुकसान हो रहा है। अब मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक और पैरा पढ़ूंगा जिसमें उन्होंने कहा है, पैरा नं. 106 - "This shall, however, not preclude Respondent No. 1 from reapproaching the State Government and seeking conversion of the usage of land and attendant approvals under the 1959 Rules. The State Government shall be at liberty to consider such a proposal in public interest and in accordance with the 1959 Rules."

मैं इसको हिन्दी में कहता हूं कि यह जो भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वह उस रेस्पोंडेंट नं. 1 को नहीं रोकता, अराफात ग्रुप को नहीं रोकता कि वह राज्य सरकार के पास वापस से उपस्थित हो जाये और अपनी लैंड का कन्वर्जन उनसे मांगे लेकिन राज्य सरकार को यह पूरी खुली छूट है कि वो इस निर्णय को पब्लिक इंट्रेस्ट में और in public interest and in accordance with the 1959 Rules.

अब मैं वापस आता हूं और इसको यहां समाप्त करता हूं कि यह जो बी.आई.एफ.आर. में जब ये गये तो एक समझौता हुआ, उस समझौते के अन्दर कुछ शर्तें थी, वो शर्तें, firsthand information ने पूरी कम्पलीट नहीं की है क्योंकि कलेक्टर ने एक बार इस

कम्पनी को नोटिस दिया हुआ है। यह नोटिस भी इन्हीं की सरकार में दिया था। यह नोटिस दिया गया था 27 नवम्बर, 2020 को तो अभी सरकार से जैसे आप अपेक्षा करते हैं पूरी तरह से हम देखेंगे कि इन्होंने शर्तें मानी हैं कितनी नहीं मानी और उसको तय करने के बाद सरकार पब्लिक इंट्रेस्ट में निर्णय लेगी। यह हमारी जनता पार्टी की सरकार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा है कि हमारी सरकार में ही इसे कॉमर्शियल किया गया और सब डिविजन किया गया। आप अपने उत्तर को करेक्ट कर लें जहां तक मेरी जानकारी है यह आदरणीय वसुन्धरा जी की सरकार में आखरी के समय में जो सिक्स मंथ में फैसले किये गये उसको हमारी सरकार ने रिव्यू किया, मेरी जानकारी है। आप इसको देख लें। तारीख देख लें। आप इसमें तारीख देख लें और तारीख देखने के बाद यह जो सिक्स मंथ में जो हमारी सरकार ने फैसले रिव्यू किये उस रिव्यू के बाद हमारी सरकार ने जो हमारी बता रहे हो वह सरकारें सब अपनी ही अपनी है। यह भी हमारी है और हमारी भी आपकी है लेकिन आप जिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जो चर्चाएं हैं उस हिसाब से जो आपने बताया तो एक तो आप इस उत्तर को फिर दुबारा करेक्ट करें, करेक्ट करके और फिर हमको यह बतायें कि यह किसकी सरकार ने इसका सब डिविजन किया था या इसको कॉमर्शियल किया था? नंबर-1...(व्यवधान)... यह तो अभी तत्काल ही है अगर आपको इन्फोर्मेशन दी है तो मेरे हिसाब से मेरी जानकारी के हिसाब से वह गलत है। नम्बर एक।

दूसरा, यह कि हम भी यही कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट जिसका हवाला आप दे रहे हो जो अपनी जिन शर्तों के साथ गवर्नमेंट ने इनको परमीशन दी जे.के. को और अराफात को उनमें कंडीशंस थीं कि एम्प्लॉयमेंट देगा, मजदूरों का पेमेंट करेगा, फैक्ट्री चालू करेगा, ये कंडीशंस थी। न फैक्ट्री चालू हुई, न मजदूरों को पूरा भुगतान किया गया और न एम्प्लॉयमेंट दिया गया। अब आप यह कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करायेंगे कि एग्रीमेंट का पालन किया कि नहीं।

मान्यवर, 2014 में ही यह मेरे पास लेटर रहा, आपने तो कमेटी बना रखी है इसकी कि इन-इन बातों की जो कमियां हैं इसकी जांच करके रिपोर्ट दें वो आपने बताया ही नहीं। अगर आपके पास है तो नहीं तो मैं आपको वह लैटर दे दूं। उसकी रिपोर्ट क्या आई, 2014 में जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट क्या आई? यह जो है यह 2014 का है, यह 13.1.2014 का है कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा का लैटर है जिसमें एक कमेटी बनाई गई है और जिन इश्यूज पर उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी उसमें उस एग्रीमेंट में लिखे हुए सारे इश्यूज हैं। ...(व्यवधान)... सारे इश्यूज हैं।

श्री अध्यक्ष: दोनों बुद्धिजीवी व्यक्तियों की बहस होने दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सारे इश्यूज हैं कि इन्होंने किन शर्तों की पालना की, काम चालू किया कि नहीं किया, फैक्ट्री चालू की कि नहीं की, एम्प्लोयमेंट दिया कि नहीं दिया।

यह तो सन 2014 में ही आपने कमेटी बना दी थी, आपसे मतलब आप यह कहोगे कि सरकार किसकी थी तो वह भी आपकी थी। सरकारें तो सब अपनी हैं, आपकी सरकार को भी हम तो अपना मानते हैं और सदन के नेता को भी नेता मानते हैं। आप यह पराये की बात मत करो लेकिन करेक्ट कर लो आप।

Kas/rtm/04.03.2025/13.20/1p

जब आपकी और हमारी बात करते हो तो फिर आपकी निकली, उसका क्या नतीजा आया। अब आप यह कह रहे हो कि हम इसकी सारी कंडीशन की जांच करवायेंगे, पता लगायेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलें, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): दूसरा यह है कि आपने जो जवाब दिया, ऐसा लगा कि कहीं यह अराफात कंपनी सबसे संपर्क तो नहीं कर रही है, जैसे उसी ने जवाब बनाया हो। मेरा इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है, मजदूर मेरे पास आये और उन्होंने यह समस्या बताई, तो मैंने इसकी जानकारी ली। इसमें न तो मेरा कोई इंट्रेस्ट है, यह पब्लिक इंट्रेस्ट की बात है, उन मजदूरों के इंट्रेस्ट की बात है। लीज का इन्होंने कोई काम नहीं किया, फैक्ट्री चालू नहीं की, मजदूरों को एम्प्लायमेंट नहीं दिया। सर, कोटा में जो बिल्डिंग्स बनाने का काम कर रहे हैं, इसके पास ही एक जमीन और है, जिसकी दीवार एक है, आप पता लगा लेना या कोटा जाओ, तो देख लेना। मुझे तसल्ली से जवाब दे देना, इसमें मेरा इंट्रेस्ट केवल यह है, पब्लिक इंट्रेस्ट में मेरा यह है कि जब एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं हुआ तो इस जमीन को आप अपने कब्जे में क्यों नहीं ले रहे हो? आपने कहा कि यह हमारी है, हमारी है तो कब्जे में लो, आपके कब्जे में ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि 233 एकड़ जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेकर उन मजदूरों का सारा भुगतान करे और कार्यवाही करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर ने भी आपको चिट्ठी लिखी है, डिपार्टमेंट ने आपकी जानकारी में नहीं दी क्या? तीन महीने पहले वर्तमान कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है आपको और यह कहा है कि हे सरकार के चलाने वालो मेरा मार्ग-दर्शन करो कि इस जमीन का मैं क्या करूं। मार्ग-दर्शन दिया ही नहीं, उद्योग विभाग से मार्ग-दर्शन ही नहीं। यह महत्वपूर्ण बातें हैं, आप तसल्ली से इस पर विचार करके जो बात मैंने आपसे कही है, उसको आप करें और इस प्रोब्लम को हल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर फिर चर्चा करूंगा कि इन्होंने अब तक क्या किया और क्या नहीं किया, आप इनको समय दे दो।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गई। माननीय मंत्री महोदय।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फेक्चुअल इन्फॉर्मेशन यह है कि 2007 में लीज अंतरण स्वीकृति जिला कार्यालय ने दी। यानी उस समय अराफात कंपनी को जो लीज ट्रांसफर हुई, वो 2007 में हुई और आप जानते हैं उस समय क्या सरकार थी, ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः अब सुनिए, आपकी बात आ गई। आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया, अब उनकी सुन लें। बैठिए, माननीय सदस्य, जिद की बात नहीं है। आपकी बात पूरी सुनवा दी, 15-20 मिनट आप बोल लिये, अब सुनिए। यह चर्चा नहीं है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष जी, इसमें मेरी ही बात रिकार्ड हो रही है, मेरी ही बात सदन में रिकार्ड में जा रही है। यह बिलकुल क्लियर है और कांग्रेस के कुछ सदस्य जो वहां से बोले हैं, मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले जे.के. ग्रुप के पास यह जमीन थी, उसके बाद जो लीज ट्रांसफर हुई, जो पूरे लीगली हुई, हमारे लैंड रूल्स के तहत हुई है, उसमें यह अराफात पेट्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड को मिली है। 2007 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब हमारी सरकार थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है 5 जुलाई, 2019 में। आप भले ही आर.टी.आई. लगा लीजिए, मैं सदन के रिकार्ड पर हूं जो मैं कह रहा हूं, उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की ही सरकार में आप सर्वोच्च न्यायालय गये, जहां पर आप चाहते थे कि जो यह आदेश हुए हैं, यह निरस्त हो, यह बिलकुल स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, एक बात तय है कि हमने भी इस बात को एम्फेसाइस किया है कि पब्लिक इंट्रेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निर्णय लें और हम जानते हैं कि पब्लिक इंट्रेस्ट क्या है, हम से ज्यादा और कौन जानता है। मुझे लगता है हरिमोहन जी, आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वर्कर्स आपसे आकर मिल रहे हैं, तो वो भी पब्लिक इंट्रेस्ट की ही बात आप कर रहे हैं, हम भी पब्लिक इंट्रेस्ट की बात कर रहे हैं। 2014 की कमेटी ने अभी तक जो निर्णय लिये हैं या जो भी इन्होंने फाइंडिंग्स की हैं, उनके आधार पर अभी हमारी सरकार आई है, उसको देखेंगे और पब्लिक इंट्रेस्ट में इसका निर्णय 100 परसेंट लेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनाएं

वित्त (कर) विभाग

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती दिया कुमारी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त/कर विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं-

1. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-119 दिनांक 06.02.2025, जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्याः एफ.12(5)वित्त/कर/2025-120 दिनांक 06.02.2025, जिसके द्वारा धारा 47 के अन्तर्गत निर्धारित विलम्ब शुल्क को माफ किया गया है;

श्री अध्यक्षः समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ''ख'' के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1 से 3)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख' 2024-25 के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं-

1. प्राक्कलन समिति 'ख', 2022-23 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट आयुर्वेद विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों पर प्राक्कलन समिति 'ख', 2024-25 का परिपालनात्मक प्रथम प्रतिवेदन;
2. प्राक्कलन समिति 'ख', 2023-24 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों पर प्राक्कलन समिति 'ख', 2024-25 का परिपालनात्मक द्वितीय प्रतिवेदन; एवं
3. प्राक्कलन समिति 'ख', 2024-25 का गृह विभाग (गृह रक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: हमीर सिंह भायल।

याचिका समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 9 से 12)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार याचिका समिति 2024-25 के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं-

1. राजस्व विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में नवम् प्रतिवेदन;
2. स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में दशम् प्रतिवेदन;
3. शिक्षा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में ग्यारहवां प्रतिवेदन;
4. महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में बारहवां प्रतिवेदन;

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कालीचरण सराफ।

याचिका

जयपुर के करतारपुरा नाले पर राधा कृष्ण नगर की पुलिया की ऊँचाई में बढ़ोतरी

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जयपुर के करतारपुरा नाले पर जयपुर दिल्ली रेल्वे लाइन के समीप राधा कृष्ण नगर को जोड़ने वाली पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़।

शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर EWS छात्रावास की स्थापना

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर EWS छात्रावास खोलने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

नोहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच एवं रसलाना वितरिका नहरों के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त खालों का पुनर्निर्माण

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र नोहर के नोहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच एवं रसलाना वितरिका नहरों के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त खालों के पुन: निर्माण करवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 अनुदान की मांगों पर विचार। श्री मदन दिलावर।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा की प्रस्तुति

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 218,82,20,69,000/- (दो सौ अठारह अरब बयासी करोड़ बीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21 माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 288,30,94,49,000/- (दौ सौ अट्ठासी अरब तीस करोड़ चौरानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रेम चन्द बैरवा।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-22 उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

25,25,55,45,000/- (पच्चीस अरब पचीस करोड़ पचपन लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़। एक सैकण्ड, माननीय मंत्री जी, आपने पूरी राशि नहीं पढ़ी, एक बार दुबारा पढ़ें। 25 करोड़ बोल दिया, 85 है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-22 उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,85,55,45,000/- (पच्चीस अरब पचासी करोड़ पचपन लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा एवं मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा पर विचार

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-20 प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या-21 माध्यमिक शिक्षा एवं मांग संख्या-22 उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह बात सही है विद्यार्थी सुराही नहीं जिसे भरा जाये, विद्यार्थी चिराग है, जिसे रोशन किया जाये। हर सरकार चाहती है कि बच्चों में अच्छी गुणवत्ता हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिले।

Msk/rtm/04.03.25/1330/1q

इसके लिए सरकार की इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कागजों को हाथ में लेकर पढ़ो तो अच्छा है, इसको स्टैण्ड मत बनाओ। यह केवल इनके लिए नहीं है, यह सभी के लिए है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हर सरकार चाहती है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। साथ ही, शिक्षा में जितने भी संसाधन मिलते हैं, सही समय पर, सही सीमा में, सही वक्त पर, सही बजट के अनुसार वे लागू किये जाने चाहिए। एक अच्छी योजना बनाकर शिक्षा दी जाये तो उनको गुणवत्ता की शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा देश विदेश के विकास की प्रगति द्योतक है और विकास का मेरुदंड है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, जो सभी समस्याओं का समाधान और निराकरण है। शिक्षा नीति ही चरित्रवान और संस्कारवान अच्छे नागरिक बनाती है। आदरणीय भैरोसिंह जी शेखावत साहब जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो सबसे पहले उनकी यह सोच थी कि गांव में शिक्षा का अभाव है, इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पलायन करके गांव छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं। सबसे

पहले उन्होंने फैसला किया कि अधिक पंचायतें बनें तो सबसे पहले उन्होंने नयी ग्राम पंचायतें बनायीं और पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ा। उस समय प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, सबसे पहले उन्होंने एक ही फैसला लिया कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर आठवीं तक की शिक्षा होनी चाहिए। तो एक ही आदेश में सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये। उसके बाद 2023 में आदरणीय वसुंधरा राजे जी की जब सरकार आयी तो उन्होंने भी फैसला किया ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें अधिक खुलनी चाहिए। उस समय पंचायतें बनायी गयीं। उस समय स्कूलें आठवीं तक की थीं तो उन्होंने एक ही फैसला किया कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

पंचायतें खोलकर एवं 3018 विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया। वह जो समय था, उस समय यह तय कर दिया था कि अब जो स्कूल 10वीं हुआ है, उससे बच्चे आगे 11वीं में जायेंगे, 12वीं जायेंगे, 12वीं तक शिक्षा होगी। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 12वीं विद्यालय तक की शिक्षा मिलने लगी।

आज मैं कह सकता हूं कि 2013 से 2018 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान 26वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया था। यह भी सही है कि उस समय, हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं, वे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया था, मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, जिसकी प्रशंसा पूरे हिन्दुस्तान में हुई। उस मॉडल को प्रत्येक राज्य लागू करना चाहता था और राजस्थान में उस मॉडल को आकर देखते थे। यह भी सही है कि प्रत्येक जिलों में एक शैक्षणिक रैंकिंग का प्रयोग किया गया, उसके अन्दर 150 का स्कोर होता था। आज मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि जब 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस की सरकार आयी तो जिस प्रकार का वह शैक्षणिक स्कोर था, उसके लिए एक मापदण्ड तय किया गया था, उस मापदण्ड में जिले खरे नहीं उतरे। कांग्रेस के राज के अन्दर मेरे हिसाब से करीब एक-तिहाई जिले 50 अंक के अन्दर रहे, उसमें भी 50 अंक वाले चार जिले, 29 जिले तो 50 के अंक से भी कम आ गये, इस प्रकार से हमारा स्तर घटता गया।

मैं कह सकता हूं, उस समय खास तौर से एक शिक्षा का उद्योग खोला गया था। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी एक शिक्षक सम्मेलन कर रहे थे। शिक्षक सम्मेलन के लिए उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या आपको ट्रांसफर करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? तो सभी शिक्षक खड़े हो गये कि बिना नारियल चढ़ाये ट्रांसफर नहीं होता, हम सबका रिश्वत देने पर ही ट्रांसफर होता है। शिक्षकों से भी रिश्वत ली जा रही थी। हालात ये हो गये कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में 1 लाख पद रिक्त हो गये। जहां पर सारे शिक्षक थे, हमारे समय में नामांकन बढ़ा था, वह नामांकन घट गया और इनके कार्यकाल के अन्दर 6 लाख 11 हजार, पूरे राजस्थान में एक साल में नामांकन घटा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की

बात करूं तो उसमें जब सब पद थे तो ऐसे हालात हो गये कि प्राधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, कुल 2948 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 2267 कार्यरत थे और 681 पद रिक्त हो गये। 500 ऐसे शिक्षक थे जो नारियल चढ़ाकर दूसरी जगह चले गये। हुआ ये कि, जीरो नामांकन वाले 151 विद्यालय, जिनमें जीरो नामांकन था, उनमें भी इन्होंने टीचर लगा दिये। इस प्रकार से यह हालत की। मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण देना चाहूंगा, आप अख़बार देखेंगे। विद्यालयों में शिक्षक की कमी, सीनियर विद्यार्थियों ने मांगी टी सी। सारे विद्यार्थियों ने यह कहा कि हमारे पूरे विद्यालय के अन्दर एक शिक्षक है। एक चौकीदार है। उसके भरोसे कैसे पढ़ें? उन्होंने सामूहिक रूप से टी सी मांगी कि हम किसी और विद्यालय में जाकर पढ़ें। यह हालात कर दिये।

मैं कह सकता हूं कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन घटे और सरकारी विद्यालयों में आम जनता, अभिभावकों को विश्वास हुआ कि हमको शिक्षित टीचर मिले हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए, जिससे उस समय नामांकन बढ़ा था और इनके समय में नामांकन घटा है। मैं आज कह सकता हूं कि इस कांग्रेस सरकार के समय दो बड़े घोटाले हुए, मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, लेकिन कह सकता हूं कि मदरसा स्कूल्स में एक लाख बच्चे पढ़ते थे और दो लाख बच्चों के लिए ड्रेसें खरीदी गयीं। एक लाख ड्रेसें कहां गबन हुईं, कैसे हुईं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे एक लाख ही बच्चे थे और उनके लिए दो लाख ड्रेस खरीद ली तो उसकी जांच विशेष रूप से सरकार को करानी चाहिए। वैसे ही मिड-डे-मील था, जो दाल 50 रुपये किलो मिलती थी, वह 75 रुपये किलो में खरीदी गयी। जितने सारे आइटम थे, उन आइटमों में पैसा बढ़ाकर मिड-डे-मील की सामग्री खरीदी गयी। मिड-डे-मील में जो घोटाला हुआ है, उसकी भी निश्चित रूप से जांच करायी जानी चाहिए। मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा।

पिछले पांच साल के अन्दर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ। जब पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं होगा तो बच्चे पूरा शिक्षण कार्य नहीं कर पायेंगे, पढ़ नहीं पायेंगे तो जब परीक्षा होगी तो पास हो जायेंगे, लेकिन मैरिट में पास नहीं होंगे। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, क्वालिटी से पास नहीं होंगे। आप देखेंगे कि जो कार्य दिवस होते हैं, वे 180 दिन होते हैं और 180 दिन पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के राज में 130 दिन पढ़ाया जाता था और शनिवार को तो नो-बैग-डे, शनिवार को कोई बैग नहीं लायेगा और ऐसे ही आयेगा। इस प्रकार से कार्य दिवस पूरे नहीं हुए। समय पर नहीं हुआ और नामांकन घटा।

अब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ायेंगे और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए आनन-फानन में महात्मा गांधी जी के नाम से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अंग्रेजी से कोई सरोकार नहीं था। वे तो स्वभाषा, हिन्दी भाषा को पसन्द करते थे, उनके नाम से खोलकर स्थिति यह कर दी कि जो सेशन चल रहा था, उसके बीच में 436 स्कूलें खोल दीं। न तो कोई कार्ययोजना बनायी, न कोई व्यवस्था की

और यह तय किया कि पंचायत मुख्यालय पर हिन्दी माध्यम का उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर छठी क्लास से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को एडमिशन देंगे। जब बच्चा प्राइमरी से छठी तक पढ़ा ही नहीं, तो वह छठी से अंग्रेजी कैसे पढ़ेगा, उसको भी किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार की तरफ से स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय खोला गया, वह सीबीएसई स्तर पर था। उसमें सारी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी। हमारे समय में प्राइमरी स्कूल खोला गया तो कांग्रेस के समय में वह प्राइमरी स्कूल भी बन्द रहा। जब भाजपा की सरकार बनी तो प्राइमरी स्कूल फिर से शुरू हुआ। ये भी अंग्रेजी विद्यालय के लिए कोई कार्य व्यवस्था करते, कोई नींव बनाते। अंग्रेजी माध्यम के 10 हजार शिक्षकों के पद खाली थे। जब अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक ही नहीं है तो वे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ायेंगे कैसे? सबसे पहले तो वे पद। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय गांव के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल थी, उसको मर्ज किया था। छोटी-छोटी स्कूलें जो पास-पास थीं, कि वे सब सीनियर में आज जायें और हमें अच्छे अध्यापक मिल जायें, उससे व्यवस्थाएं ठीक हुईं। यहां पर उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विधान सभा में हम थे। खूब बोले, खूब नारे लगाये कि इन्होंने 20 हजार स्कूलें बन्द कर दीं। हमारी सरकार आयेगी तो हम ये 20 हजार स्कूलें खोलेंगे। लेकिन इनकी सरकार आयी, स्कूलें तो खोलीं, लेकिन उन 20 हजार स्कूलों को इन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। सभापति जी, मैं कह सकता हूं कि अगर इनको अंग्रेजी माध्यम खोलना था, जो विद्यालय प्राइमरी सेक्शन बन्द हुए थे, उनकी बिल्डिंगें बनी हुई थीं, आप उसके अन्दर अंग्रेजी माध्यम के खोल सकते थे, तो हिन्दी माध्यम के साथ में क्यों मजाक किया? अभिभावकों और बच्चों के साथ में धोखा किया। आज मैं कह सकता हूं कि जहां पर 700-800 बच्चों का नामांकन था, आज वह 100-150 पर आ गया, ऐसे हालात इन्होंने कर दिये।

mdp/rtm/04.03.25/13:40/2a

ऐसे हालात इन्होंने कर दिए। यही नहीं 2022-23 में इन्होंने 3400 स्कूल खोले, जिसमें से 1625 स्कूल शुरू हुए। 2023 के बजट में मुख्य मंत्री से घोषणा करवा दी की शहर में हजार स्कूल खोलेंगे और ग्रामीण स्कूलों में भी 1000 अंग्रेजी माध्यम खोलेंगे। वे भी खुले नहीं। इसी प्रकार से ये अंग्रेजी का हुआ। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजी माध्यम खोलें, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसके लिये नयी नीति बने, नियम बने, मापदंड बने, अगल से भूमि आवंटन हो, पद स्वीकृत हो, पदों पर भर्तियां की जाए और उसके लिए अलग से बजट देकर अलग व्यवस्था हो, न कि हिंदी माध्यम से हो। जो हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम खोला है या दूसरी पारी में खोल सकते थे। हिंदी माध्यम पढ़ाते। हम चाहते हैं कि जहां भी इस प्रकार से हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम खुले हैं, वे हिंदी माध्यम खुलने चाहिए और अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था सरकार हमारी अलग से करे। यह मैं खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा।

भाजपा शासन में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था। अब स्टाफिंग पैटर्न क्या था कि नामांतरण के अनुपात में शिक्षक होंगे और उनके पद स्वीकृत होंगे। लेकिन अब हालात ये हो गये कि स्टाफिंग पैटर्न जो बीजेपी की सरकार में था, वह लागू नहीं किया। बच्चे कम, अध्यापक ज्यादा, अध्यापक ज्यादा वहां बच्चे कम, इस प्रकार से ये चलता रहा और इन्होंने स्थानांतरण का जो उद्योग खोला, उससे भ्रष्टाचार पनपा। मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों में कुपोषण नहीं हो, इसलिए हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार, वसुन्धरा जी की सरकार बच्चों को दूध पिलाने की योजना लायी। दूध पिलाने से जो गांव में हमारा कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था, अगर बच्चों को दूध मिलेगा तो हमारे किसान भी पशुपालन करेंगे, गायों को पालेंगे, गाय रखेंगे और उनको दूध मिलता था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आयी, चार साल बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया। जब लास्ट एक साल कार्यकाल बचा तो इन्होंने वापस दूध की योजना शुरू की। दूध तो नहीं पिलाया, लेकिन डेयरी के दूध का जो पाउडर होता है, वह पाउडर भेजा। हुआ ये कि स्कूल में पाउडर गया, बच्चों को मिला नहीं और उन पाउडर के पैकेट वापस ब्लैक में बिके। ऐसे हालात हुए। आप ईमानदारी अगर कहीं वह दूध पिलाया हो, पाउडर पिलाया हो तो ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो ला सकते हैं। वह पैकेट वापस बिके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अब फिर से जो भाजपा शासन में व्यवस्था थी बच्चों को गाय का, भैंस का अच्छा दूध, मैं तो कहता हूं गाय का दूध मिलना चाहिए। दूध पिलाने की योजना आप वापस शुरू कीजिए। वास्तव में ये योजना इस प्रकार की हुई इसलिए नामांकन कम हुआ, नामांकन घटा है। हम चाहते हैं कि जो मॉडल 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान में था, वही मॉडल वापस लागू होना चाहिए।

अब ट्रांसफर पालिसी के लिए, हर सरकार आती है और कहती है कि हम ट्रांसफर पालिसी बनाएंगे। स्थानांतरण की नीति बनाएंगे। ट्रांसफर सारे हुए, प्रिंसिपल के हुए, प्रधानाध्यापक के हुए, सेकण्ड ग्रेड हुए, फर्स्ट ग्रेड हुए, लेकिन थर्ड ग्रेड आज भी इंतजार कर रहा है। थर्ड ग्रेड के शिक्षक आज भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले कांग्रेस के राज के अन्दर भी इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे कि जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर कराना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करे। 85000 आवेदन आए, लेकिन 85000 में से एक भी ट्रांसफर हुआ नहीं। आज भी वह इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार चाहते हैं कि सारे शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड के शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा है? उनके ट्रांसफर की नीति लाए, चाहे ऑनलाइन लें, जहां पर नियुक्त है, कोई ऐसा सिस्टम नियम बनाए जिससे उनका भी स्थानांतरण हो सके। यह मेरा खासतौर से आपसे निवेदन रहेगा।

भाजपा शासन के समय स्कूलों के अन्दर बच्चे जहां स्वस्थ शरीर होगा, वहां स्वस्थ दिमाग होगा, इसलिए योगाभ्यास का एक पीरियड शुरू किया था। अब योगाभ्यास बीजेपी ने शुरू किया, इसलिए कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया कि योगाभ्यास नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी को

कि जैसा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अन्दर एक योग दिवस की शुरूआत की है, जिसका अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है और वह योग दिवस हमेशा 21 जून को मनाया जाता है तो फिर से योगाभ्यास शुरू हुआ है और साथ-साथ ही सभी जगह सूर्य नमस्कार शुरू हुआ है। ये बहुत ही अच्छा अनुकरणीय कार्य किया है। हम चाहेंगे कि जैसे सूर्य नमस्कार हुआ है, वैसे ही हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर, हम चाहते हैं कि खासतौर से राजस्थान में महाभारत, गीता और रामायण को भी पढ़ाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही हमारे विद्यालयों के अन्दर साफ-सफाई के लिए, चौकीदार के लिए, रंग-रोगन के लिए एक कम्पोजिट स्कूल ग्रांट शुरू की थी। जो कांग्रेस के समय में वितरण नहीं हुआ और स्कूलों के हालात खराब हुए। हम चाहते हैं कि कम्पोजिट स्कूल ग्रांट जो शुरू की थी, वह भी समय पर हो जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि विद्यालय जैसे मांग रहे हैं, कांग्रेस के समय में क्रमोन्नत करते गये। विद्यालय तो क्रमोन्नत कर दिए, लेकिन पद स्वीकृत नहीं किए। कहीं पर पद स्वीकृत कर भी दिए तो पद भरे नहीं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि इसकी एक नीति होनी चाहिए। इसका एक कलेण्डर होना चाहिए कि पूरे साल में कौन-कौनसे ग्रेड के शिक्षक कब रिटायरमेंट हो रहे हैं। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले उनकी भर्तियों का कलेण्डर निकाला जाना चाहिए। जैसे ही पद रिक्त हो, वह पद भरे जाने चाहिए, जिससे हमारे गांवों में अच्छी शिक्षा मिल सके और समय पर भर्ती हो सके। इसके लिए कलेण्डर और भर्तियां सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी रीट प्रकरण, आप देखेंगे कि आर.ए.एस. से भी ज्यादा पढ़ाई यदि किसी की है तो बी.एड. के छात्र की है। उसको नर्सरी से लगाकर ग्रेजुएशन, फिर बी.एड., बी.एड. के बाद में रीट करो, रीट के बाद में फिर परीक्षा दीजिए और परीक्षा देकर फिर आओ। बच्चा वास्तव में पढ़ते-पढ़ते कितना कुंठित होता है। रीट की जब वह परीक्षा देता है तो ये पेपर माफिया लाखों रुपये लेकर पेपर लीक हो जाता है, जिससे अभिभावकों का सपना चकनाचूर होता है। जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं, इनका एडजस्टमेंट, इनके साथ होता है। मैं यह चाहूंगा कि अभी जो रीट का एक्जाम हुआ है, इसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया और न ही कोई लीक हुआ। बड़ी ही पारदर्शिता से रीट परीक्षा हुई है। हम चाहेंगे कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी बने हैं, इनके लिए एक नियमावली बनाए और प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में जो बच्चे शिक्षा समय पर दें, मेहनत करके दें, जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपने चकनाचूर होते हैं। वे सुसाइड करते हैं। वे सुसाइड नहीं करें, इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए।

साथ ही, हम यह चाहेंगे कि भाजपा के समय में पहली बार बहुत ही अच्छी तरीके से डी.पी.सी. हुई थी। एक ऐसे शिक्षक जिनकी तीन-तीन बार डी.पी.सी. हो गयी और पिछले 15 साल से डी.पी.सी. नहीं थी, इनको पांच साल में तीन बार डी.पी.सी. मिली। इसकी भी समय सीमा होनी चाहिए। समय पर डी.पी.सी. हो, जिससे गांव में हमारा शिक्षक सही ढंग से पढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 40 हजार प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाया था।

उनको सेकेण्ड ग्रेड के समान दर्जा होगा, लेकिन आज भी उनको ये दर्जा नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि उनको 9-18-27 का लाभ मिले। विद्यालयों में हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि व्यावसायिक मेकिंग शिक्षा होनी चाहिए। बिजनैस मेकिंग शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिले, यह मेरा खास तौर से निवेदन रहेगा।

पहले क्या था कि विद्यालय 5वीं तक थे, 8वीं हुए, 10वीं हुए, 12वीं हो गये। अब 12वीं के बाद हमारे गांव के बच्चे जाएं कहां? तो विश्वविद्यालय दिखता था, लेकिन आज हमारी जब से सरकार आयी है तो गांव में राजकीय महाविद्यालय खोल रही है। मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजकीय महाविद्यालय भी खोले हैं। अभी-भी कॉलेज शिक्षा में 70 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कई जगह पद रिक्त हैं, उनको सही समय पर भरा जाए। आई.टी.आई., हमारे ब्लॉक मुख्यालय पर आई.टी.आई., जब मैं 2013 से 2018 के बीच यहां सदस्य था, उस समय हमारे शेखाड़ा में और शेरगढ़ में आई.टी.आई. खुले 10-10 करोड़ के, लेकिन बने हुए भवन हैं, आज दिन तक वह शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे राजस्थान में कई आई.टी.आई. बने हैं, 10-10 करोड़ के, लेकिन वहां शिक्षक नहीं है। सही ढंग से आई.टी.आई. चल नहीं रहे हैं। इसको भी संभाले।

अब स्थिति यह है कि अभी जो हालात हैं, 25 या 30 जो नामांकन होता है, उसके ऊपर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 115 बच्चों पर एक टीचर है। यह भी व्यवस्था हमको ठीक करनी चाहिए। यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा। दूसरा, मेरा निवेदन है कि हम विश्वविद्यालय से आए हैं। छात्रसंघ के अध्यक्ष बनकर आज राजस्थान की विधान सभा में हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ जब देखते हैं तो कहते हैं कि 'मोर फूटरो घणो ही, पण पगा न देख रोवे।' हमारे विश्वविद्यालय के हालात ये है कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, वहां जो शिक्षक रिटायरमेंट हो गये, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे यहां भी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अन्दर शिक्षक लम्बे समय से धरना दे रहे हैं। उनको पेंशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस सरकार में आनन-फानन में जो पूरे विश्व में हमारे एम.बी.एम. इंजीनियरिंग संकाय का नाम था, उसके नाम से एक अलग विश्वविद्यालय खोल दिया, लेकिन कोई संसाधन वहां नहीं हुए। आज भी वह विश्वविद्यालय सही ढंग से नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि जब संसाधन सही नहीं मिल रहे हैं और सही ढंग से वहां शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसे विश्वविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद करके फिर से हमारे विश्वविद्यालय में एम.बी.एम. इंजीनियरिंग संकाय थी, उसी में कर लेना चाहिए, जिससे सही ढंग से कार्य हो।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के समय में मेरे हिसाब से तो रेवड़िया बंटी। जैसे ही कोई विधायक आए कि राजकीय महाविद्यालय खोल दीजिए, तो खोल दिया। लेकिन राजकीय महाविद्यालय में न तो शिक्षक भर्ती किए और इन्होंने राजस्थान एजुकेशन सोसायटी के हवाले कर दिया। अब वह जो राजकीय महाविद्यालय खुले, वह राजस्थान एजुकेशन

सोसायटी के हवाले करने से न तो उनमें सरकारी शिक्षक गया और न वहां पढ़ाई हुई।

Ans/rtm 13.50 2b 04.03.2025

वहां अतिथि शिक्षक के नाते वह विद्यालय चल रहे हैं, तो वह राजकीय भी हो और उन विद्यालयों में भी राजकीय शिक्षक लगे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए।

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इन सबमें चिंता का विषय है। आजकल तो जो अँग्रेज़ी विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में नशे की प्रवृति बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आपने अखबरों में भी पढ़ा होगा, कई अँग्रेज़ी माध्यमों में कोल्ड ड्रिंक के अन्दर शराब मिलाकर ले जाते हैं और बच्चों को चखाते हैं। बच्चों को नशे की प्रवृति के लिए आदतन बनाते हैं। कई जगह स्कूलों, कॉलेजों के पास हुक्का बार चल रहे हैं, रेव पार्टियां हो रही है, एमडी आ रही है, स्मैक आ रही है, हेरोइन, चरस, गाँजा, शराब, सिगरेट की प्रवृति बढ़ी है इसके लिए आप सख्त कानून बनाइये और शिक्षा में नशे की प्रवृति को दूर रखे, नशा मुक्त रखे, इसकी व्यवस्था भी आपको विशेष तौर से करनी चाहिए1

सभापति महोदय, मैं हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं 2003 में पहली बार विधायक बनकर आया था, आपने गाँवों में शारदा छात्रावास खोला, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास खोला, आपने अनुसूचित जाति का छात्रावास खोला, अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोला। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अब ई डब्ल्यू एस के भी छात्रावास खोल रहे हैं। यह छात्रावास खुलेंगे तो हमारे गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति भीलों की बच्चियां हमारे मनुहार करने से भी स्कूलों में नहीं आती थी, आज सिफारिश के आती है। आज वह बच्चियां डॉक्टर, नर्स, कम्पाउण्डर, आरएएस बन रही है। हम चाहते हैं कि सभी पंचायत समिति मुख्यालय है, उन मुख्यालयों पर शारदा छात्रावास, कस्तूरबा छात्रावास, एस सी, एस टी छात्रावास, ई डब्ल्यू एस का छात्रावास खुले, जिससे बच्चा हमारी मुख्य धारा में आये और पढ़ सके।

खेल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। जो नियम बने हुए हैं, मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 12 वीं विद्यालय है इसका साढ़े सात बीघा का नोर्म्स है तो आप नरेगा से व कुछ पैसा अपने डिपार्टमेंट से लगार प्रत्येक 12वीं विद्यालय को खेल मैदान जरूर मिलना चाहिए। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने शहीदों का सम्मान किया और सरकार बनते ही 51 विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम से किया है। हम चाहते है कि राजस्थान के सभी शहीद है उनके नाम से विद्यालयों का नामकरण हो। विद्यालयों के अन्दर सरस्वती माता जी का मन्दिर बने, लाइब्रेरी बने, सीसीटीवी कैमरे लगे। सब बच्चियां पढ़ने लगी है, तो जिस विद्यालय में 500 से अधिक बच्चियां हो गई है वहां पर हमको अलग से बालिका विद्यालय खोलने की जरूरत है। बालक विद्यालय खोले, उनका अधिक नामांकन हो।

शिक्षक गांव में पढ़ाते हैं, वहां आंधी चलती है, तेज सर्दी पड़ती है, तो जो चिकित्सा

विभाग में व्यवस्था है कि जो नर्स, एएनएम जो सेवाएं दे रहे हैं उनको ग्रामीण भत्ता मिलता है तो क्यों नहीं जो शिक्षक विषम परिस्थितियों में गांव में पढ़ा रहे हैं उनको ग्रामीण भत्ता दे, उनको ग्रामीण भत्ता जरूर दे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो मिनट, बस कर रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों में ड्रेस होती है, एक तरफ सरकारी स्कूल में ड्रेस होती है, तो एक भेदभाव की स्थिति होती है। प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी ड्रेस होती है। हम यह चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में प्राइवेट व सरकारी स्कूलों का एक ही ड्रेस कोड हो, ताकि भेदभाव नहीं हो। सुलभ कॉम्पलेक्स बने, रंग-रोगन हो, सफाई हो।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की। पीएम श्री योजना में आवश्यक संसाधन विकसित करने का सफल माध्यम बनी। योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों में लगभग 03 लाख 15 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यूटी, गार्डन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण, स्वास्थ्य योग, खेल, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी और सामुदायिक गतिशीलता जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही है।

श्री सभापतिः विराजे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): शिक्षा मंत्री जी, अगर ऐसी योजना अगर सभी विद्यालयों में लागू हो तो बहुत अच्छा काम होगा।

श्री सभापतिः विराजें। धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभी स्कूलों में डिजिटल क्लास रूम हो। लेपटाप व टेबलेट मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी भजनलाल सरकार ने 57 राजकीय महाविद्यालय आई टी आई, कृषि महाविद्यालय, आई टी का आधुनिकरण..

श्री सभापतिः प्लीज, विराजें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सैनिक स्कूल, पीजी तक शिक्षा की व्यवस्था, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, खेल स्टेडियम, कन्या महाविद्यालय, मेरे यहां भी बालेसर में कन्या महाविद्यालय ...

श्री सभापतिः विराजें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): राजकीय महाविद्यालय, दो दिये हैं, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करुंगा। भवन स्वीकृत किये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दे रही है इसके लिए मैं खास तौर से शिक्षा मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री पितराम सिंह काला।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक मिनट, मेरे क्षेत्र की मांग है। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की हमारी जो अनुदान माँगें हैं, कक्षा कक्षों की कमी वाले राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य। नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने व विद्यालय

क्रमोन्नत करना। राजकीय विद्यालयों में विभिन्न रिक्त पदों को शीघ्र भरवाये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त विषय एवं नवीन संकाय की स्वीकृति प्रदान करना। बंद राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को पुनः शुरू करना। राजकीय विद्यालयों में जर्जर भवनों की मरम्मत करवाना। भवनविहीन विद्यालयों को भवन की स्वीकृति देना। तहसील मुख्यालय नाधव एवं झीरनाकल्या में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाना।

श्री सभापतिः विराजे।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 व 22 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको व मेरे दल के नेताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो पूरे शिक्षा विभाग को संचालित करती है, मॉनिटरिंग करती है और प्रभावी तरीके से राजकीय योजनाओं को संचालित करती है, वह जिला शिक्षा अधिकारी का पद होता है। चूंकि मैं भी चूरू में दो साल जिला शिक्षा अधिकारी रहा था। जब मैंने चूरू जिला शिक्षा अधिकारी पद ज्वाइन किया था तो चूरू उस समय 29वें नम्बर पर था। मेरे दो साल के कार्यकाल के अन्दर चूरू हमेशा पहले नम्बर पर रहा। यहां हमारे जिला प्रमुख भी बैठे हैं चूरू से आने वाले। हमारे विधायक उस समय जिला प्रमुख थे। आपकी सरकार थी राज्य स्तर पर मुझे बेस्ट डी ई ओ के रूप में सम्मानित किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिला शिक्षा अधिकारी महत्वपूर्ण पद है उसके राजस्थान के अन्दर 350 पद रिक्त है। यह नहीं है कि कर्मचारी नहीं है। अभी पिछले दिनों 329 जिला शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति हुई थी, उनमें से 65 तो सेवानिवृत्त हो गये और 265 बचे हैं, वह स्कूलों में बैठे हैं और जिले की शिक्षण व्यवस्था को दुरूस्त करने वाला पद है, उनको पोस्टिंग नहीं दी गई है।

इसके अलावा 212 ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी है जो छह महीने से अधिक समय से एपीओ बैठे हैं। उच्च न्यायालय ने उसके लिए निर्देश दिया है, कि जिला और ब्लॉक के पद रिक्त है, 06 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, प्रधानाचार्य, व्याख्याता का डी पी सी उपरांत पदस्थापन नहीं हुआ, ए पी ओ किए अधिकारियों में से क्या किसी को आरोप पत्र दिया है, लगातार ए पी ओ रखने से शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग प्रभावित होती है, यह स्थिति कोर्ट ने दी है। इसके बावजूद अब तक उनका पदस्थापन नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां उनको पद स्थापित किया जाए ताकि मॉनिटरिंग व शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो।

सभापति महोदय, प्रधानाचार्य के 04 हजार 242 पद है, उन पर डी पी सी हो चुकी इसके बावजूद भी उनको पदस्थापन नहीं किया गया है। थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड के व्याख्याता जो बने हैं उनके भी 05 हजार 500 पद की डीपीसी हो चुकी है, लेकिन अब तक पदस्थापन नहीं

किया गया। महात्मा गांधी विद्यालयों में जिनका सलेक्शन हो गया है, सलेक्शन होने के बाद भी उनको पदस्थापन नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार की मंशा केवल शिक्षण व्यवस्था को सुचारु करना नहीं है इसको पटरी से उतारना है, जिससे राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था निरन्तर घटती रहे।

मैं आपको बताना चाहूंगा एपीओ के अन्दर यह नियम बने हुए हैं कि एक महीने से ज्यादा एपीओ नहीं रखा जाए। उनको वेतन देना पड़ता है। अनावश्यक 12-12 महीने से एपीओ बिठा रखे हैं।

मेरे से पूर्व माननीय सदस्य महात्मा गांधी विद्यालय का जिक्र कर रहे थे। इनको मैं बताना चाहूंगा, यह एक ऐसी स्कीम थी जो राजस्थान के अन्दर सर्वश्रेष्ठ स्कीम थी।

VPS-RTM-04.03.2025-14.00-2c

इसका परीक्षण किया गया और सबसे पहले जिला स्तर पर महात्मा गांधी विद्यालय खोले गये थे। वे जब सफल हुए तो उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गये और जब उनकी सफलता सुनिश्चित हुई तो उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे और खुलने के बाद उनकी इतनी प्रसिद्ध हुई, इतना उनके प्रति लोगों का लगाव हुआ कि जितने सेक्शन थे, उन सेक्शनों के अन्दर बच्चे आये नहीं। उस समय मैं संयुक्त निदेशक भी था। हमने पद बढ़ाने के लिए निदेशालय के अन्दर प्रस्ताव भेजे और सेक्शन बढ़ाये तब जाकर भी सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ आज उन महात्मा गांधी स्कूल को केवल इसलिए ये बरबाद करना चाहते हैं कि वह महात्मा गांधी के नाम से है।

जब हम 2022-23 की बात करते हैं तो हमारे राजकीय विद्यालयों का जो नामांकन है वह 99.8 लाख था और आज वह घटकर 75 लाख हो गया है। जिस होटल के अन्दर ग्राहक जाना बंद कर देता है तो आप यह मान लो कि वह होटल फेल है और यही स्थिति सरकारी विद्यालयों की इन्होंने कर दी। आज वह 99 लाख से 75 लाख हो गये तो आप मान लो कि उसकी क्या स्थिति है, मैं आगे नहीं कहना चाहता, नहीं तो कोई शब्द निकल जायेगा और वह वापस बहस का मुद्दा बन जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, उन स्कूलों को ये जानबूझकर बंद इसलिए करना चाहते हैं कि भ्रामक स्थिति पैदा करके जो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, दलित के बेटे हैं, कमजोर के बेटे हैं, वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में नहीं पढ़ लें। आज समय यह आ गया है कि हमारे चाहे खुद के बच्चे हों या चाहे किसी के भी बच्चे हों, हर अभिभावक का यह सपना होता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े और जहां प्राइवेट स्कूलों के अन्दर हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां चाहे इंग्लिश मीडियम नाम की चाहे छोटी से छोटी स्कूल हो, उसकी फीस तीस से चालीस हजार रुपये से कम नहीं है और वह ही स्कूल के अन्दर, राजकीय स्कूल के अन्दर, महात्मा गांधी विद्यालयों के अन्दर वह बच्चा पढ़ता है तो उसके

अन्दर फ्री सुविधाएं दी जाती हैं। महात्मा गांधी विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिनके अन्दर अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं और सरकार के अन्दर जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं तो उस सिस्टम को खतम करने के लिए जानबूझकर यह महात्मा गांधी विद्यालयों के अन्दर ऐसा माहौल कर दिया कि इनके रिक्त पद हम भरेंगे नहीं, लोगों के अन्दर ऐसी भावना आ जायेगी, वे अपने बच्चों को निकाल लेंगे और जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वह खतम हो जाये, इस प्रकार से इनकी यह मानसिकता है तो इसको आप दुरुस्त करें।

महात्मा गांधी विद्यालय की, ये कह रहे थे कि साधन और सुविधा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर झुन्झुनूं की मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया था तो 219 का नामांकन था और आज वहां पर 385 का नामांकन है। जब वह विद्यालय इंग्लिश मीडियम के अन्दर क्रमोन्नत हुआ था तो वहां पर केवल आठ कमरे थे और वह भी सोलह बाई बीस के थे। इस कार्यकाल के अन्दर वहां सात कमरे और नये बन गये, वह सारे बीस बाई छब्बीस के बने हैं। प्रिंसिपल का कार्यालय कलक्टर के कार्यालय जैसा बन गया। स्कूल का खेल मैदान था उसके चारों तरफ चारदीवारी कर दी गयी और ऐसी शानदार स्कूल चल रही है कि आज भी वहां पर लॉटरी से एडमिशन लेना पड़ता है। यही स्कूल घड़ाणा स्कूल है, जीनी स्कूल है और किड़वाना स्कूल है जहां पर लाखों रुपयों से भवन बनकर तैयार हो गये और आज वह प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया भवन चल रहे हैं तो यह स्थिति सुधरी है, लेकिन इनकी नजर कहीं दूसरी ओर है, इनका इरादा दूसरा है, इनकी नीयत दूसरी है और इनकी नीति दूसरी है, वह क्या है कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

राजकीय विद्यालयों को सबसे समृद्ध करने वाली योजना थी वह, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जन सहभागिता योजना की स्कीम थी। जिसके अन्दर चालीस प्रतिशत पैसा भामाशाह दान देता था और साठ प्रतिशत पैसा राज्य सरकार अंशदान के रूप में देती थी। उससे पूरे राजस्थान के अन्दर विद्यालयों का कायाकल्प हुआ, बढ़िया भवन बने, फर्नीचर की व्यवस्था हुई, गेट बने, चारदीवारी बनी, कक्षा कक्षा बने, कम्प्यूटर लैब बनी और सारी सुविधाएं थीं, वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हुईं और प्रत्येक जिले के अन्दर करोड़ों रुपये का काम हुआ। मेरे झुन्झुनूं जिले के अन्दर भी करोड़ों रुपये का उसके अन्दर काम हुआ लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के अन्दर आयी है उस मुख्य मंत्री जन सहभागिता योजना है, उसके अन्दर एक भी रुपया जारी नहीं किया है। आज वे भामाशाह जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार के अन्दर, विद्यालयों के अन्दर पैसे जमा करवाये थे और वे यह चाहते थे कि हमारे विद्यालयों का कायाकल्प हो, बच्चे अच्छे स्कूलों के अन्दर पढ़ें, अच्छे साधन उनको उपलब्ध हो और वह पैसा आपके समसा के माध्यम से यहां जयपुर आ गया है, अब तक उसकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की हैं। अतः माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को यह कहना चाहूंगा कि आप उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करायें जिससे विद्यालयों के अन्दर उनके भौतिक डवलपमेंट के

लिए, उनके अन्दर सुविधाओं के लिए वह राशि मिले और उन विद्यालयों की प्रगति हो।

इसी के साथ आगे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, उसके अन्दर विदेशों में जो लड़के पढ़ते हैं, उसके अन्दर 300 बच्चों का चयन किया जाता है और 200 बच्चों का राजस्थान के अन्दर किया जाता है तो उसकी संख्या बढ़ाई जाये और उसके अन्दर एस.सी., एस.टी. का आरक्षण, जिस प्रकार से अन्य जगह दिया जाता है, उसी प्रकार से इसके अन्दर भी आरक्षण दिया जाये, जिससे वे बच्चे भी विदेश के अन्दर, अच्छी संस्थाओं के अन्दर पढ़कर समाज का नाम रोशन कर सकें, देश की प्रगति के अन्दर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों के अन्दर, अभी मेरे से पहले वाले वक्ता बता रहे थे कि इतने पद रिक्त पड़े हैं। इन्होंने कम बताये हैं। डेढ़ लाख के लगभग पद रिक्त पड़े हैं तो उन पदों को भरा जाये और ये पद तो क्या भरेंगे, ये स्कूल के डवलपमेंट की बात क्या करेंगे? इन्होंने साढ़े चार सौ स्कूल बंद कर दिये। नई खोलने वाली क्या बात? मैं यह चाहूंगा कि उसके अन्दर जो रिक्त पद हैं उनकी समयबद्ध डी.पी.सी. हो, उनको भरा जाये, जिससे शिक्षा का जो सिस्टम है, उसके अन्दर गुणवत्ता हो और आगे बढ़े और राजस्थान का शिक्षा के अन्दर नाम हो।

अभी पिछले दिनों वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की डी.पी.सी. हुई थी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एस.सी. और एस.टी. वर्ग की घोर उपेक्षा हुई है। जो वर्ष 2023-24 की डी.पी.सी. हुई है, उसके अन्दर 5551 तक जो प्रधानाचार्य की डी.पी.सी. होनी थी, उसमें से और एस.सी. और एस.टी. के पद वर्ग के हिसाब से नहीं लिये गये और यह कोर्ट के अन्दर प्रावधान किया गया। इन्होंने यह कहकर नहीं लिये कि सामान्य का, जो एस.सी., एस.टी. का है, उतने पद हम नहीं ले सकते तो कोर्ट का जो कार्मिक विभाग राजस्थान का आदेश है, ग्रुप-2, दिनांक 13.09.2013 के अनुसार वरिष्ठ आरक्षित कार्मिक की अनारक्षित कोटे में पदोन्नति होगी। इसके बावजूद इन्होंने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के अन्दर 358 एस.सी. के और 156 एस.सी. और एस.टी. के, दोनों के जो पद हैं, वह कम भरे हैं तो मैं इनसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनकी पूर्ति की जाये और उनको न्याय दिया जाये।

अभी ये बता रहे थे, ये एस.सी. और एस.टी. की बात कर रहे थे तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इनकी कैसी दुर्भावना है और कैसी क्या स्थिति है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आपकी जब बी.जे.पी. सरकार बनी तो उस अवधि के अन्दर किस प्रकार से एस.सी. और एस.टी. के लोगों के ऊपर विद्यालयों के अन्दर क्या अत्याचार हुए? वर्ष 2022-23 में पृथ्वीराज बैरवा, व्याख्याता, इतिहास के थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजाखेड़ा, धौलपुर के अन्दर थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत फेसबुक पर डाक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले एवं अन्य समाज सुधारकों को पुस्तकों में उद्धत प्रसंगों को सोशल मीडिया में डालने के आरोप में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। हमारा संविधान यह हमें

अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि कोई भी विचार हो, वह उसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं।

ssy/rtm/04.03.2025/14.10/2d

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कोई भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इस सरकार में एससी के साथ जो अन्याय किया गया है, यह बहुत गलत है। दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को दौसा क्षेत्र के मंडावरी गांव में एससी समुदाय की आठवीं कक्षा की स्कूल छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया।

26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान श्रीमती हेमलता बैरवा, प्रबोधक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई, तहसील किशनगंज, जिला बारां को अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के दौरान स्थानीय गांवों के पार्टी विशेष के स्थानीय प्रभावशाली समुदाय के दबाव में आकर राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया गया एवं अनुसूचित जाति की महिला शिक्षक को बिना किसी दोष के निलंबित किया गया। उसका केवल यह था कि महात्मा ज्योतिबा फूले की धर्म पत्नी मां सावित्री बाई फूले थी, जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी, उसकी फोटो लगा दी। वह तो प्रथम शिक्षिका थी, जिसने महिला शिक्षा की अलख जगायी थी, जिसके कारण से महिला शिक्षा आगे बढ़ी। उसकी फोटो लगाने पर इन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी?

15 फरवरी, 2024 को झालावाड़ रोड स्कूल में विकलांग दिवस उप प्रधानाचार्य श्री प्रवीण कुमार जाटव को इस विद्यालय के अध्यापक श्री विनोद कुमार धाकड़ के द्वारा अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया। कोई कार्यवाही नहीं हुई। 8 फरवरी, 2024 को श्रीमती पूजा बुनकर अनुसूचित जाति की अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रोजड़ा, जालसू, जिला जयपुर के साथ स्कूल के स्टाफ द्वारा जातीय भेदभाव, अत्याचार एवं उत्पीड़न से प्रताड़ित किया गया। उन्हें किस आधार पर निलंबित कर दिया गया?

फरवरी, 2024 में श्रीमती पूजा बुनकर के पति श्री मुकेश कुमार वर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रोजगारी, जस्सू, जयपुर का भी जातीय भेदभाव के आधार पर निलंबन किया गया। 14 सितम्बर, 2023 को झुंझुनूं जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय, बीबासर की कनिष्ठ सहायिका सोनो कुमारी के साथ स्कूल के ही प्रधानाचार्य परमजीत सिंह द्वारा निरंतर जातीय भेदभाव, उत्पीड़न से परेशान किया गया। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट है। उसके अन्दर दोषी है। उसके बावजूद प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। 3 महीने बाद में वहां गांव वालों ने आंदोलन किया और वहां के एक विधायक ने जब उसका विरोध किया तब जाकर प्रिंसिपल को सस्पैंड किया।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को श्री शंकर लाल, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी जो वर्तमान में अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग, जिला डीग ने 21 सितम्बर, 2022 को आयोजित एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के सामूहिक सामाजिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने पर जान-बूझकर जातीय द्वेषता, भेदभाव व बदले की भावना के आधार पर उनके विरुद्ध

असत्य प्रकरण बनाकर उन्हें निलंबित किया गया। सामाजिक संस्कारों में सभी जाते हैं। कल को अभिमन्यु पूनिया जी का रिसेप्शन था, सारे एमएलए गये थे। मुख्य मंत्री जी भी गये थे। सामूहिक जो सम्मेलन होता है तो बढ़िया बात है। उसमें खर्चे कम लगते हैं, लेकिन वहां जाने के आधार पर उसको निलंबित कर दिया गया, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी।

भरतपुर जिले के श्री बलराम मंडोदिया, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर को भी दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर के द्वारा जातीय द्वेषता, दुर्भावना और बदले की भावना की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया।

श्री सुनील कुमार, अध्यापक, ये कई प्रकरण हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्या है कि मेरा समय हो जायेगा। पहले मैं मेरी मांग रख देता हूं। उसके बाद आगे की बातें मैं बाद में करूंगा।

माननीय, मेरी मांग इस सरकार से है कि पिलानी के अन्दर तहसील है, 2 नगरपालिकाएं हैं और वहां एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहां जो निजी महाविद्यालय था, जिसको एड दी जाती थी, वह बंद हो गया है। आपसे निवेदन है कि वहां एक महाविद्यालय खोला जाये। पिलानी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। जिस शहर के अन्दर 2 नगरपालिकाएं हों, तहसील मुख्यालय हो और वहां बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन है कि यह भी एक खोलने की कृपा करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की स्थानांतरण नीति की आपने घोषणा की थी। उसको नीति बनायें और उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण किये जायें। इसी के साथ क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। हमारी जब सरकार थी तो 6232 स्कूलें हमने खोली थीं और उन स्कूलों को अब क्या है कि व्याख्याताओं के पद भी स्वीकृत कर दिये, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई, तो माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वह वित्तीय स्वीकृति उनकी जारी करें।

एससी और एसटी की जो छात्रवृति है, वह बहुत अधिक बकाया है। मैं, आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह बकाया छात्रवृतियां जारी की जायें, जिससे उन छात्रों को फायदा हो सके। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित शिक्षकों का पदस्थापन किया जाये। क्योंकि जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं, उनके अन्दर शिक्षक लगा देंगे, यह वातावरण बनाओ कि यह खुलेंगे या बंद करेंगे, चलेंगी या नहीं चलेंगी, तो वह स्थिति आप स्पष्ट करें। कई बार यह कह रहे हैं कि कई ऐसी स्कूलों को खोल दिया गया जहां दूसरी स्कूल नहीं थी या संसाधन नहीं थे। संसाधन तो आदमी जब नया घर बसाता है तो होते नहीं हैं। धीरे-धीरे संसाधन हो जाते हैं।

जब हमारी सरकार ने 6232 स्कूलें खोली तो जहां आपको यह आवश्यकता थी कि यहां विद्यालय नहीं हैं तो वहां नये विद्यालय खोलें। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, इनको किसी भी

सूरत में बंद नहीं करें। हमारा जो नामांकन 99.8 लाख था उससे घटकर 75 लाख आ गया, वापस उस स्थिति के अन्दर पहुंच जायेगा, राजस्थान एक नम्बर पर रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हैं।

माननीय महोदय, इसी के साथ पिलानी विधान सभा क्षेत्र में जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनके अन्दर एक भी पद नहीं है। अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। उनके पास मैं बात सभापति महोदय के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा कि कम से कम जो व्याख्याता है, वह तो स्थाई पद दिया जाये। यदि स्थाई पद दिया जायेगा तो औरों की तो व्यवस्था हो जायेगी, जब किसी घर के अन्दर आप एक स्थाई आदमी दोगे तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? आप उसके अन्दर व्यवस्था करें। इस प्रकार की व्यवस्था होने से लोगों के अन्दर विश्वास पैदा होगा। अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे तो असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। आपकी नीति और नीयत जो है, उन दोनों को आप ठीक करें, जिससे विद्यालयों का, महाविद्यालयों का वातावरण ठीक रहे।

रिक्त पदों के बारे में अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि डेढ़ लाख के लगभग रिक्त पद पड़े हैं। उनको समयबद्ध तरीके से, पहले तो डीपीसी की जाये, जब डीपीसी हो जायेगी, जब डीईओ की डीपीसी हो जायेगी तो प्रिंसिपल का पद खाली हो जायेगा, प्रिंसिपल की हो जायेगी तो वाइस प्रिंसिपल का हो जायेगा। उसके बाद में सेकण्ड ग्रेड की हो जायेगी। थर्ड ग्रेड की हो जायेगी। सबसे पहले तो उनकी डीपीसी की जाये। डीपीसी करने के बाद में जो रिक्त पद हैं, उनको समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से भरा जाये क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम है वह शिक्षा है। शिक्षा के अन्दर इनवेस्टमेंट किया हुआ उससे समाज के अन्दर प्रगति होती है। अन्य क्षेत्रों के अन्दर कटौती करके शिक्षा का जो बजट है वह बढ़ाया जाये और समय पर जो पद हैं, इनको भी भरा जाये।

वेतन विसंगति शिक्षा विभाग के अन्दर कई चल रही हैं। कई हमारे जो साथी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर्ड हो गये। वह रोज कभी तो निदेशक महोदय के पास चक्कर काटते हैं, कभी मंत्री महोदय के पास चक्कर काटते हैं। उनकी जो वेतन विसंगति है, वह आप बैठकर तय करें। जिससे उनको भी लाभ मिल सके।

एक स्कूलों के अन्दर कंपोजिट ग्रांट होती है, उस कंपोजिट ग्रांट के अन्दर विद्यालय की साफ-सफाई व्यवस्था का काम होता है। विद्यालय के शौचालय वगैरह का काम होता है। विद्यालय के अन्दर जो आवश्यक उपकरण होते हैं, वे लिये जाते हैं। डेली के अन्दर जो आवश्यक उपकरण होते हैं, वह लिये जाते हैं। डेली के जो खर्च हैं, वह लिये जाते हैं। उससे खर्चा चलता है।

हमारी जब सरकार थी तो जो कंपोजिट ग्रांट है वह समय पर जारी की जाती थी। लेकिन आपके समय के अन्दर कंपोजिट ग्रांट मात्र 10 परसेंट जारी की गई है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह ग्रांट जारी की जाये, जिससे स्कूल के अन्दर आवश्यक जो संसाधन हों, वे उपलब्ध हो सकें और दिनचर्या के

जो कार्य हैं, वह समय पर संपादित हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि विद्यालयों के अन्दर को-करिकुलम एक्टिविटी चलती है। पढ़ाई के साथ खेल भी उतने ही आवश्यक हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि, sound mind is found in sound body. बच्चे का शरीर मजबूत होगा तो उसका मस्तिष्क मजबूत होगा। बच्चे खेलेंगे तो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। पहले क्या होता था कि विद्यालय स्तर पर तय होता था कि कौन-कौनसी खेल सामग्री क्रय की जायेगी।

spp/rtm/04.03.2025/14.20/2e

किसी स्कूल में क्रिकेट का खेल होता था तो क्रिकेट की सामग्री खरीदी जाती थी। किसी में फुटबॉल का खेल होता था, वह फुटबॉल खेला जाता था। कहीं वॉलीबाल की आवश्यकता थी तो वॉलीबाल खरीदी जाती थी लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अब उस सिस्टम को चेंज करके और माननीय मंत्री महोदय ने केन्द्रीयकृत कर दिया है कि सारा सामान हम खरीदेंगे और हम विद्यालय में भेजेंगे। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी नीयत और नीति दोनों साफ होनी चाहिये। यह क्रय का अधिकार पहले एस.डी.एम.सी. को था, उसी प्रकार से उनको वापस दिया जाये जिससे वह विद्यालयों के अन्दर सामग्री क्रय कर सके। आवश्यकतानुसार अपनी खरीद कर सकें।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ आप लोगों को मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपको उर्दू विषय और इस समुदाय से इतनी घृणा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कामां से आने वाली विधायक महोदय ने उर्दू के अन्दर बड़ी शायरी कही थी। लोगों ने बड़ी मेजें थपथपायी थीं, लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ कि बारां जिले के शाहबाद विद्यालय के अन्दर महात्मा गांधी विद्यालय के एक प्रधानाचार्य ने निमंत्रण पत्र छपवाया। जिसमें उसने लिख दिया जश्न-ए-अलविदा। विदाई समारोह होता है तो यह कहा कि यह तो उर्दू का शब्द है, इसको आपने कैसे लिखा और उसकी जांच कमेटी बिठा दी। यह उसका आर्डर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या हो सकती है?

श्री सभापतिः विराजें, माननीय सदस्य।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहनी है। आपने, जहां उर्दू संचालित हैं, राजस्थान के अन्दर उर्दू उन विद्यालयों में संचालित है जहां अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते थे। उस उर्दू को बन्द करके आप संस्कृत संचालित करना चाहते हैं। यह उन बच्चों के साथ घोर अन्याय है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जहां उर्दू है उस विषय को बन्द नहीं किया जाये। संस्कृत चलाना हमारी मातृभाषा है तो उसको आगे बढ़ायें, लेकिन उर्दू के स्थान पर उसको नहीं किया जाये, यह भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ कई बार विद्यालयों के अन्दर जाते हैं और यह

चर्चाएं चलती हैं कि स्कूलों के अन्दर यह स्थिति है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनका शिक्षा पर तो स्टेटमेंट कम आता है। शायद महीने में एक-दो ही आयेगा और गैर-शैक्षिक गतिविधियां उनके ऊपर बार-बार स्टेटमेंट आते रहते हैं तो जो घर और परिवार अपने मूल विभाग को नहीं संभालता है, और अन्य बातों पर अनावश्यक बहस और चर्चा करता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। कई स्कूलों के अन्दर गये थे तो माननीय मंत्री महोदय महिलाओं की ड्रेस की तरफ देख रहे थे। माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ आप देखते तो राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गुरवीर सिंह।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम युवा राष्ट्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि हमारी शिक्षा, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है और इस युवा राष्ट्र में, जहां आज हमारे देश की कुल आबादी का 25 प्रतिशत युवा ऐसा है जिसकी उम्र 15 साल से कम है। 50 प्रतिशत युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है और हमारा 35 साल से कम का युवा की आज इस देश में 65 प्रतिशत आबादी है, जो दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र आज हमारा भारत है और इस भारत की शिक्षा नीति कैसी हो, हमारा युवा किस दिशा में आगे बढ़े, किन योजनाओं के साथ सरकार उन युवाओं को तराशे, कैसे उनको कैसी तालीम मिले, यह चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार हो या देश के किसी भी कोने की सरकार हो, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे युवाओं को नई दिशा होने की होनी चाहिये। मुझे खुशी है प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के 2014 के कार्यकाल शुरू होते ही जो सबसे पहला विषय उनके द्वारा लिया गया वह स्किल्ड डवलपमेंट के नाम पर सबसे पहले विभाग बनाया और उससे शुरूआत करते हुए उसके बाद जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी वह आज देश को नई दिशा देने का काम कर रही है। उसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा गया, बल्कि उसको पूरे देश में जो-जो हमारी नीतियां और जो-जो उद्देश्य थे, वे पूरे देश में एक साथ लागू किये गये हैं। आज देश के युवाओं को नई दिशा मिलेगी। इसके लिये सभी को शिक्षा, सम्पूर्ण विकास और इंटरनेशनल लेवल पर जो चल रहा है, उसको अडॉप्ट करते हुए हमारे देश का युवा कैसे एडवांस टैक्नोलॉजी के साथ, एडवांस सिस्टम के साथ, एडवांस क्लासेज के साथ कैसे आगे बढ़ सके, यह पूरे देशभर में लागू हुआ है और उन योजनाओं के नाम पर, आज मैं अगर उनका जिक्र करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समग्र शिक्षा अभियान हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना हो और पी.एम.ई.विद्या योजना व दीक्षा पोर्टल हो। अगर पी.एम.ई.विद्या की बात करूं, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफार्म, वन क्लास वन चैनल रेडियो

पॉडकास्ट, इन सब चीजों की अगर राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। पर डेन्सिटी के मामले में हम बहुत से क्षेत्र चाहे बाड़मेर जिला हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, हमारी डेनसिटी बहुत कम है। जहां पर शिक्षा के टीचर नहीं पहुंच पा रहे हों और जहां कहीं स्कूल में कोई कमी भी हो सकती है, वहां इन माध्यमों से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन की स्थापना हो और पी.एम.श्री योजना हो, पी.एम.श्री योजना में जहां राजस्थान के 402 विद्यालयों को शामिल करके हमें लाभान्वित किया गया है। पी.एम.उषा योजना, यह सभी योजनाएं ऐसी हैं जो देश के हर स्टेट के लिये, हर जिले के लिये, इसमें कोई राजनीतिक चश्मा नहीं है, पूरे देश का युवा इससे लाभान्वित होगा। मैं जून, 2024 के जो आंकड़े पूरे भारत के सदन के सामने रखना चाहूंगा। जहां हमारे देश में 2015 में 760 यूनिवर्सिटीज थीं, आज हमारा देश का वह आंकड़ा टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी का 1200 हो गया, जो हमारे लिये एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात है। मई, 2024 में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो कहीं 2005 में, आज से 20 साल पहले जो उच्च शिक्षा के लिये मात्र 6 प्रतिशत युवा स्कूली शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिये जाते थे, आज हमारा वह रेशो 28.4 है, जो काफी संतोषजनक है। पर हमें इस पर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्लोबल एवरेज हमारी जी.ई.आर. की है, वह 36.7 है और हमारे प्रधान मंत्रीजी ने 2035 के लिये जो लक्ष्य लिया है, वह 50 प्रतिशत युवा को स्कूली शिक्षा के बाद वह हायर एजुकेशन के लिये जाये। वह हमारे आगे आने वाले 10 सालों के लिये 50 है। इसके लिये हमें और मेहनत करनी होगी और कड़े कदम उठाने होंगे। सभी साथी, जो यहां बैठे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोई शहर, कस्बा, जिला हो, वहां हम कैसे हायर एजुकेशन, कैसे स्कूल एजुकेशन में और योगदान दे सकते हैं, ये अपने सुझाव इस सदन में रखने चाहिए। मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि यह डबल इंजन की सरकार उस पर काम करेगी।

इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2024-25 के आंकड़े लेंगे तो पिछले एक साल में मात्र में 13.8 प्रतिशत की प्रोग्रेस है, जहां पिछले साल हम 23.7 प्रतिशत पर थे, आज हम 28.4 प्रतिशत के रेशो पर खड़े हैं, जो काफी अच्छा आंकड़ा है। पर मैं इसमें हमारा और लक्ष्य बड़ा हो और तेजी से आगे बढ़े। मैं सरकार से मांग करता हूं। वर्तमान जी.डी.पी. जो हमारी इकोनोमिक सर्वे में, एजुकेशन के लिये मात्र 2.9 और कभी 3.2 का फिगर टच करती थी, आज हमारी नेशनल जी.डी.पी. में हमारा जो लक्ष्य प्रधान मंत्रीजी ने लिया है, वह 6 प्रतिशत का है। एजुकेशन को कितना महत्व इस डबल इंजन की सरकार में दिया जा रहा है, यह आप सब भली-भांति जानते हैं।

हायर एजुकेशन की ग्रोथ इंडिया की अगर पैरामीटर्स चैक करें तो मुझे सदन को बताते हुए मुझे यह खुशी है जहां आई आई टी कॉलेजेज की बात करें तो 2014-15 में जहां हमारे पास 16 आई आई टीज. थे, आज हमारे पास 23 हैं। आई आई एम का हमारे पास 13 थे

2014 में, आज हमारे पास 20 आई आई एम कॉलेज हैं। इसी के साथ मेंडिकल कॉलेजेज में एक बड़ी क्रांति आयी है और इसके लिये जब हमने कोरोना को फेस किया। पूरी दुनिया ने इस महामारी को देखा और जब उसके भयानक दृश्य हमने यूरोपियन कंट्रीज के और बड़े डवलप कंट्रीज के फेसबुक पर देखें और सोशल मीडिया और टी.वी. पर देखे तो शायद देश को लगा कि हमारा देश कहीं पिछड़ रहा है। पर मुझे खुशी है कि यह दो-तीन सालों में जो क्रांति आयी है, कोई राजनीतिक सोच ना रखते हुए, बिना किसी भेदभाव के राजस्थान को भी उसका बड़ा लाभ मिला। चाहे वह तमिलनाडु हो, राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो एक साथ प्रधान मंत्रीजी ने दस-दस मेडिकल कॉलेजेज की परमिशन दी। आज राजस्थान के हर जिले में गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों जिलों में एक-एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं।

jyg/rtm/04.03.25/14.30/2f

जहां देश में 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे आज हमारे देश में 780 मेडिकल कॉलेज है, यह एक रिमार्केबल प्रोग्रेस है, देश इसको नोटिस कर रहा है। मुझे लगता है कि आज हमारे युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज यूक्रेन और दूसरे देशों में हमारे बच्चे एमबीबीएस करने बाहर जाते थे, आज उनके लिए प्लेटफॉर्म इंडिया में खोल दिये गये हैं। राजस्थान की सरकार और केन्द्र की सरकार ने इन युवाओं के लिए दरवाजे खोल दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं, वो बहुत अलार्मिंग है, कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, आज भी हमारे 9 लाख युवा विदेश में जा रहे हैं। एक जुनून है, आज भी वो एक दूसरे की देखादेखी भाग रहे हैं और जो उनका टोटल वहां खर्चा हो रहा है, पिछले एक साल का 60 बिलियन डॉलर है जो हमारा टोटल खर्चा, पूरे केन्द्र से पूरे इण्डिया के जीडीपी का शेयर है एजुकेशन पर वो मात्र 44,090 करोड़ है। 44 हजार करोड़ का हमारा जीडीपी है एजुकेशन का और 60 बिलियन डॉलर जबकि 5 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का हमारा पैसा हमारे ही बच्चे बाहर विदेशों में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमें बहुत कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं सदन से मांग करता हूं कि इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठायें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देते हुए हमें काम करने की जरूरत है। आज अगर ऑल इण्डिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन को देखा जाये, 58 हजार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ वर्ल्ड में हम दूसरे नम्बर पर खड़े हैं, दुनिया में दूसरे नम्बर पर खड़े हैं पर हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। आज अगर वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो यूएसए से पहले नम्बर पर है और भारत दूसरे नम्बर पर है, यह हमारे लिए खुशी की बात है, पर इसमें एक चुनौती हमारे सामने है कि जो स्किल फिट पैरामीटर्स हैं वहां हम तीसवें नम्बर पर खड़े हैं, ये जो बीच का का गैप है। हमारे अन्दर पोटेंशियल है, हमारे पास युवा आबादी है, पर ये गैप भरने के लिए जहां आज रोबोटिक्स साइंस की बात हो रही है, जहां आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आज हमारा सिलेबस, आज हमारा करिकुलम शायद हम गवर्नमेंट क्षेत्र में नहीं दे

पा रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे स्कूलों के होंगे जो इन पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं और उस सिलेबस को कम्पीट कर पायेंगे। मैं राजस्थान की सरकार से भी मांग करूंगा कि यूनिफोर्म सिलेबस हमारे पूरे देश में लागू हो ताकि हमारे बच्चे भी इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर, आज हम दुनिया को प्रोवाइड करें, इण्डिया एजुकेशन का हब बने और देश-दुनिया के लोग यहां पढ़ने आयें न कि हमारा बच्चा बाहर जाये, इसके लिए जो भी हमें कार्यवाही करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बजट इसके लिए निकालें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का चाहे वो पिछली सरकार हो या अबकी सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधीजी के नाम पर योजना शुरू की, आज उसमें 200 स्टूडेंट्स को विदेश भेजने के लिए बजट अलॉट किया गया। स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए इसका टार्गेट बढ़ाकर 500 स्टूडेंट्स कर दिया गया है। जो बच्चे विदेश जायेंगे, उनके पैरामीटर्स कमेटी द्वारा तय कर दिये गये और उनमें कैटेगिरी शामिल कर दी गयी कि ई-1, ई-2, ई-3 पर मैं यह सोचता हूं कि जितना पैसा चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार है, एक-एक सरकार ने जैसे अभी 300 करोड़ का टार्गेट पर इयर ले लिया है, अगर कांग्रेस का तीन साल का कार्यकाल और भाजपा के पांच साल का कार्यकाल, कुल आठ जोड़ा जाये तो तीन-तीन सौ करोड़ रुपये हम विदेश भेजने के लिए तैयार हैं और मांग भी अभी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में प्रतिपक्ष के नेता ने भी सवाल उठाया कि कितने बच्चों का आपने उसमें सलेक्शन कर लिया और कितने पेंडिंग है, मेरी इस सदन से मांग है, सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि आप इन पांच-पांच सालों में 1500-1500 करोड़ रुपया बाहर भेजने के लिए देना चाहते हैं 1500 करोड़ रुपये अगर आप राजस्थान में लगायें तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी राजस्थान में बन सकती है, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। हम किसी के बाहर जाने के खिलाफत में नहीं है पर हमारा बच्चा जो टेलेंटेड है, जो हमारे ही यहां से निकलकर बाहर जाये, आप उनको पढ़ाकर वापस राजस्थान आये, भारत आये, हमारे पैसे से हमारे देश की सेवा करे तो मानना, यहां पढ़ा लिखाकर आप विदेशों में भेज दो और उसमें हमारा टेलेंट बाहर जा रहा है और हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का पढ़ा, अगर हमारी साक्षरता दर की रिपोर्ट को चैक करें, भारत का एवरेज लिटरेसी रेट से हमारा राजस्थान पिछड़ रहा है। हमारे राजस्थान में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 20 साल तक अभी बीजेपी ने भी राज किया है लेकिन साक्षरता दर के 2001, 2011, 2024 के अगर आप आंकड़े उठायेंगे तो नेशनल एवरेज में कहीं न कहीं हमारे मेल या पुरुष हैं उनमें साक्षरता दर मैच करता है पर महिलाओं में हम काफी पीछे हैं। 52 परसेंट हमारी महिलाओं को हम साक्षर कर पाये हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। मैं मांग करूंगा सदन से कि इसके लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जहां वसुन्धराजी के कार्यकाल में इस रेशो को बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, उस टाइम 2016 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की, जिन बच्चियों को

कॉलेज आने जाने में 10 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज थी उनको पर डे के लिए 20 रुपये दिये गये इससे काफी बच्चियों को इसमें लाभ मिला पर आज हमें इसमें और काम करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री राजश्री योजना, जहां बच्चियों के जन्म से लेकर हायर एजुकेशन तक वसुन्धराजी के कार्यकाल में 50 हजार तक की योजना को जोड़ा गया, पिछली सरकार ने इसका सिर्फ नाम बदला और आज की सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में इस राशि को 8 साल बाद बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रुपये कर दिया, इससे निश्चित तौर पर हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को शिक्षा लेने में लाभ होगा। अगर मैं इसके अलावा पीएम ऊषा योजना की बात करूं, इसमें भी हमारे 320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो बजट घोषणाएं 2024-25 की 4 लाख भर्तियों की जहां घोषणा है, बहुत स्पीड से सरकार इसमें काम कर रही है, तकरीबन 60 हजार नौकरियां दे दी गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, 1 आईआईटी कॉलेज, 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 12 राजकीय महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय और 3 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पिछले बजट में प्रावधान किया गया और बजट वर्ष 2025-26 में रोजगार नीति हमने अपनायी है। विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल शर्मा जी ने किया है। 1500 नये स्टार्ट अप्स को फण्ड उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट हों, 8 मिनी आईटीआई कॉलेज हों, 3 पोलिटेक्निक कॉलेज हों, 11 राजकीय महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय और सबसे बड़ा सैनिक स्कूल का किया है जिसमें मेरा सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र जो भारत-पाक सीमा पर है वहां पर एक स्कूल देकर 5 महिला सैनिक स्कूल देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब्स हों, सादुलशहर में मेरे दादा गुरुजंट सिंह जी ने वसुन्धरा जी से 2008 में पहला तहसील लेवल का महाविद्यालय वहां लिया, उसको आज पहली बार 17 साल बाद पहली बार किसी सरकार ने पैसा दिया है, रंग-रोगन तक वहां नहीं कराया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, अगर आप दो मिनट का समय मुझे तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आज वक्ताओं की संख्या ज्यादा है, समय कम है। बस आप विराजिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, डेढ़ मिनट दे दीजिये।

श्री सभापतिः श्री मनीष यादव।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, 2023 के गवर्नर एड्रेस की बात करें तो मेरी एक ही मांग है कि जो कुछ भी मिले, ...(व्यवधान)... हमारे जिले की मांग रखने दो। श्रीगंगानगर में पूरे राजस्थान में जहां यूनिवर्सिटीज हम खोल रहे हैं, कॉलेजेज खोल

रहे हैं, हमारा इलाका राजधानी से 470 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 425 किलोमीटर दूर है, मेरी मांग है कि आप एक यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर को जरूर दें। हमारे कॉआपरेटिव स्कीम्स में जब पिछली बार सरकार ने घोषणा कर दी, सारे पद खाली हैं, इसके अलावा कृषि महाविद्यालय में पद खाली हैं। मेरी सदन से एक मांग है कि सभी पंचायत हैडक्वाटर पर लाइब्रेरी कम्पलसरी कर दीजिये, इसके साथ कम्प्यूटर लैब कम्पलसरी कर दीजिये, ताकि वो बच्चे जो पढ़ना-लिखना चाहते हैं, नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनको पंचायत लेवल पर लाइब्रेरी होगी तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके सामने सदन के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु जो राज्य की उच्च शिक्षा से, हमारे छात्र कल्याण से, विश्वविद्यालय, से, सामान्य शिक्षा से जुड़े हैं, उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन जो हमारी 2025 नीति है, उसमें कहा गया है, उसमें प्रावधान शामिल गया है कि उच्च शिक्षा का जो पूरा ढांचा है उसमें कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर हम उद्योगपति और नौकरशाहों को नियुक्ति देने का प्रावधान रख रहे हैं।

MLS/RTM/04.03.2025/14:40/2g

यह प्रावधान हमारे शिक्षाविदों और शिक्षकों की भूमिका को नकारने जैसा है। इसमें मैं यह मानता हूं कि विश्वविद्यालय में एक लाभ कमाने का उद्देश्य है, अगर हम एक ब्यूरोक्रैट को, उद्योगपति को बैठा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे शिक्षाविदों की जो गुणवत्ता है, विश्व में हमारे भारतीय शिक्षकों का जो भाव है, जो उनका नाम है, इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया है, उनको नकारने जैसा है।

चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय भी है, इसलिए निश्चित रूप से जिस तरह से एबीआरएस जैसे संगठन ने इसका विरोध किया है, इस नीति को लेकर हम सबको कठोरता से इस बात को रखना चाहिये कि यह लागू नहीं हो। इसमें गरु-शिष्य परम्परा भी दूर हो जायेगी, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रैट या उद्योगपति आयेगा तो उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए वह सक्षम नहीं है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी प्रतिभावान बालिकाएं हैं, उनको जो स्कूटी वितरण की योजना है, वह एक अव्यवस्था के रूप में बदली हुई है।

दैनिक समाचार की एक खबर भी है कि 385 करोड़ का कबाड़ा, जो स्कूटियों को लेकर हो गया, 185 करोड़ की 29 हजार स्कूटियां कबाड़ हो रही हैं और 200 करोड़ का कबाड़ा करने की तैयारी है, यह प्रदेश की इस व्यवस्था को दिखाता है कि किस तरह से जो अच्छी शिक्षा के लिए आवागमन के लिए हमारी बेटियों, बहनों को जो सुविधा सरकार प्रदान करना चाहती है, और वे स्कूटियां उन्हें तब मिल रही हैं, जब उनका सैशन पूरा हो रहा है।

मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि उनको वे समय पर मिलें और उसमें जो विसंगति है, क्योंकि यह विसंगति बहुत बड़ी विसंगति है, उनको जो स्कूटियां, मैंने स्कूटी वितरण की समय-सीमा को लेकर एक प्रश्न पूछा था, उसमें उत्तर में कहा गया कि यथा सम्भव परिणाम घोषित होने के 3 माह के भीतर स्कूटी वितरण की कार्यवाही पूरी की जायेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि छात्राओं को समय पर स्कूटियां नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उनका मूल उद्देश्य है, जो वास्तव में उनके आवागमन के लिए महाविद्यालय में स्कूटी उपलब्ध करायी जाती है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है। इसे सही समय पर किया जाये।

न्याय का तकाजा यह है कि देरी से मिला न्याय भी अन्याय के समान है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। जो योजना में बड़ी विसंगति ओबीसी की छात्राओं के लिए हो रही है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। सामान्य वर्ग को 4162 स्कूटियां वितरित की जाती हैं, अनुसूचित जाति की जो छात्राएं हैं, उन्हें 2461 स्कूटियां वितरित की जाती हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को 1477 स्कूटियां वितरित की जाती हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को 1848, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 14778 और घुमन्तू जाति की छात्राओं को 1577 स्कूटियां वितरित की जाती हैं।

इसमें ओबीसी जैसे बड़े समुदाय की कोई पृथक् से व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह ओबीसी वर्ग की छात्राओं के साथ पूर्ण रूप से अन्याय है। उनके लिए भी सरकार यह योजना लेकर आये और उन्हें अलग से, जो शिक्षा में हम समान अधिकार की बात करते हैं, उनको भी इस बात की प्राथमिकता दी जाये कि उनको अलग से स्कूटी मिले। दूसरी तरफ, जो पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे जो शोधार्थी हैं, जो नैट और सैट से उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनको 20 हजार मासिक शोध छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की थी और एक बजट भी अलॉट किया था, लेकिन हकीकत में इस योजना का अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना को शुरू करें और शोधार्थियों को उसका लाभ दें।

दूसरा, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों का, क्योंकि आज बच्चे हैं, लेकिन क्लास नहीं लगती और कक्षाएं नहीं लगने के अभाव में हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही। इसका उदाहरण हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी 50 शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति ड्यू है। 30 ऐसे शिक्षक हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति के योग्य हैं, लेकिन वह भी अभी ड्यू है। 230 शिक्षकों का सलेक्शन ड्यू है। इसके अलावा 98 सीनियर शिक्षकों का सलेक्शन ड्यू है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इनकी पदोन्नति सही समय पर करें।

एक बड़ा उदाहरण नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में देखने को मिला, जहां पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में, जिसमें 23 में से 19 पदों में, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के पद हैं, उसमें आपने एनएफएस कर दिया, ''नॉट

फाउंड सूटेबल'' कर दिया। क्या ये जो नैट, सैट, पीएचडी योग्यताधारी हैं, अगर ये साक्षात्कार में भी अयोग्य हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आरक्षण से छेड़-छाड की जा रही है। इस पर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ बरदाश्त नहीं है। उनको ''नॉट फाउंड सूटेबल'' करके सरकार ने या विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, वह निन्दाजनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्या सम्बल योजना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जो शिक्षक है, वे एक नब्बे कालांश, जो वर्ष भर में हमारा शैक्षणिक सत्र है, उसके लिए होती है, लेकिन वर्तमान में जो सैमेस्टर शिक्षा प्रणाली है, उसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहे और फरवरी के बाद में छात्रों की पूरी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसमें भी आप सब लोग इस बात को प्राथमिकता से लें कि उनको पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए नियुक्त किया जाये।

दूसरा, जो मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि हमने विद्या सम्बल के तहत 2700 शिक्षक नियुक्त किये हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किये गये। सच्चाई यह है, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 2700 ऐसे शिक्षक हैं, जबकि एक-दो जिलों के अलावा पूरे राजस्थान में लगभग 350 महाविद्यालय हैं, जिनमें विद्या सम्बल योजना में एक भी शिक्षक अभी नियुक्त नहीं है। मुझे लग रहा है, अधिकारियों ने मुख्य मंत्री जी को कोई पर्ची पकड़ा दी और उन्होंने पढ़ दी। यह गलत है। गलत तथ्य उन्होंने पेश किये। अभी ऐसा एक भी शिक्षक यहां पर ऐसा नहीं है। इसकी भी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आज जो हमारे छात्र हैं, जो कोचिंग के नाम पर, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जो विद्यार्थी तनाव में रहते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई नियामक आयोग नहीं है कि किस प्रकार से कोचिंग करायी जाये, कितने घण्टे वे पढ़ सकते हैं और मनमानी मोटी फीस उनसे वसूली जा रही है। इस ओर भी हमको एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है। उनको कैसे एक अच्छा वातावरण मिले, ऐसा एन्वायरनमेंट जहां बेहतर पानी और हवा हो। आज के अख़बार का जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर एकाग्रता से मन लग सके, वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, एन्वायरनमेंट अच्छा हो, उस बात पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बेहद जरूरी है।

कैसे उनका तनाव कम हो, क्योंकि 28 अगस्त, 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसने दिशा-निर्देश जारी किये कि मानसिक स्थिति को असैस करने का, उपचार किया जा सके, परन्तु 15 महीनों का कालखण्ड हो गया, अभी वह जो सलाहकार समिति थी, उसमें जो भी मनो-सलाहकार या काउंसलर नियुक्त करने की बात थी, अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

आत्महत्याओं के प्रकरण बढ़ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अभी आत्महत्या की, कोटा की कोचिंग में किस तरह से आत्महत्या की घटनाएं हैं, जोधपुर में

घटनाएं हैं, इस पर कोचिंग में किसी पर ओवरलोड नहीं डाला जाये और कोचिंग पर कोई नियामक कानून बने कि किस कीमत में फीस वसूली जा सके। वह भी हमें छात्र-छात्राओं के साथ निश्चित रूप से अन्याय को समझना है कि किस प्रकार के नियम लागू किये जाएं।

पिछली सरकार की जो पूर्ववर्ती बजट घोषणा थी, उसमें बिन्दु संख्या 27(1) में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार और ओरिएंटेशन के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डवलपमेंट अकैडमी स्थापित करने की घोषणा थी, लेकिन 19 सितम्बर को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी, अभी तक उस परियोजना पर कोई प्रगति नहीं है, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

राजस्थान में स्कूली शिक्षा में, मैंने शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रश्न लगाया था, बड़ी चिन्ताजनक बात है कि आपने वरिष्ठ अध्यापक और स्कूली व्याख्याताओं के केवल 4310 पदो पर भर्ती निकाली है, जो कुल रिक्त पदों का 5 प्रतिशत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बाड़मेर का भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आज के अख़बार में बाड़मेर में जिस प्रकार से छात्रों ने पदों को बढ़ाने का आन्दोलन किया है, पूरे प्रदेश का नौजवान चाहता है कि उसके साथ अन्याय न हो, उसके साथ अत्याचार न हो। वरिष्ठ अध्यापक और हमारे स्कूल व्याख्याता के जो पद हैं, वे बढ़ाये जाएं, नहीं तो युवाओं को निश्चित रूप से सड़कों पर आना पड़ेगा।

मैं छात्रसंघ चुनावों की भी बात करना चाहूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, मुझे तो इस सदन में बोलने का जो अवसर मिल रहा है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर आया हूं और तमाम ऐसे नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर आये हैं। आज छात्रसंघ के चुनाव शुरू कराइये, छात्र अधिकारों की जो बात है, उसके लिए लड़ने, छात्रों को आन्दोलन करने की अगर कोई सही जगह है तो वह छात्र राजनीति है। अगर छात्रसंघ के चुनाव होंगे, छात्रसंघ के पदाधिकारी रहेंगे तो छात्रों के साथ न्याय सम्भव होगा, उनकी मांगों पर बात होगी, अन्यथा जिस प्रकार से छात्रसंघ चुनावों को बन्द करके उनको दबाने की साजिश है, वह बिलकुल गलत है।

MKD/RTM/04.03.2025/14:50/2h

प्रदेश में पुनः छात्रसंघ के चुनाव शुरू कराये जाएं, यह हमारी सबकी मांग है। मैं स्कूली शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं। 6 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और स्थिति यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के 250 से अधिक पद अभी तक रिक्त हैं, जो परीक्षा होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसकी चिन्ता भी हमको करनी है।

जो पदोन्नति प्राप्त 267 अधिकारी एक साल से अभी तक एपीओ चल रहे हैं, जबकि 30 दिन से ज्यादा हम एपीओ नहीं रख सकते तो ऐसे एपीओ रखकर हम क्या करना चाह रहे हैं? डीपीसी में चयनित 4 हजार 242 प्रधानाचार्यों और 15000 से अधिक व्याख्याता, अभी

जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, उनमें चयनित शिक्षक लम्बे समय से पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, क्या हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को उनकी समीक्षा के नाम पर बन्द करना चाहते हैं, यह अन्याय होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि गरीब विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़े। यह सरकार समीक्षा के नाम पर उन विद्यालयों को बन्द करना चाहती है, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय शुरू किये गये हैं, निश्चित रूप से वे शुरू रहने चाहिए, उनके पदों को भरना चाहिए, यह भी मैं मांग करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात राजस्थान के स्कूलों में जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको जो निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलने वाली थी, वह इस शैक्षणिक सत्र में वितरित नहीं की गई, यह चिन्ताजनक है, बड़ा शर्मनाक है। बेहद चिन्ताजनक स्थिति है कि सर्दी जैसे मौसम में उनको यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही है। सरकार यूनिफॉर्म नहीं मिलने का कोई कारण स्पष्ट करे कि क्यों नहीं मिल पा रही है। बच्चों के साथ अन्याय है, समयबद्ध ढंग से उनको लागू किया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ जिस प्रकार का अन्याय सरकार करना चाह रही है, स्कूलों को बन्द करके, उनको यूनिफॉर्म नहीं देकर, मैं चाहता हूं कि आप उनको यूनिफॉर्म दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की और आसपास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह भी आपके समक्ष कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के खेजरोली और मनोहरपुर में सह शिक्षा के नये महाविद्यालय खोले जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत-बड़ी आबादी रहती है। वहां पर अभी कोई सह शिक्षा का महाविद्यालय नहीं है। राड़ावास में हमारा राजकीय महाविद्यालय है, उसमें विज्ञान का संकाय खोला जाए। यहां पर विद्यार्थियों की बहुत बड़ी मांग है।

हमारे उप खण्ड पर दो एडीजे कोर्ट संचालित हैं और पूरे जिले में एक भी राजकीय विधि महाविद्यालय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शाहपुरा में विधि महाविद्यालय की सौगात दी जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के छात्रों को और हमारी जनता को लाभ मिल सके।

विशेष रूप से, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के महान ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री नारायणदास जी महाराज ने 1977 में चिमनपुरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करवाई। इस महाविद्यालय की स्थापना में आसपास के लोगों का सहयोग भी था। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान, कॉमर्स के संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी खोला जाए।

एक समय था, जब प्रदेश से विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए यहां पर आते थे और आज उसकी स्थिति बड़ी दूभर है, उसको भी ठीक किया जाए। कृषि संकाय, एक समय में पूरे देश भर से विद्यार्थी वहां आते थे। वहां उस समय छात्रावास की व्यवस्था भी थी। दुर्भाग्य से 25 वर्षों से सरकार का ध्यान इस महाविद्यालय के कृषि संकाय पर नहीं है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कृषि संकाय में जो आवंटित सौ बीघा जमीन है, उसमें अलग से कृषि संकाय का एक विद्यालय खोला जाए और नारायणदास की स्मृति में कृषि

महाविद्यालय की स्थापना की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय, एक मिनट।

इसे जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। दूसरी तरफ चिमनपुरा में कृषि संकाय के फार्म हाउस में कृषि अनुसंधान और कृषि विज्ञान केन्द्र जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएं, ताकि आसपास के लोगों को लाभ मिल सके।

महोदय, मैं सन्त नारायणदास जी का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की और अगर उनके द्वारा चिमनपुरा में स्थापित इन संस्थाओं को नहीं सम्भाला जायेगा तो यह बिलकुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय, एक मिनट।

मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सुनारोंवाली, खेजरोली, कुमावतों की ढाणी, राड़ावास, ढाणी रेडान पीपलोन, ढाणी खुडालिया की खोरी, भृतहरि मोड़ को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने और महोदय मेरे क्षेत्र में..।

श्री सभापति: विराजें, प्लीज। अंकित नहीं होगा, विराजें।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): 0000

श्री सभापति: आज बोलने वाले सदस्य बहुत हैं। माननीय सदस्य, आज वक्ताओं की संख्या बहुत हैं, आप मंत्री महोदय को दे देना। श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 20 प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21 माध्यमिक शिक्षा और मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की बात आती है तो पूरे सदन में शिक्षा को लेकर चिन्ता जाहिर करना वाजिब भी है। जो भी सरकार आती है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करती है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना था, उस समय किस मुख्य मंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों में शिक्षा का प्रचार कैसे हो, पंचायत तक शिक्षा कैसे पहुंचे, इसको लेकर किसी मुख्य मंत्री ने चिन्ता की तो मैं पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व उप राष्ट्रपति आदरणीय भैंरोसिंह जी शेखावात साहब को याद करना चाहूंगा। जिन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, जिस समय विद्यालय नहीं हुआ करते थे, गांवों में किसी एक घर में बच्चे पढ़ते थे, एक गुरुजी हुआ करते थे, उस समय बड़ी मुश्किल से बड़े-बड़े कस्बों में, छोटे-छोटे घरों में कोई पढ़ाई की व्यवस्था थी, उस समय भैंरोसिंह जी शेखावात साहब ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय का एजेंडा रखा।

उसके बाद में, जब 2003 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, वसुन्धरा राजे की

सरकार बनी तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं के विद्यालय होंगे। इन माध्यमिक विद्यालयों का एक बहुत-बड़ा प्रभाव पडा और प्रत्येक, हम लोग जब पढ़ते थे आसपास के गांवों में पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं हुआ करती थीं तो विद्यालय छोड़ना पड़ता था और कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए चले जाते थे, लेकिन 2003 में जब इस तरह की घोषणा हुई, दसवीं तक के विद्यालय की घोषणा हुई तो बच्चे और विशेषकर बालिका शिक्षा की बात करते हैं, जैसा अभी गुरवीर सिंह जी ने भी कहा था कि बालिका शिक्षा का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। 10वीं तक विद्यालय बनने से गांव में बालिका भी पढ़ने लगी। वहां पर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक स्कूल नहीं हुआ करती थी, वहां माध्यमिक शिक्षा हुई।

उसके बाद फिर इनको चांस मिला, 2008 से 2013 तक, इन्होंने कुछ काम करा नहीं, किसी विद्यालय को क्रमोन्नत किया होगा तो 20 विद्यालय की घोषणा की होगी, 50 विद्यालय की घोषणा की होगी। वापस 2013 से 2018 में भाजपा की सरकार बनी। एक ही आदेश में निकाला कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक विद्यालय होगा। जिसका इतना बड़ा फायदा हुआ कि जो बालिका है, आज की स्थिति हम देखते हैं, आज जब हम स्कूलों में जाते हैं, हम वार्षिकोत्सव में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि बालिकाएं कितनी पढ़ रही हैं, तो 150 बालिकाएं पढ़ती हैं और 150 ही बालक, मतलब बराबर का अनुपात आ गया। इसका कारण है, माननीय पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे जी की सरकार के कारण से यह हुआ। पिछली सरकार ने क्या किया है, पिछली सरकार ने वापस इनको जब चांस मिला, इन्होंने कुछ विद्यालय जो माध्यमिक बचे हुए थे, एक ही गांव में माध्यमिक हुआ करते थे और उच्च माध्यमिक भी थे, इन्होंने माध्यमिक की घोषणा की, लेकिन वहां पर व्याख्याता के पद सृजित नहीं करे। यह बहुत बड़ी विडम्बना है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों को पिछली सरकार ने क्रमोन्नत किया था, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में, आज भी उनविद्यालयों में व्याख्याता के पद सृजित नहीं हैं।

इसलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देते हुए, ये पद सृजित करें, जिससे उस विद्यालय में व्याख्याता लगे और वहां पर भी पढ़ना आसान हो। उन्होंने जो घोषणा की थी, उन्होंने कुछ 50, 100, 200 स्कूल उच्च माध्यमिक उस समय बनाये होंगे, उसमें भी अभी तक पद सृजित नहीं हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, जोहड़ा में, छाडन में, छिपरवाड़ा में, मालगढ़ में इस प्रकार से पांच विद्यालय थे, ऐसे चार-पांच विद्यालय जो उच्च माध्यमिक हैं, आज भी वहां पर व्याख्याता के पद नहीं है। मैं वहां जाकर पूछता हूं, तो कहते हैं, सर, यहां पर पद बोलते ही नहीं हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय तो है, लेकिन वहां पर पद सृजित नहीं हैं।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस सरकार की जो कमियां हैं, उसको ठीक करते हुए, वहां पर पद सृजित करें।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस मौके पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने डीपीसी को गम्भीरता से लेते हुए व्याख्याता को वाइस प्रिंसिपल बनाया और वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल करने का काम किया है। जो बहुत ही डीपीसी की, इस एग्जाम के बाद में मुझे विश्वास है, जो पद रिक्त पद बोल रहे हैं, सभी विद्यालयों में जहां-जहां पर पद रिक्त हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट रिक्त नहीं रहेगी।

अभी एग्जाम का समय, जो लैक्चरार हैं, वे वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, वाइस प्रिंसिपल जो हैं, वे प्रिंसिपल बनेंगे, डीपीसी करने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को।

Bhs/Rtm/04.03.25/15.00/2j

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस बार बजट में जिस प्रकार से मैंने देखा कि जो घोषणा की है अपने-आपमें बहुत, एक उदाहरण पेश करूंगा, मैं उच्च शिक्षा की बात भी करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की जरूरत थी उसको लेकर पूर्व में जो ग्रेजुएशन तक की कॉलेज थी उसको पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अबकी बार आहोर में कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस बार घोषणा हुई है वह एक ऐतिहासिक घोषणा है जिन्होंने क्लास रूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, यह अपने आप में अनूठा उदाहरण है। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लगभग चार हजार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में फर्निचर और एक बहुत बड़ा जो विषय है जो हमारे लिये बहुत गम्भीर विषय था, हम विद्यालयों में जाते थे तो हमेशा एक शिकायत-सी रहती थी, बालिकाओं के माता-पिता की शिकायत रहती थी, अबकी बार सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने की दृष्टि से राज्य के पन्द्रह हजार विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना के लिए 75 करोड़ की घोषणा की है। यह अपने आप में बहुत, जिसको पता नहीं है, जो स्कूलों में आना-जाना नहीं करते उनको पता नहीं है कि सी.सी.टी.वी. कैमरा जो बहुत आवश्यक था, कक्षा कक्ष में लगने से कई माता-पिताओं को जो डर था, कई तरह की घटनाएं होती थीं, इससे सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, वहां पर कोई अनहोनी घटना नहीं होगी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को खूब सारा धन्यवाद देना चाहूंगा। कई विद्यालय जो भवन विहीन थे जिनको क्रमोन्नत तो कर दिया था, नयी स्कूल तो खोल दी थी लेकिन वहां पर नये विद्यालय के भवन के लिए पैसों की आवश्यकता थी तो 175 नवीन भवन विहीन और जर्जर विद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, 2 हजार विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपये देने

की घोषणा की, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं इस अवसर पर कई तरह के जिस प्रकार से नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की 37, सामान्य शिक्षा 20, सहशिक्षा 13, कन्या 13 विद्यालय और 4 कृषि विद्यालयों की घोषणा की इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। महाविद्यालय में नवीन विषय स्नातक स्तर तक 10 और स्नातकोत्तर पर 33 विषयों की घोषणा की, इसके लिए भी धन्यवाद। महाविद्यालयों में नवीन संकाय विज्ञान संकाय के 9 और वाणिज्य संकाय के 4, इस प्रकार की जो घोषणा की है वह अपने आप में दिखाता है कि शिक्षा के प्रति यह सरकार कितनी गम्भीर है और हमेशा पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर राजनीतिकरण करना चाहा, आपने देखा होगा कि जो स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल चला करती थी।

श्री सभापतिः दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैंने तो शुरू ही किया है।

श्री सभापतिः अपना विषय रख दें दो मिनट में, समय इतना ही है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से पूर्व में जो विवेकानन्द मॉडल स्कूल भाजपा की सरकार ने शुरू की थी उसको द्वेषतावश इन्होंने नयी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के नाम से किया और उसी विद्यालय को जो पहले से शुरू थे, जो खाली बिल्डिंग थी, खाली आनन-फानन में प्रत्येक ब्लॉक में खोलने का काम किया लेकिन वहां पर इंग्लिश का कोई तरह का काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय की सीमा बांध दी है तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ विषय बताना चाहूंगा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढोतरा, मीठड़ी, सेलड़ी, रसियावास खुर्द, सुमेरगढ़ खेड़ा, बागून्दा, बिझली, गोविन्दला को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। उसी प्रकार से बागरा और नोसरा जो बड़े कस्बे हैं 15-15 हजार आबादी के कस्बे, वहां पर बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां पर बालिका विद्यालय था लेकिन उसको मर्ज कर दिया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बागरा और नोसरा 15-15 हजार आबादी है वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाये, बालिकाओं का बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से बूढा बालोतान, हरजी, बाजाजून, चांदलई और उम्मेदपुर में साइंस फैकल्टी जहां पर बड़ी-बड़ी आबादी के गांव हैं वहां पर साइंस फैकल्टी की बहुत अति आवश्यकता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के साइंस फैकल्टी खोलने से हमारे यहां जो आवश्यकता है, हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी कि साइंस फैकल्टी खोलें, वहां पर कम साइंस फैकल्टी के स्कूल्स हैं इसलिये इन विद्यालयों में साइंस फैकल्टी खुल जायेगी तो हमारे वहां भी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

इसी प्रकार से महाविद्यालय की मैं बात करूं तो भवरानी, चांदरई, बागरा, हरजी और बूढा बालोतान में कन्या महाविद्यालय या को-एजुकेशन के महाविद्यालय खोले जायें जिससे हमारे क्षेत्र में भी कई तरह की जो उच्च शिक्षा की कमी है।

श्री सभापतिः श्रीमती इन्द्रा।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी विषय, दो मिनट तो, ...

श्री सभापति: मंत्री महोदय को दे देना आप टेबल कर देना।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान सरकार ने कार्य किये हैं...

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापतिमहोदय, आपने मांग संख्या 20,21 और 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। महोदय, जब बात शिक्षा पर हो रही हो तो मैं अपनी बात प्रसिद्ध शिक्षाविद् जॉन डीवी के विचार से प्रारम्भ करना चाहूंगी। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है।

मैं बात करना चाहूंगी उच्च शिक्षा पर। आज जिस तरीके से पिछले 70 सालों के अन्दर दलितों को तरक्की मिली उसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है और यहां जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा और प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा के वो भी अनुसूचित जन जाति से हैं लेकिन इनके रास्ते शिक्षा से ही यहां पर पहुंचे हैं लेकिन ये लोग आज आने वाली पीढ़ी के रास्ते बन्द करना चाहते हैं।

मैं बात करना चाहूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एन.ई.पी., एन.ई.पी. 2020 इसके अन्दर कितनी जटिलताएं हैं। किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो हमें चाहिये कि नियम कायदे और प्रक्रिया को सरल किया जाये। महोदय, आप एन.ई.पी. का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा जो कथित सर्वश्रेष्ठ एन.ई.पी. लागू की गयी है वह विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर विद्यार्थी तक किसी को भी समझ में नहीं आ रही। कॉलेज के प्रोफेसर एन.ई.पी. की जानकारी विश्वविद्यालय से लेते हैं तो जवाब मिलता है कि हमें जानकारी नहीं है। विद्यार्थी अगर प्रोफेसर से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि क्या है एन.ई.पी., लेकिन वहां से जवाब मिलता है कि पता नहीं है इसीलिये इस एन.ई.पी. के मकड़जाल में राजस्थान के लाखों ग्रामीण विद्यार्थी भटकाव की स्थिति में आ गये हैं। एन.ई.पी. के तहत मल्टी डिसिप्लीनरी सब्जैक्ट चला दिये गये हैं जैसे पर्यावरण अध्ययन कम्प्यूटर, निर्वाचन, साक्षरता जैसे विषय जोड़ दिये गये हैं जिनकी आज तक किसी कॉलेज में कोई कक्षा नहीं चली और न ही उनके लिए कोई विषय विशेषज्ञ कॉलेजों के अन्दर आज तक नियुक्त हुए।

सभापति महोदय, बहुत ही चिन्ताजनक विषय है कि जिस पॉलिसी को लागू किया जाता है और उसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया धरातल पर नहीं है और प्रतिक्रिया यहां सदन के अन्दर भी नहीं है क्योंकि दोनों मंत्री गायब हैं। मेरी बात सुनेगा कौन? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यह पता चल रहा है कि ये कितने सीरियस हैं शिक्षा को लेकर क्योंकि ये शिक्षा के अन्दर इस राजस्थान को गर्त में ले जाना चाहते हैं। इस देश के अन्दर शिक्षा ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दोनों मंत्री सदन में नहीं हैं। एजुकेशन पर चर्चा है, कितने सीरियस हो आप लोग, देखो। ...(व्यवधान)... दोनों मंत्री नहीं हैं, बातें कर रहे हो।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, ऐसा कभी नहीं देखा पिछले पांच सालों के अन्दर हमने अगर कोई मंत्री जाता है तो अपना असिस्टेंट, अगर जरूरी काम के लिए भी बाहर जाता है तो कोई असिस्टेंट बैठा कर जाता है लेकिन यहां पर पता नहीं क्या हो रहा है, कौन हमारी बातें नोट कर रहा है। ...(व्यवधान)... आप शान्त रहिये, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम बना रखा है लेकिन आज देखा जा रहा है कि 20 प्रतिशत उपस्थिति है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिये है क्योंकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और अगर हम करना चाहें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायें तो बालकों का स्वतः ही इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो कॉलेजों में आना शुरू करेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इनकी सरकार में सवा साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर कोसों दूर है। यह हमारी सरकार के अन्दर कॉलेज खोले गये, बिल्डिंग्स बनायी गयी। हर ब्लॉक के अन्दर कॉलेज खोले गये, उनका फीता काटने का काम इन लोगों ने किया और उन कॉलेजों के अन्दर एक कील तक नहीं लगायी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी चार कॉलेज हैं, उनके अन्दर इन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन करने का काम किया क्योंकि ये चाहते हैं इनकी संकीर्ण मानसिकता है और ये तो चाहते हैं जैसा कि इनके बड़े नेता कहते हैं कि पकौड़े तलिये तो पकौड़े तलने का काम ये युवाओं को देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर कुल 623 सरकारी कॉलेज हैं और ये डबल करने का धन्यवाद मैं माननीय अशोक गहलोत जी को देना चाहूंगी जिन्होंने इन सरकारी कॉलेजों को डबल किया और विश्वविद्यालयों के अन्दर साथ के साथ ही बिल्डिंग खड़ी करने का काम किया।

Kas/rtm/04.03.2025/15.10/2k

मैं कहना चाहूंगी कि सरकार को चाहिये कि उनमें पुस्तकालय का निर्माण करें, फर्नीचर और पुस्तकें उपलब्ध कराएं और उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाये, ताकि बालक उसमें कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें।

मैं बात करना चाहूंगी कि इन्होंने आरक्षण पर किस प्रकार से डाका डाला। हमारी सरकार द्वारा 2000 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली गई, उनकी तुलना में इस सरकार ने मात्र 575 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली, जिसमें एससी, एसटी के आरक्षण पर खुलेआम डाका डाला गया। अंग्रेजी विषय में एक एससी को छोड़कर एससी, एसटी का कोई किसी प्रकार का आरक्षण इन लोगों ने निर्धारित नहीं किया। ये किस दिशा में शिक्षा को ले जाना चाहते हैं? बहुत सारे एससी, एसटी के विधायक सत्ता पक्ष में भी हैं और पिछले पांच सालों का मेरा रिकार्ड उठा कर देखिए, जब-जब कहीं भी पिछड़े और गरीब लोगों पर आंच आती थी तो मैं

सत्ता पक्ष में भी बात करती थी, आज इनके मुंह बंद हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इनको बोलना चाहिये। जिस आरक्षण से, जिस संविधान की वजह से ये इस सदन में आये हैं, इनको उसकी रक्षा के लिये और अपने अधिकारों के लिये बात करनी चाहिये।

दूसरी तरफ, राजस्थान में 27 विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी का कोई भी वीसी नियुक्त नहीं किया गया, यह भी बड़े सोचने की बात है।

हाल ही में कल ही संपन्न हुई रीट परीक्षा की हम बात करते हैं। दिशा-निर्देश दिये गये कि धागा या किसी भी प्रकार का कोई मंगल सूत्र, जनेऊ, कान में, नाक में अगर लोंग है, तो इस पर भी टेप चिपकाई गई। इनकी सरकार ने मंगल सूत्र के नाम पर बवाल कर दिया। एक एससी की शिक्षिका को और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि हाथ में एक धागा भी नहीं होना चाहिये। जनेऊ, मंगल सूत्र से बड़ा नहीं होता, बिछिया से बड़ा नहीं होता। हिन्दू धर्म में एक स्त्री की जो पवित्र चीजें हैं, उनको यह उतरवा सकते हैं, लेकिन जनेऊ उतरवाने पर इन्होंने बवाल कर दिया और उनको सस्पेंड कर दिया। मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से उन दोनों कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, उनका निलम्बन रद्द किया जाये और जिस कलेक्टर ने कार्यवाही की, उस पर सरकार के द्वारा कार्यवाही की जाये। पिछड़ों का साथ देना ही हमारा धर्म है और इस सदन में इस सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल चार कॉलेज हैं। मित्रपुरा, बौंली, सुकार व बामनवास। इनमें से तीन तो पिछली बार मैंने ही खुलवाये हैं। इनमें कुल 40 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में वहां मात्र 7 पद भरे हुए हैं, बाकी सारे के सारे खाली हैं। एक पद के विरुद्ध यहां 10-10 आयुक्तालय में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। गांवों के बालक पढ़ाई से वंचित हैं और यहां पर सैटिंग से प्रतिनियुक्ति पर सारे प्रोफेसरों को बैठा रखा है। इससे बालकों पर पढ़ाई का संकट पड रहा है, लेकिन सरकार को यह भी नहीं दिख रहा। माननीय सभापति महोदय, बौंली में 200 सीट हैं, लेकिन आवेदन 400 से ऊपर आते हैं। मैं मांग करना चाहूंगी कि हमारे बौंली के कॉलेज को पीजी में क्रमोन्नत किया जाये। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी क्यों बजाई, 8 मिनट ही तो हुए हैं, मेरे 15 मिनट हैं।

श्री सभापति: 10 मिनट।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): हमारी सरकार में पांच साल में 310 कॉलेज खोले गये। हर ब्लॉक में एक कॉलेज खोला गया। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से शिक्षा में इनका प्रतिशत था, हमारा प्रतिशत बढ़ा और उसी का परिणाम है कि आज सारे के सारे कॉलेज चल रहे हैं। मैं एक और बात करना चाहूंगी कि इन्होंने एक सोडानी कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं की, इसका क्या कारण है? कॉलेजों को बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये ग्रामीण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई से वंचित रखना चाहते हैं, यह इनकी

मानसिकता का परिचय है।

मानननीय सभापति महोदय, वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में मैं बात करना चाहूंगी।

श्री सभापतिः विराजिए। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरे 15 मिनट थे।

श्री सभापतिः 10-10 मिनट हैं।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैंने 15 मिनट देखे हैं इसमें।

श्री सभापतिः इसमें 10 मिनट का आया हुआ है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 की अनुदान की मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, एक सेकण्ड, आज बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी है, तो जो आपकी समय सीमा निर्धारित है उसमें ही अपनी बात को रखें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, आपको मेरे यह 21 सेकण्ड डिलीट करने पड़ेंगे और वापस से मुझे इन 21 सैकिण्ड का बेनिफिट देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बामनवास से आने वाली हमारी माननीय विधायक महोदय को मैं कहना चाहूंगी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आज यहां शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, जिस पर हमें पॉजीटिवली चर्चा करनी चाहिये थी। ....(व्यवधान).... आप जब बोल रहे थे, तो हम भी सुन रहे थे।

श्री सभापतिः कृपया कोई बीच में नहीं बोलेगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने कहा कि ध्यान से सुनो और जवाब दो, तो हम सब मिलकर सरकार की तरफ से आपको जवाब दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, चर्चा तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। माननीय विधायक बोल रहे थे कि किस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में क्या नहीं किया। हमारी सरकार ने आकर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने का एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और योजनागत तरीके से हम वापस उनको चालू करेंगे। इस निर्णय का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, क्योंकि बिना सोचे-समझे हिन्दी मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो बच्चे हमारे पास आते थे। वो बच्चे हमें यह कहते थे कि हम लोगों ने बचपन से हर पढ़ाई हिन्दी में की है, सडनली अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट हमको इंट्रोड्यूज कर दिये जायेंगे तो हम कैसे अपने पेपर्स को लिख पायेंगे? सभापति महोदय, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम से हिन्दी मीडियम में और हिन्दी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में करने में चैलेंजेज होते हैं। सडनली उसी स्कूल को इन लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट

कर दिया कि नहीं, हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ायेंगे। सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन बिना सोचे-समझे किया हुआ फैसला था, ऐसा फैसला आपकी सरकार ने लिया है। वहीं हमारी सरकार ने जब से वह आई है, निरंतर यह प्रयास किया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरकी से बेहतर हो सके, जिसमें इस बार करीबन 50 प्राथमिक विद्यालयों को 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

माननीय विधायक महोदय, आप हमारी बातें नहीं सुनेंगी तो हम आपकी बातों को कैसे सुनेंगे? इतना तर्क आपने दिया कि हमारे यहां पर लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे और आप हमारी बातों को महत्व नहीं दे रहे, आप भी विराजिए और बात को सुनें। ....(व्यवधान).... आप चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूं।

हमारी सरकार ने इस बार के बजट में कौशल केन्द्रों की घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूं, लेकिन इसके साथ एक बात कहना चाहूंगी। हम जब विद्यालयों में जाते हैं और जब बच्चे 12वीं करके, महाविद्यालय से बी.कॉम. करके निकलते हैं तो बी.कॉम. करने के बाद किस फील्ड में उसको जाना चाहिये, यह कितनी बार अनक्लियर होता है, कितनी बार नहीं पता पड़ता कि उनको किस दिशा में जाना चाहिये। अगर हम लोग इसमें स्कूल शिक्षा से, भले ही 9वीं से या 11वीं से और कॉलेजेज में भी साथ में स्किल डवलपमेंट का भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूज करें, तो उससे कहीं न कहीं बच्चों को यह बेनिफिट होगा कि वो यह तय कर सकते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है। कौशल विकास की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि विकसित भारत में स्वावलंबी होने के लिये, अपने पैरा पर खड़े होने के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम कहीं न कहीं अपनी स्किल को भी उतना ही डवलप करें, जितना हम लोग अपनी पढ़ाई को महत्व देते हैं। एक बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे कही थी कि पढ़ाई के साथ-साथ अपने पैशन को फोलो करना बहुत जरूरी है। यह स्किल डवलपमेंट कहीं न कहीं उस पैशन को निखार सकता है। अगर किसी बच्ची का आर्ट में बहुत अच्छा हाथ है, वह बहुत अच्छे से स्कैचिंग करना चाहती है, तो उस स्किल को डवलप करने के लिये अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूज किया जाये तो उसको पता है कि बी.कॉम तो करना ही है...

Msk/rtm/04.03.25/1520/2I

जो पारम्परिक शिक्षा है वह तो उसको लेनी है, लेकिन उसके साथ स्किल डवलपमेंट से वह अपनी दिशा, अपनी करियर को, अपने आने वाले समय को, बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं। इस विषय पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। इसके साथ-साथ बेरोजगारी की जो समस्या है, वह भी हम लोग कहीं न कहीं इसमें हल कर पायेंगे। जब बच्चे अपने-आप इंडिपेंडेंट होंगे और स्किल डवलपमेंट को हम और महत्व देंगे। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया है, तृतीय श्रेणी

की अध्यापिकाओं का रिजर्वेशन है वह 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है। मैं आज, चूंकि महिला दिवस भी आने वाला है, मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद 81,000 भर्तियों का उन्होंने जो कैलेण्डर जारी किया है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को आभार देना चाहूंगी कि वे युवाओं को रोजगार देने के लिए नये-नये कदम उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कहीं न कहीं आज भी जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार बहुत है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहां पर मार्बल इंडस्ट्री, वहां पर माइनिंग इंडस्ट्री एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और कृषि, ये दोनों वहां के रोजगार के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वहां पर अगर हम कभी फैक्टरी ऑनर से भी बात करते हैं या कृषि विभाग के साथ हमारी अलग-अलग चर्चाएं होती हैं, दोनों की एक बात होती है कि हम लोगों के पास स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है। हमारे पास रोजगार है, हम चाहते हैं कि रोजगार दें, पर कहीं न कहीं हम लोगों को स्किल लेबर नहीं मिल पाती है।

साथ ही, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि के अन्दर भी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जब हम यूरोप या कहीं भी विदेश में जाते हैं, इण्डिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से यूज की जाती है, लेकिन राजस्थान में हमारे यहां पर भी आज भी कृषि के, चूंकि सब्जेक्ट्स के अभाव में बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते हैं और उसके अन्दर जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस तरीके से वे ला सकें, वह कहीं न कहीं अभाव है। मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक कृषि महाविद्यालय खोला जाये। साथ ही साथ हमारे जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, उनके अन्दर भी स्किल डवलपमेंट के लिए और सब्जेक्ट इंट्रोडूयस करने की जरूरत है, वे इंट्रोड्यूस जरूर करें।

इसके साथ-साथ आयुर्वेद पर आजकल हमारे यहां पर बहुत बड़ा फोकस है कि आयुर्वेद चिकित्सा में पंचायतों में लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा होता है। मैं आपके माध्यम से एक आयुर्वेद महाविद्यालय की मांग मेरे क्षेत्र के लिए रखनी चाहूंगी।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

उसके साथ-साथ हमारे यहां पर राजसमन्द विधान सभा जिला मुख्यालय भी है, हमारे यहां पर एक लॉ कॉलेज की बहुत कमी है, बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे समक्ष नहीं हैं, उन बच्चों को इस सोच को ड्रोप करना पड़ता है कि वे भी लॉ कर सकें। एक लॉ कॉलेज की डिमांड आपके माध्यम से करना चाहूंगी।

हमारे यहां पर एसआरके कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स की जरूरत है। साइंस में, आर्ट्स के अन्दर, कॉमर्स के अन्दर, वह सब्जेक्ट की सूची, समय, चूंकि आपने कहा कि निर्धारित में ही बोलिए, मैं उसको टेबल करना चाहूंगी कि किन-किन सब्जेक्ट की हमें एसआरके कॉलेज में जरूरत है। मंत्री महोदय बैठे हैं और ये हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं

और इनका दिल भी बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है कि ये जरूर से हमारे राजसमन्द के अन्दर अपने नेतृत्व में कॉलेजेज की घोषणा मुख्य मंत्री जी के साथ मिलकर जरूर करायेंगे। इसके साथ-साथ स्कूल्स की बात करें। स्कूल्स में भी चूंकि 50 प्राथमिक विद्यालय और 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, आवाज नहीं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसके साथ-साथ नवीन विद्यालयों को बनाने की बात रखी गयी है, उसकी एक सूची भी मैं टेबल करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर इतने सारे स्कूल हैं जिनकी हालत जर्जर हो रही है। वह तो मैं टेबल करूंगी ही।

लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कितनी बार हमारे पास बहुत भामाशाह आते हैं, गांव से निकलकर वे बड़े शहरों में, गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं और जब कुछ करने की बात आती है तो शिक्षा को वे महत्व देते हैं कि हम शिक्षा में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, लेकिन इसके अन्दर जब वे अपनी निजी जमीन हम लोगों को देते हैं, जब वे निजी जमीन को डोनेट करते हैं तो उसमें यह प्रावधान तो है कि एमपी लैड से पैसे लग सकते हैं, लेकिन एमएलए लैड से हम उस प्राइवेट जमीन जो कि पंचायत को चुके हैं, उसका प्रावधान नहीं है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उस प्रावधान को आप इसमें इनक्लूड करायें, ताकि एमएलए लैड में भी हम अपना लगा सकें। इसके साथ रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करते हैं कि कक्षाओं की जो जर्जर हालत है, हम जब कभी भी गांव में जाते हैं और हम लोगों से मांग की जाती है कि कक्षा-कक्ष की कमी है तो हम लोग अपने एमएलए लैड से पांच लाख, छह लाख, दस लाख में एक कक्ष बना सकते हैं, लेकिन अगर रिपेयर मेंटेनेस भी अलाऊ किया जाए कि स्कूल को हम रिपेयर, मेंटेनेस, जो इनक्लूडेड कक्षा हैं, जो यूज नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी गिरता है या किसी भी वजह से, तो उनको भी आप एमएलए लैड के अन्दर सम्मिलित करें। अगर अलाउड है तो अच्छी बात है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। श्री सी.एल.प्रेमी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन जो एमएलए से बनी क्लास रूम हैं, ...(व्यवधान)... दूसरे बनाते हैं। सभापति महोदय, आप तो मेरे पड़ोसी भी हैं। मुझे दो मिनट में संक्षिप्त में समापन तो करने दीजिये।

श्री सभापतिः आज 40 सदस्य बोलने वाले हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैंने अपने सारे गांवों को टेबल करने के लिए ऑलरेडी बोला है। अंत में, मैं हमारे भजन लाल जी की सरकार के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि-

हमारी सरकार के शासन में उज्जवल भविष्य बच्चों का तय होगा,
पोषक भोजन, श्रेष्ठ शिक्षा और बेहतरीन विद्यालय होगा।

धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 20, 21, 22, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे यशस्वी पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं। ...(व्यवधान)... क्या हो गया तो।

श्री सभापति: प्लीज, आवाज नहीं।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): गांव-गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गये। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का सपना साकार हुआ। भारत के कई राज्यों ने हमारे समय के स्कूलों के शिक्षा मॉडल को लागू किया। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। कांग्रेस सरकार में स्कूलों को मजबूत करने के लिए 2400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गयी। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किये गये।

माननीय सभापति महोदय, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आयी है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गयी है। पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की है। न तो अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा गया है, न स्कूलों की मरम्मत के लिए कोई कार्य किया गया है। और तो और, हमारे मंत्री जी ने 450 स्कूल बन्द कर दिये हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप स्कूलों को पुन: खोलें ताकि शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा बनाया जाये।

मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मेरा कई स्कूलों में जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने बच्चों से पूछा, प्रोग्राम चल रहा था। बच्चों से मैंने जनरल नॉलेज के कई क्वेश्चन किये कि देश का प्रधान मंत्री कौन है, राजस्थान का मुख्य मंत्री कौन है? भारत की महिला प्रधान मंत्री कौन रही? मैं समझता हूं कि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कुछ शर्म करो।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा के साथ-साथ, पढ़ाई के साथ-साथ अध्यापकों को बच्चों को जनरल नॉलेज भी सिखाना चाहिए, यह मैं आपसे कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि कोटा में एक बालिका पर स्कूल की दीवार गिरने से उसकी डैथ हो गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के फटूखड़ा में जर्जर भवन होने की वजह से दीवार गिर गयी और एससी, एसटी के आठ-दस लड़के उसमें आ गये। मैं हॉस्पीटल गया, उनको देखा, करा।

mdp/rtm/04.03.25/15:30/2m

मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी जर्जर स्कूल हैं, जिनकी बिल्डिंग्स खराब हैं, जो बरसात में चू जाती हैं, आप उनके लिए भी अलग से फंड देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की नान्ता, केशव नगर, पाली, बलदेवपुरा, निमोठा, धाकड़खेड़ी, बालापुरा, कापरेन, छपायदा, पादड़ा, हरदेवगंज, कोटड़ी, नैनवा बिलकिक, कुम्हारिया, नयागांव, कलवास, काठपुरिया के प्राथमिक विद्यालय के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, इनको सुधारने की कोशिश करें ताकि इन हादसों से बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, केशोरायपाटन में सरकारी स्कूल के वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 129 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 65 ही कार्यरत हैं और 44 पद खाली हैं। इसी प्रकार अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के 1,134 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1,057 ही हैं और बाकी 77 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां के विद्यार्थी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर में पोस्टिंग हैं, लेकिन कई वर्षों से वह अटक रहे हैं। आपके समय से अटक रहे हैं। आपने अभी तक इसके लिए पॉलिसी नहीं बनायी है। बच्चे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पोस्टिंग हैं। मेरा, मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि ये जितने भी शिक्षक हैं, इनको यहां लाया जाए और जो नया रिक्रूटमेंट आप करें, उनको वहां किया जाए और इनका यहां ट्रांसफर किया जाए। हमने किये या नहीं किये आप तो कीजिए। हमने तो जो किया वह कर लिया, अब आप तो कीजिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है। आप अपनी बात रखिए, आसन को संबोधित करते हुए।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, अभी मेरा समय पूरा थोड़े ही हुआ है।

श्री सभापतिः आपको पूरा समय मिलेगा। मगर आप इधर-उधर मत कीजिए।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपने पाटन में कॉलेज दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि कापरेन में आप इसी सत्र में यदि कन्या महाविद्यालय खोल दें तो मैं समझता हूं कि आपकी कृपा होगी। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। लाखेरी में आपने एक कॉलेज खोला, विद्यार्थी वहां हो गये 350 और टीचर हैं 04, बिल्डिंग नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि बिल्डिंग के लिए आप पैसा दीजिए और वहां अध्यापकों की नियुक्ति कीजिए।

मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां के सरकारी विद्यालयों में कृषि संकाय नहीं है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां कृषि संकाय नहीं है या साइंस नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि करवर में और कापरेन में कृषि विषय खोलने की कृपा करें। मैं दिलावर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरा, दईखेड़ा में साइंस संकाय खोलने की कृपा करें। आप मुस्कुराएं नहीं, लेकिन खोल दें तो बहुत अच्छी बात है। करवर में

मॉडल स्कूल आप दें तो मैं समझता हूं कि करवर और जो आसपास का क्षेत्र है, उसमें गुणवत्ता बढ़ेगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद जी।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 व 22 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुसार ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल आधार ही हमारी शिक्षा है। कहा गया है "जैसा खावे अन्न वैसा बने मन।" यहां पर अन्न का अर्थ भोजन है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आजकल मानव समाज में जो तरह-तरह के छोटे-बड़े दोष दिखलाई पड़ रहे हैं उनका मूल हमारी शिक्षा ही है। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई-नई योजनाएं बन रही हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को मिटा देगी। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और वह किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा तीन भागों में बंटी हुई हैं।

शरीर की सुव्यवस्था और रक्षा होनी चाहिए। इसमें बतलाया जाये कि हम कब कितना खायें, कब कब कितना सोयें, कब और कितना तथा किस-किस प्रकार अपना मनोरंजन करें, कब कितना-कितना और किस प्रकार व्यायाम करें। मनोरंजन तथा व्यायाम की शिक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में दी जानी चाहिए, ताकि हमारे भीतर सहयोग की भावना का विकास हो और हम समाज में मिलकर काम करना सीखें।

मानसिक शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारे दिमाग का उचित रीति से विकास होना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम केवल अपनी पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों को भली प्रकार समझकर याद कर सकें वरन् इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने शरीर-रक्षा की विधि को जानकर तदनुकूल आचरण करें। हम में सेवा भाव उत्पन्न हो, हमारे हृदय में बन्धु भाव जागृत हो, हम नई बात जानने को उत्सुक हों और निरन्तर अपनी ज्ञान वृद्धि करते रहें, हम में कार्य क्षमता आवे और हम में भले-बुरे का विवेक उत्पन्न हो। यह हमारी मानसिक शिक्षा है।

आध्यात्मिक शिक्षा के तहत यह है कि हम में सम्मान तथा आदर का भाव उत्पन्न हो, अपने आस-पास वालों के प्रति बन्धुत्व की भावना का उदय हो और दया तथा करुणा के भावों की वृद्धि हो। मनुष्य में जब तक अपनी राष्ट्रीय, धार्मिक, जातीय, सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं अथवा परम्पराओं के प्रति समान बुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उन्नति की आशा दुराशा मात्र है। मानुषी और दैवी कार्यों की महत्ता के सम्मुख भी हमको नतमस्तक होना चाहिये। वयोवृद्ध जनों का सम्मान तथा दुर्बल और बालकों को अपना **वरदहस्त** प्रदान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सद्गुणों और सद्व्यवहार

के प्रति भी हमको श्रद्धा का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि ये सब मनुष्यत्व के चिह्न हैं।

शिक्षा का यह भी प्रभाव होना चाहिये कि हम विश्व के प्रत्येक पदार्थ में अपने स्वरूप आदर्श न पावें तथा उसके प्रति प्रेम भाव रखें। प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म तथा प्रत्येक राष्ट्र के लिए हमारे हृदय में प्रेम का भाव हो, हम किसी को न तो बुरा समझें न किसी से घृणा करें। सबको अपने ही समान स्वाभिमानी समझें। हमारी शिक्षा हमें इस योग्य बनावे कि हम प्रत्येक बात को को निष्पक्ष भाव से समझ सकें, अपने निजी विचारों के अनुरूप अपनी धारणाएं निर्धारित कर सकें। आध्यात्मिक शिक्षा का एक परिणाम यह भी होना चाहिए कि हमारे अन्दर संसार के सभी असहाय, निरुपाय, दलित, पीड़ित, शोषित, दुखी, निर्धन व्यक्तियों के प्रति दया एवं करुणा के भाव हों। क्रोध और घृणा के पात्र न समझकर हम उनके प्रति दया रखें। उसके साथ हमारी उदारता का संयोग होना ही उचित है। इतना ही नहीं हम दीन दुखियों पर दया करके ही रह जाते हैं, वरन् परिस्थिति तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनके दुःख में हाथ बंटाना भी आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था में मूल्य आधारित शिक्षा होना चाहिए।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बीसवीं सदी के पश्चात प्रादुर्भाव में आयी कई नई-नई प्रणालियों का समेकित रूप है। शिक्षा में नित-नित नए-नए प्रयोग एवं नई-नई शिक्षा तकनीकों ने वर्तमान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं।

अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शिक्षण तकनीक वास्तव में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित तकनीक का ही प्रतिफल रहा है । आजादी के पश्चात 1953 में गठित मुदलियार आयोग, 1961 में स्थापित एन.सी.ई.आर.टी., 1966 में गठित कोठारी आयोग ने अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही शिक्षा प्रणाली में कई जरूरी बदलाव किए हैं। हमारे नौनिहाल बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही वर्तमान शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा का घोर अभाव है। अब जबकि संयुक्त परिवार टूटा चला जा रहा है एवं पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में मूल्य आधारित चेतना समाप्त होती चला जा रही है। शासन-प्रशासन के प्रत्येक कोने में निःस्वार्थ प्रेम समाप्त होने के साथ ही नैतिकता में दिन-प्रतिदिन हो रही गिरावट एवं पद तथा गोपनीयता की शपथ लेने वाले हमारे देश के माननीय चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, द्वारा जनता को किए जाने वाले कार्यों के बदले निजी स्वार्थ को तरजीह दिया जा रहा है, तब हमें यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारी भावी पीढ़ी में नैतिकता की शिक्षा का ज्ञान देना अति आवश्यक हो गया है।

Ans/rtm 15.40 2n 04.03.2024

भारतीय संस्कृति एवं इंटरनेट तथा टेलीविजन के द्वारा ज्ञान का प्रसारण हमारे देश को नैतिकता में आकंठ डूबा कर रख दिया है। आज की युवा पीढ़ी एकल परिवार के चलन, कामोत्तेजक कपड़ों के प्रचलन, लिव-इन-रिलेशनशिप एवं जुगाड़ तकनीक से सरकारी नौकरी की प्राप्ति तथा भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी को अपनी सांस्कृतिक प्रगति मान बैठे हैं।

इस प्रकार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को मूल्य की अवधारणा से इस प्रकार बनाना आवश्यक हो गया है ताकि हमारी अगली पीढ़ी नैतिक मूल्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक हो गया है। एक नैतिक मूल्य पर आधारित प्रेरक प्रसंग एवं ऐतिहासिक कहानियों को वर्ग छह से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। प्रदूषण स्वच्छता पॉलिथीन के दुरुपयोग इत्यादि के प्रति जागरूक एवं इस संबंध में चेतना भी पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बने। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव इसके रोकथाम हेतु सुझाव एवं उपाय भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं एवं शिक्षा में उन्मुक्त सेक्स की को भी उचित स्थान माध्यमिक स्तर से ही मिले ।

पवित्रता तथा जीवन, प्राचीन भारत में प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य था। शिक्षा आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक बालक के उपनयन संस्कार की पूर्ति करना, शिक्षा प्राप्त करते समय अनेक प्रकार के व्रत धारण करना, योग करना, प्रातः तथा सायंकाल की महिमा के गुणगान करना तथा ...(व्यवधान)... क्या आपको आपत्ति आ रही है। गुरु के कुल में रहते हुए धार्मिक त्योहारों का मानना आदि सभी बातें बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करते उसे आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान बनाती है।

चरित्र निर्माण भारत की प्राचीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था, बालक के नैतिक चरित्र का निर्माण करना। उस युग में भारतीय दार्शनिकों का अटल विश्वास था कि केवल लिखना-पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, वरन नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण करना परम आवश्यक है।

व्यक्तित्व का विकास, बालक के व्यक्तित्व को पूर्णरूपेण विकसित करना प्राचीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक को आत्म-सम्मान की भावना को विकसित करना परम आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रत्येक बालक में इस महान गुण को विकसित करने के लिए आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता, आत्म- नियंत्रण तथा विवेक एवं निर्णय आदि गुणों एवं शक्तियों को पूर्णतः विकसित करने का अथक प्रयास, यह हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाया है।

हमारे पूर्वजों ने प्राचीन युग के साहित्य की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को सुरक्षित ही नहीं रखा अपितु अपने यथाशक्ति योगदान द्वारा उसमें निरन्तर वृद्धि करके उसे मध्य युग तक भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे राजकीय महाविद्यालय अकलेरा दिया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। रानीपुरा, खेजड़ा, पाटलियालोठान, हनोतियालोठान, नेशगुजरान, गुराड़ी, मोग्याबेह, देवकादार,ढाबली, दहीखेड़ा, नीमखेड़ा, उचावदा, संस्कृत विद्यालय गेहूखेड़ी एवं ब्लाक अकलेरा को क्रमोन्नत तथा हनोती, बोरदा में नवीन विद्यालय बनाने की आवश्यकता

है।

नवीन संकाय की जो घोषणा की है उनमें मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मेरे ज्यादातर कला वर्ग है, साइंस और एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालय चंदीपुर, जावर, आवलहेड़ा, कामखेड़ा, कोलु खेडीमाल्यान, बाखेडीमोवातियान, खाताखेड़ी, कोलुखेडीकलां, समरोल, बड़बद, शोरती, डूगरगांव, खेड़ला, टाडीसोहनपुरा, लावासल,असनावर, जूनाखेड़ा, बडोदिया, घाटोली, ल्हास, चुरेलिया, नयापुरा, सरड़ा...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। श्री घनश्याम जी।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): एक मिनट। ...आदि गांवों के विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता है। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 व 22 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है। माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई देश हो या प्रदेश हो, बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई देवी-देवता या शक्ति नहीं जो आपकी गरीबी व गुलामी को दूर करेगी। वह स्वयं आप खुद या शिक्षा के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज की स्थिति में स्कूलों में जो हालत है वह पर्याप्त नहीं है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार सिर्फ 12 प्रतिशत स्कूलो में इंटरनेट है, 30 प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर है, तो यह बड़े दुःख की बात है कि ग्रामीण स्कूलों में ना तो इंटरनेट की सुविधा है और ना ही कम्प्यूटर की सुविधा है। इसके साथ-साथ 42 प्रतिशत स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। 23 प्रतिशत स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 22 प्रतिशत स्कूलों में शारीरिक निशक्तजनों के लिए रेम्प की व्यवस्था नहीं है। 15 प्रतिशत स्कूलों में जल, सफाई, स्वच्छता की सुविधा नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस देश को, प्रदेश को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर शिक्षा पर काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, माध्यमिक स्तरों पर देखे तो विद्यालयों में 14 से 16 वर्ष के अधिकांश छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। इसके बहुत सारे कारण है, उन कारणों पर अपने को विचार करना पड़ेगा। उसमें वित्तीय संसाधन भी है, गरीबी के कारण, पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह स्कूल छोड़ देते हैं, तो इन पर सरकारों को विचार करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में स्कूलों में 6 से 17 वर्ष की आयु में 21 प्रतिशत बच्चे, बालिकाएं स्कूल छोड़ देती है, जिसका मुख्य कारण पढ़ाई में रुचि नहीं होना बताया है। इस सर्वे में यह बताया है कि रुचि क्यों नहीं है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम सरकारी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। जब तक हम सरकारी स्कूलों के ढांचे को सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक हम ग्रामीण, मजदूर, किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तो इस पर सरकार को बहुत विचार करने की जरूरत है।

एक समस्या यह है, देश में आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में बड़ी संख्या से छात्रों को चुनौती पूर्ण शिक्षण व्यवस्था, वातावरण का निर्माण किया गया है, जिसमें शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता है, उसको सरल किया जाए। जब वह विदेशों में जाते हैं तो उनकी क्वालिटी, योग्यता है वह विदेशों के काम आती है हमारे देश के काम नहीं आती है, तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में उनके लिए साधन उपलब्ध कराए। ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज या जो भी सरकारी व्यवस्था दें तो उनकी व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 2020 तक भारत में विश्व के सर्वाधिक युवा आबादी होगी। युवा आबादी इस विशाल आकार में तभी वरदान सिद्ध होगा जब युवा कार्यबल क्षमता होने के लिए पर्याप्त कुशल होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा पायेगी। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे भी ख़र्चे करते हैं उनको कम करके शिक्षा पर ट्रांसफर करना चाहिए।

अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल हमारी सरकार ने खोले थे, आज उनको सरकार बंद करने जा रही है, यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जब ग्रामीण का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा तो वह फिर आगे कैसे बढ़ सकता है? यह सरकार की एक ईर्षा मानी जाती है कि सरकार को इन लोगों से ईर्ष्या है कि ग़रीबों के बच्चे पढ़े-लिखे नहीं हो और अंग्रेज़ी से नहीं पढ़ें, अगर वह अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, इस तरह की सरकार की जो सोच है वह बहुत दयनीय है, दुखद है।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान की स्थिति में शिक्षा पर निम्न सरकारी व्यय जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से कम है, जबकि हमें इसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम पैसा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। आज स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं हैं, बाथरूम की सुविधा नहीं है, ऐसी बहुत सारी असुविधाएं हैं कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। गांवों में भी एक माहौल बन गया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ही हर आदमी अपनी शान समझने लग गया है।

VPS-RTM-04.03.2025-15.50-2o

इस बात को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार एक स्कीम लायी थी उसमें उन्होंने निजी विद्यालयों के मुकाबले संसाधनों की कमी के कारण, अभिभावकों को निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ते रुझान के बीच कर्नाटक में सरकारी स्कूल के एक प्रधानाध्यापक ने स्वागत योग्य एक अनूठी पहल की। उस स्कूल में दाखिला लेने वाले प्रत्येक नये विद्यार्थी के लिए उन्होंने अपनी निजी आय से एक हजार रुपये का फिक्स डिपोजिट (एफ.डी.) करवाने का निर्णय किया। निश्चित ही इस तरह का प्रयास शिक्षा के प्रति संस्था प्रधान की प्रतिबद्धता ही कहा जायेगा। यह सराहनीय प्रयास बच्चों के अभिभावकों और सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करने वाला सहायक होगा। तो इस तरह की सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए कि सरकारी

स्कूलों में आये दिन बच्चों की संख्या घटती जा रही है और जब संख्या घटती जा रही है तो सरकार भी ध्यान नहीं देती। उन बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देती है। न तो स्टाफ लगा पा रहे हैं और न अपन मास्टरों की भर्ती कर पा रहे हैं, तो अगर इस तरह से धीरे-धीरे यह सरकारी स्कूलों को हमने कमजोर किया तो फिर शिक्षा एक व्यापार बन जायेगा और प्राइवेट स्कूलों में फिर व्यापारीकरण हो जायेगा। जिन लोगों के पास पैसा है, मोटी रकम है, वे ही लोग शिक्षा ले पाएंगे, बाकी गांव का गरीब किसान शिक्षा से वंचित रह जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ चिंताजनक पहलू यह भी है कि सरकारी स्कूलों में लम्बे समय से कमोवेश देश के हर हिस्से में वह उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। बुनियादी सुविधाओं में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रति आकर्षण पैदा हुआ है और उस आकर्षण को हम उलटा खतम कर रहे हैं, उन स्कूलों को खतम कर रहे हैं, तो यह भी एक चिंता का विषय है। गांवों में आज कोई भी जाकर सर्वे कर सकते हैं, सब गांव के लोग भी यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश स्कूलों में पढ़े और वह अच्छी शिक्षा ले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले और वह हमारा नाम आगे करे, देश का नाम आगे बढ़ाये, ऐसी सुविधा सरकार को देनी चाहिए। हालांकि, जहां तक जागरूकता और समर्पित शिक्षक हैं, वे सरकारी स्कूलों को भी अपने-अपने तरीके से बेहतर बनाने में जुटे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों का व्यक्तिगत प्रयास अपनी जगह पर है लेकिन सरकार को भी इन स्कूलों की दशा सुधारने के लिए काम करने चाहिए। बेहतर बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय, खेल मैदान, शौचालय, स्वच्छ पेयजल के साथ स्मार्ट क्लास, लर्निंग, फार्मिंग स्कूलों के नामांकन बढ़ाने का आपको ध्यान देना चाहिए। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, समय तो अभी चालू ही हुआ है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पर अब दो मिनट मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखूंगा। राजकीय विद्यालय खेड़ी, मंडेरलू, मध्यपुरा, भोपर, पदमपुरा, बलात, टोडाभीम में कृषि संकाय खोलने की पहले भी मैंने बजट में मांग रखी थी, वह आज तक पूरी नहीं की गयी है। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वह इन संकायों को खोलें।

इसके साथ-साथ हमारे नादोती और टोडाभीम में कृषि महाविद्यालय खोले जाए। इसके साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेरड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पेचला को क्रमोन्नत किया जाये। यह तीस-तीस, चालीस-चालीस साल पुराने स्कूल हैं पर आज तक इनको क्रमोन्नत नहीं किया गया है। इसके साथ ही मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र में मेरे जो कॉलेज है, कॉलेज की आज भी चारदीवारी नहीं बनी है तो उस चारदीवारी के लिए मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है, उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि कॉलेज में चारदीवारी नहीं होने के कारण उसमें आवारा पशु घुस जाते हैं, आवारा जानवर घुस जाते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति है, तो कॉलेज की चारदीवारी का फंड, माननीय उप

मुख्य मंत्री से निवेदन है कि टोडाभीम के कॉलेज की चारदीवारी का निर्माण करवाया जाये।

इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह निवेदन है कि आने वाले समय में नामांकन बढ़ाने के जो तमाम प्रयासों के बावजूद निजी क्षेत्र के दबदबे के बीच सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराना, उनको राज़ी करवाना आसान नहीं रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों के नामांकन घटने का सिलसिला बना हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए। श्री भागचन्द टांकड़ा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर मुझे अपने विचार रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ज्ञान, समझ और व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा से हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है और हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भजन लाल सरकार प्रदेश के युवाओं एवं विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जाग्रत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बजट 2025-26 में घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आपकी सरकार जब से बनी है उसके बाद मुख्य मंत्री जन सहभागिता योजना में कोई भी एक भी काम नहीं किया है। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि एक तो वे खुद शिक्षक हैं और एक शिक्षक होने के नाते जब विद्यालय में छात्र आता है तो यह कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है और घर के नीचे सांप है। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस स्कीम में दस विद्यालयों में जन सहभागिता से पैसा जमा करवाकर काम हुआ है और यह क्रमांक नम्बर 2024-25/907, दिनांक 06.02.2025 को यह वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। प्रशासनिक स्वीकृति तो इससे पहले ही निकल गयी, वित्तीय स्वीकृति इस दिन निकली है और पूरे जिले में ऐसे 23 काम हुए हैं, तो माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक किसी के बारे में आक्षेप, प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है और विपक्ष जब तक असत्य ऐसे ही बोलता रहेगा तो आपकी कौन बात मानेगा? हमको यहां 200 को इसीलिए चुनकर भेजा है। 200 लोगों को यह समझकर भेजा है एक गुदड़ी की तरह कि बिछा ले तो नरम और सर्दी पड़े ओढ़ ले तो गर्म, बींटा बांधकर खूंटी पर लटका दें तो लोगों में रहे भ्रम और उसको चोर ले जाये तो उसके फूट जाये कर्म।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बात आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आभानेरी ग्राम पंचायत के ग्राम आमाली में राजकीय भवन बना हुआ है, वहां नवीन प्राथमिक

विद्यालय खोला जाये तथा जावली के बाढ़ के ग्राम भोपा की ढाणी तथा अरनिया के ग्राम कोली की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है इसलिए ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ कृषि का भी ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसवा, नंदेड़ा, श्यामसिंहपुरा एवं आभानेरी में कृषि संकाय खोला जाये। इसी प्रकार आज के जमाने में मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण स्टडी जो है वह विज्ञान की है इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि नंदेड़ा, धांधोलाई, केसरीसिंहपुरा, अक्षयपुरी, बास बिवाई, अंतवाड़ा, श्यामसिंहपुरा में विज्ञान संकाय खोले जायें। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों में जो एक्स्ट्रा टेलेंट भी होना चाहिए इसलिए धांधोलाई में चित्रकला विषय भी खोला जाये, वहीं घुडलिया में गणित, डी.एन.जोशी बांदीकुई तथा बालिका विद्यालय, बांदीकुई में संस्कृत विषय खोला जाये। करनावल में अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास विषय खाला जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से कुछ विद्यालय जो गांव पंचायत स्तर के विद्यालय हैं, गांव राणापाड़ा, गोलाड़ामोड, बाग़ की ढाणी, नारायणपुरा, कांच की ढाणी, हरसोरा, बड़वाली, भावती, सिमला, भोजबाड़ा इन गांवों के विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इन्हें क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया जाये क्योंकि यह आबादी के हिसाब से पंचायत हैडक्वार्टर से भी ज्यादा इन गांवों की आबादी है और यह बहुत बड़े गांव हैं और इनमें बच्चों की संख्या भी पूरी है। इन विद्यालयों के क्रमोन्नत होने पर बच्चों को आगे की पढ़ाई की सहूलियत होगी। इस प्रकार महादेवपुरा, पाड़ावालों का बास, रावली की कोठी, ढाणी बगथल, दुड़की, नानगबाड़ा, रामपुरा के प्राथमिक विद्यालयों को भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत विद्यार्थियों की अच्छी संख्या है परंतु विधान सभा क्षेत्र में चुनिंदा गांवों में ही संस्कृत विद्यालय है, इस कारण विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ाई हेतु आवागमन की परेशानी होने के कारण संस्कृत विषय का अध्ययन नहीं हो पाता है।

ssy/rtm/04.03.2025/16.00/2p

इसलिए पुराना खेड़ा, आमाली, छिलार की ढाणी, कोलाना, बांदीकुई, फूलेला एवं झाड़ला में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले जावें। वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र का राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हरनाथपुरा को कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया जावे तो विद्यार्थियों को, विशेषकर बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए 35 किलोमीटर दूर दौसा नहीं जाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जो कि हमारे प्रदेश के उप मुख्य मंत्री भी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का स्वर्गीय राजेश

पायलट राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई जो कि वर्ष 1977 में स्थापित हुआ था, महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष आने वाला है। अभी तक महाविद्यालय में केवल 2 ही विषयों में स्नातकोत्तर, पी जी कक्षाएं संचालित होती हैं। उक्त महाविद्यालय में 3 हजार से ज्यादा विद्यार्थी प्रतिवर्ष अध्ययन करते हैं एवं लगभग 11,500 स्वयंपाठी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। हाल ही जनवरी, 2025 में नेक का निरीक्षण हुआ, जिसमें महाविद्यालय को 'बी' ग्रेड प्राप्त हुई। निरीक्षण समिति ने अपने निरीक्षण में महाविद्यालय को कम से कम 10 विषयों में पी जी होना चाहिए, की अनुशंसा की है। ऐसे में मेरी मांग है कि महाविद्यालय को उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के लिए नये पी जी विषय एवं कला संकाय में इतिहास, भूगोल, संस्कृत तथा विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में चित्रकला, गृह विज्ञान, संगीत विषय तथा बी सी ए पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जावें। यदि राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों का अत्यधिक अभाव है तो उक्त नये विषय पूर्व की भांति राष्ट्रीय सोसायटी के अधीन अथवा स्व वित्त पोषित स्तर पर प्रारंभ करने की अनुमति दी जावे। उक्त महाविद्यालय का भवन काफी पुराना हो चुका है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए नये भवन अथवा ब्लॉक निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में संचालित राजकीय महाविद्यालय बसवा का राणा सांगा के नाम पर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांदीकुई का सावित्री बाई फुले के नाम तथा राजकीय महाविद्यालय आभानेरी का स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला के नाम पर नामकरण किया जावे। इन महापुरुषों के नाम पर महाविद्यालयों का नाम रखने से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। इनकी यादगार बनी रहेगी। इनके योगदान और बलिदान को सम्मानित किया जा सकेगा। युवाओं को इनके जीवन और कार्यों से सीखने का, जीवन में अपनाने का अवसर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले का महिला शिक्षा में योगदान को संपूर्ण देश की आधी आबादी भूला नहीं सकती है। किंतु संपूर्ण भारत की तरह राजस्थान में भी महिला शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अभी कम है। इसके पीछे अपने सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदायी है।

अतः सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। महिलाओं के शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनने से ही विकसित राजस्थान का संकल्प साकार हो सकेगा। इसके लिए सरकार द्वारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर राज्य द्वारा वित्त पोषित सावित्री बाई फुले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय खोला जावे।

सभापति महोदय, राज्य में विधि शिक्षा के लिए संपूर्ण राज्य में पृथक से एक विश्वविद्यालय डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय है। पत्रकारिता के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। तकनीकी शिक्षा और कृषि शिक्षा के लिए अलग-अलग

विश्वविद्यालय हैं। इसी प्रकार संपूर्ण राज्य के 11 हजार बी एड, एम एड महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को एकीकृत और विशेषीकृत रूप में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना उचित होगा। यह विश्वविद्यालय बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र, जिला दौसा जहां अब तक कोई भी विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान नहीं है और इस क्षेत्र से देश का मुख्य मार्ग दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाई वे गुजर रहा है। साथ ही यहां पर सड़क, ट्रेन कनेक्टिविटी की उत्तम सुविधा है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): जिसके आसपास ही इसे स्थापित किया जावे तो उचित होगा। सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का मौका दिया, आपका एवं मेरे नेता, प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और मुख्य सचेतक रफीक खान साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, 'शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा जीवन में ज्ञान, कौशल और समत्व प्रदान करती है। शिक्षा ही हमें लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेहतर जीवन जीने में मदद करती है।' गांधी जी ने कहा था कि 'मुझे आजादी से भी ज्यादा कोई चीज प्यारी है तो वह शिक्षा है।'

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी गोविन्द सिंह डोटासरा साहब को मैं बहुत-बहुत तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्व सरकार में जो महत्वपूर्ण फैसले शिक्षा में किये, चाहे 300 से ज्यादा कॉलेज खुलाईं या हर ग्राम पंचायत, हर गांव के अन्दर स्कूलें खुलाईं। उसके लिए भी मैं तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरे सामने हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। मैं मांग संख्या 22 पर पहले बोल जाता हूं। हमारे मकराना के अन्दर कॉलेज पिछले 4 सालों से चल रही है। जहां 450 बच्चे पढ़ रहे हैं। मंत्री जी, आप सुनिये, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): संसदीय कार्य मंत्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं मंत्री जी को।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): उच्च शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी।

श्री सभापतिः आप बोलिये। नोट हो रहा है। सब नोट हो रहा है।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): हमारे 450 बच्चे मकराना के अन्दर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहां पर विद्या संबल योजना के तहत 6 शिक्षक काम कर रहे थे उन्हें 24 दिसम्बर, 2024 हटा दिया गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): भाईसाहब, एक सैकण्ड, हम सब आराम से सुन रहे हैं। अच्छी बातें कह रहे हैं। हम ग्रहण भी कर रहे हैं और हम मंत्री जी को भी कह

रहे हैं कि यह बात कहें तो गहनता से सुनो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मंत्री जी सुनेंगे तो कुछ मेरी मदद करेंगे।

श्री सभापति: प्लीज। अपनी बात रखिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): यह 6 विद्या संबल के अन्दर, महाविद्यालय के अन्दर कार्य कर रहे थे। 24 दिसम्बर, 2024 को इनको हटा दिया गया। दो महीने तक मकराना कॉलेज के ताले लगे हुए थे। दो महीने तक वहां के जो छात्र थे, वह मकराना कॉलेज 8-10 किलोमीटर है, वहां डायरी के अन्दर अटेंडेंस लगाने जाते थे। जब छात्रों ने 10 फरवरी को मुझे बताया कि एमएलए साहब, हमारी कॉलेज में दो महीने से ताले बंद हैं, आप आओ और आप बात कीजिए, तो मैंने ताले खोले, वहां स्कूल की हालत ऐसी थी, वह कबूतरखाना जैसे होता है ना, वहां न फर्नीचर था, न और कुछ था। मैंने वहीं से ही, कॉलेज में माननीय मंत्री जी से बात की। मैंने कहा, मंत्री जी हमारे यहां एक भी अध्यापक नहीं है और जो 6 संबल योजना में लगे हुए थे विद्या संबल से, उनको भी हटा दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने प्रतिनियुक्ति में एक अध्यापक लगाया। जो कि अभी भी कभी आता है, कभी नहीं आता है ...(व्यवधान)... ताले लगे थे, शर्म की बात है। ताले लगे हुए थे। वह ताले हमने खोले।

वह कॉलेज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4 कमरों के अन्दर चल रही है, जिससे हमेशा वहां पर दिक्कत भी होती है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम तो आपकी बात मनवा रहे हैं। पड़ोसियों का विश्वास मत करो। खतरनाक मामला हो जायेगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप चिंता ही मत करो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): आप चिंता ही मत करो। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि विद्यालय के अन्दर जो कॉलेज चल रहा है, वहां आधी बालिकाएं हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत के अन्दर मकराना की कॉलेज चल रही है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर दिलढाणी के अन्दर दो साल पहले जमीन स्वीकृत की हुई है। वह कोर्ट के अन्दर मामला चल रहा है। उसमें कोर्ट का स्टे हटाकर कॉलेज के लिए भवन बनायें। पूर्व की सरकार ने उसका पैसा दे रखा है। उसको आप करायें। राजकीय महाविद्यालय में भौतिक संसाधनों की पूर्ति भी कराई जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोर्ट का स्टे हम हटायेंगे क्या?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोर्ट का स्टे हम हटायेंगे क्या?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): कोर्ट तो एसडीओ वगैरह, वकील वहां भेजो। वहां जाते ही नहीं हैं। वहां कोई सुनवाई करता ही नहीं है। हाई कोर्ट के अन्दर जाने के लिए सरकार ही काम करेगी ना। आप विधि मंत्री बैठे हो। कोर्ट के अन्दर स्टे लेकर आ गये, लेकिन वह व्यवस्था आप ही कराओगे ना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): स्टे कौन लेकर आ गया?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): स्टे वह गांव वाले।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह आपके ही गांव वाले हैं ना?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): नहीं, नहीं, वह पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र में आता है। हमारे वहां पर भौतिक संसाधनों की भी पूर्ति करायें। महाविद्यालय के अन्दर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान विषय खोलने की भी कृपा करें।

spp/rtm/04.03.2025/16.10/2q

तो ताला तो खुलाया है टेम्प्ररेरी चलता है मनोज जी। राजकीय महाविद्यालय में नियमानुसार व्याख्याता और अन्य स्टाफ लगायें। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं मकराना में 75 प्रतिशत किसान लोग रहते हैं। वहां पर बूडसू के अन्दर कृषि महाविद्यालय खोलने के लिये मुख्य मंत्रीजी से बोलकर वहां खुलवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 20, 21 पर बोलूंगा। शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अभी 10.02.2025 को एक जयपुर के अन्दर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आर.ए.सी. बटालियन जयपुर को एक पत्र लिखा। उसमें इन्होंने यह कहा है कि उर्दू का विषय समाप्त करें और संस्कृत विषय वहां पर लागू करें। संस्कृत विषय आप लगा रहे हो, मैं उसका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं मंत्री महोदय, लेकिन उर्दू विषय हटाने का तात्पर्य, आपकी मंशा क्या है?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): वहां पर बच्चे कितने हैं?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): वहां पर मैं बताता हूं। वहां पर 127 बच्चे उर्दू के पढ़ने वाले हैं और 17 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं। आप बताओ यह उचित है क्या? 127 की मैं रिपोर्ट देखकर आया हूं। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप पूछ रहे हो न, मंत्रीजी, आपको ज्ञान का अभाव है। 127 बच्चे उर्दू वाले हैं और 17 बच्चे संस्कृत के हैं। फिर भी आप संस्कृत का सब्जैक्ट खोल लो, कोई एतराज नहीं, लेकिन उर्दू वाले बच्चे, जो उर्दू पढ़ रहे हैं, आपकी मानसिकता ..(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 127 बच्चे हैं उर्दू के पढ़ रहे हैं वहां पर और पद सृजित है। आपको संस्कृत का एडिशनल पद सृजित करना था। वह तो आपने किया नहीं।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मैं इस पर एक शायरी कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय –

'अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जुबां थी प्यारे
उफ सियासत ने उसे भी जोड़ दिया मजहब से।'

उर्दू को मजहब से जोड़ दिया। उर्दू सभी धर्म के लोग बोलते हैं। आपने उसे मजहब से जोड़ दिया। जिस उर्दू भाषा की पैदाइश हिन्दुस्तान में हुई, आज उसे अपने ही देश में पराया बनाया जा रहा है। जिस जुबान को हर धर्म के लोगों ने अपनाया। मुंशी प्रेमचन्द, पंडित

कृष्ण बिहारी नूर, चाँद बिहारी, रघुपति सहाय, फिराख गोरखपुरी, पद्मभूषण पंडित गुलजार, पद्श्री पंडित बृजनारायण जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। केन्द्र सरकार उर्दू क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार देती है और हमारी राज्य सरकार उर्दू को बंद करने के आदेश देती है। आप शिक्षा विभग और मदरसा बोर्ड की रिपोर्ट देखो, सब धर्मों के बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी सभी धर्मों के हैं। फिर क्यों उर्दू को मिटाने की बात की जा रही है? यह गंगा-जमुनी तहजीब की भाषा है। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को पढ़ने का अधिकार है। लिहाजा उर्दू भाषा को बंद करना, यह गैर संवैधानिक है। इस आदेश को आप निरस्त करें।

आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप जिस तरह से भेदभाव करते हो, हमारे 6 डी.ई.ओ. थे, उनमें से 3 डी.ई.ओ. माइनोरिटीज के थे, तीनों को छह महीने के लिये ए.पी.ओ. कर दिया गया है। मैन बात यह है कि अगर कोई भी अध्यापक हो, डॉक्टर हो या कोई जानकार हो, साहित्यकार हो, चाहे किसी धर्म या जाति का हो, अगर आप जाति के हिसाब से इनका ट्रांसफर करते हो, इनको ए.पी.ओ. करते हो तो यह बहुत ही गलत बात है। हालांकि उनको छह महीने बाद पोस्टिंग दे दी गयी है। शिक्षा मंत्रीजी, जो प्रदेश के अन्दर हालात बने हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षा की आप दो-चार उपलब्धि भी नहीं गिना सकते हो। हमारी सरकार ने जो स्कूलें खोली थीं, आपने उनमें से 429 स्कूलें बंद कर दीं।

मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने 17 हजार 800 रुपये मदरसा पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाया। संविदाकर्मियों को नियमित करने के लिये कांट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2022 में सरकार ने बनाये। इस नियम के तहत आप सभी विभागों में लगे संविदाकर्मियों को नियमित किया जाये।

मैं यह कहना चाहता हूं मेरे मकराना ग्राम लोहारी के अन्दर 2019 में ग्राम पंचायत बनी। वहां पर नियमानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलना चाहिए। मेरे मकराना में भविष्य में माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री ताराचंद जी जैन। (अनुपस्थित) श्री जेठानन्द जी व्यास।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मेरे 10 मिनट हुए नहीं अभी। माननीय सभापति महोदय, स्कूलों की मरम्मत के लिये बहुत से मकराना में ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मां भारती के चरणों में नमन। जय श्री राम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इन कांग्रेस की, जो कि आजादी के बाद से लगातार इनकी सरकार रही है। शिक्षा के साथ और मेरे क्षेत्र बीकानेर के साथ इन्होंने क्या-क्या किया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश के विलीनीकरण के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ राजस्थान 06 अप्रैल, 1949 व 21 मार्च, 1950 में विभागों के बंटवारे के सम्बन्ध में

उल्लेख किया गया है कि शिक्षा के समस्त मुख्यालय बीकानेर में स्थापित किये जायेंगे। इस रिपोर्ट के चैप्टर 8 के बिन्दु 1 में श्रीमान् मोहन को निदेशक शिक्षा लगाकर शिक्षा के समस्त चार्ज उन्हें दिये गये थे। जब यह हुआ तो उस समय के महाराजा शार्दुल सिंहजी ने अपनी एक बिल्डिंग राज्य सरकार को किराये पर दी, जिसका आज भी किराया एक रुपये है। वह इसी शर्त पर दी गयी थी कि शिक्षा सारी बीकानेर में रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार राज्य की उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संयुक्त रूप से एक ही निदेशक व निदेशालय के अधीन स्थापित की गयी। किन्तु कालान्तर में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बीकानेर स्थित शिक्षा के केन्दों को क्रमशः बीकानेर से जयपुर से स्थानांतरित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, 01 जनवरी, 1998 से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मुख्यालयों का पृथक्करण कर अलग-अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार जब आयी 1998 के बाद तो यानी प्रारम्भिक शिक्षा को वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन वहां से एक बड़े संघर्ष के पश्चात् वह बीकानेर में ही रही। किन्तु जिस उद्देश्य से उच्च कार्यों का पृथक्करण किया गया, उन उद्देश्यों की पूर्ति इन्होंने नहीं की। इस हेतु पृथक्करण के समय निर्धारित कार्य व स्टाफ का पारस्परिक समायोजन किये जाने की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो कह रहे हैं कि हमने बहुत विद्यालय खोल दिये थे उस समय। इन्होंने विद्यालय खोले, वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी। एक विद्यालय ऐसा है प्राथमिक विद्यालय खोला और एकदम नया क्षेत्र, लेकिन आज उसकी जिद यह है कि वहां पर पर्याप्त संख्या भी नहीं है। अपने एक कार्यकर्ता को लाभ देने के लिये वहां पर प्राथमिक विद्यालय की घोषणा की और उसके घर में वह विद्यालय खोल दिया। वह आज भी स्थित है। अभी जब वहां पर संख्या न होने के कारण सरकार ने हटाने को कहा तो इन्होंने बवाल मचाया। मेरे पास, जिसकी बिल्डिंग है, वह मेरे पास आया कि मेरे इन्कम हो रही है, वह समाप्त हो जाएगी। यानी ऐसे विद्यालय इन्होंने खोल दिये। वहां पर अध्यापक नहीं, वहां कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। प्राइवेट बिल्डिंग में खोलकर अपनी वाहवाही ये लोग लूट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालय की इन्होंने क्रमोन्नति भी की। कागजी आदेश जारी किये जिसमें न तो मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही वहां पर अध्यापक और मंत्रालयिक कर्मचारी लगाये, न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाये हैं। ऐसे करके इन्होंने शिक्षा का बंटाधार करने का पूरा प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि पूर्ण स्वीकृत समस्त विद्यालयों में नॉर्म्स के अनुसार पदों को सृजित करके वहां पर भर्ती की जाये।

jyg/rtm/04.03.25/16.20/3a

माननीय सभापति महोदय, मैं बताता हूं कि इन्होंने जो स्कूलें खोली वहां पर स्थिति यह है कि वहां पर उस क्षेत्र में यानी कई स्कूलें ऐसी भी हैं, जहां पर दस-बीस मकान भी नहीं हैं।

दस मकान भी नहीं है और ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने विद्यालय खोले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि मेरे बीकानेर क्षेत्र में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय शुरू किया जाये क्योंकि वहां पहले था। आठवीं बोर्ड की स्थापना बीकानेर में की जाये क्योंकि सारा निदेशालय से काम होता है तो जब इधर होता तो वहां के कर्मचारियों को, वहां के प्रशासन को बहुत तकलीफ होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि इनके राज में डायरेक्टर कभी भी वहां नहीं बैठा, प्रायः जयपुर में ही मिलते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं निदेशक महोदय जी को कि वर्किंग डे में वो वहां निदेशालय में ही मिलते हैं। जो भी वहां जाते हैं उनकी वो वहां समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे शिक्षा विभाग का एक उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, जहां राजकीय विद्यालय है वहां पर कक्षा कक्षों के निर्माण, जीर्ण-शीर्ण कक्षों की मरम्मत पुनः कराने की मैं मांग रखता हूं। स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की मैं मांग करता हूं। राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हो क्योंकि इनके समय में तो वहां स्थिति यह थी कि वहां लोटा और बाल्टी भी नहीं मिलता था। इनकी स्थिति यह थी कि वहां जो विद्यार्थी पढ़ते थे वो घर से यानी पड़ोस से भी पानी मंगवाना पड़ता था। आज स्थिति थोड़ी बदली है जब से यह सरकार आयी है, बजट दिया गया है और वहां सुविधाएं मिलनी प्रारम्भ हो गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो बालिकाएं हैं, आज भी हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बच्चों के जो गार्जियन हैं, वो अपनी बालिकाओं को पांचवीं कक्षा के बाद वो बालकों के साथ नहीं बैठाना चाहते तो आज जो हमारी स्कूल है, हो सकता है संख्या के कारण भी हो सकता है और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि 15 नम्बर के नाम से जानी जाती है, वहां दो स्कूलें हैं, बालक और बालिकाओं की, तो मेरा निवेदन है कि उस बालिका स्कूल को उन बालकों के साथ नहीं मिलाया जाये, वो अलग रखी जाये क्योंकि अगर उसको एक साथ कर दिया तो मैं यह कह सकता हूं कि वो बालिकाएं उस स्कूल में नहीं जायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसका एकीकरण रोका जाये। मेरा निवेदन है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनाथ घाटी की जो स्कूल है, वो भवन छोटा है, मैं मानता हूं, वहां पर्याप्त स्थान नहीं है लेकिन उसके आसपास कोई भी स्थान देखकर, स्थानांतरित किया जाये, उसको बंद नहीं किया जावे, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, ये बात करते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में इन्होंने खूब कॉलेज खोली हैं, मेरे क्षेत्र में भी दो कॉलेज खोली हैं इन्होंने, एक कॉलेज खोली है मुरलीधर व्यास नगर में, एक कॉलेज गंगाशहर में, नाम तो गंगाशहर का, लेकिन वो खुली है भीनाशहर में। दोनों की स्थिति यह है कि कॉलेज खोल दिये, लेकिन वहां लेक्चरर नहीं। एक जो कॉलेज खोली वो सामुदायिक भवन में खोली गयी है, उसकी आज तक, यानी इन्होंने उसकी जमीन की परवाह नहीं की और वो केवल सामुदायिक भवन में चल रही है। वहां पर स्थायी स्टाफ

नहीं लगाया और कॉलेज खोलने की वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने कॉलेज खोल दी। ऐसी कॉलेज खोलने से क्या फायदा जहां लेक्चरर नहीं है, जहां मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं है? केवल एक प्रिंसिपल को डेपुटेशन करके बैठा दिया। ऐसी कॉलेज खोलकर इन्होंने शिक्षा के साथ मजाक किया है। इसमें मेरा निवेदन है कि जो कॉलेज खुली है वहां पर जमीन भी उपलब्ध हो उनको और वहां स्थायी स्टाफ लगाया जाये, क्योंकि कन्या महाविद्यालय वहां है और उस क्षेत्र की कन्याओं को लाभ मिले, इन्होंने जो किया है, जो कमी रखी है उसको हम दूर करें और उस महाविद्यालय को हम एक अच्छा महाविद्यालय बनायें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा महाविद्यालय इन्होंने गंगाशहर के नाम से खोला है। अगर कोई जाकर वहां पूछे कि गंगाशहर में महाविद्यालय है क्या, कोई नहीं बतायेगा, वो महाविद्यालय भीनाशहर में खुला है।

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, वहां जवाहर स्कूल है, इसलिए मेरा निवेदन है कि उस जवाहर स्कूल को उस कॉलेज के नाम में, जवाहर सिंह जी का नाम जोड़ा जाये और वहां भी स्थायी स्टाफ दिया जाये।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन जी शर्मा।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड और।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजकीय जितने भी महाविद्यालय हैं वहां पर कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जाये। मेरा निवेदन है कि वहां जितने भी कॉलेज है वहां पर स्वच्छ पानी...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): 000

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया।

आदरणीय दिलावर साहब,

रिश्ता हो न हो, भावना होनी चाहिए,
मोहब्बत हो न हो, बात होनी चाहिए।
यूं तो उलझे सभी अपनी उलझनों में,
पर सुलझाने की कोशिश भी होनी चाहिए।।

आपने बजट प्रावधान किया 2024-25 में ...(व्यवधान)... सुनो। 2024-25 के प्रावधान में आपने जो घोषणाएं की, 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन, 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ, 50 प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की, की न? यह तो सही है? आप यह बता दें कि आपने जो बजट भाषण में 2024-25 में घोषणा की, कितनी प्राइमरी स्कूल खोली या बंद की? आप की बता दीजिये। कितने विषय खोले? यह आप बता देना। इस

बजट घोषणा में, 2024-25 में की वो कतई पूरी नहीं हुई। फिर भी आप उन्हीं बजट घोषणाओं को 2025-26 में क्या बता रहे हो? वो ही बता रहे हो। 2025-26 में भी वही बता रहे हो। 2025-26 में भी आप वो ही बता रहे हो ना? 50 प्राथमिक विद्यालयों को आठवीं तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक तक, पहले की तो खुली नहीं, पहले की तो आपने 400-450 प्राइमरी स्कूल बंद कर दी और यह नई घोषणा है, उसकी भी वो ही दुर्गति हुई है। ...(व्यवधान)... आप तसल्ली रखो, आपको तो जवाब देना है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आप पंडित हो, सही बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप बीच में बोलोगे तो ठीक नहीं रहेगा। आपको तो जवाब देना है न? बार-बार उठोगे तो थक जाओगे, थक जाओगे। मेरी बात को जवाब देते-देते थक जाओगे, आप आराम से बैठे रहो।

आप शिक्षा को किस दृष्टिकोण से ले जाना चाहते हैं? आपका सोच क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? आप अपनी विचारधारा के हिसाब से पूरा सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ कर पूरे राजस्थान में छोड़कर जाने वाले हैं। आप अपने मन में, आपकी मजबूरी है, आपके नेताओं की कि आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन मन में जो महात्मा गांधी के प्रति नफरत है न वो बाहर निकल ही नहीं रही है। जुबान पर महात्मा गांधी, मन में महात्मा गांधी नहीं है और इसीलिए महात्मा गांधी के नाम से जो इंग्लिश स्कूलें चालू की, नाम से नफरत है आपको, इंग्लिश स्कूल से नफरत नहीं है, तो नाम बदलो न, इंग्लिश स्कूल तो रखो। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि आप नाम रखें, नाम बदल दें, आपको शौक है नाम बदलने का, आप नाम बदल दें, आप बच्चों की ड्रेस कोड बदल दें, यहां तक भी कर दें चाहे सरकार का पैसा जहन्नुम में चला जाये कि काली साइकिल है तो उसको पीली कर दो, थोड़ा बहुत तो सोचो, इनसे कोई शिक्षा में फर्क पड़ने वाला है? साइकिल का कलर बदलने से, ड्रेस बदलने से, महात्मा गांधी का नाम बदलने से आप उच्च स्तर पर पहुंचे जाओगे? मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, विचारों से इस राजस्थान के शिक्षा मंत्री, विचारों के साथ-साथ भाषा से जाने जाते हैं। हर बच्चा, हर बच्चा जो शिक्षा में अनुसरण करता है, वो आपने जो पाठ्यक्रम किया, उस पाठ्यक्रम में आपने जो सामग्री दी उसको पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन करता है। अपने परिवार के हिसाब से भी परिवार वाले भी चाहते हैं कि कैसा ज्ञानवर्धन हो, जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया वो भले ही आप अपनी विचारधारा के हिसाब से करना चाहते हो या करोगे वह दृष्टिकोण तो दूसरा है लेकिन आप मेहरबानी करके भाषा में तो परिवर्तन कर लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी जैसे ही बोलते हैं और जैसे ही बच्चे सुनते हैं और घर आकर कहते हैं वो, मम्मी, आज हमारे शिक्षा मंत्री ने यह कहा।

MLS/RTM/04.03.2025/16:30/3b

वह मां ऐसा डांटती है उनको, ''नहीं, यह सीखकर मत आना।'' आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि उन बच्चों पर मेहरबानी करो। शिक्षा मंत्री की ही भाषा अगर संयमित न होगी

तो बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए मेरा आपसे, व्यक्तिगत भी आप हमारे डिविजन के हैं, आपसे प्रार्थना है कि मेहरबानी करके, क्योंकि आपकी भाषा का, आपके बोलने का या किसी भी मंत्री के बोलने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मैं पहले भी कह चुका, मुख्य मंत्री जी की प्रतिष्ठा पर आघात लगता है।

अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ो आप, मुख्य मंत्री जी की तो रखो। यूं क्या करते हो? मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप अपने आप में ...(व्यवधान)... बोल लेने दो न, फिर वो कह देंगे, कृपया प्लीज बैठो। आंकड़ों की बात मैंने बजट 2024-25 की बता दी आपको, 2025-26 की बता दी। यह सही है कि प्रिंसिपल और उसके इक्विलेंट पद जो हैं, सैंक्शंड पद हैं आपके 17 हजार 912 और लगे हुए हैं 10 हजार 213, आपके लैक्चरर फर्स्ट ग्रेड के पद हैं 55 हजार 784 और लगे हुए हैं 36 हजार 972, आपके सीनियर टीचर्स जो हैं 1 लाख 9 हजार 542 और लगे हुए हैं 75 हजार 550, आपके टीचर लेवल II हैं 1 लाख 2 हजार 758 और लगे हुए हैं 90 हजार 160, आपके टीचर लेवल I 1 लाख 41 हजार 340 हैं और लगे हुए हैं 1 लाख 28 हजार 928।

आपके जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं 18 हजार 890 और लगे हुए हैं 16 हजार 303, इसी प्रकार आपके लाइब्रेरियन का देख लो, जूनियर असिस्टेंट का देख लो, सब पदों में है। यह भी सही है कि ये इसी साल में नहीं हुए हैं खाली, पिछले के भी हैं, लेकिन इन पदों को भरने का क्या रोडमैप है, यह बता दें आप। ये जो पद हैं, कितने साल में भरोगे? गये साल में तो कुछ नहीं हुआ। यह साल आ गया, इसमें क्या करोगे? यहीं आप भाषण दो तो बता देना कि इतने हजार पद जो खाली हैं, उनमें से हम इतने हजार भर देंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे और आपका आभार प्रकट करेंगे।

मेरा एक और निवेदन है। अभी-अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी के विभाग, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा था कि डाबी में कॉलेज खोला जाना चाहिये। कॉलेज की घोषणा हो गयी। मुझसे गलती यह हो गयी कि बून्दी जाकर मैंने समाचार पत्रों में दे दिया कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने डाबी में कॉलेज खोला तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देखो आप, कोटा के जितने भी बीजेपी के नेता थे, नहीं, इन्होंने नहीं खुलाया, यह तो हमने खुलाया है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं मुख्य मंत्री जी को, उसमें क्यों ऐतराज करते हो? जब ही मैं कहता हूं कि डिविजन के अलग-अलग मुख्य मंत्री हैं। मैंने कहा था न कि अलग-अलग डिविजन में अलग-अलग मुख्य मंत्री हैं।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने बन्द करने का फैसला किया। उर्दू का तो आपने सुन ही लिया अभी। महात्मा गांधी जो इंग्लिश स्कूलें खुली हैं न, हो सकता है, हमारे टाइम पर जो खुली हों, उनमें कुछ कमियां रही हों, आप खोलेंगे, उनमें भी कमियां रहेंगी, आप कोई नया काम करेंगे तो पूरा तो करके आप भी नहीं जाएंगे, दूसरी सरकार आयेगी, वह करेगी। एक तो यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जिन बच्चों का भविष्य उन इंग्लिश स्कूलों में जो सुधरा है न, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप

चलना मेरे साथ नमाना में जो वहां की महात्मा गांधी सीनियर हायर सैकंडरी स्कूल है, चमचमाते बच्चे हैं गांवों के। प्रिंसिपल जो उनको इंग्लिश में बात करवाता है न, आप भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता।

आप उसकी गुणवत्ता को देखो। आप महात्मा गांधी के नाम से नफरत मत करो। आप गुणवत्ता को देखो। चलें आप बताइये, आप शिक्षा मंत्री हैं, हर जगह हर गांव में, ज्यादातर गांव जो हैं, उनमें प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं कि नहीं? चल रही हैं न। वही टाई पहनकर, सूट पहनकर बच्चे आते हैं। क्यों आते हैं? वहां इंग्लिश में पढ़ाते हैं न वो।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): समाप्त करें? चलो आप कहते हैं तो दो मिनट में समाप्त कर देते हैं। अपना इसमें भी विवाद नहीं है। जो मोटे रूप में कहना था...

श्री सभापतिः श्री गोपाल लाल जी शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक मिनट रुकें। एक आखिरी बात चलो एक शेर से ही समाप्त कर देता हूं मैं। शेर सुन लो, माननीय शिक्षा मंत्री जी।

उजाले अपनी यादों में, अपने साथ रहने दो,
न जाने किस गली में अपनी शाम हो जाये।

इसलिए भावना ठीक रखो। भावना ठीक रखो। इधर वालों से नफरत मत करो।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, आपने शिक्षा व उच्च शिक्षा की अनुदान मांग संख्या 20, 21, 22 की चर्चा पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सर्वप्रथम, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने बजट में शिक्षा क्षेत्र को पर्याप्त महत्व दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैंने एक छोटी-सी मांग की, उसमें मेरे माण्डलगढ़ को नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा के लिए मेरे क्षेत्र की जनता और युवा वर्ग में बहुत-बहुत खुशी है। मैं और मेरी जनता की ओर से व्यक्तिशः आभार।

तलवारों की धार पर इतिहास हमारा चलता है,
जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है।

शिक्षा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए और इसके अच्छे परिणाम लाने के लिए ऐसा बजट राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने दिया है। जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की घोषणा एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बजट में जहां वैदिक गुरुकुल की स्थापना का संकल्प है, वहीं 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, प्रदेश में तीन स्थानों पर डिजिटल प्लैनेटोरियम व साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना है।

इन संकल्पों से स्पष्ट होता है कि सरकार प्रदेश के विद्यार्थी वर्ग को नित नूतन, चिर पुरातन दोनों से जोड़कर उनके जीवन को नयी दिशा देना चाहती है। प्रदेश में 3 नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज, 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। नये बालिका सैनिक स्कूलों की घोषणा भी हुई है। 50 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक और 100 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा स्वागत योग्य है। विद्यालयों में अब आधारभूत सुविधाएं व कक्षा कक्षों का निर्माण विधायक, सांसद, डी एम एफ टी व जनजाति के बजट से अधिकांश होता रहा है, परन्तु इस सरकार ने इस बजट में विद्यालयों के कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, शौचालय निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्रदेश के 15 हजार विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति महोदय, मैं इन सभी प्रावधानों के लिए सरकार के मुखिया माननीय भजन लाल जी शर्मा को एक बार फिर बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी बून्दी से आने वाले माननीय विधायक जी कह रहे थे कि पहले इनकी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा विभाग को नौसिखिये वैज्ञानिक की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया था।

MKD/RTM/04.03.2025/16:40/3c

विगत सरकार ने बिना आधारभूत व्यवस्था किये, बिना नई भर्ती किये, हिन्दी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिया था और कैसे बनाया, जादूगर ने एक छड़ी घुमाई, यहां बजट में एक जादूगर एक छड़ी घुमाता था और आप सब मेजें थपथपाते थे और काम जीरो, जीरो, जीरो होता था, यह आपके सामने हैं। भवन नहीं, स्टाफ नहीं, विद्यार्थी नहीं, अध्यापक नहीं केवल बाहर का बोर्ड बदला और स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गये।

विगत सरकार ने कहा था कि हम पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बन्द किये विद्यालय वापस खोलेंगे? क्या हुआ? उनमें से कितने खोले? मैं प्रतिपक्षी मित्रों से पूछना चाहता हूं, आपको जानकारी देनी चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या-क्या काम किया, अभी आप जानकारी दीजिये।

विगत सरकार में स्कूल के भवन में कॉलेज खोल दिये। चार कमरों के भवन पर कॉलेज का बोर्ड लगा दिया, प्रिंसिपल नहीं, कहीं प्राध्यापक नहीं, कहीं विद्यार्थी नहीं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नियुक्त कार्मिकों के वेतन व विद्यार्थियों का अनुपात विगत वर्षों में क्या रहा। इस पर विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि विगत सरकार ने केवल पूरे पांच साल में कृपापात्रों को उपकृत किया है, पूरे पांच साल में यही काम किया है।

पिछली सरकार में एक विश्वविद्यालय की मंजूरी का भी आया। हम भी इस सदन में थे

और आप भी थे।

श्री सभापति: प्लीज, मंत्री महोदय।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): चर्चा के दौरान, तत्कालीन प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने मामला उठाया कि विश्वविद्यालय की प्रस्तावित भूमि पर अभी भवन तक नहीं बना है, भूमि समतलीकरण का काम चल रहा है, परन्तु रिपोर्ट मंगवायी गई, सरकार को बिल वापस लेना पडा। ये थी, विगत सरकार की शिक्षा की नीति, स्थिति, आपकी मनोस्थिति।

मान्यवर, शिक्षा भावी पीढ़ी के संस्कार का माध्यम है, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप का पाठ नहीं पढ़ाया। हमने अकबर महान का पाठ पढ़ा दिया। हमने शिवाजी और सम्भा जी का इतिहास नहीं पढ़ाया। हमने बाबर, औंरगजेब की वंशावली बच्चों को याद करा दी। हमने पन्नाधाय, भामाशाह छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास, अमर सिंह, राणा सांगा को भूला दिया। नई पीढ़ी विदेशी हमलावरों का इतिहास पढ़कर गौरव का अनुभव।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़। हमारे प्राचीन गौरव को गौण करके मुगलकाल को स्वर्ण युग बताया गया। शिक्षा में पाठ्यक्रम के नाम पर तथाकथित बुद्धिजीवियों ने षड्यंत्र किया है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के शिक्षा विभाग की सम्बन्धित मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं- पहले की सरकार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिये थे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निम्न विद्यालयों को अवलिम्ब अगले सत्र में वापस शुरू कराने का आदेश फरमावे:-

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इटावा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमारों का झौपड़ा, झावल, बिल्या का झौपड़ा, भान का खेड़ा, चौरड़ी, हस्तीनापुर स्कूल को डीमर्ज कर वापस खोला जाए।

मेरे क्षेत्र में निम्नलिखित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न संकाय खोलने का श्रम करावें:-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माल का खेड़ा, होड़ा, बरूणी, महुआ, खटवाड़ा, जोजवा में कृषि एवं जीवन विज्ञान संकाय खोलने का आदेश करें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडपुरा व ककरवा घाटी में विज्ञान संकाय खोला जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांडलगढ़ में भूगोल संकाय खोला जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुटेवा में वाणिज्य संकाय, राजकीय उच्चमाध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ में विज्ञान संकाय के स्थान पर कला संकाय खोला जाए। राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय, मांडलगढ़ व राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया में कम्प्यूटर विज्ञान व संस्कृत संकाय खोला जाए।

मैं मांग करता हूं कि आज कम्पीटिशन है तो बच्चों के लिए हर पंचायत में एक पुस्तकालय खोला जाये। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बागल्या की झौपडा, उम्मेदपुर, श्रीपुरा, देवीपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक

विद्यालय, रेणवास, किशन जी का खेड़ा, भैरू खेड़ा, उंदरो का खेड़ा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराए जाए।

मान्यवर, मैं आपका और सदन का ध्यान वर्तमान में शिक्षा जगत पर आने वाले संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले भूमि माफिया, खनन माफिया, टोल माफिया, वन माफिया सुने थे, लेकिन अब शिक्षा माफिया पैदा हो गये हैं। शिक्षा क्षेत्र पवित्र का भी अब व्यापारीकरण करके दूषित किया जा रहा है। निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों व छात्रों एवं अभिभावकों को शोषण से मुक्त करने के पुख्ता प्रबन्ध किया जाए। निजी संस्थाओं के मनमाने पाठ्यक्रम व मनमानी फीस, इस पर नियंत्रण कैसे हो, कई छात्र एवं अभिभावक इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हमें इस दर्द को समझना चाहिए। मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो,
जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो,
शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं,
देश व प्रदेश में शिक्षा के प्रसार से जन जीवन खुशहाल हो,
युवा वर्ग को नई राह मिले,

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री मोतीराम जी। केवल तीन मिनट।

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुख्य मांग संख्या 20, 21 और 22 प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभागों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय, विद्यार्थियों के हित के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करना बहुत आवश्यक है। यूपीएस, जावल, ग्राम पंचायत मगरीवाड़ा, यूपीएस गोरेली, ग्राम पंचायत मकावल, यूपीएस सांगरली, ग्राम पंचायत अनादरा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नवीन विद्यालय खोले जाने की अति आवश्यकता है, वांती, ग्राम पंचायत मारोल, पोसीतरा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत हो गये हैं, किन्तु यहां स्टाफ की कमी है, जिसके कारण विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में परेशानियां होती हैं। वे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करजीया, ग्राम पंचायत दतानी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा पी, गुंदवाडा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वासाडा ग्राम पंचायत जैतावाडा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनापुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरणी अमरापुरा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेवदर में अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद खाली हैं, वे निम्नानुसार हैं, बांट, जेतावाडा, मण्डार, गुंढवाडा, सोनेला,

मगरीवाडा, जीरावल, अनादरा, दोलपुरा, लूणोल, मालगांव, जोलपुर एवं पादर।

मान्यवर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेवदर में कृषि संकाय खोला जाना है। यह संकाय खोला जाना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है।

मान्यवर जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के महाविद्यालय में निम्नांकित कमियां हैं, जिन्हें दूर करना विद्यार्थियों के हित में है। वहां स्टाफ की बहुत कमी है। बालक एवं बालिकाओं को कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड रेवदर से साढ़े चार किलोमीटर महाविद्यालय दूर पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करता हूं कि बालिकाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बस की सुविधा करें, ताकि उनको आने-जाने में सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीवाराम जी चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने एक बालिका छात्रावास खोलने की सौगात दी है, मैं उन सभी क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार को और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मुझे लगता है, आप जल्दी घंटी बजाने के मूड में हैं। इसलिए पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ स्कूलों की मांग है, वह निवेदन कर देना चाहता हूं। प्राथमिक विद्यालय, नये विद्यालय खोलने हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रेबारियों की ढाणी, रेबारियों का गोलिया, खेज़डियांली, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोलियों की गढ़ी, होती गांव, राजकीय बालिका प्राथिमक विद्यालय, जोधावास।

Bhs/Rtm/04.03.25/16.50/3d

राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामढेली भीलों का वास, बड़वल यह तो नवीन प्राइमरी विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। दूसरे, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर और चितलवाना में जब 2003 से 2008 में हमारी सरकार थी, 148 प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करके उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय की सरकार को भी आप अंदाजा लगाइए सभापति महोदय, अगर 148 स्कूल कई सालों-साल से प्राइमरी चल रही थी तो उस समय उन गांवों की और उन बालकों की, उन बच्चों की, उन छात्र-छात्राओं की क्या स्थिति रही होगी? एक ज़माना था कि बालिकाएं स्कूलों में नगण्य थी। 1970 की बात है, मैं जब जिस स्कूल में पढ़ता था उस समय हमारे स्कूल के छात्र संख्या 600 के बराबर थी और उसमें एक बालिका केली नाम की बच्ची पढ़ती थी। आज व्यवस्था उसके बिल्कुल विपरीत हो गयी है प्रत्येक स्कूल में आप जा करके देखें तो बालक और बालिकाओं की संख्या लगभग बराबर के चल रही है आज जो व्यवस्था हमारी शिक्षा की चल रही है उसमें

बहुत कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हमारे आठवीं, दसवीं और बारहवीं के जो विद्यालय है, उसमें बालक और बालिकाएं साथ पढ़ती हैं।

सभापति महोदय, 12वीं में पढ़ने वाली बालिका 17-18 साल की हो जाती है। आज अपन ऐसी शर्मसार घटनाएं अखबारों के माध्यम से सुनते हैं, इस सब पर रोक लगाने के लिए आने वाले समय में बालिकाओं के लिए बालिका विद्यालय ही अलग हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला शिक्षक हों और उनके साथ बालिकाओं की शिक्षा चले, ऐसी मैं मांग करता हूँ। पांचवीं से आठवीं में मेरे वहाँ तीन विद्यालय हैं बाकी सारे क्रमोन्नत हो गए थे 2003 से 2008 में। एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोटेश्वर केसूरी रह गया, एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलियों का बास, साकरिया और एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमा की ढाणी अगार, ये तीन विद्यालय जो हैं वो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करवाना चाहता हूँ। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आठवीं से दसवीं में जो विद्यालय क्रमोन्नत करने हैं उनकी सूची निम्न है - राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीलू, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वापा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजोल का गोलिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दीनपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेरोल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कागोड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भाटवास, राज़कीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरणाय का गोलिया। सभापति महोदय यह अरणाय का गोलिया जो स्कूल है, सन 1952 में खुली थी और इस स्कूल में मेरे ही गांव के श्री उम्मेदाराम जी विश्नोई पांचवी तक पढ़ाई कर के आई.जी. की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस स्कूल को पांचवीं से आठवीं में हमारी सरकार में 2004 में करवाई थी ये हालत इनकी सरकारों की थी। आज जिस गुजरात पैटर्न से अगर उसी पैटर्न के नक्शे से हमारे राजस्थान में भी अगर शिक्षा की व्यवस्था करें तो बहुत कुछ हो सकता है। आज हम एक शिक्षक को लाख-सवा लाख रुपये सैलरी देते हैं। हजारों हमारे युवा बी.ए., बी.एड. किये हुए बेरोजगार हैं। एक मास्टर की सैलरी में आज अगर 30 और 40 हजार रुपये की व्यवस्था से अगर आप नयी भर्ती करते हो तो चार-पांच शिक्षक आपको उस एक व्यक्ति की सैलरी में मिल सकते हैं। ऐसा कानून में संशोधन करके नई भर्तियां अगर इस प्रकार से की जाए तो हमारे प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मेरा यह निवेदन है।

शिक्षा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा बड़ौदा के पूर्व महाराजा गायकवाड़ साहब ने उस समय उनके राज्य में उनकी असेंबली चलती थी और उस समय गायकवाड़ के राज़ में अगर कोई परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो एक रुपया दंड था। सभापति महोदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं तो उस समय के जो बच्चे पढ़े हैं वो आज पूरे विश्व में वो और उनका परिवार अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वो सब चले गये और वहां जा करके अपना कारोबार शुरू किया, नौकरियां की, उसी स्तर से हमारे यहां राजस्थान में अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती तो आज हमारे बालक- बालिकाओं की शिक्षा का जो प्रतिशत है 60-65%, वो 99% पर पहुँच जाता।

सभापति महोदय, इस प्रकार से अभी जो वर्तमान में कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी है मान लेते हैं लेकिन जो शिक्षक, शिक्षा में गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसको इतना पवित्र माना गया है उस रिश्ते को बरकरार रख करके जो शिक्षक बालकों को पढ़ाते हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जो सिर्फ गांवों की ढाणियों में जो दूरदराज की स्कूलें हैं, उसमें 15 दिन में एक बार जा करके दस्तख्त करके आ जाते हैं और उसमें 10-12 बच्चे हैं या उनके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको बैठा देते हैं कि मेरे बदले में तू इन बच्चों को पढ़ा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है ऐसे लोगों को सरकार के ध्यान में जब ये बात लावें तो ऐसे लोगों को तुरंत शिक्षा की नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। आप ने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक हमारे मुख्य मंत्री जी के लिए दुआ बोल देता हूँ, हमारे मित्र भी बोले हैं, कि 'फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी, जिसको रोशन खुदा करे।' हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की नीयत में खोट नहीं है, ये पूरे प्रदेश को अपने पूरे परिवार की तरह संचालित करते हैं और परिवार की तरह सबको समय और प्रेम देते हैं। बजट में तो इतना दिया है मैं गिनाने जाऊं तो काफी समय लग जायेगा इसके लिए मेरी ओर से, सांचोर की जनता की ओर से खूब-खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः आपको और हमारे पूरे मंत्री मंडल को धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री भीम राज भाटी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं आपका। मेरा निवेदन है सबसे पहले तो कि अंग्रेजी स्कूलें बन्द करने के बारे में सोच रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से इतना ही प्रेम है, महात्मा गांधी के हिसाब से अगर आपके दिल में वास्तव में आदर है, वास्तव में आप समझते हो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे तो उन अंग्रेजी स्कूलों को भले ही आप बंद कर दीजिये लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता दिला के उन स्कूलों में राजस्थानी भाषा में पढ़ाई कराना चालू कर दीजिये, यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान में स्कूलें बंद कर दी गई हैं, 429 स्कूलें बन्द की हैं तो मेहरबानी करके शिक्षा के महत्व को कम नहीं करें शिक्षा बहुत जरूरी आइटम है। अगर आदमी शिक्षित है तो वो बहुत कुछ कर सकता है तो ये स्कूल जो बंद की है आपने वो मेहरबानी करके वापस चालू करें। मेहरबानी करके हमारे नया गांव में डाकियो की ढाणी में एक स्कूल थी उस स्कूल के बच्चों को छह किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वो स्कूल बंद कर दी। शेखों की ढाणी में स्कूल नहीं है, उन बच्चों को छह किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खुटाणी में 150 बच्चियां छह किलोमीटर दूर मांडावास पढ़ने के लिए जाती है उस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है तो खुटाणी की स्कूल को भी क्रमोन्नत करने की मेहरबानी करें। मंडिया में सरकारी स्कूल है, उसको भी क्रमोन्नत करने की मेहरबानी करें। मंडली खुर्द में भी स्कूल है उसको भी क्रमोन्नत करने की मेहरबानी करें। मंडिया की स्कूल की मरम्मत, स्कूल

की जो बिल्डिंग है वो बहुत जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है उस स्कूल को भी रिपेयर करने की कृपा करें। होदियों की ढाणी में स्कूल 20 साल पहले खुली थी वह स्कूल अभी भी प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल को भी क्रमोन्नत करने की मेहरबानी करें।

माननीय सभापति महोदय, पाली विधान सभा क्षेत्र में एक मुकुंदपुरा गांव है उस मुकुंदपुरा गांव की स्कूल की हालत यह है कि वह स्कूल की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कभी भी जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसी तरह मेरे पाली विधान सभा क्षेत्र में पांच पदरिया गांव हैं, बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पर भी जो स्कूल है वो भी जब खुली, जब खुली उसको भी आज दिन तक क्रमोन्नत नहीं किया गया। मेहरबानी करके माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से कि भाकरी वाला गांव में कृषि और विज्ञान सब्जेक्ट खोलने की मेहरबानी करें। खूंडाबास गांव में विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो खोलने की कृपा करें। खूंडाबास गांव के छह किलोमीटर की दूरी में किसी भी विद्यालय में विज्ञान का विषय नहीं है। विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों की जो कमी है उन अध्यापकों की कमी को, जो रिक्त पद हैं, उनको भी भरवाने की कृपा करें। मेहरबानी करके पुख्तारी गांव में जो स्कूल की चारदीवारी है वह बहुत नीचे है तो उसमें कई लोग कभी तो कोई जानवर उसमें घुस जाते है, कभी कुछ वो कर देते हैं तो उस स्कूल की चारदीवारी को भी मेहरबानी करके थोड़ा ऊंचा उठवायें ताकि हम लोग कुछ कर सकें। दूसरा, मंडली दर्जियान की स्कूल में भी क्लास रूम की कमी है राणा की स्कूल में भी क्लास रूम की कमी है।

Kas/rtm/04.03.2025/17.00/3e

उसके लिये मैं राज्य सरकार से, माननीय वित्त मंत्री महोदय से और उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस स्कूल के कमरों के लिये मेहरबानी करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लालाराम जी बैरवा।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 20, 21 व 22 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि किसी राष्ट्र को अगर समझना है, तो उसके जीवन मूल्यों को, उसकी संस्कृति को और उसकी शिक्षा को समझ लीजिए, राष्ट्र समझ में आ जायेगा। हमारे भारत की शिक्षा पद्धति को बीच के कालखंड में योजनागत तरीके से बदला गया। महाराणा प्रताप को पढ़ाना था, भगत सिंह को पढ़ाना था, उसकी जगह अकबर और बाबर जैसे विषयों को पढ़ाया गया। हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो शिक्षा से जुड़ी रहती है, वो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस प्रकार का निर्माण उनका होता है, उसी प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति, जो पहले गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, जिसमें जीवन मूल्यों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी और वहां युवा शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिये समर्पित होकर शिक्षा का उपयोग करता था, लेकिन आज की शिक्षा केवल आर्थिक रूप से निर्धारित हो चुकी है। हमारे अभिभावक भी और हमारे समाज के प्रबुद्धजन भी हमारी आने वाली पीढ़ी को केवल आर्थिक रूप से, पैसा कमाने की मशीन कैसे बनाया जाये, उसके लिये उनको तैयार किया जाता है। मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में आज भी जिस प्रकार का माहौल देखा जाता है, राष्ट्र में जिस प्रकार से युवा पीढ़ी भटक रही है, जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हर किसी के बहकावे में आकर जल्दी लिप्त हो जाती है, जिस प्रकार से नशे के व्यापार में नीचे तक चली जाती है। मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज भी हमारी शिक्षा पद्धति में जीवन मूल्यों को, राष्ट्र भक्ति को और राष्ट्र धर्म को समझाते हुए शिक्षा देनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी शिक्षा प्राप्त कर, हमारे अभिभावक मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा कर उनको पढ़ाते-लिखाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई को हमारे युवा यहां शहरों में आकर पढ़ाई में खर्च करते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में चले जाते हैं। विदेशों में जाकर हमारे ज्ञान को, जो ज्ञान देश के लिये काम आना चाहिये, देश के लिये पैसा कमाना चाहिये, उनका पहला धर्म राष्ट्र धर्म बनता है, जीवन मूल्यों पर पढ़ाई नहीं होने के कारण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की पढ़ाई नहीं होने के कारण विदेशों में जाकर वो वहां पर लुप्त हो जाते हैं। वहां जाकर वो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य भी भूल जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में हमारी राष्ट्रीयता का और जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाना भी आज के समय में बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मेरे शाहपुरा क्षेत्र में जो स्कूलें डीमर्ज हुई हैं, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर करना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत बोरड़ा में प्राथमिक विद्यालय 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद भी कांग्रेस शासन काल में उसको मर्ज कर दिया गया। इससे वहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। बहुत दूरी पर जाकर उस स्कूल को मर्ज किया गया है। ऐसे डीमर्ज स्कूलों की तुरंत प्रभाव से जांच करके उनके विद्यालयों को वापस खुलवाने का काम करना चाहिये। सभापति महोदय, घुमंतू समाज के बच्चों का स्थाई स्थान नहीं होता है, इस कारण से वो लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। घुमंतू जाति के बच्चों के लिये वहां पर आवासीय विद्यालयों को संचालित करना चाहिये, जिससे घुमंतू जाति के पढ़ने वाले युवा उसका लाभ ले सकें। कांग्रेस शासन काल में घुमंतू जातियों के शैक्षणिक विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। घुमंतू जातियों को समाज की मुख्य धारा में मिलाने एवं उनके समावेशी विकास के लिये, उनके शैक्षणिक विकास की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरे शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में एबीएल रिसर्च सेंटर, गतिविधि

आधारित शिक्षण सन्दर्भ केन्द्र की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की नींव होती है। उसको मजबूत करने के लिये पंचायत या संकुल स्तर पर एबीएल रिसर्च सेंटर अर्थात गतिविधि आधारित शिक्षण सन्दर्भ केन्द्र को प्रभावी ढंग से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये हमें भारतीय ज्ञान, परम्परा के अनुसार भारतीय मनोवैज्ञानिक और शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर काम करना पड़ेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट के माध्यम से भारतीय ज्ञान, परम्परा पर आधारित शोध केन्द्रों को बढ़ावा देना होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शिक्षा विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रभावी प्रशिक्षण के लिये भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनकी व्यवस्था के लिये भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अगर प्रभावी बनाना है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रभावी प्रशिक्षण के लिये मजबूत व्यवस्था किये जाने पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिये योग्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी आदमी लगाने पडेंगे। हमने देखा है कि कांग्रेस शासन काल में ..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट का समय है।

श्री सभापतिः दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): 10 मिनट का समय दिया है।

श्री सभापतिः 8 मिनट हो गये हैं।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): कांग्रेस शासन काल में केवल अपने चहेते लोगों को इन पदों पर लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बहुत बड़ी कमी आई है। अगर हमें अमृत काल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें राजस्थान की शिक्षा की नींव को मजबूत करके अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सीएसजी ग्रांट 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर दिलाना चाहूंगा। प्रत्येक विद्यालय में समग्र शिक्षा का बजट पारित होता है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी मांग है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों की प्रतिस्थापन तथा विद्यालय संस्था एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का भी प्रावधान है।

Msk/rtm/04.03.25/1710/3f

विद्यार्थी हित में विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सहभागी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक, भौतिक आवश्यकताओं

की पूर्ति करना है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय को इस प्रकार सीएसजी की ग्रांट 25 प्रतिशत ही प्राप्त हुई है और 75 परसेंट आवंटित किये जाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति जी, प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए वैंडिंग इंसीनरेटर मशीन लगाये जाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: श्री समरजीत सिंह जी।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति जी, पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: समय हो गया, 10 मिनट 12 सैकेण्ड हो गये।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21, 22 पर आपने जो बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आभारी हूं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करने के लिए यहां इकट्ठा हैं और उसी के बजट की अनुदानों मांगों के पास करने के लिए। शिक्षा हमारा फंडामेंटल अधिकार है, हमारा राइट है और प्रत्येक सरकार जो भी पॉवर में आती है, अपनी तरफ से एक प्रयास करती है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाये। शिक्षा की सुविधाएं दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): समरजीत सिंह जी, एक सैकेण्ड। माननीय सभापति महोदय, जूली साहब, आज शिक्षा की डिमांड पर बैठे हैं, सभी माननीय सदस्यों की ओर देखें। बहुत पुराने अनुभवी हैं। नजर घूमायेंगे तो देखेंगे कि हमारा आने वाला जो भविष्य है, वह थोड़ा कम है। इस पर आप और हम दोनों गंभीरता से विचार करें।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): उधर भी कम लग रही है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने दोनों तरफ का कहा है, एक तरफ का नहीं कहा है।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उच्च शिक्षा मंत्री जी भी हैं। शिक्षा मंत्री जी सो गये थे, आप खुद जगाकर गये हैं। तीन ही मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल गायब है तो आप शिक्षा पर क्या चर्चा करेंगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जिनको करनी है, वे नहीं हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम सारी व्यवस्था फिट कर देंगे।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि चिंतित नहीं हैं। जो चिन्ता कर रहे हैं, उनकी तो आप सुन लें। आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप बात पहुंचाइयेगा। मंत्री जी विराजें हैं।

हर सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है। इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। कई बार जब मैं पढ़ता हूं कि अमरीका जैसी डवलप कंट्री है, वहां पर शिक्षा सरकार का ही दायित्व है। सरकार ही चलाती है, वहां प्राइवेट सेक्टर की स्कूल/एजुकेशन नहीं है। होना यही चाहिए कि सरकार के कंट्रोल में हो, सरकार की स्थिति

बने, आप सभी ने प्रयास किये हैं। हमारी सरकार ने भी किये हैं। चाहे पिछली सरकार ने सारी स्कूलों को 12वीं कर दिया। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि कुछ ऐसी योजना लाएं ताकि जो प्राइमरी स्कूल हैं, 20-30 साल से चल रही हैं, उन स्कूलों का भी आप कुछ सोचिए, बच्चों की स्ट्रैंथ अच्छी हो, उन स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने का प्रयास में आप लोगों को प्राइमरी से मिडिल करना चाहिए।

कई बार शिक्षा के बारे में सोचते हैं। हमारे बच्चे आईआईटी की परीक्षाएं देते हैं। एक लाख में से हजार बच्चे सलेक्ट होते हैं और 99 हजार रिजेक्टेड होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी तो मान्यता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए आप आज जो राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, हमने इतना फंड लिया है। आप एजुकेशन सेक्टर में लाइये। जब तक हम हमारी पीढ़ियों को तैयार नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर की कंपनियां तो आकर, कमाकर चली जाएंगी, वे नौकरी पर भी लगायेंगी तो अपने लोगों को लगायेंगी। जब तक हम हमारे यहां के ह्यूमन रिर्सोसेज को तैयार नहीं करेंगे, वह तैयार कब होगा? जब हमारे यहां अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छी शिक्षा संस्थान स्थापित करंगे। एमबीएज हो, इंस्टीट्यूट हों। अभी सरकारों ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज किये, तो आप देखना कि आने वाले समय में हर जिले में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी।

इस तरह से मेरा सुझाव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया जाए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा राजस्थान की जनता को ही होगा, अंत में हम सब को होगा। लाइसेंस सिस्टम है, स्कूलों के लाइसेंस के लिए भटकना पड़ता है, उसको भी कम किया जाए। शिक्षा की स्थिति तो यह है, मैं अभी पत्रिका की यह न्यूज देख रहा था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की न्यूज है। कक्षाएं नहीं लगतीं, परिणाम गिर रहा है, सिलेबस तक उपलब्ध नहीं है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से टीचर्स के पद, हम सभी अगर अन्दर झांककर देख लें या हम पार्टी-पक्ष की बातें कर लेंगे, पर जब हम गांवों में जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में पद खाली पड़े मिलते हैं और जो सिटी एरियाज हैं, उनमें पद ज्यादा भरे पड़े हैं और ग्रामीण इलाकों के पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री जी, विराजें हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई नीति बनायें कि ज्यादा से ज्यादा हर स्कूल में प्रपोशनली बच्चे, टीचर्स के अनुपात में,, यह स्थिति रहे। वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशंस आपने कर दिये। सभी एक जगह बैठे हैं। जिन प्रिंसिपल के प्रमोशन हो गये, उनको भी नहीं लगाया गया। इस चीज पर भी आप ध्यान दें। डेपुटेशन है, यह सबसे बड़ा रोग है। डेपुटेशन पर शिक्षकों को भेज दिया जाता है। अधिकारी लोग लेकर चले जाते हैं, एसडीएम ऑफिस में, तहसील में, सब जगह बैठा दिया जाता है। इस डेपुटेशन के रोग को भी आप कम कीजिये, क्योंकि अगर डेपुटेशन नहीं होगा तो पद खाली नहीं रहेंगे। यह मेरा आपको सुझाव है।

इसके अलावा, मैं आपसे उच्च शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री जी, भीनमाल में 1966 में कॉलेज खुली थी और भामाशाह ने उस कॉलेज को खोला था। वहां पर 1648

नियमित विद्यार्थी हैं, जिसमें विज्ञान संकाय है, कला संकाय है, वाणिज्य संकाय है। कला संकाय में 1333 के करीब स्टूडेंट है, पर पीजी में वहां पर खाली एक विषय है, हिंदी का। उस विषय में, आज वहां सबसे बड़ी मांग है कि भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, ये सारे शुरू करेंगे तब लोगों को लाभ मिलेगा। भीनमाल में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पीजी में साइंस फैकल्टी नहीं है। भामाशाहों में वहां पर साइंस की इतनी बढ़िया लैब बना रखी है, जो मेरे खयाल से राजस्थान में कहीं नहीं होगी। आप इनिशिएट करें। इसलिए मैंने इनसिस्ट किया कि हम राइजिंग राजस्थान की बातें करते हैं। इन्वेस्टमेंट लाने की बात करें। आप इन्वेस्टमेंट शिक्षा के क्षेत्र में लाइये, एजुकेशन के क्षेत्र में। तब हम हमारी पीढ़ियों को आगे के लिए तैयार कर पायेंगे। विज्ञान संकाय का मैंने आपको निवेदन किया। भीनमाल कॉलेज में शैक्षणिक स्टाफ में 21 पद स्वीकृत हैं और 8 पद ही भरे हुए हैं, इसमें भी फिर वही डेपुटेशन का रोग आ गया। डेपुटेशन पर काफी शिक्षक चले गये हैं, लैक्चर्स चले गये हैं। इस डेपुटेशन से छुटकारा दिलायें, इससे तो ट्रांसफर कर दो तो पद खाली होंगे तो कम से कम भरे तो जाएंगे। वरना डेपुटेशन कराकर टीचर्स/लैक्चरर चले जाते हैं और पद वहीं के वहीं खाली रह जाते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि किसने क्या किया? हर सरकार आती है, हमारी सरकार आयी, चाहे हमने 12वीं तक स्कूलें कीं तो अच्छा डिसिजन था। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलीं, आप लोग उसका विरोध करते हैं। किसके बच्चे पढ़ते हैं? आज भी मैं आपको कहता हूं कि सरकारी विद्यालय से निकले हुए बच्चे ज्यादा आईएएस अफसर बने हैं, पदों पर पहुंचे हैं या प्राइवेट स्कूलों के। हम सब यहां बैठे हैं, अगर हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी इस चीज का फायदा होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए आपने कहा कि टीचर्स आयेंगे, वगैरह आयेंगे तो सिस्टम को लागू करने व डवलप होने में समय लगता है। यह डिसिजन भी आने वाले समय में ऐतिहासिक डिसिजन बनकर रहेगा। इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता, आप लाइये, आप भी योजना लाइये, हम उसकी तारीफ करेंगे, पर शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हम जितना ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं जाकर, मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो आपने बातें कहीं और मुझे भी समय दिया। एक तो ये खाली पद भरें। आज कोई प्राथमिक स्कूल 30 साल से, मेरे यहां पर एक पीपलीनाड़ी स्कूल है, 1998 में बनी और एक कमरे में चल रही है।

mdp/rtm/04.03.25/17:20/3g

200 बच्चे हैं उसके अन्दर, सिर ढकने की जगह नहीं है। इस तरह के आप पता करके, अभी अच्छा था, सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि बजट के बाद जब चर्चा के समय सारे प्रभारी मंत्रियों और सेक्रेटीज को भेजा गया जिलों में कि पता लगाओ कि क्या लागू हुआ और क्या

नहीं हुआ। मेरा सुझाव है कि आप लोग फीडबेक लीजिए, अपडेट लीजिए और जो सिस्टम में खराबी है, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तभी हम एक अच्छी शिक्षा इस देश को और इस जनता को उपलब्ध करा पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री देवेन्द्र जोशी जी। श्री सुभाष मील जी।

श्री सुभाष मील (खंडेला): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे शिक्षा पर, अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

आज जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उस पर चर्चा हो रही है। काफी समय से पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे थे। कई बातें सामने निकल कर आयीं और कई तरह के आरोप विपक्ष के माननीय सदस्यों ने लगाए। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व की जो सरकार है, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इसका स्तर सुधारने के लिए और हमारे देश के नौजवानों को, छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए हमने पहले बजट में और इस बजट में कि शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किये हैं।

अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया? आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि विपक्ष के जो साथी कह रहे थे कि हमने एक सपना पूरा किया, यह भी एक हास्यास्पद है कि आपको 2018 में जब जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया, तो आपको सपने सरकार के जाते वक्त क्यों आते हैं? आपने अंतिम समय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का काम किया और इसमें केवल आपका इतना-सा योगदान है कि आपने जो हिंदी मीडियम के स्कूल थे, उसके मुख्य द्वार का बोर्ड हटाकर उस पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिर्फ लिख दिया। इसके अलावा अगर आपकी सरकार ने, अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों की अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के लिए, अगर एक भी शिक्षक की नियुक्ति की हो, एक भी शिक्षक की भर्ती की हो, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ा सकता है तो आप इस सदन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। केवल बातें करने से शिक्षा का भला नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो तमाम हम लोग सदन के अन्दर बैठे हुए हैं और जो अधिकारियों की गेलेरी में अधिकारी बैठे हैं, हमारा किसी का बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता। इसलिए आरोप-प्रत्यारोप की बजाय हमें मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी सरकारी विद्यालयों की दशा सुधर सकती है, सरकारी महाविद्यालयों की दशा सुधर सकती है।

माननीय विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि आपने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं

कि इस बजट में भी हमने स्कूलों के बुनियादी ढाँचों और विस्तार के लिए 175 भवन विहीन और जर्जर स्कूलों के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट में प्रोविजन किया है। 2000 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए हमने 175 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। विभिन्न विद्यालयों में क्लासरूम, लैब, कम्प्यूटर लैब और टॉयलेट्स के लिए 225 करोड़ रुपये देने का बजट के अन्दर प्रावधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, हम केवल बातें नहीं करते। हम विद्यालयों का स्तर सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बड़े संकल्पबद्ध होकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 65 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने केलिए विभिन्न विद्यालयों में 75 करोड़ रुपये के सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की बजट में घोषणा की है। विभिन्न स्कूलों के लिए 100 नवीन संकाय खोलने का काम करने जा रहे हैं। 50 प्राथमिक विद्यालयों को और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम करने जा रहे हैं। 225 प्रवेशिका विद्यालयों का वरिष्ठ उपाध्याय में और 17 शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों का आचार्य स्तर पर क्रमोन्नयन करने जा रहे हैं। साथ ही, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना और मिरजावाला श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल की स्थापना करने हम लोग जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, देश और प्रदेश के अन्दर डबल इंजन की सरकार है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये जो विपक्ष के साथी यहां पर बैठे हैं, आपने भी गौर किया होगा आपकी विधान सभा में समग्र शिक्षा अभियान के अन्दर जो पैसा स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने के लिए आ रहा है, वास्तव में वह आने वाले एक नये युग का संकेत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि पिछले एक साल के अन्दर नवीन भवनों के लिए, विद्यालय में कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए और मरम्मत के लिए केवल मेरे अकेले खंडेला विधान सभा क्षेत्र में 15 से 16 करोड़ रुपये विद्यालयों में आए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे विद्यालयों की बेहतरी का संकेत है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए विद्यालयों में भवनों के निर्माण के लिए और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 3-3 करोड़ रुपये हमको पिछले एक साल में देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष के कई बड़े साथी बड़े-बड़े जोर-जोर से बात कर रहे थे। अगर आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में शिक्षा की भलाई के लिए कुछ किया होता तो अभी आपके जो सदस्य, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो मेडल दे रहे थे, इससे बड़ी विड़म्बना नहीं हो सकती कि आज शिक्षा के ऊपर बहस हो रही है और आपके तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री सदन के अन्दर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी विडम्बना हो नहीं सकती। ...(व्यवधान)... मैं आपको कहना चाहता हूं...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे किसी कार्य से नहीं आये हैं। ...(व्यवधान)... यह

क्या बात हुई? इसको एक्सपंज कीजिए।

(आसन द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश।)

श्री सुभाष मील (खंडेला): मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)... सुबह से, माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं, अभी चार-पांच घंटे से बहस चल रही है।

श्री सभापति: प्लीज, आसन को संबोधित कीजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): आप ही को संबोधित कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। चार-पांच घंटे से बहस चल रही है, आपके माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): सभापति जी, दोनों मंत्री मौजूद नहीं हैं।

श्री सभापति: अधिकारी नोट कर रहे हैं। मंत्री यहीं हैं। आप विराजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं....।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक को तो बुला लीजिए, दोनों ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि एक मंत्री को तो बुला लीजिए। दोनों ही नहीं हैं।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय जूली साहब, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... मैं तो साहब, माननीय जूली साहब के सब्र की भी दाद देना चाहता हूं। कहां-कहां पर इनके तत्कालीन मंत्रियों के कामों पर पर्दा डालेंगे। कहीं कोई बात हो जाती है, सदन में खेद इनको प्रकट करना पड़ता है। आज शिक्षा पर बहस है।

Ans/rtm 17.30 3h 04.03.2025

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, जो बात सदन में हो चुकी, आसन ने व्यवस्था दे, दी उस बात का यह बिना बात ही जिक्र कर रहे हैं ...(व्यवधान)...ऐसे नहीं होता, भई।

श्री सभापति: ऐसा कोई वाक्य है तो उसको डिलिट कर दीजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपने शिक्षा के ऊपर काम किया होता तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय के, जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद होते। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी बात सुनने के लिए आपका शिक्षा मंत्री नहीं है। पुराने की बात मत करो। आज जिसकी जिम्मेदारी है वह नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है वह नहीं बैठा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अकारण उत्तेजना पैदा कर दी। हाउस का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सुभाष मील (खंडेला): सभापति महोदय, विपक्ष के साथी खाली पदों की दुहाई दे रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): डिलिट करें सारी की सारी बातें। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, समय हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सुभाष मील (खंडेला): अभी मेरे तीन मिनट शेष है।

श्री सभापति: श्री सोहनलाल जी नायक।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री सोहनलाल जी नायक।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 व 22 पर बोलने का मौका दिया, आपका व हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता का मैं तहदिल से धन्यवाद करता हूं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मांग है। शिक्षा के बिना मानसिक, सांसारिक या संस्कार कहते हैं वे अधूरे रहते हैं।

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले घोषणा पत्र में आपने कहा था कि पहले वर्ष में सभी पद भर दिये जाएंगे। रिक्त पद भर दिये जाएंगे, आपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह सभी पद भरे गये, अगर नहीं भरे गये तो क्यों? आपने इस पवित्र सदन में घोषणा की है। आपकी घोषणा पर आपने अभी तक अमल क्यों नहीं किया? सत्ता-विपक्ष दोनों ने यह कहा था कि हमारे क्षेत्र के विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहां पद रिक्त हैं, दोनों तरफ से यह बात आई और पिछले घोषणा पत्र में यह कहा था कि सब रिक्त पद भर देंगे, कब तक भरेंगे, इसका जवाब हमें शिक्षा मंत्री जी दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 परसेंट पद अध्यापकों के रिक्त हैं। अध्यापकों के पद रिक्त होने की वजह से हम क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी।

दूसरा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त है। बच्चों को स्कूल से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। आपने तो कहा था कि हम सब कुछ कर देंगे, काया पलट कर देंगे, कौनसी काया पलट हुई आप मुझे यह बताइये?

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा समसा विभाग द्वारा विद्यालयों के अन्दर कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाता है। आप उठाकर देखिये, टोटल जो प्रस्ताव जाते हैं उनके अंदर मेजर रिपेयरिंग के नाम पर पैसा दिया जाता है, नये कक्षा कक्ष भवन का निर्माण नहीं किया जाता। मेजर रिपेयरिंग के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला होता है। उसमें नोर्म्स बने हुए हैं कि छत से ऊपर, जो दरवाजा है उसके ऊपर की छत को ऊँचा करेंगे जबकि वह पुरानी बिल्डिंग है वह पांच-पांच फिट नीचे जा चुकी है। मेजर रिपेयरिंग के नाम पर पैसा खाया जा रहा है। नये

कक्षा भवनों का निर्माण नहीं किया जा रहा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो कमियां हैं उनको शिक्षा मंत्री जी दूर करें।

राजकीय विद्यालयों में एससी बच्चियों की संख्या 70 परसेंट है, परन्तु उनके लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्वच्छ शौचालयों की की व्यवस्था करवाई जाए। आपने अभी बहुत से विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया है। 7-7,8-8 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र से दूर-दराज के स्कूल, जिनमें कोई संसाधन नहीं है उन बच्चों के पास, क्योंकि उन विद्यालयों के अन्दर किसानों, मज़दूरों, आम गरीब आदमी की बच्चियां पढ़ती है, उनके लिए संसाधन नहीं होने के बाद भी विद्यालय मर्ज कर दिये गये। उनको अपनी शिक्षा बंद करनी पड़ी। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस तरह के दूर-दराज के जो स्कूल हैं उनको मर्ज नहीं किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अँग्रेज़ी विद्यालयों के बारे में निवेदन करूंगा। यह सरकार हमेशा समीक्षा के नाम पर, कभी किसी के नाम से, विद्यालयों के ऊपर एक तलवार लटका रखी है, बंद कर देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विजयनगर में एक भामाशाह महावीर मिड्डा ने 80 लाख रुपये लगाकर राजकीय महात्मा गांधी अँग्रेज़ी विद्यालय का भवन बनवाया है, आप क्या उसको बंद करेंगे? 80 लाख रुपये, प्राइवेट संस्था का ऐसा कोई भवन नहीं है, हम उसको बंद करेंगे? गांव के अन्दर जब स्कूल खोले गये, गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 20-25 लाख में डिजिटल कक्षा कक्ष बनवाये, आप क्या उसको बंद करेंगे? भामाशाह कौन आयेगा, कौन स्कूल में जाकर उनकी मदद करेगा? सरकार तो कुछ दे नहीं रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि अँग्रेज़ी माध्यम के जो स्कूल है उनको समीक्षा के नाम पर बंद नहीं किये जाए। गरीब आदमी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा क्या अँग्रेज़ी पढ़ने का हक नहीं रखता, उसका अधिकार नहीं है? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि निजी स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अँग्रेज़ी विद्यालयों को बंद नहीं किया जाए।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी अभी यहां नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विजयनगर ब्लॉक में शहर के अन्दर 12 बीघा जमीन जिसकी कीमत दस करोड़ है, पांच लाख, सरकारी मापदंडों के हिसाब से बिल्डिंग बनाकर देने के लिए कॉलेज की बात की तो शिक्षा मंत्री जी ने उस कॉलेज को मंजूर किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा रायसिंहनगर में शहीद भगत सिंह कॉलेज है, जिसका कई बार सरकारीकरण हो चुका है, प्रिसिंपल बैठ गया था, प्रिसिंपल को हटा दिया गया, आज तक सरकारीकरण नहीं किया। उस महाविद्यालय की कोई संस्था नहीं है, एसडीएम उसका प्रशासक है। मेरा आपके माध्यम से सदन से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि उस विद्यालय का सरकारीकरण किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी आ गये हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय विद्यालय रायसिंहनगर का था, उसमें विज्ञान विषय था उसको बंद कर दिया गया। वह एक ब्लॉक है, नगर पालिका है, एक भी स्कूल में साइंस नहीं है, तो उसको खोला जाए। मेरा यह भी निवेदन है कि जहां भी 400 बच्चियों का स्कूल है उस स्कूल के अन्दर विज्ञान खोला जाए चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। हमारी सरकार ने तो यह कहा था कि 500 बच्चियों वाले को हम कॉलेज घोषित कर देंगे और बना भी दिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कॉलेज नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, लेकिन 400 बच्चियों से ऊपर वाले स्कूल में साइंस हो। बच्चियों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है।

मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अध्यापकों की बी.एल.ओ. में ड्यूटी लगती है। एक-एक विद्यालय में तीन-तीन अध्यापकों की बी.एल.ओ. में ड्यूटी लगती है। पहले ही ऑलरेडी 5-5,6-6 अध्यापक हैं, उनमें से आपने अगर तीन को बी.एल.ओ. बना दिया तो शिक्षा बाधित हो रही है। अध्यापकों को बी.एल.ओ. की डयूटी से हटाया जाए। इतना ही कहते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

VPS-RTM-04.03.2025-17.40-3j

श्री सभापति: श्री पब्बारामजी विश्नोई।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक शिक्षक को बोलने का अवसर प्रदान किया और वह भी दस मिनट के अल्प समय में अपनी बात को कह पाना बहुत मुश्किल है फिर भी आपके दिये गये समय के अनुसार मैं अपनी बात को पूरी करने का प्रयास करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा अंबेडकरजी ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा यानी, शिक्षा के अन्दर वह ताकत है। धन का भाई आपस में बटवारा कर लेते हैं परंतु शिक्षा का बटवारा नहीं हो सकता, वह जहां पर भी व्यक्ति जायेगा तो उसके साथ में वह शिक्षा जाएगी और जीवन पर्यंत उसका मार्गदर्शन करेगी इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

शिक्षा के बारे में हमारी भजन लालजी की सरकार, हमारी सरकार इसके बारे में बहुत संवेदनशील है। मैं इन शब्दों से अपनी बात को शुरू करूंगा-

जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
फिर मुश्किल क्या और आसान क्या? बस ठान लिया तो ठान लिया।
मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर,
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।

विद्या विनय को प्रदान करती है- विद्यां ददाति विनयं, विद्या विनयेन शोभते। विनयपूर्वक कोई भी बात को यहां पर कहा जा सकता है। हम सभी यहां पर आठ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस राज्य की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसको कैसे ठीक किया जा

सकता है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति को अपने भावी जीवन के लिए तैयार भी करती है और शिक्षा चरित्र का निर्माण भी करती है। पिछले 2018 से 2023 के समय में विद्यालय खोले गये। हम यह मानते हैं। हमने भी खोले और उन्होंने भी खोले। लगभग 6273 सीनियर सैकेण्डरी, उनमें अधिकतर तो नई शिक्षा नीति के अन्दर आपके सैकेण्डरी जो स्तर है वह समाप्त कर दिया, मिडिल से सीधा सीनियर सैकेण्डरी, वह आपकी मजबूरी थी कि आपने सीनियर सैकेण्डरी उसको कर दिया, वह तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही हुआ है और वह आपके समय में ही हुआ है, परंतु जब आपने विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया तो आपका यह फर्ज बनता था कि उन विद्यालयों के अन्दर पदों का सृजन तो करो, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तो भेजो। अपने पांच साल तक एक भी पद सृजित नहीं किया और बगैर शिक्षकों के पांच साल आपने गुजार दिये और राजस्थान के युवाओं का भविष्य आपने बरबाद करके छोड़ दिया।

ये बारबार यह कहते हैं कि हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले। हां, आपकी मंशा ठीक हो सकती है कि आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, पर कम से कम उस लोकेलिटी के लोगों से पूछ तो लिया होता कि आपके बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। जबरदस्ती आप खोल रहे हैं। मैं अंग्रजी पढ़ाऊंगा, लोग वहां से दस-दस किलोमीटर, वह गरीब का बेटा जाकर दूसरे विद्यालय में जा रहा है। छठी तक वह हिंदी पढ़ा है, हिंदी माध्यम से पढ़ा है और अंग्रेजी की जो बुक्स हैं, लाकर आपने छठी के अन्दर पकड़ा दी कि तू अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना शुरू कर दे। कुछ तो विचार, किसी शिक्षाविद् से तो पूछ लेना, अपनी मर्जी से किये जा रहे थे और आपने यह अन्याय जो किया है न यह राज्य की जनता को बहुत महंगा पड़ा है। आपको अगर करना ही था तो स्वामी विवेकानंद विद्यालय के रूप में हमने जो किया है न, कितना शानदार विद्यालय बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है, लैब्स उसके अन्दर दिये हैं, खेलकूद के सारे साधन मुहैया करवाये हैं और वहां पर परीक्षा होती है, वहां पर शिक्षा भी अंग्रेजी की होती है। आपने तो वे ही शिक्षक जो खुद ही अंग्रेजी नहीं जानते, उनको कह दिया कि तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, यह समझ से परे बात है। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी माध्यम का कोई लाभ हुआ हो तो आप बता देना। आपकी समस्या यह है कि जो पढ़ा-लिखा बच्चा है न, वह आपसे दूर होता जा रहा है। पढ़ी-लिखी जो पीढ़ी है, वह आपसे दूर होती जा रही है इसलिए आप उसी अनपढ़ता के गर्त के अन्दर उनको धकेलना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमने 2013 से 2018 के बीच में सभी पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय की है और लगभग साढ़े छह हजार तो विद्यालय एक साथ में खोले हैं और वहां पर पद सृजित किये हैं और वहां पर शिक्षक भी लगाये हैं और वह जो 2013 से 2018 वाला पीरियड था, वह शिक्षा विभाग के लिए एक स्वर्णिम काल था। माननीय अध्यक्षजी उस समय शिक्षा मंत्री थे। राज्य मंत्री थे परंतु कैबिनेट मंत्री आकर यह कहता था कि यह करना पड़ेगा तो वे यह कहते थे कि नियमों में आयेगा तो ही करूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। कुछ न कुछ तो अपने को मापदंड रखना पड़ेगा और उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न लागू

किया। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब जितने स्टूडेंट्स हो उस हिसाब से पद सृजित करो और वह वहां पर पढ़ाने का काम करो। आपने असमान वितरण कर दिया। हां, उन्होंने काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया यानी, काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक को लगाओ। जहां पर मान लीजिए 70 परसेंट पद आपने भरे हैं तो बॉर्डर की स्कूल में भी 70 परसेंट पद भर कर करें। सभी जगह पर पढ़ाई चल रही थी, वहां उस समय में बोर्ड की परीक्षा में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरिट में आने लगे थे और एनरोलमेंट इतना बढ़ गया था। वापस यह अंग्रेजी विद्यालय में, जहां-जहां हजार-हजार, पन्द्रह सौ-पन्द्रह सौ स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो वे वहां पर सौ-डेढ़ सौ पर आ गया और वह पता नहीं या तो प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर हो गये और या दूर के विद्यालय में गरीब का बेटा वहां जाकर पढ़ने लग गया और आप कहते हो कि मैं तो अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। अंग्रेजी का विद्यालय खोलना ही था तो आप पंचायत समिति स्तर पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के बाद में वह खोलते। अंग्रेजी अध्यापक लगाते और वे व्यवस्थाएं करते, जैसे मॉडल स्कूल में है। मेरा आपसे यह निवेदन है शिक्षा मंत्रीजी, आप अंग्रेजी विद्यालयों की स्कूल रखिये, परंतु एक पंचायत समिति में क्लस्टरवाइज दो-दो, तीन-तीन विद्यालय खोलकर उनके अन्दर अंग्रेजी पढ़ाने की सारी व्यवस्था मॉडल स्कूल के तर्ज पर कीजिए और अभी यह जो जबरदस्ती किये गये हैं, सिर्फ बोर्ड लटका कर तो आप वहां के लोगों से यह पूछ लीजिए कि क्या वे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो अभिभावक नहीं चाहते और आप कह रहे हैं कि हम तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे और पढ़ाने वाला कौन? मेरा जैसा जो नहीं जानता है अंग्रेजी, वह ही मास्टर। जो अंग्रेजी की ए.बी.सी.डी. ही नहीं जानता है तो इस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है।

साथ ही, एक यह विषय, विशेषकर मेरे समुदाय के अन्दर नीले वस्त्र वर्जित किये हैं हमारे गुरु महाराज ने। हमारे ही नहीं आप यह बता दीजिए कि कहीं पर कोई मन्दिर के अन्दर पूजा नीले वस्त्र पहन कर अगर की जाती है तो वह व्यक्ति उसका फोटो लाकर हमें दें। नीला वस्त्र सनातन संस्कृति में पूजा में भी वर्जित है और आप सरस्वती के मंदिर के अन्दर जहां पर साधक/बच्चा बैठकर वह पढ़ाई करता है तो जबरदस्ती उसको नीला पहना दो। हमारे वाले रंग से आपको तकलीफ थी तो सफेद कमीज और मटियाला रंग, वह कर देते। वापस वह क्यों लाद रहे हो हमारे ऊपर इस रंग को? तो मेहरबानी करके, मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इस नीले वस्त्र को हटाकर, इनको हमारे पहले वाले रंग से एतराज है तो छोड़ो, आप दूसरा कर लो। खाकी पैंट कर दो और पहले हुआ करता था, सफेद कमीज कर दो, वह कर दो पर ईश्वर के लिए इस रंग से छुटकारा दिलवाओ। यह हमारे सनातन संस्कृति के विपरीत है। इसको पहन कर व्यक्तित्व नहीं बन सकता, संस्कार नहीं मिल सकते इन वस्त्रों के अन्दर, इन वस्त्रों के अन्दर कोई भी पुजारी बैठकर पूजा नहीं करता, इसलिए आपसे यह निवेदन है।

आपको अच्छी पढ़ाई के लिए, कभी-कभार अपने पास में शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। आजकल अब सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाना शुरू कर दो क्लासेज। अच्छे शिक्षक

जो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और वहां पर डिस्प्ले करके उनका पढ़ाइये। कम से कम उनको भी अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, एक दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी रिक्त पदों को आप भरिये और स्टाफिंग पैटर्न से, बारबार हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने ऐसा किया, कम से कम युवाओं के उस घाव को तो मत कुरेदो।

ssy/rtm/04.03.2025/17.50/3k

क्या-क्या किया उन्होने? रीट की परीक्षा में क्या किया? दूसरी परीक्षाओं में क्या किया? ईश्वर के लिए उनको उनका अतीत मत याद दिलाओ। अब पिछली बार भी रीट की परीक्षा हुई है, एक भी किसी की औकात हुई है नकल करने की तो मुझे बता दें। हम लोग परीक्षा करवा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): शर्म आती है कि ऐसे लोगों का गुणगान किया जा रहा है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): जिसके समय में रीट जैसी परीक्षा को कलंकित करने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण था कि सदन के अन्दर इसकी चर्चा, मेरे को पता है यहां पर क्या कहता था, रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। वह नाथी का बाड़ा है। ईश्वर के लिए कुछ तो सोचो।

श्री सभापतिः श्री मांगेलाल जी।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका और हमारी पार्टी के, प्रतिपक्ष के नेता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

विगत 4 वर्षों में 6273 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया था। 4441 सैकण्डरी स्कूल से सीनियर सैकण्डरी में और 1832 स्कूल उच्च प्राथमिक से सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत की गई थी। इनमें व्याख्याताओं के पद, लेक्चरर के पद 19319 होने चाहिए। लेकिन 1746 पदों की सरकार के ओर से स्वीकृति मिली है। 17573 पदों की स्वीकृति अभी भी सरकार ने नहीं दी है। इनकी स्वीकृति देकर, इन रिक्त पदों को भरवाने का काम करें। एक दूसरे की आलोचना करने से शिक्षा जगत का उद्धार नहीं हो सकता और ना विकसित भारत की आप परिकल्पना कर सकते हैं।

माननीय सत्ता पक्ष के सभी सदस्य कहते हैं कि कांग्रेस ने यह किया, बीजेपी ने यह किया। आप सब लोग जो बैठे हैं, देश आजाद हुआ था उस समय आपके पास क्या था? कौनसी सरकारी स्कूल थी? कौनसे विश्वविद्यालय थे? अपने पास में क्या रिसर्च सेंटर थे? यह सब कुछ कांग्रेस ने दिया और आप भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हो।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): कांग्रेस ने नहीं दिया, जनता ने दिया है।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): जनता का पैसा होता है, टैक्स से वसूला जाता

है। आप और कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, अपने पास कोई फंडिंग नहीं करता है। जनता के पैसों से काम करते हैं। आप भी अहसान नहीं करते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैरी गुड, बहुत बढ़िया।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): पिछले 12 वर्षों में व्याख्याताओं की 5 बार भर्तियां निकाली गई। 2013 में 4010, 2015 में 13098, 2018 में लगभग 5 हजार, 2022 में 6 हजार और यह डबल इंजन की सरकार, 2202 हैं। शायद इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं टू, टू का फिगर इसमें समायोजित किया गया है।

श्री सभापति: प्लीज, मंत्री महोदय, आवाज कम करें। प्लीज, मंत्री महोदय।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): मैं कहना चाहता हूं कि इन पदों को भरने के प्रयास किये जायें। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि सारे रिक्त पदों को भरेंगे। आज तक भरने के लिए कोई कवायद शुरू नहीं की है। अब तक क्यों नहीं भरे गये? सरकार अपना स्टेटमेंट देने के बाद भी रिक्त पदों को नहीं भर पाई है। अब इनको कब तक भरने की आपकी योजना है? माननीय मंत्री जी, आपके प्रत्युत्तर में इसका समावेश निश्चित करें।

इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन इनके सारे पद रिक्त हैं। सभी को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। भर्ती प्रक्रिया में एक लंबा समय लग जाता है और 2202 व्याख्याताओं की भर्ती करें। ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसके बच्चे पढ़ते हैं? एसटी, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्युएस और एमबीएस, गरीब लोगों के बच्चे यहां पढ़ते हैं। जो शहरों में नहीं भेज पाते। उनके साथ में अपन एक भ्रम फैलाकर, भर्ती नहीं करके शिक्षकों को नहीं लगाना यह उनके साथ में एक धोखा है। वंचितों को वंचित रखने की योजना सरकार की लगती है।

उच्च शिक्षा में भी प्रोफेसरों के लगभग 50 परसेंट सीटें वैकेंट हैं। मैं राजगढ़ कॉलेज की बात करूं कि ज्योग्राफी के एक प्रोफेसर हैं। जो लगभग 3 हजार बच्चों को अध्ययन कराते हैं। क्या यही अपनी शिक्षा है? क्या इसी से अपन विकसित भारत की परिकल्पना करेंगे? अपने को यह भी देखना चाहिए कि उनकी क्षमता कितनी है। आज राजगढ़ कॉलेज में कम से कम 7-8 हजार बच्चे पढ़ते हैं। पहले 400-500 बच्चे पढ़ते थे तो भी उतने ही प्रोफेसर होते थे और अब भी प्रोफेसर्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। इन बिन्दुओं पर विचार करने की जरूरत है आलोचना करने की बजाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल के साथी प्रयागराज में गये। कुंभ स्नान करके आये थे। अब तो लगता है कि राजधर्म निभाने के लिए, सब जगह अच्छे भाव से काम करवाने के लिए आपने मन बना लिया होगा। लेकिन बजट में और कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। 'सियाराम मय सब जग जानी करहू प्रणाम जोरि जुग पानी', तो आपको वहां जाने के बाद तो सारा संसार राम मय ही हो जाना चाहिए। राम ही राम नजर आना चाहिए। राम नजर आता है तो वह राजधर्म निभाता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक बढ़िया कीर्तन चल रहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन समय बढ़ाना है।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होते के लिए बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा एवं मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा पर विचार

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आदरणीय मांगेलाल जी अपना प्रवचन चालू रखें।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): भगवान राम समाज के वंचित लोगों के पास में स्वयं चलकर गये थे। केवट, शबरी, अहिल्या प्रसंग इसके परिणाम हैं। आप मानते हो? देश है जो बाबा साहब के दिये गये संविधान से चलता है, अहंकार से नहीं चलता। आप अपना अहंकार निकाल दीजिये।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अहंकार तो आपमें था जो ...(व्यवधान)...कम हो गया।

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): आपको अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के व्याख्याताओं, अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए। वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम करना चाहिए।

श्री सभापति: प्लीज, आवाज नहीं।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): आप कहते हैं कि इनको बंद करेंगे। समीक्षा करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, गुमराह करने से इनके नामांकन कम होते हैं। आप वंचितों को गुमराह मत करो। इनमें अब शिक्षकों की भर्ती करिये और इनको चलाइये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान विषय अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी माध्यम के बिना ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो उससे वंचित रह जाते हैं। उनको आगे लाने का आपको प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, समीक्षा नहीं करनी चाहिए। गहलोत सरकार के द्वारा आपको चलाये गये सभी योजनाओं का प्रबंधन, समीक्षा नहीं, उनके प्रबंधन को समझने की जरूरत है। बस यह समझ लो सब बेड़ा पार हो जायेगा।

मैं राजगढ-लक्ष्मणगढ विधान सभा की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। महाविद्यालय रैणी, कन्या महाविद्यालय राजगढ़, महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, कृषि महाविद्यालय माचाड़ी, राजसेस से चलाये जा रहे हैं। कृपया इसे हटाकर राजकीय मद से

संचालित कराने का मेरा आपसे आग्रह है।

कृषि महाविद्यालय माचाड़ी के लिए 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति है, लेकिन कलेक्टर के यहां से सरकार को फाइल भेजी जाती है और आज तक उसकी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। शीघ्र उसकी जमीन का आवंटन करवाया जाये।

spp/rtm/04.03.2025/18.00/3l

महाविद्यालय स्तर के राजगढ़-रेणी-लक्ष्मणगढ़ 200 क्षमता के छात्रावास का निर्माण किया जावे। पहले विवेकानन्द हॉस्टल राजगढ़ में एस.सी., एस.टी. के बच्चों के लिये चलता था, अब किराये के भवन भी उपलब्ध नहीं होते तो वहां छात्रावासों के निर्माण की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समसा में, अन्य योजनाओं में सरकारी स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद आप कहते हो कि पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहिए। क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले डवलप किया जाता है? नहीं किया जाता। जिस समय राज्य बना था तो अपने पास कौनसा विधान सभा भवन था?

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अपन भी तो चलते थे। उसमें विधान सभा चला रहे थे, बाद में विधान सभा बनी। आप इसकी संरचना को, ढांचे को मजबूत करने का काम करें और स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य करवाया जाये। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में .. (व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री रामसहाय वर्मा।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा ही देश एवं परिवार के सर्वांगीण विकास का आधार हैं, जिसके लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं यथा पर्याप्त भवन, अन्य सह-शैक्षिक गतिविधियों सहित खेल मैदान के लिए पर्याप्त भूमि, सहायक कर्मचारी, मंत्रालयिक एवं टीचिंग स्टाफ के पदों की स्वीकृति के अनुसार स्टाफ का होना नितांत आवश्यक है।

क्षेत्र में भ्रमण के दौरान तथा जनता एवं कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई विद्यालय हैं जिनके नाम विधिवत रूप से भूमि आवंटित नहीं होने के कारण भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी होने में तकनीकी अडचनें आती हैं। मेरे क्षेत्र के सभी श्रेणी के कई विद्यालयों में पर्याप्त भवन नहीं होने के कारण छात्रों को उचित एवं सुव्यवस्थित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के लिए सुविधायुक्त शौचालय एवं अन्य खेलकूद की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

सभी विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों के पद काफ़ी वर्षों से रिक्त हैं। निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी निरीक्षण नहीं किये जा रहे हैं या फिर कहीं न कहीं कागजों में महज खाना पूर्ति हो रही है।

शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, संस्कारयुक्त एवं आध्यात्मिक तथा जीवनपयोगी तकनीकी बनाने की मांग करता हूं ताकि स्वयं को मिलने से बेरोजगारी दर में वृद्धि नहीं हो पाए।

कई विद्यालयों में छात्रों के अनुपात से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और कई विद्यालयों में काफ़ी संख्या में पद रिक्त हैं, इसलिए सभी विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक लगाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार की उदासीनता के कारण पांच सालों में शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों के भवनों की ऐसी दुर्दशा हुई कि इस बार बारिश में 70 प्रतिशत से अधिक विद्यालय ऐसे थे जिनमें बच्चों को बैठने तक की समस्या उत्पन्न हो रही थी। विगत सरकार ने भवनों के मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति का कार्य किया है। यदि वास्तविकता में कार्य किया होता तो बारिश में कुछ कक्ष तो ऐसे होते जिनमें बैठकर बच्चे अध्ययन कर पाते, लेकिन अधिकांश विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण बच्चों को बारिश के समय छुट्टियां करनी पड़ी हैं। उपखण्ड पीपलू के ग्राम फजलपुरा के विद्यालय में बारिश के समय ग्रामीणों ने विद्यालय के ताले लगा दिये जिसे मैंने विद्यालय मरम्मत का आश्वासन देकर खुलवाया।

माननीय सभापति महोदय, सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उन जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए मैंने अपनी विधायक विकास निधि से 1 करोड़ 76 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत कर विद्यालयों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करवा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार के शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 कक्षा-कक्ष दिये जिससे कि काफी कुछ समस्या का समाधान हुआ।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार ने अपनी कोरी घोषणाओं से शिक्षा के मंदिरों को भी अछूता नहीं छोड़ा। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के नाम पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोलने का खूब ढिंढोरा पीटा है जबकि वास्तविकता में एक भी नवीन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नहीं खोला गया, बल्कि पूर्व में संचालित विद्यालयों के नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कर दिये गये हैं। पूर्व में संचालित कई बालिका विद्यालय इनकी इस मनमानी की भेंट चढ़ गये। इन विद्यालयों में जिले के बाहर पदस्थापित अपने चहेते अध्यापकों को बैकडोर एंट्री से गृह जिलों में स्थानान्तरित कर दिया। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ना आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया, ना ही समीचीन प्रकार से कार्मिकों की नियुक्तियां की गईं।

माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जिन विद्यालयों को जबरन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाया गया, उन विद्यालयों को पुनः पूर्व स्वरूप में ही करने की कृपा करावें। जहां पूर्व में पृथक से बालिका विद्यालय संचालित थे उन्हें पुनः बालिका विद्यालयों के रूप में संचालित करवाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण राजकीय विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त दरियां, फर्नीचर एवं कक्षा कक्षों की व्यवस्था नहीं थीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने सरकार बनने के साथ ही विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु तीन-तीन करोड रुपये की राशि बिना भेदभाव के राजस्थान के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में देने का पुनीत कार्य किया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे सदन को बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू के विद्यालयों में एक करोड 72 लाख 92 हजार रूपये की राशि अपनी विधायक विकास निधि से स्वीकृत कर बच्चों के बैठने हेतु दरियों की व्यवस्था करवाईं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि विगत सरकार द्वारा पूरे पांच साल में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की नीति निर्माण का गाना गाया गया जबकि एक बार भी तबादले नहीं किये, जिसका जवाब मेरे शिक्षा विभाग के साथियों ने विधान सभा चुनाव में भली प्रकार से दिया है। सभापति महोदय, सन 2018 में पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अन्तिम बार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले किये थे जिससे कई शिक्षक साथियों को राहत मिली थी, लेकिन टी.एस.पी. तथा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले उस समय भी नही हो पाये थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि शीघ्र ही प्रतिबंधित जिलों के नियम को समाप्त करते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों सहित शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों के तबादले करवाने की कृपा करावें ताकि वर्षों से दूरदराज कार्य कर रहे अल्प वेतन भोगी मेरे शिक्षक भाइयों को अपने गृह जिलों में आकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय हमीरिया, बंजारा ढाणी करीमपुरा, गंगापुरा, करीमबक्श की ढाणी, ललवाडी, भैरूबुल्या, राजधिराजपुरा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करवाने की तथा बीजवाड़, जयकिशनपुरा, बालिका बगडी, फजलपुरा, इब्राहिमपुरा ठाठा, मोहम्मद नगर ढाणी, कीरों की ढाणी ककराजकलां, जगसरा, बंशीपुरा, देवरी सीदडा, आकोडिया, मेहताबपुरा, टोरडी, सिसोला में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार द्वारा विद्यालयों में नवीन संकाय तक संचालित नहीं किये गये जिससे कि हमारे बच्चे आज भी सीमित विषयों का अध्ययन करने हेतु मजबूर हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के चनानी, श्रीरामपुरा, राहोली, करेडा बुजुर्ग,

चौगाई, जौंला, कठमाणा, प्यावडी, बगडी, झिलाय में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय तथा करेडा बुजुर्ग, चौगाई, जौंला, बगडी, प्यावडी, संदेडा, में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालन की स्वीकृति प्रदान करवाने की कृपा करें। जिन विद्यालयों में पूर्व से ही विज्ञान संकाय संचालित हैं उनमें गणित विषय अनिवार्य रूप से संचालन करवाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, निजी विद्यालयों में आज कुछ नयी प्रणालियों का आगम हो चुका है। आर.टी.ई. में साक्षात्कार तथा प्रवेश परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर दिये जाने के बावजूद भी निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों तथा उनके माता-पिता के साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश की बाध्यता थोपी जाती है। ग्रामीण परिवेश के अभिभावक कम पढे लिखे होने के कारण उनके बच्चों को अच्छे विद्यालयों में अध्ययन के सपने को माता पिता के साक्षात्कार से चकनाचूर कर दिया जाता है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमर्जी से फीस वसूली जाती है, किताबें कॉपियां, गणवेश विद्यालय से ही खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि निजी विद्यालयों के लिए नियम बनाकर समुचित फीस निर्धारण किया जाये, बच्चों व माता-पिता का साक्षात्कार समाप्त करवायें । समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों के कार्मिकों व छात्रों की समान गणवेश लागू करवाने की कृपा करावें जिससे गरीब छात्रों को असमानता का अनुभव ना हो और मानसिक रूप से उन पर गलत प्रभाव ना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार ने विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ तक की सुविधा नही दी जिस कारण कई विद्यालय पीएम श्री विद्यालय की योग्यता रखने के बावजूद भी उनका चयन पीएम श्री विद्यालय के रूप में नही हो पा रहा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि निवाई में स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय तथा पीपलू में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में संस्कृत विषय तथा विज्ञान संकाय संचालन की स्वीकृति प्रदान करवाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, आपका हृदय से आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 20 21 22 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री विकास जी चौधरी।

jyg/rtm/04.03.25/18.10/3m

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम लास्ट में था लेकिन पहले दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मांग संख्या 20, 21 और 22 पर मंतव्य रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप और हम जानते हैं कि, education is the escape route from poverty. शिक्षा ही

गरीबी से मुक्ति दिलाने का मार्ग है आदरणीय मंत्री महोदय, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता और आधुनिकता पर हम प्रयास करें। लेकिन आज प्रदेश में और देश में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधरने की बजाय स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सेंटर फोर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के टोप 2 हजार में देश के मात्र 65 संस्थान हैं और इनमें से 33 संस्थान 2024 में इस रैंकिंग से बाहर आ चुके हैं। इसलिए आप और हमको ये प्रयास करने चाहिए। एक तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हमारे साथी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत की संकल्पना की बात करते हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, आरएण्डडी पर सरकार का प्रयास नगण्य नजर आ रहा है। आज के बदलते परिवेश में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए प्रदेश में, आदरणीय मंत्रीजी, एक्सपर्ट टास्क फोर्स और स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए। नीति आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए कम से कम 6 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च करना चाहिए लेकिन प्रदेश की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

आदरणीय सभापति महोदय, आज के इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी के युग में शिक्षा में जरूरी है कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एआई का उपयोग भी हो। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग की महत्ता आज के परिप्रेक्ष्य में नजर आ रही है। Technology should not be viewed as a solution but as a supportive tool in overcoming certain barriers to education. मैं आपका ध्यान यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की ओर आकर्षित करता हूं। इस रिपोर्ट में स्मार्ट फोन डिवाइस के उपयोग को युक्तियुक्त और प्रतिबंध करने की सिफारिश की गयी है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से विद्यालय हों, चाहे महाविद्यालय हों, चाहे विश्वविद्यालय हों, उनमें मोबाइल फोन का लगातार उपयोग हो रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज इस मंच पर बोलने के लिए यहां अधिकृत हुआ हूं तो उसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के उस छात्र संघ चुनाव का है, जिस चुनाव ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। आज जेएम लिंगदोह कमेटी की सिफारिश से चुनाव हो रहे थे, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव के कारण उसको बंद कर दिया लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे समय बंद हुआ।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): उस समय आप हमारी तरफ ही थे। आपने पाला बदल लिया।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): पाले तो चेंज होते रहेंगे, पांच साल बाद हम उधर आयेंगे, आप इधर आ जायेंगे। ...(व्यवधान)... आप भी थोड़े दिन में इधर आयेंगे, चिंता न करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप जो इतना अच्छा बोल रहे हो, आपकी ट्रेनिंग हमारी ही है।

श्री सभापति: प्लीज, सदस्य, आसन को सम्बोधित कीजिये, आपका समय समाप्त हो रहा

है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए? मैं चुनाव बहाल करने की मांग करता हूं। चुनाव इसलिए होने चाहिए कि हमारे जैसे नौजवान सड़क से आकर यहां सदन में अपनी बात कह सकें। उनमें राजनीतिक जागरुकता आये, लोकतंत्र की चेतना आये, नेतृत्व क्षमता का विकास हो, राजनीतिक तर्कशीलता एवं संवाद कौशल के लिए छात्र संघ चुनाव आवश्यक है। हमारी सामूहिकता से, टीम वर्क के लिए छात्र संघ चुनाव आवश्यक है। इसलिए मैं इस सदन में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग करता हूं और इस मांग के लिए हमारे विपक्ष के सारे साथी साथ हैं, मन ही मन मुझे लग रहा है कि आप भी हमारे साथ हैं लेकिन उप मुख्य मंत्रीजी, आपको थोड़ी ताकत दिखानी पड़ेगी। छात्र संघ चुनाव होंगे तभी हमारे जैसे नौजवान यहां आयेंगे, अपनी बात रखेंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं अजमेर के उस विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करके आया हूं जिस विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई। मेरा जन्म भी 1987 में हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सवा छह फुट का हो गया लेकिन आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अपनी बाल्यकाल अवस्था में कदम ताल कर रहा है, कदम ताल इसलिए कर रहा है कि वहां फैकल्टी मेरे समय में 36 हुआ करती थी आज वो फैकल्टी 12 हो गयी, 12 में से भी 3 लोग, 3 लोग इसी साल रिटायर हो जायेंगे, 9 फैकल्टी से विश्वविद्यालय चल सकता है? मेरे से विश्वविद्यालय के कई लोगों का टेलिफोन आया, बीकानेर से आया, जोधपुर से आया कि हम जो रिटायर हुए हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या यह सरकार रिटायरमेंट हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन देने में भी समर्थ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं महर्षि दयानंद जैसे विश्वविद्यालय में आज वाइस चांसलर क्यों नहीं है, वहां डिप्टी रजिस्टार क्यों नहीं है, वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? राज्य के सभी विश्वविद्यालय की यही स्थिति है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी है लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय का लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ के राजकीय रतनलाल कंवरलाल पाटनी महाविद्यालय में 5 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं बावजूद इसके वहां 65 से ज्यादा पद स्वीकृत हैं, आप देखिये, 65 से ज्यादा पद स्वीकृत है, आज भी वहां 36 फैकल्टी है, उसमें 12 लोगों को आपने डेपुटेशन पर प्रतिनियुक्ति दे रखी है, आखिर क्या वो इतने मिले हुए लोग हैं जो कम फैकल्टी होने के बाद भी 12 लोगों को आपने प्रतिनियुक्ति पर भेजा हुआ है? आखिर वो शिक्षक किससे मिले हुए हैं? आरआई कॉलेज जो हमारी सरकार ने पूरी बिल्डिंग बना दी, उसके बाद भी उसकी स्थिति दयनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे मेलबॉर्न में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खबर भेजी और यह अख़बार में छपी है, दिसम्बर की खबर है, जिस पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का भी

बयान है, इसमें माननीय प्रतिष्ठित अख़बार ने लिखा, कतार में लगकर मुफ्त का खाना लाती हूं, पढ़ने गयी थी, सरकार ने भिखारी बना दिया। यह एक गरीब परिवार की छात्रा में विदेश में पढ़ने जा रही है, स्कॉलरशिप का नाम आपने राजीव गांधी जी स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप कर दिया, हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस गरीब की बच्ची का दोष है कि वो विदेश में पढ़ने गयी और आपने भीख मांगने के लिए कतार में खड़ा कर दिया, आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी, आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का।

आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के लचर रवैये से दम तोड़ रही विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना, 10 हजार आवेदन, 500 में से सिर्फ 130 छात्रों को मिला लाभ। ये अख़बार की सुर्खियां बता रही हैं कि हमारी सरकार प्रदेश को और देश की आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई क्रियान्विति नहीं कर रही है, इनका ध्यान इस ओर नहीं है, इनका ध्यान तो केवल बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का है आदरणीय सभापति महोदय।

आदरणीय सभापति महोदय, लगातार हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, इसके बावजूद हमारे युवा लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं करने का क्या कारण है, इसके पीछे हमें जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दूदू से आने वाले मंत्री महोदय, मदन दिलावर जी तो चले गये, मैं उनसे कहना चाहता हूं दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों को, आप मुझे लगता है कि उनको सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे,

'हो गयी है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए,'

और मंत्रीजी, गंगा दूदू से किशनगढ़ की ओर जानी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, ओबीसी की छात्राओं को प्रदेश में काली बाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना जो है, मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी ओबीसी की बच्चियों को भी उसमें शामिल करे। मैं स्वागत करता हूं कि आपने 30 हजार स्कूटी देने को 35 हजार किया, लेकिन ओबीसी की बच्चियों को भी आप ध्यान में रखकर यह काम करे, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आज यह सूचना मिली है कि शिक्षा विभाग के मौजदा हालात ये हैं कि चार साल में 6,273 विद्यालय क्रमोन्नत हुए जिनमें 4,441 विद्यालय सेकण्डरी से सीनियर सेकण्डरी तथा 1,832 विद्यालय उच्च प्राथमिक से सीनियर सेकण्डरी में क्रमोन्नत हुए, इन विद्यालयों में 17,573 व्याख्याताओं की आवश्यकता है लेकिन बेरोजगारों के लिए केवल 2,202 पदों पर ही भर्ती निकाली गयी।

MLS/RTM/04.03.2025/18:20/3n

आखिर इतने पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं? दूसरी तरफ व्याख्याताओं को पद से क्रमोन्नत नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के भरोसे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अध्ययन करना पड़ रहा है।

श्री सभापतिः श्री शत्रुघन गौतम। अंकित नहीं होगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, हृदय के अन्त:स्थल से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्त्वपूर्ण विभागों की सदन में चर्चा हो रही है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है आपका। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग वह विभाग है जिसमें समाज के अन्दर शिक्षा के दर्पण से सरकार का चेहरा दिखता है। मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और शिक्षक समाज में, चाहे वह जनगणना का काम हो, चाहे वह चुनाव कराने का काम हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का काम हो, चाहे वह बीएलओ बनने का काम हो, समाज में शिक्षक करता है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय, विराज जाएं आप। माननीय सभापति महोदय, शिक्षक समाज में, चाहे वह बीएलओ हो, चाहे वह चुनाव कराने का काम हो, कोई भी काम हो, शिक्षक द्वारा कराया जाता है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री सभापतिः प्लीज, आपको दस मिनट दिये थे। आपके नेता प्रतिपक्ष से बात कर लीजिये। बोलने दें। नेता, प्रतिपक्ष, उन्हें समझाएं। दस मिनट दिये हैं, फिर भी बोलते रहते हैं। अनुशासन का नाम ही नहीं है।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): शिक्षा के क्षेत्र में सतयुग से लेकर आज तक समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं। गुरुकुल में भी शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। प्रारम्भिक शिक्षा, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है, गुरु और शिष्य के भावनात्मक रिश्ते आज के इस भौतिक युग में तार-तार हो गये। ये जो सदन में सब लोग बैठे हैं, ये लोग जब स्कूल में पढ़ने जाया करते थे तो जब अध्यापक द्वारा, इनके शिक्षक द्वारा इनकी पिटाई कर दी जाती थी तो क्या मजाल जो घर पर आकर कह देते कि नहीं, मेरी पिटाई हुई है स्कूल में। जानते थे कि स्कूल में पिटा हूं, यहां अगर बोलूंगा तो घर में भी पिटूंगा।

शिक्षक समाज में वह भूमिका निभाता है, एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार एक पत्थर की

मूर्ति को, संगमरमर की मूर्ति को तराशने का काम करता है, उसके हाथ बनाता है, उसकी आंख बनाता है, उसकी नाक बनाता है और जब प्राण-प्रतिष्ठित होकर वह मूर्ति मन्दिर में स्थापित हो जाती है, वह शिल्पकार जाकर उस मूर्ति के प्रतिबिम्ब के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि, हे ईश्वर, मेरी यह मनोकामना पूरी होनी चाहिये। जिस शिक्षक ने इस सदन के सभी सदस्यों को पढ़ाया है, आज वह शिक्षक जब सामने नजर आता है, उस शिक्षक की आंख में आंसू आ जाते हैं कि इस बेटे को मैंने तैयार किया है, इसे मैंने पढ़ाया है, आज राजस्थान की विधान सभा में यह प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उस शिक्षक की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हमारी भी आंख में आंसू आते हैं, वे भावनात्मक रिश्ते आज नहीं हैं। यह विचारणीय, सोचनीय प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारें आती हैं, जाती हैं, सरकारें अलग-अलग अन्दाज से काम करती हैं, लेकिन मैंने पहले कहा है कि शिक्षा विभाग में सरकार का प्रतिबिम्ब दिखता है, सरकार का आईना दिखता है। जिस तरह से अभी बामनवास से आने वाले, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं रामचरितमानस की एक चौपाई बताता हूं-

'जाको प्रभु दारुण दु:ख देई।
ताकि मति पहले हर लेई।।'

शिक्षा विभाग में इन्होंने ध्यान दिया होता, राजस्थान के नौजवान के लिए काम किया होता, राजस्थान के युवा के लिए काम किया होता तो आज ये विपक्ष में नहीं बैठते। 19 में से 17 बार पेपर आउट नहीं होते और राजस्थान के नौजवानों के मन में इनके प्रति प्यार और स्नेह होता, लेकिन उनके मन और दिमाग से वह चीज निकल चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, जब 2000 से 2005 में मैं सरपंच था, देवगांव ग्राम पंचायत से आता हूं, मेरे गांव में दसवीं का स्कूल था, 2003 में जब वसुन्धरा जी की सरकार बनी, हम 20 बार गाड़ियां लेकर वसुन्धरा जी से स्कूल क्रमोन्नत कराने के लिए आये। जब हमारी स्कूल क्रमोन्न्त हुई तो मुझे अच्छे से याद है कि गांवों में कन्धों पर बैठाकर सात घंटों तक जुलूस निकाला गया। ज्यों-ज्यों 2013 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनीं, उनके मन में सोच थी कि राजस्थान में 9 हजार 175 पंचायतें हैं और साढ़े 4 हजार ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकंडरी स्कूल हैं।

मेरे गांव की बेटियां दसवीं पढ़ने के बाद 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए दूसरे गांव में दूसरी पंचायत में पढ़ने जाती थीं, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर सेकंडरी स्कूल नहीं था और 2015 के बजट में राजस्थान के इतिहास में साढ़े 5 हजार सीनियर सेकंडरी स्कूल राजस्थान की सरकार ने क्रमोन्नत करके, कि मेरी बेटियां 12वीं पढ़ने के लिए दूसरी ग्राम पंचायत में नहीं जाएंगी। आज मुझे गर्व है यह कहते हुए कि पूर्व शिक्षा मंत्री और आज के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब उस समय शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो आमूलचूल परिवर्तन किये, उन परिवर्तनों का यही है कि स्कूल

के अन्दर बच्चों के रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर और ज्यादा हो गये थे।

राजस्थान की जनता राजस्थान के सरकारी स्कूलों पर भरोसा व्यक्त करने लग गयी थी। इसका कारण था सरकार की समुचित सोच, सरकार की अच्छी सोच। अच्छी सोच का मतलब कि हर स्कूल के रजिस्ट्रेशन से, कि विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन क्या है, शाला दर्पण एक पोर्टल बना, उस पोर्टल पर उस शिक्षक की एजुकेशन की पात्रता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ कि यह कहां तक पढ़े हैं और विद्यार्थी कितने हैं, उसी अनुपात में उनके प्रमोशंस हुए, उसी अनुपात में शिक्षक वहां पर दिये गये कि कितने हैं, नहीं तो पीछे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 35 बच्चों पर 13 अध्यापक पढ़ा रहे थे। 35 बच्चों में 2 अध्यापक दिये गये।

निश्चित रूप से वे चीजें, वह 2013 से 2018 का समय याद आता है, लेकिन जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो निश्चित रूप से आप सबको पता होगा कि क्या हुआ। निजी शिक्षण संस्थानों की आज किस तरह से मनमानी है, इन भौतिक परिस्थितियों में, इस चुनौती भरे प्रतिस्पर्धा के युग में आज सरकारी स्कूलों की हालत क्या है और हमारी हालत क्या है, प्राइवेट स्कूलों की हालत क्या है, जबकि संसाधनों की कमी नहीं। हमारे पास जमीन है, अच्छी लोकेशन पर जमीन है, लेकिन सरकारी स्कूल सर्वाइव नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह चिन्ता का विषय है, यह सोचने का विषय है। इस पर हम सबको चिन्तन करना चाहिये। यह नहीं कि हमने ऐसा किया, आपने वैसा किया।

अभी बहुत से मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार का बजट 10 जुलाई, 2019 को पेश हुआ। पेज नं. 31 के पैरा 131 में ''नयी नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से नये कॉलेज खोले जाएंगे'', उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ 2 लाइनें थीं, तीसरी लाइन नहीं थी। एक भी नया कॉलेज सरकार ने नहीं खोला। पैरा 132 में ''राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक सम्पदा का अधिकार नीति लागू की जायेगी'', माननीय सभापति महोदय, पूरे एक साल में एक भी सही कॉलेज कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 2019 में नहीं खोली।

आया 2020, 20 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ। पेज नं. 28 के पैरा 101 में लिखा, ''आरएसएलडीसी के माध्यम से 10 हजार छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा।'', पैरा 102 में ''प्रदेश के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो लैक्चर्स सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कॉन्टेंट बैंक की स्थापना की जायेगी'', आपके सम्मानीय नेता का भी आप ध्यान नहीं दे पाये। उनके नाम से योजना चालू की और उसको धरातल पर लागू नहीं कर पाये। यह कौन-सी सोच है, यह कौन-सा विचार है और आप कहते हैं कि हम हमारे नेता के लिए, हम हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे आदर्श के लिए जीते हैं। पैरा 103 में ''नये कॉलेज खोलने की नीति निर्धारित करने की घोषणा करते हैं'' और एक भी नया कॉलेज 2020 के बजट में नहीं खोला।

तीसरा बजट 24 फरवरी 2021 को आया। पेज नं. 19 के पैरा 45 में जोधपुर और जयपुर

में दो मूकबधिर नवीन महाविद्यालय खोले और पैरा 48 में कहा कि 10 नये महाविद्यालय और 13 नये कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। मैं राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को उसमें बधाई दूंगा कि हमारी जो पूर्व मंत्री थीं किरण माहेश्वरी जी, उनका स्वर्गवास होने पर कुंवारिया के अन्दर राजसमन्द में उनके नाम से एक कॉलेज की स्थापना की। उसके लिए हृदय के अन्तःस्थल से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने विपक्ष के एक नेता के नाम से कॉलेज दिया।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 23 फरवरी 2022 को जो बजट आया, उसमें 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद जब 2023 का बजट आया। 2023 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को पता था कि हमें चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है, किस मुंह से जाएंगे, पूर्व मुख्य मंत्री जी ने 2023 के बजट में 108 राजकीय महाविद्यालय नये खोलने का निर्णय लिया।

MKD/RTM/04.03.2025/18.30/30

कितना बड़ा काम किया है कि आपको चार साल दिखा नहीं कि राजस्थान के नौजवान का क्या होगा, राजस्थान के आने वाले भविष्य का क्या होगा। उन 95 सामान्य शिक्षा के कॉलेज, तीन विधि महाविद्यालय, 10 एग्रीकल्चर कॉलेज।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, वहीं हमारे राजस्थान की, भजन लाल जी की सरकार ने 2024 के 10 जुलाई के बजट में प्रदेश के अन्दर एक साथ 13 नये कॉलेज खोले, 8 कन्या महाविद्यालय खोले, पीजी से यूजी 25 कॉलेजों में दिया।

श्री सभापतिः श्री अमित चाचाण जी।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): दस कन्या महाविद्यालय खोले और 2025 के बजट में भी...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): 000

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा और उच्च शिक्षा की मांग पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीएगा, उतना दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि चाहे पैरों में चप्पल, जूतें न हो, लेकिन हाथ में किताब होनी अति आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्र का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है।

माननीय सभापति महोदय, आज पक्ष और विपक्ष के साथी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गुरुजन का स्थान आज पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च है। गुरुजन का हम आदर, मान, सम्मान करते हैं। जब प्रारम्भिक क्लास में बच्चा प्रवेश लेता है तो वह एक माटी के पुतले के समान होता है और शिक्षक अपनी शिक्षा और संस्कार के द्वारा जिस सांचे में ढालना चाहे, उस सांचे में वह बच्चा ढल जाता है।

शिक्षक अपने पूरे जीवनकाल के दौरान हजारों, सैकड़ों बच्चों को, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आरएएस हो, बनाने का काम एक शिक्षक ही करता है। हमें भी सोचना होगा उस शिक्षक के बारे में कि हम उसको मजबूती प्रदान करें, उसके मन में एक विश्वास प्रदान करें। जो शिक्षक अपने स्कूल के प्रति समर्पित रहा हो, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहा हो और दृढ़ इच्छा के साथ उस स्कूल के परिणाम को आगे बढ़ाने का काम करता है तो हमें भी उन्हें सम्बल देने का काम करना चाहिए।

आज हम देखते हैं, इस दौर में विद्यालयों में शिक्षा के साथ गैर-शैक्षणिक कार्य इतने अधिक हो रहे हैं कि वह शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय सरकार के अन्य कार्यक्रमों में बीजी रहता है, यह भी हमें सोचने की बात है। उस शिक्षक को हमें, इसके साथ-साथ आज शिक्षक कोई न कोई विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होता है। राजनैतिक पार्टियों से भी जुड़ा होता है, लेकिन जिसकी भी सरकार आती है, उसको प्रताड़ित करने के लिए दूर दराज उसका ट्रांसफर किया जाता है, जबकि यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो उस बच्चे का भविष्य बनाने का काम करता है। अगर कोई शिक्षक गलती करता है, अगर उसका व्यवहार सही नहीं है तो उसका ट्रांसफर भी होना चाहिए, एपीओ भी होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने गरीब के बच्चे का दर्द जाना और जो समय की मांग थी कि इस युग में जिसमें आज हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत अधिक है, गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा पा रहा था, उन्होंने एक नवाचार किया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की। आज जो साथी उसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष में ये साथी बैठे थे, किसी भी साथी ने विरोध नहीं किया। विपक्ष के साथी तो डिमांड करते थे कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने चाहिए।

आज ये कह रहे हैं कि आपने हिन्दी के विद्यालय बन्द कर दिये, लेकिन आप सबको भी यह पता है कि हिन्दी के विद्यालय बन्द नहीं हुए। ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वहीं खोले गये, जहां एक दूसरा विकल्प हिन्दी मीडियम का था। जहां दो-दो स्कूलें हिन्दी मीडियम की चल रही थीं, दूसरी जगह वे इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गईं। बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से, चाहे वे हिन्दी मीडियम स्कूल में पढ़ें, चाहे वे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्योंकि आज की यह मांग है। आज का दौर है कि प्रत्येक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कमजोर और गरीब तबके के बच्चे, जो धन के अभाव में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनके दु:ख दर्द को दूर करने के लिए मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह नवाचार करने का काम किया।

भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इन्हें गरीब, दलित, मजदूर से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो सदैव निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया। ये अपने गिरोबान में नहीं झांकते, ये 2013 से 2018 की उपलब्धियां तो गिना रहे हैं। आप यह भी तो बता देते कि बीस हजार स्कूलों को आपने बन्द करने का जो काम किया था। वे स्कूल जिनको किसी

दानदाता ने बनाई थी, भामाशाह ने बनाई थी। जिन विद्यालयों पर उनका नाम लिखा हुआ था और आज जब वे विद्यालय बन्द हो गये थे, उस दानदाता भामाशाह के मन में पीड़ा हुई कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भवन, आज ये भवन जर्जर हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है।

इस सरकार ने भी वही परिपाटी अपनाते हुए विद्यालयों को बन्द किया। आप कहते हो नामांकन कम है। आपके एक स्कूल बन्द करने से अगर एक भी बच्चा आउट होता है, तो यह सरकार की नाकामी है। हमें उन बच्चों का, जो हमारा उज्ज्वल भविष्य हैं, जो हमारे परिवार, समाज के उज्ज्वल भविष्य हैं, जो आगे बढ़कर हमारे परिवार और समाज का नाम रोशन करता है, आज हमें सामूहिक रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि उसमें मूलभूत सुविधाएं कैसे पूरी हों, उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, यह हमें सामूहिक प्रयास करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे नोहर में भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। उस विद्यालय में लॉटरी के द्वारा एडमिशन किया जाता है, इतनी संख्या में आवेदन कर रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की हम बात करें। आप बार-बार कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने तो मात्र कॉलेज खोल दिये, उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जब कॉलेजों की घोषणा की तो क्या आपने भवन बनाने के बाद घोषणा की थी, क्या आपके कॉलेज नये भवनों में चल रहे हैं? पहले घोषणा होने के बाद वह सामूहिक प्रयास होता है। सदस्यों का भी प्रयास होता है कि वे किसी दानदाता, भामाशाहों को तैयार करें, जिससे वह भवन जल्दी बन सके।

मेरे 70 साल के इतिहास में एक मात्र राजकीय महाविद्यालय था, वह भी 40 वर्ष पूर्व बियानी परिवार के स्वयं के प्रयासों से खोला गया था।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

40 वर्षों में अनेक जनप्रतिनिधि आये, एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खुला, लेकिन गत पांच वर्षों में 5-5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने दी।

मैं इस मंच से धन्यवाद दूंगा हमारे उसी बियानी परिवार को कि 40 वर्ष बाद भी उन्होंने गौरी शंकर बियानी के नाम से 6 करोड़ रुपये लगाकर कन्या महाविद्यालय खोलने का काम किया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला। आज 500 से ज्यादा बालिकाएं उस विद्यालय के अन्दर पढ़ रही हैं। पल्लू में जो कॉलेज हुआ, चार करोड़ में लगभग उसकी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। कृषि कॉलेज की जो हमें सौगात मिली, 10 करोड़ रुपये से उसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। आईटीआई कॉलेज की जो हमें सौगात मिली, उसकी जमीन का भी आवंटन हो चुका है, दो बार उसकी निविदाएं भी लग चुकी थीं, लेकिन वे

निविदाएं किन्हीं कारणों से निरस्त हो गईं, पुनः निविदा लगाई गई है।

जो संस्कृत महाविद्यालय खोला था, उसकी भी ढाई करोड़ रुपये की निविदा आमंत्रित की गई है। 5-5 राजकीय महाविद्यालय एक कार्यकाल में खुलना, युवाओं के सपने को साकार करने का काम मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया था। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया था। 400 से 310 नये कॉलेज खोले, उसमें 130 बालिका कॉलेज खोले, क्योंकि युवा जब पैसे का अभाव होता था तो शिक्षा बीच में छोड़ देते थे। जब उनके घर के समीप शिक्षा नहीं मिलती थी, वह बालिका शिक्षा छोड़ देती थी। उनके घर के समीप कोई भी बालिका महाविद्यालय नहीं है। यह काम मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया। चाहे आप आलोचना कितनी भी कर लें, लेकिन धरातल पर जाकर देखिये आज पूरे राजस्थान के अन्दर कहीं भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का विरोध नहीं हो रहा है। किसी भी गांव में विरोध नहीं हो रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि विरोध नहीं कर रहा है। फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह हमारे समझ से बाहर है। शायद यह महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ, इसलिए आप यह नहीं चाहते कि यह काम हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कल्लासर, स्वरूपसर, नहराणा ढाणी, रायका और बीदासर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय किया जाए। जो वंचित विद्यालय हैं, उनमें खेल मैदानों के निर्माण कार्य करवाया जाए। जो हमारे रिक्त पद हैं, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद तमाम रिक्त पदों को भरा जायेगा, स्थानांतरण नीति बनाई जायेगी, लेकिन न तो आपने उन पदों को भरने का काम किया, न ही आज आपने स्थानांतरण नीति बनाने का काम किया।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं, जो हमारे भामाशाह ने कॉलेज बनाया नर्मदा देवी बियानी कॉलेज, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसमें वाणिज्य और विज्ञान के संकाय को खोलने का काम करें। जो पिछले 40 वर्षों से हमारा नर्मदा देवी बियानी कॉलेज चल रहा है, उसमें विभिन्न संकाय स्ववित्त पोषित चल रहे हैं, उसमें भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उसको राजकीय संकाय करने का आप काम करें।

इसके अलावा इन विद्यालयों में आज भी हमारे कमरों की आवश्यकता है, उनमें कमरों के निर्माण कार्य करवाया जाए। जिन मूलभूत सुविधाएं की हमें विद्यालयों में आवश्यकता है, हम उनकी पूर्ति करवायें जिससे कि हम हमारे आने वाले उज्ज्वल भविष्य को एक अच्छी और गुणवत्ता की शिक्षा दे सकें, हमारे परिवार का, समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बहुत से महाविद्यालयों में भी पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को भी आप आरपीएससी के माध्यम से भरें, जिससे बच्चों को अच्छी और गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 20, 21 और 22 पर

मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से आज हमको पक्ष विपक्ष को भूलकर इस शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम अच्छा काम करें, यह सबको सोचने की आवश्यकता है।

प्रकृति के परिवर्तन, ऋतुओं के बदलने और बसन्त के आगाज के साथ, जहां एक ओर सृष्टि के जीवन में उमंग और उल्लास का संचार होता है।

Bhs/Rtm/04.03.25/18.40/3p

वहीं दूसरी ओर मानव के लिये शिक्षा प्राप्ति हेतु नयी सकारात्मक ऊर्जा का संचार मां सरस्वती के करकमलों द्वारा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन ही शिक्षकों के शिक्षण के लिये किये गये प्रयासों का परिणाम होता है। एक मात्र शिक्षक ही होता है जो बच्चों को ऊंचाइयों का रास्ता दिखा सकता है एवं मार्गदर्शन कर सकता है। यदि शिक्षक नहीं होगा तो संसार में घट रही घटनाओं का हमको पता ही नहीं लगेगा, ऐसे में माननीय सभापति महोदय, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने वर्ष 2021 और 2023 के बजट में प्रदेश के कई विद्यालय खोले, जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, किसी विद्यालय में कक्षा कक्ष पूर्ण नहीं हुए, किसी विद्यालय में चारदीवारी का अभाव था। हमारी सरकार आने के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं भजन लाल जी सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र महवा में जो बिल्डिंगें खराब थीं, जिन पर पूर्ववर्ती सरकार में ध्यान नहीं दिया गया, उसमें करीब 2 करोड़ 53 लाख रुपये की स्वीकृति मेरे अकेले महवा विधान सभा क्षेत्र में हुई है और करीब 80% काम सभी विद्यालयों में हो चुका है, ताकि आने वाली बरसात के समय में छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

मैं पूर्ववर्ती सरकार के समय में 2022 में मेरे विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं बाकी मैं करीब चार-पांच उदाहरण दे रहा हूं कि मेरा दुल्हेपुरा जो सीनियर सेकंडरी स्कूल है, 13 पद स्वीकृत किये थे, पांच वहां पर कार्यरत हैं। भेड़को में 13 पद स्वीकृत किए थे पूर्व सरकार ने, चार वहां पर पद अभी चल रहे हैं और अम्बेडकर कॉलोनी में दो पद स्वीकृत किए गये थे, लेकिन अभी तक वहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा के लिये बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर अभी तक वो उतरी नहीं हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने इस बजट में बहुत सारी ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में घोषणायें की हैं निश्चित रूप से आप, हम सब मिलकर उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज वर्तमान समय में बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा परेशानी, वर्तमान में स्थिति यह है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि एक नीति बनाई जाये ताकि आने वाले समय में तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण

किया जाये, क्योंकि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर हुए थे, उसके बाद आज तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ।

सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मैं ये कहना चाहूंगा सदन को कि अगर विद्यालय में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो पानी की दिक्कत है इसलिये शिक्षामंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बच्चों को पानी के लिये बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिये पूरे प्रदेश के अंदर सभी विद्यालयों में पानी की व्यवस्था कम से कम होने की आवश्यकता है।

साथ ही, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मेरे राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय महुआ को अभी क्रमोन्नत करके यू.जी. से पी.जी. किया गया है, लेकिन वहां पर कमरों की बहुत जबरदस्त कमी है इसलिये मैं चाहता हूं करीब 10 कक्षा कक्ष का निर्माण वहां होना चाहिये और जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सहभागिता से सभी भामाशाहों के द्वारा करीब 20 साल पहले वहां पर बनाई गई थी, लेकिन उसकी चारदीवारी का बड़ा अभाव है, इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर चारदीवारी भी हो जाये तो निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी। राजकीय महाविद्यालय मण्डोर में भी काफी रिक्त पद चल रहे हैं, उनको भी भरा जाये। बालाहेड़ी में महिला कॉलेज की स्थापना हो, यह मैं मांग करता हूं आपसे। वर्तमान में एक वर्ष के कार्यकाल में मैंने मेरे विधायक कोटे से लगभग 11 राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी के लिये पैसा दिया है और करीब 80% काम उन लाइब्रेरीज का हो चुका है।

साथ ही, जो परिसर होता है विद्यालय में उसमें भी बच्चों को बैठने की कई बार दिक्कत होती है जब भी फंक्शन होते हैं, तो मैंने मेरे विधायक कोटे से भी इंटरलॉक ईंट निर्माण कार्य वहां पर चालू किये हैं, यह मेरे अकेले का काम नहीं है, यह सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकगण बैठे हैं, मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार पर भी निर्भर नहीं रहते हुए अपन को भी सरकार ने जो पैसा दे रखा है तो उस शिक्षा पर भी अपन को लगाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो।

एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार शिक्षकों के ऊपर बड़ी विपदायें आती हैं, उनको बचाने के लिये कई बार हम भी प्रयास करते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षकों की समस्या के लिये एक उपखंड स्तरीय 8-10 लोगों की ऐसी कमेटी बनाई जाये कि जब भी शिक्षकों को कोई विपदा आये, आपत्ति आये तो वो पूरे कमेटी के लोग उस शिक्षक को सुन कर उसका निदान करे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो क्षेत्र है कि अगर शिक्षा को हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का और हमारी तहसील का भी नाम होगा, क्योंकि शिक्षा अगर हमारे पास नहीं है और शिक्षा को हमने बढ़ावा नहीं दिया तो निश्चित रूप से हम विकास नहीं कर पायेंगे इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिये मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि

आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो रीति-नीति जो शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में घोषणा की है उसको धरातल पर उतारने का काम करें ताकि आने वाला हमारा देश का भविष्य ऊंचाइयों पर जाये और हमारे प्रदेश का नाम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चेतन पटेल कोलाना।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, शिक्षा और उच्च शिक्षा पर बोलने का मौका दिया सदन में, जिसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में यह तय हुआ कि 6% of the GDP has to be spent on education. Are we really spending this amount on education? यह आज सोचने का विषय है, 6% ऑफ जी.डी.पी. केंद्र सरकार क्या शिक्षा के उपर देती है? 4.1% टू 4.6% जी.डी.पी. का इस बजट में दिया गया है और हमारे राज्य सरकार में अगर हम बजट की बात करें इस बार तो हेल्थ और एजुकेशन का 28.25% इस बार इस बजट में दिया हुआ है, इसमें हेल्थ भी आ गया और एजुकेशन भी आ गया। आज जो शिक्षा की स्थिति है, गहलोत सरकार के बारे में मैं बाद में आऊंगा पर जो 400 स्कूल बंद किये गये और गत गहलोत सरकार में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गये उनको बंद करने का काम इस सरकार ने किया। और अभी की ताजा-ताजा खबर 14 फरवरी की मैं आपको बताऊं कि इस सरकार में जो काम हो रहा है शिक्षा के ऊपर, स्कूल और आंगनबाड़ी में खोल दिये पशु अस्पताल। आंगनबाड़ी, बच्चों की कक्षा में पशुओं का इलाज हो रहा है। यह न केवल शिक्षा बल्कि पशु चिकित्सा पर भी सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। टीचर्स लगा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा में साढ़े तीन लाख में से डेढ़ लाख के आस-पास पद खाली हैं और ये खबर है 29.07 की इसमें शिक्षा विभाग में डेपुटेशन बैन, इस आदेश के बाद 27 जिलों में हो गये 111, डेपुटेशन। अगले दिन माननीय मंत्री जी का आदेश निकलता है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व शिक्षकों का डेपुटेशन निरस्त होगा ये बात हैं 26.07.2024 और आज मार्च, 2025 में भी यह स्थिति है कि मेरे पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में और आप के गृह जिले में, माननीय शिक्षा मंत्री जी, तीन शिक्षक डेपुटेशन पर लगे हुए हैं सुलतानपुर तहसील में और पीपल्दा तहसील में 20 शिक्षक, आपके आदेश करने के बाद भी 20 शिक्षक डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, यह सोच का विषय है।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारों का, समाज का आज विज्ञान पर कम और धर्म पर ज्यादा रुझान हो गया है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए क्योंकि धर्म से ही हम संस्कार ग्रहण करते हैं, इससे ही हमारी संस्कृति है, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए क्योंकि यह देश विज्ञान से चलेगा, संविधान से चलेगा और जहां आज हमारे को जरूरत है कि हम जमीन के नीचे ढूंढें, जमीन के नीचे पानी ढूंढें, खनिज ढूंढें, तेल ढूंढें, वहां आज क्या ढूंढा जा रहा है? मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। यह आज शिक्षा का स्तर हमारे देश में हो चुका है, जो बहुत

सोचने का विषय है और यही प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो देश के मुखिया हैं, यही सन्देश वो देश को देते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो मंगलसूत्र भी आ जाता है और जब उनको गरज पड़ती है, जब कतर से अमीर शेख आते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़कर उनको गले लगने एयरपोर्ट में वो चले जाते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है।

Kas/rtm/04.03.2025/18.50/3q

यह सोचने का विषय है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप पंचायती राज मंत्री भी हैं, वैसे तो आज शिक्षा पर चर्चा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके गृह जिले में प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू, सरपंच नसीर बानो, अमीनी पठान जो पहले बीजेपी में थे, बाद में कांग्रेस में आ गये, उनकी क्रिकेट अकादमी तोड़ दी गई, क्योंकि वो फोरेस्ट में जगह आती थी। जब तक वो बीजेपी में थे तब तक कोई फोरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब सबका साथ, सबके विकास की बात होती है, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम आप पर ज्यादा बोझ नहीं देना चाहते, हमको हमारे विधायक कोष से पीपल्दाकलां गांव में मदरसा के लिये 10 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, जगह आवंटित हो गई। जो भूमि आवंटित हुई, वह आबादी क्षेत्र से दूर है, उसकी एएस निकल गई, टीएस निकल गई, एफएस निकल गई, उसके बाद उसका काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद उस पर विरोध दर्ज करवा दिया गया। काम चालू होने के बाद भी उस काम को रुकवा दिया गया। विरोध तो हर चीज में होते हैं, किस चीज में नहीं होते? लेकिन इस विरोध को खतम करना प्रशासन का दायित्व बनता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मोदी जो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, वह दिखना भी चाहिये।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

सुल्तानपुर के पास दरबीजी में एक बच्ची की मौत हो गई। शौचालय की छत उस पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। जर्जर भवनों की स्थिति हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसके लिये मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराता हूं, वैसे तो मैं बहुत बार पत्रों के माध्यम से भी आपको अवगत करा चुका हूं, पर हो सकता है कि नहीं पहुंचा हो, मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराता हूं। उकल्दा के नये कक्षा कक्ष हेतु सरकार को अवगत कराया गया, उसकी छत गिर गई थी, गनीमत रही कि बच्चे उसकी चपेट में नहीं आये। इसी के साथ मेहदी, कोटडापुरा, किशोरपुरा, खूमला जागीर (ब्लॉक सुल्तानपुरा) एवं बंजारी, छतरपुरा, लाखूनी, अमरपुरा, चकखेडली, आडागेला, गणेशपुरा, झोपडियों, संग्रामपुरा, मदनपुरा, खेडली महाराजा, उम्मेदपुरा जो कि ब्लॉक ईटावा में है, इनके जर्जर कक्षा कक्ष के स्थान पर नये कक्षा कक्ष की स्वीकृति प्रदान करने का आप कष्ट करें। साथ ही पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दाखुर्द, झाडौल एवं खेडलीकाल्या,

बालिका मंडावरा, छापोल एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय झोपडिया को क्रमोन्नत कराने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। इन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से स्थानीय बच्चों को शिक्षा में फायदा मिलेगा, आप इस पर भी ध्यान देवें। खातोली सीनियर सेकण्डरी स्कूल में जीव विज्ञान, होम साइंस, चित्रकला संकाय खोला जाये।

सभापति महोदय, शिक्षकों की कुछ मांगे मुझे प्राप्त हुई हैं, उससे माननीय शिक्षा मंत्री जी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिस पर आप ध्यान देवें, क्योंकि शिक्षक अगर तनाव मुक्त रहेगा, तो निश्चित रूप से वह बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पायेगा, शिक्षा का अच्छे से विकास हो पायेगा। शिक्षकों को 7, 14, 21, 28 एवं 32 वर्ष पर चयनित वेतनमान दिया जाये। संस्कृत शिक्षा विभाग में डीपीसी की प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ की जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा की जाये। स्थायी स्थानांतरण नीति लागू की जाये। स्थानांतरण में डिजायर व्यवस्था बन्द की जाये। अध्यापकों के सभी संवर्गों के स्थानांतरण शीघ्र खोले जाये। शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाये। कंप्यूटर अनुदेशक का पदनाम कंप्यूटर शिक्षक किया जाये। प्रयोगशाला सहायकों को 1997 से अध्यापक मानते हुए समस्त लाभ दिये जायें। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी के व्याख्याता के पद सृजित किये जायें। सभी नवसृजित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये। वर्ष 2024 में आरपीएससी की विज्ञप्ति में उर्दू टीचर के लिये टीएसपी क्षेत्र में मात्र 9 पदों की राजस्थान में विज्ञप्ति जारी की गई। आज एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी भी उर्दू पढ़ते हैं, इसलिए यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा में आती है। एक बार विज्ञप्ति निकलने के बाद लगभग 5 वर्ष का समय निकल जाता है। इसलिए उर्दू संकाय के पद इस विज्ञप्ति में और बढ़ाये जाये।

सभापति महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ईटावा में कृषि महाविद्यालय खोला जाये, क्योंकि हमारा पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। वहां 12वीं कक्षा तक कृषि के विषय की पढ़ाई करवाई जाती है, इस पर आप ध्यान दें।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालय ईटावा में तीन शिक्षकों को तीन साल पूर्व कोटा जिले से अन्यत्र डेपुटेशन पर लगाया गया था, जिसके कारण ईटावा राजकीय महाविद्यालय में अन्य पदों के साथ-साथ तीन महत्वपूर्ण सहायक आचार्यों के पदों की कमी चल रही है। ईटावा के राजकीय विद्यालय में विज्ञान संकाय की सीट भी स्वीकृत करवाई जाये। इस मांग को लेकर स्थिति यह बन गई है कि बच्चों को अनशन पर जाना पडा। तीन दिन के अनशन के बाद उनको भरोसा दिलवाया गया, तब जाकर उन्होंने आमरण अनशन तोड़ा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र पर ध्यान देते हुए इन मांगों पर ध्यान दें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उदयलाल डांगी।

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-22 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत किये बजट में प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाने वाले क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा है। साथ ही प्रदेश के युवाओं के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाओं से आहत युवाओं के लिये हमारी भाजपा सरकार ने युवाओं के सुनहरे अवसर को सुरक्षित करने एवं रोजगार देने के उद्देश्य से नई भर्तियां करने की घोषणा की। इन युवाओं के लिये न सिर्फ सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई, बल्कि इनकी कौशल क्षमताओं को विकसित करने हेतु नई योजनाएं लाई गईं।

सभापति महोदय, शिक्षा विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। विद्या के मंदिरों में चरित्रवान और संस्कारी पीढ़ी तैयार की जाती है। मेरा मानना है कि विद्यालयों में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाये जिससे बचपन से ही उनके नैतिक मूल्यों का विकास हो और हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो एवं राष्ट्र प्रेम उनके लिये सर्वोपरि रहे। आज पीएम श्री योजना विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं विकसित करने का सफल माध्यम बनी है। योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों में लगभग 3 लाख 15 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य के 4 हजार से अधिक विद्यालयों में 18 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये गये हैं। पिछले एक साल में लगभग 33 हजार मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट वितरित किये गये हैं, इससे वो डिजिटल तकनीक से जुड़ कर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री जी के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरोली, बटेवर, हिता में विज्ञान संकाय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभ नगर, अमरपुरा, खालसा, रूंडेरा में कृषि विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भावपुरा, पचोरिया, आवरा, टांक, खाना तालाब, खापुरिया का खेडा, खुसरिया, रामाखेडा, कडेचा, मूडीखेडा, भमेला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। आलूखेडा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को हिन्दी माध्यम में करवाने की कृपा करावे। इसके बजाय बांसडा में बामनिया में हिन्दी मीडियम को इंग्लिश मीडियम करने की कृपा करें। साथ ही 54 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत वरनी के गांव कलवल में प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी, सन 1985 में यह विद्यालय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ, अब इस विद्यालय में प्रति वर्ष बच्चों के नामांकन में निरंतर कमी आ रही है, ग्रामवासी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिये भेज रहे हैं। इस गांव में हिन्दी माध्यम का एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम वासियों की मांग अनुसार

ब्लॉक भिंडर के कलवल में हिन्दी माध्यम का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की कृपा करें।

Msk/rtm/04.03.25/1900/4a

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र के महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति और मांग के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी से मैंने कॉलेज खोलने का निवेदन किया, 13 महीनों के अल्प कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र को दो कॉलेज दिये। तकनीकी शिक्षा में वल्लभनगर में, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं कानोड़ में राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं। वर्षों से की जा रही मांग को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के कानोड़ नगर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुआ है। महाविद्यालय स्वीकृत होने से पूर्व कानोड़ तहसील के सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु उदयपुर जाना पड़ता था, मगर अब कानोड़ में महाविद्यालय संचालित होने के कारण छात्र/छात्राओं को काफी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, भिण्डर में एक नवीन महाविद्यालय खोलने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। भिण्डर के आसपास कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से छात्रों को कॉलेज की शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। ऐसे में कई गरीब विद्यार्थी 12वीं के बाद कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भिण्डर में एक नवीन महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें या भिण्डर स्थित कन्या महाविद्यालय को सामान्य महाविद्यालय में बदलने की कृपा करावें। साथ ही, इस महाविद्यालय में कला संकाय चल रही है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसमें विज्ञान संकाय को भी जोड़ा जाये, जिससे छात्राओं के साथ-साथ छात्रों को भी कॉलेज शिक्षा अपने घर के निकट मिल सके, वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें।

सभापति महोदय, एक राजकीय महाविद्यालय वल्लभनगर में संचालित है। यहां कला संकाय के सात विषय चल रहे हैं। इसके साथ ही विज्ञान संकाय भी इसी कॉलेज में खोलने की मांग करता हूं। वल्लभनगर के कॉलेज में 21 स्वीकृत पदों में से कई पद खाली हैं, इन पदों पर भरने की मांग मैं सरकार से करता हूं। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ घोषणाएं सरकार बचाने के लिए कीं, लेकिन सरकार बची नहीं, चली गयी। कुछ थोथी घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं में वल्लभनगर के भटेवर में आई टी कॉलेज की घोषणा की, जिसका कोई अता-पता नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर संज्ञान लें व संसाधन एवं आधारभूत संरचना की व्यवस्था करें। भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट जारी करावें, ताकि वहां के स्थानीय छात्रों को इसका लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): ...(व्यवधान)... घूमकर आया हूं। सभापति महोदय, आज शिक्षा के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री

जी, आप टीचर्स तो लगा नहीं पा रहे हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि कम से कम, आप मास्टर नहीं लगा पा रहे हैं, जो गर्ल्स स्कूल हैं और जहां गर्ल्स की संख्या, मेरे राजाखेड़ा में जहां-जहां 100-100 गर्ल्स पढ़ रही हैं, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। आप स्वच्छ भारत मिशन में, मैं आपको बता भी देता हूं, आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप डवटेल करा लीजिये। आप हमको डांग विकास बोर्ड का पैसा दे रहे हैं, आप कलेक्टर्स को यह कह दीजिये कि डांग विकास बोर्ड से पानी की टंकियां, हैंडपम्प लग जायें, जिससे इन बाथरूमों के टॉयलेट्स की गन्दगी से हमारी लड़कियां बच सकें, क्योंकि लड़कियों को बाथरूम जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमने अपनी कोशिश की। मेरे जमाने में, मैंने इसके लिए एम एल ए फंड से काफी पैसा दिया है, लेकिन फिर भी हर स्कूल में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि कम से कम राजाखेड़ा में जहां 100-100 लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां पर आप इन टॉयलेट्स को बनाने की कृपा करें। स्वच्छ भारत मिशन से कर लें। यदि नहीं हो रहा है तो डांग विकास से ले लें। आपने डांग विकास का पैसा दिया है ना। डांग विकास में हमारे यहां कम से कम 16 से 18 पंचायतें आ रही हैं और दोनों को मिलाकर 30 पंचायतें डांग विकास में आती हैं तो उससे हम पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि यह गाइडलाइन, क्योंकि दोनों प्रभार आपके पास हैं। आप यदि रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री को गाइडलाइन दे देंगे तो हमारे दोनों काम हो जायेंगे।

दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि सी एस आर का पैसा आ रहा है। सी एस आर का पैसा, जितनी कम्पनीज हैं, सी एस आर का सब पैसा या तो हेल्थ में चला जाता है, एजुकेशन में वह पैसा नहीं आ रहा है। सी एस आर का जो भी पैसा है, वह आप कोशिश करें कि सी एस आर का पैसा आप शिक्षा विभाग में लेकर आयें। आप टोटल 200 करोड़ का बजट दे रहे हैं और इतने सारे स्कूल पड़े हैं, हमारे अपग्रेड हो गये। जो केन्द्र सरकार की जो नयी शिक्षा नीति है, उसमें 10 वाले स्कूल 12 वाले में हो गये। यह राज्य सरकार ने तो किये नहीं। वह तो आपकी पॉलिसी थी, उसमें 10 से 12 उनको करने थे। उसमें न टीचर्स दे पाये। आप यह कह रहे थे कि आपके जमाने में टीचर्स नहीं है, आपने क्या किया? 2202 व्याख्याताओं की आपने की, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2200 व्याख्याताओं की पोस्ट खाली है और आपने पूरे राजस्थान में 2202 पोस्टें निकाली हैं। अपन क्या मजाक कर रहे हैं? आपको सिर्फ यह ब्लेम करने में मजा आता है कि पिछली सरकार ने किया, आपने डेढ़ साल में क्या कर दिया? आप ब्लेम गेम खतम करिये। इस सरकार का हनीमून पीरियड खतम हो चुका है। लोग-बाग अब आपको देख रहे हैं कि कि आप कैसे काम कर रहे हैं।

हमारे कॉलेज शिक्षा मंत्री जी कहां गये? 385 करोड़ की स्कूटियां कबाड़ हो रही हैं। एक भी स्टूडेंट को नहीं मिली हैं। 385 करोड़ के कंपनियों के स्टॉक पड़े हुए हैं, गोदामों में। वे कबाड़ हो रही हैं। साहब, क्यों नहीं बांट रहे हैं? किसने आपको मना किया? आप यह तो कम से कम बांटिये। यह तो पेपरों की कटिंग है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां कॉलेज

एजुकेशन डायरेक्टर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? What are we doing? तो यह सब आपको देखना पड़ेगा। आज राजसेस के जो टीचर्स लगे हैं। जो राजाखेड़ा, मणिया और मरेना में राजसेस के टीचर्स लगे थे, जो हमारी भरतपुर वाली यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलियेटेड हैं, उन राजसेस के सब टीचर्स को निकाल दिया। वहां स्टूडेंट के कोर्स आज भी नहीं हो रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने यहां अनाउंस किया था कि हम एक भी नहीं निकालेंगे और वहां पर एक भी टीचर नहीं है। न उनके 45 पीरियड पूरे हुए, न उनके कोर्सेज पूरे हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है। यह सिर्फ बात करने से और यहां पर यह कहने से कि हम यह कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब यह काम खतम हो गया है। आपको राज करते हुए डेढ़ साल हो गये हैं, पर नीचे जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कूल के अन्दर न कोई टीचर है। प्राइमरी टीचर्स तक तो स्कूल में हैं नहीं, जहां 100-100, 150-150, 200-200 बच्चे हैं, उन प्राइमरी स्कूल को आप मिडिल स्कूल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। वहां बच्चे पढ़ने के लिए कहां जायेंगे? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में हर प्राइमरी स्कूल में 200-250 बच्चे हैं, वहां आप मिडिल स्कूल में बच्चों को कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हैं। धौलपुर वालों ने भी तो बीजेपी को वोट दिया था। वहां सिर्फ कांग्रेस के एमएलएज हैं तो आपने एक स्कूल को भी अपग्रेड नहीं किया। पूरे बजट में कुछ नहीं किया। क्या वहीं काम होगा, जहां सिर्फ बीजेपी के एम एल एज हैं? यह तो मत करो। पता पड़ा, इस बार तो जीरो आया था, पता पड़ा पूरा भरतपुर संभाग आपको जीरो कर देगा। यदि इसी तरह की आपकी हरकत चलती रहेगी तो मेरी आपसे फिर विनती है कि जहां प्राइमरी स्कूल में 150-150, 200-200 बच्चे हैं, उनको मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करिये। आप कुछ तो करिये, एक करिये, दो करिये, पांच करिये, दस करिये, जो भी आपकी इच्छा है, कुछ तो करिये। जीरो तो मत लगाइये। क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो, बजट के अन्दर विंडो ड्रेसिंग करने के अन्दर, बजट इतना दे दिया, काम जीरो करते हो।

आपको मैंने इतनी कितनी सारी स्कीम्स दिखा दीं, जहां आपने कुछ काम ही नहीं किया है, डेढ़ साल के अन्दर। फाइनेंस बिल में भी आपको बता दूंगा कि आपने क्या किया है। वे फीगर्स भी मेरे पास आये हुए हैं। फाइनेंस बिल में आपको यह बता दूंगा कि क्या करेंगे, आपने क्या नहीं किया है। मेरी आपसे विनती है कि कॉलेज एजुकेशन में जो राजसेस के टीचर्स हैं, उनको मत निकालिये, बच्चों को पढ़ने दीजिये। नहीं तो बच्चे आपके खिलाफ सड़क पर उतरकर आ जायेंगे। जैसे कल बाड़मेर में हुआ है कि 2202 व्याख्याताओं के लिए बाड़मेर में प्रदर्शन हुआ है, बच्चों ने प्रदर्शन किया है। आपके पास जगह खाली पड़ी है, 40 हजार है। आप निकाल रहे हैं, 2203, 'ऊंट के मुंह में जीरा' भी नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपसे पुनः विनती करता हूं कि गर्ल्स एजुकेशन में राजाखेड़ा और मनिया ब्लॉक में जहां पर भी गर्ल्स पढ़ रही हैं, कम से कम वहां टॉयलेट बनाइये। आप हमको अलाऊ करिये कि डांग विकास से हम इसका विकास कर सकें, स्कूलों का विकास कर सकें। डांग विकास

में, जहां-जहां हमारे पास कमरे कम हैं, यदि आपके पैसा नहीं है तो हमें अलाऊ करिये कि हम डांग विकास से उन स्कूलों में कमरे भी बनाएं, बाथरूम भी बनाएं, टॉयलेट्स भी बनायें। यदि आपका शिक्षा विभाग इसको सपोर्ट नहीं कर सकता तो हम डांग विकास से ही कर लेंगे। उसकी गाइडलाइन आपके पास है। धन्यवाद।

mdp/rtm/04.03.25/19:10/4b

श्री सभापतिः डॉ. प्रियंका चौधरी।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 व 22 पर चर्चा करने का समय दिया। आज चूंकि शिक्षा का विषय है तो मैं सबसे पहले अपने प्रथम गुरु माता-पिता, दूसरे गुरु मेरे शिक्षक, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे शिक्षा दी, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इस लायक बनाया कि सदन में आऊं, उन सबको मैं आज नमन करती हूं सदन के माध्यम से।

आज हम इस सदन में बैठे हैं, ये लोकतंत्र का पवित्र मन्दिर है। लोकतंत्र का अर्थ हम सब जानते हैं, 'जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए।' जब सरकार ने हम सभी जन-प्रतिनिधियों को इस सदन में भेजा है तो बहुत विश्वास के साथ भेजा है कि जैसा हाल पिछले पांच साल में हुआ था शिक्षा का, युवाओं का छात्रों का, वह शायद इस बार नहीं होगा। अभी आदरणीय माननीय सदस्य बाड़मेर की बात कर रहे थे कि वहां जो युवा हैं, वे आंदोलन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि पिछली विगत सरकार के अन्दर चूंकि 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, वही बाड़मेर के नौजवान थे, जब हम उनसे मिलते थे तो खून के आंसू रो रहे थे। वे किसानों के बच्चे थे, जिनकी मेहनत की कमाई पिछली विगत सरकार में बर्बाद हुई और आज अगर वह छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें विश्वास है कि यह सरकार संवेदनशील है और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से भर्तियां निकाली हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। इसी भरोसे के साथ वह छात्र आंदोलन कर रहे हैं।

आज का जो विषय है शिक्षा, मैं मानती हूं कि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है। यह विषय है मनन का, चिंतन का। आज हम यहां बैठकर उस युवा, उस छात्र की बात कर रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य है। मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे मन की शांति बढ़े, जिससे बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये राजस्थान के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे भारत के अन्दर साक्षरता दर में हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। केवल 66 परसेंट साक्षरता दर है। मेरी बहिनें तो 28 परसेंट पुरुषों से कम साक्षर है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस विषय पर सकारात्मक चर्चा हो। लेकिन मैंने देखा पूरे सदन में जब चर्चा हुई तो चर्चा किस बात पर हुई दीवार टूट गयी, रंग पर चर्चा हुई, फोटो पर चर्चा हुई और ऐसे अनावश्यक, आदरणीय बापू

महात्मा गांधी जी के नाम पर विवाद हुआ। इन विवादों से मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई सकारात्मक परिणाम आयेगा। हर सरकार आती है, सबका अपना विजन होता है, सबकी अपनी नीति होती है, सबकी अपनी पॉलिसी होती है।

मैं याद करना चाहूंगी आदरणीय भैरोसिंह जी शेखावत साहब को, जिन्होंने शिक्षा नीति में, उन्होंने गांव की सोची, गरीब की सोची और उन्होंने पंचायत स्तर पर एक 8वीं, उच्च प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए, यह निर्णय किया। उसके बाद आदरणीया पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने फिर से गांव में बैठे गरीब बच्चे की चिंता की और पंचायत स्तर पर 10वीं स्कूल की शुरुआत की। फिर जब वे पुन: सरकार में आयीं तो उन्होंने हर पंचायत पर 12वीं स्कूल को क्रमोन्नत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि क्रमोन्नत किया और क्रमोन्नत करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उस वक्त आदरणीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं वासुदेव देवनानी जी, उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कई नवाचार किये और उनका प्रयास था। इसलिए उस वक्त सिर्फ 10 परसेंट जो पद थे, वही रिक्त थे। हां, पिछली विगत सरकार ने पॉलिसी अच्छी बनायी कि हां, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिलनी चाहिए। स्कूल क्रमोन्नत होने चाहिए, लेकिन आपने उसके लिए कोई न तो भौतिक संसाधन, न वित्तीय संसाधन, न कोई सोच रखी, न कोई नीति रखी, न कोई विजन रखा।

जो शिक्षा का स्तर आज गिरा है, उसके लिए हम सब कहीं न कहीं दोषी है, इसलिए इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जो शिक्षा नीति 2020 लाए। पी.एम. उषा योजना लाए, पी.एम. श्री विद्यालय लाए और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे राजस्थान को लाभ होगा। जो अभी खाली पदों की बात आयी, वह बिलकुल सही बात है कि स्कूलें क्रमोन्नत हो गयी, लेकिन उन नव क्रमोन्नत स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि जो नव क्रमोन्नत स्कूल हैं, उनमें पद सृजित किये जाएं। विगत सरकार ने जो किया, वह कर दिया, लेकिन अब हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले। इसके लिए शिक्षकों का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए।

चार साल से पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है, अगर विगत सरकार ने कर ली होती तो आज इतनी समस्या नहीं होती। जो नवीन भर्ती निकाली है, उसमें मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से कि वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की जो संख्या है, वह बढ़ाई जावे।

मैं बाड़मेर जिले की बात करूं तो यहां की जनसंख्या 26 लाख है और घनत्व बहुत कम है, 92 पर्सन पर किलोमीटर है। साक्षरता दर अगर देखें तो राज्य की साक्षरता दर से भी कम है। यहां जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जो साक्षरता दर है उसमें 30 परसेंट की कमी है। मैं आज इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने विद्यालय स्तरीय सावित्री बाई फुले छात्रावास बाड़मेर विधान सभा में खोलने की इस प्रोजेक्ट में घोषणा की। महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास इस बजट

सेशन में खोलने की घोषणा की। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से मेरी वहां की बेटियों को, बहिनों को पढ़ने का मौका मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी अनेक योजनाएं हैं।

मैं मांग करती हूं कि वहां का चूंकि सामाजिक और आर्थिक माहौल ऐसा है, इसलिए नये बालिका स्कूल और खोले जाएं। राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक भूगोल सब्जेक्ट में आवश्यकता है। वह संकाय खोला जाए। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि जो बच्चियां कॉलेज जा रही है, उनके कॉलेज के अन्दर ही वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए जाए तो निश्चित रूप से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी हो सकती है। हमारे बाड़मेर जिले से एन.सी.सी. कैडेट के माध्यम से 26 जनवरी को परेड में कर्तव्य पथ में एक बच्ची गयी। बाड़मेर जिले से ही एक बच्ची फाइटर प्लेन की पायलट बनी है तो मेरी मांग है कि एक बालिका सैनिक स्कूल बाड़मेर जिले में खोला जाए। अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हो रही थी। माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि स्टेशन रोड हाई स्कूल, उसमें 2018-19 में 574 स्टूडेंट्स थे। इस स्कूल में हर सब्जेक्ट है। साइंस की बहुत बड़ी लैब है। यहां आदरणीय मुख्य मंत्री जी और अभी जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, इन्होंने भी विजिट किया था और स्टेट लेवल का विज्ञान मेला लगा था। जब से इंग्लिश मीडियम उसको कंवर्ट किया गया है, तब से छात्र संख्या मात्र 112 हो गयी है। इतना रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट घट गया है। मैं मांग करती हूं कि ये बहुत बड़ी स्कूल है और बाड़मेर जिले की बहुत पुरानी स्कूल है, इसको दो पारी में संचालित किया जाए।

अर्द्ध घुमंतू और घुमंतू समुदाय के लिए जालोर की तर्ज पर बाड़मेर में भी छात्रावास खोला जाए। नीति आयोग के मुताबिक बाड़मेर राजस्थान का सबसे गरीब जिला है। 56 परसेंट लोग गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को और मंत्री जी को, जिन्होंने पोलोटेक्निक कॉलेज में सिविल की नई ब्रांच शुरू की और साथ ही केमिकल ब्रांच की सीटों में भी वृद्धि की गयी। मैं मांग करती हूं कि बाड़मेर जिले की संभावनाओं को देखते हुए आर.आई.टी. की स्थापना बाड़मेर में की जाए। जब कृषि कॉलेज की बात करते हैं तो विगत सरकार ने बहुत सारी एग्रीकल्चर की कॉलेज खोल दी, लेकिन नियमित भर्ती नहीं की। आज बाड़मेर कृषि कॉलेज की यह स्थिति है कि वहां 28 पद हैं, लेकिन एक भी कार्मिक वहां उपस्थित नहीं है। 150 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी टीचर, एक भी शिक्षक वहां नहीं है। केवल एक टीचर आता है जो एक्जाम कराने केलिए आता है। शीघ्र इन पदों की भर्ती की जाए।

अंत में मैं इतना कहूंगी कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि 3500 की जनसंख्या पर उन्होंने हर पंचायत में एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा 6 से कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। राइट-टू-एजुकेशन की तरह राइट-टू-प्ले कानून बनाया जाना चाहिए। जिला स्तरीय, राज्य

स्तरीय प्रतियोगिताओं में जो खुराक भत्ता दिया जाता है, वह बहुत कम है। उसको बढ़ाकर 250 पर-छात्र करना चाहिए। पी.एम. श्री स्कूल्स, जो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने खोली हैं, उनमें भी शारीरिक शिक्षा का व्याख्याता का पद स्वीकृत करना चाहिए। मैं मानती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी और आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी बोलने में कड़े हैं, लेकिन मन से बहुत अच्छे हैं।

Ans/rtm 19.20 4c 04.03.2025

अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि नये टीचर्स को बाडमेर, जैसेलमेर भेजो और पुराने एक्सपीरियंस को इधर लाओ, तो यह गलत है। बाड़मेर भी राजस्थान का ही हिस्सा है। सीमांत में बैठे हैं, रक्षा करने के लिए बैठे हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि शिक्षा मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक बाड़मेर ज़िले पर अपनी नजर रखेंगे और शिक्षकों व छात्रों के हित में अपना कार्य करेंगे।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, आपने शिक्षा पर मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम शिक्षा की मांग पर विचार कर रहे हैं। किसी देश-प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा के बिना किसी देश व प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता जिस प्रदेश में होगी वह प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज हमारे बच्चे शिक्षा लेते हैं, 11वीं पास कर लेते हैं, बी ए, एम ए कर लेते हैं, लेकिन उनका माइंड फर्टाइल नहीं होगा शिक्षा से, तो हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता।

एक बात बहुत ही अचंभित है कि जब भी सरकार बदलती है, नई सरकार आती है वह पुरानी सरकार की नीतियां, उनकी योजनाएं बंद करने की कोशिश करती है और आप तो इस चीज में माहिर हो। वाह-वाह, बहुत माहिर हो। आप अपनी राजनीतिक विचारधारा से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, उसी के हिसाब से सिलेबस बनाना चाहते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह सरकार है, सरकार आती जाती है, इसलिए किसी सरकार की एक योजना बनती है, सरकार द्वारा कोई नवाचार होता है, अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो कितना खर्चा होता है, कितना समय बरबाद होता है, यह देखने की बात है।

मैं सुबह से सुन रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया, थोथी घोषणाएँ कर दीं, यह सारी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। स्कूलें खोल दी, अनाप-शनाप स्कूलें खोल दीं, कॉलेज खोल दिये, विश्वविद्यालय खोल दिये, अँग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोल दिये, आई आई टी व आई टी आई खोल दी। खोले ही तो है, हमने किसी चीज को बंद करने की योजना तो नहीं बनाई। सरकार बनते ही आपका यह पहला स्टेटमेंट था कि हम अँग्रेज़ी स्कूल बंद करेंगे, आपने कमेटी बना दी।

सभापति महोदय, हम लोग आज शिक्षा पर बात कर रहे हैं, अगर एक स्कूल बंद होती है तो बहुत तकलीफ होती है। आप मर्ज के नाम पर स्कूलें बंद कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताइये, अगर संख्या कम है, नामांकन कम है तो आपके यह प्रयास होने चाहिए कि नामांकन कैसे बढ़े और वह स्कूल कैसे अच्छे से संचालित हो। एक बच्चा भी ड्रॉप आउट होता है वह बहुत खतरनाक बात है, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो, मंत्री महोदय, आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... हमने नीतियां बनाई, हर ग्राम पंचायत पर सीनियर स्कूल खोले, हर ब्लॉक में एक कॉलेज खोला और 11वीं व 12वीं में बालिका अगर किसी भी स्कूल में है तो उसमें कॉलेज की घोषणा की, कोई करके तो दिखा दो।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी अँग्रेज़ी मीडियम स्कूल, आज इनको बंद करने की बात चल रही है। मैं मेरे साथियों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या एक गरीब बच्चे को इंग्लिश पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसको अधिकार है। आज गरीब का बच्चा इस अँग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहा है। आप और हम सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़ी-बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपके पोते-पोतियां कहां पढ़ रहे है? बताओ। आपके पोते-पोतियां महंगी अँग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक गांव के बच्चे के लिए स्कूल खोला, स्कूल ऐसे ही नहीं खोला, स्कूल एक सोच के साथ खोला। सबसे पहले ज़िले के अन्दर खोला, उसकी सफलता को देखकर एक ब्लॉक में खोला, उस ब्लॉक की सफलता को देखकर गांव में स्कूल खोला और आप कहते हैं कि आपने स्कूल को उसी स्कूल में खोल दिया। गांव की रजामंदी ली गई, गांव वालों के कहने पर अँग्रेज़ी मीडियम स्कूल खोला गया। प्रयास यह रहे कि जिस गांव में दो विद्यालय है उनमें एक अँग्रेज़ी खोला जाए, लेकिन लोगों की डिमांड थी। मैं कहना चाहता हूं, आप यह विचार छोड़ दीजिए कि अँग्रेज़ी स्कूल बंद करेंगे, नहीं तो चार साल बाद आप जाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): सात में से एक आई।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): एक आई मतलब?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): सात में से एक आई राजस्थान में।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की बता दो? ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं अँग्रेज़ी स्कूल में कोई कमी है, कमी हो सकती है एक नवाचार है, इस कमी का सुधार कैसे हो इस पर विचार होना चाहिए। अच्छे टीचर नहीं है तो टीचर लगाने चाहिए, सलेक्शन करना है तो सलेक्शन करिये, अँग्रेज़ी स्कूल में भर्ती करिये, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आप में यह सब काम करने का माद्दा नहीं है, बंद करने की बात सोचते हो।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह सबके लिए सोच का विषय है कि आज शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। आज हमारी स्कूलों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फैक्ट्री बना दिया है। शहरी स्कूल में तीन महीने प्रतियोगी परीक्षाएं चलती है। ग्रामीण क्षेत्र में

या तो टीचर जाते नहीं है या वह स्कूलें खाली है। आज हमारी शिक्षा के यह हालात हैं कि तीन महीने स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तीन महीने छुट्टियां रहती है और तीन महीने या तो अध्यापक छुट्टी पर रहते हैं या बच्चे छुट्टी पर रहते हैं। साल में नौ महीने का समय जाता है, तीन महीने में हम कौनसी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय, आज 25-30 नम्बर आते हैं और पास हो जाता है। अध्यापकों पर यह दबाव रहता है कि 100 परसेंट रिजल्ट लाओ, कहां से लाएंगे? सारा काम तो हम दूसरा करवा रहे हैं। कितनी सूचनाएं लेते हैं आप स्कूलों के अध्यापकों से? चुनाव कराते हैं, बी एल ओ बुलाते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य में सारा समय बरबाद होता है और हमारा राजस्थान का बच्चा सफर कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

VPS-RTM-04.03.2025-19.30-4d

माननीय सभापति महोदय, सरकार बनते ही कहा, बड़े जोर-जोर से कहा कि हम एक साल के अन्दर-अन्दर सारे रिक्त पद भर देंगे। क्या हुआ? टांय-टांय-फिस्स, क्या हुआ बताओ? मंत्रीजी, बताओ तो सही, आप बहुत सीनियर सदस्य हो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अभी बताऊंगा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): एक फरवरी तक माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 लाख 71 हजार 126 पदों से 1 लाख 16 हजार 442 पद रिक्त हैं। आपके द्वितीय श्रेणी अध्यापक 8,332, लेवल द्वितीय के अध्यापक 4,387, लेवल फर्स्ट के 6,286 और शारीरिक शिक्षक के 1,184 पद खाली हैं। बीस हजार पद खाली पड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमने स्कूल खोले, निश्चित रूप से खोले लेकिन फिर सरकार बदल गयी तो आपका काम क्या है यह बताओ मुझे? क्या आप हमारी कमी ही निकालते रहोगे कि पिछली सरकार ने यह कर दिया, पिछली सरकार ने यह कर दिया पर आप क्या करने वाले हो? स्कूल हमने खोले हैं तो आप अध्यापक लगाइये, कौन रोक रहा है आपको? आपको राजस्थान की जनता ने बैठाया है यहां पर तो आप यह काम करिये, लेकिन हमने स्कूल खोले, पद भी स्वीकृत किये। चार वर्षों में 6,273 सीनियर स्कूलों में 19 हजार पद रिक्त हैं। प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के 52 हजार पद रिक्त है। आपने सबसे छोटी भर्ती केवल 4,331 की निकाली है जो 12 साल में सबसे छोटी भर्ती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब कॉलेज शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे उप मुख्य मंत्रीजी बहुत भले आदमी हैं और एकदम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस सरकार ने, हमारे प्रदेश के ये बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करें तो क्या उनको यह अधिकार नहीं है? हमने एक योजना बनाई, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना बनाई, आपने नाम बदल दिया तो कोई बात नहीं। बदलने का तो यह है कि आप बदलते ही रहते हो नाम तो, यही काम बचा है, बस, बदलिये। हमारा 500 छात्र

प्रत्येक साल भेजने का निर्णय किया था। आपने उसको 300 कर दिया। कर दीजिए, कोई बात नहीं लेकिन अब हालात क्या बने हुए हैं? आपके कमिश्नरेट के चक्कर काट रहे हैं लोग। 2024-25 में आवेदन तो आपने मांग लिये लेकिन सूची क्यों नहीं निकाल रहे? आप बताओ तो सही सदन को। आप जवाब दें तो बताना इस बात को कि उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने बाहर, विदेशों में यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए एडमिशन ले लिया, वे पढ़ना चाहते हैं तो आप कम से कम अपनी नीति तो स्पष्ट करिये। आप नीति ही स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आप सूची जारी करेंगे या नहीं करेंगे? यह बता तो दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): नहीं करेंगे या करेंगे?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपके सदस्य अभी बोल रहे थे कि विदेश में पढ़ाने पर ज्यादा खर्चा लगता है तो हमारे यहां ही ऐसी संस्थाएं डवलप करें जिनसे वे वहां नहीं जाएं और यहां पर ही पढ़े। यह आपके ही सदस्य बोल रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह गुरवीरजी बोल रहे थे, यह आपके ही सदस्य हैं, आप यह ध्यान रखो। गुरवीरजी ने बोला है। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, यह बात सही है कि हमें भी ऐसी शिक्षण संस्थाएं डवलप करनी चाहिए जहां हमें विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक तो यह नीति हो गयी, लेकिन यह तो सोच ही नहीं है आपका। आपका सोच ही नहीं है। ठीक करने का काम तो है ही नहीं आपके पास, आप तो बंद करना जानते हो। आप तो बंद करना जानते हो तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं, राजस्थान के बच्चे विदेश में पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है, उनके माता-पिता बहुत चिंतित हैं तो कृपा करके आप इन बच्चों की फीस का भुगतान करवा दें तो आपकी बहुत-बहुत कृपा होगी। बहुत-बहुत बधाई देंगे हम सब लोग आपको।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपसे ज्यादा दी है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैं यही तो बोल रहा हूं कि फीस का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यह योजना आनन-फानन में लागू की गयी है। इसकी केटेगरी बनायी गयी है। ई-1, ई-2, ई-3, यह कैटेगरीवाइज बनायी गयी है और उस कैटेगरी को आपने भी माना है। आपने कमिश्नरेट के अन्दर स्टाफ भी लगा रखा है। सरकार का खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। आपके मन में क्या है, मुझे पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अब मेरा समय हो जायेगा। नहीं, अभी नहीं हुआ। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं। तारानगर में चार महाविद्यालय है, चार महाविद्यालय। एक महिला, बालिका महाविद्यालय, एक लड़कों का कॉलेज है और एक साहवा के अन्दर कॉलेज है। आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। साहवा के अन्दर कॉलेज खुला, 12 करोड़ रुपये एक दानदाता ने लगाये हैं। क्या शानदार कॉलेज खुला है। मुख्य मंत्रीजी भजन लालजी ने उसका उद्घाटन किया है। मुख्य

मंत्रीजी के द्वारा उद्घाटित कॉलेज जिसमें मात्र एक लेक्चरर है और वह भी कार्य व्यवस्था में लगा हुआ है। आप थोड़ा बहुत तो देखो। मुख्य मंत्रीजी ने उद्घाटन किया है तो उप मुख्य मंत्रीजी, आपका यह फर्ज बनता है कि आप तुरंत वहां पर स्टाफ लगायें। चारों कॉलेजों में ही यही हालत है। कृषि महाविद्यालय, तारानगर जैसी जगह पर, छोटे से कस्बे में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने तारानगर के अन्दर कृषि महाविद्यालय खोला। खोला है, बिल्डिंग बना दी हमने, क्लासेज चालू हो गयीं, लेकिन एक भी व्याख्याता नहीं है, एक भी पढ़ाने वाला नहीं है। सारे बच्चे स्ट्राइक पर, आंदोलन पर, भूख हड़ताल पर, लेकिन ताकत से, उनको पुलिस से उठा-उठाकर जबरन अस्पताल में डाल दिया गया। यह हालात है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तारानगर के अन्दर जो मेरी कॉलेजेज हैं। राजकीय कृषि महाविद्यालय मां जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय, तारानगर, राजकीय महिला महाविद्यालय, तारानगर और श्रीमती मोहिनी देवी चाचाण राजकीय महाविद्यालय, साहवा, इनमें खाली पदों को आप भरने का काम करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मुझे यह पूरा विश्वास है आप पर कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे।

आज स्कूलों की हालात ठीक नहीं है। आज स्कूलों में कमरों की कमी है। जर्जर अवस्था में स्कूलों के कमरे हैं, उनमें पढ़ने को मजबूर है बच्चे। पेड़ों के नीचे बैठते हैं। एक-एक कमरे में तीन-तीन क्लासेज लगती हैं, चार-चार क्लासेज लगती हैं। क्या पढ़ेगा बच्चा हमारा? हम किस ओर ले जा रहे हैं राजस्थान को? आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। आपको इस दिशा में सोच कर प्राथमिकता से, अभी एक साथी यह कह रहे थे कि विधायक कोटे से, आप तय करिये न, कौन रोक रहा है आपको? आप तय करिये। कोई मना नहीं है लेकिन आप भवन जो जर्जर हो गये हैं, जहां पर भवनों की कमी है, वहां पर आप भवन बनाइये, यह मेरा निवेदन है।

ssy/rtm/04.03.2025/19.40/4e

अभी दो घटनाएं हुई हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक मानपुरा है। उस मानपुरा के अन्दर एक दानदाता ने कुछ सालों पहले एक गेट बनाया, मरम्मत के नाम पर उस गेट को हटा दिया और दूसरा गेट लगा दिया। कौन देगा दानदाता? मैं कहना चाहता हूं, अधिकारी बैठे हैं यहां पर, ऐसा जुल्म मत करो कि दानदाता द्वारा बना हुआ, उसका सम्मान छीनने का काम आप कर रहे हो। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप तुरंत उस गेट का वापस लगाइये।

भलाऊ टीबा के अन्दर, मैंने भी डायरेक्टर साहब से थोड़े दिन पहले बात की थी। वहां पर आठवीं की स्कूल अलग चल रही थी, सीनियर की स्कूल अलग चल रही थी। 7 कमरों में स्कूल चल रही थी, उसको हटाकर के 4 कमरों में ले आये, उनमें से 2 कमरे जर्जर हैं। एक में प्रिंसिपल रहता है, एक हॉल के अन्दर 5 क्लास चल रही हैं। क्यों भाई, आपने क्यों बंद कर दिया? आपने जो स्कूल चल रही है, आपने अभी कहा कि 12वीं स्कूल के बच्चों को आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो आप स्कूल बंद कर दोगे? नहीं, गलत बात है

यह। आप इसके ऊपर विचार करिये।

मेरे क्षेत्र के अन्दर सीनियर स्कूल है पूनरास में, गाजूवास में, पूनसीसर में, सरायण में, ढाणी आशा में, इनमें विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता है। मैं मांग करता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से और हमारे शिक्षा मंत्री जी से कि जब भी आपके पास संसाधन हों, जब भी आप खोलें तो इन स्कूलों के अन्दर विज्ञान संकाय खोलने का काम करें। हमारे बास सरायण, अभयपुरा, झांझणी में माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है। लोगों की बड़ी मांग है। मैं मांग करता हूं कि आप मेरी इन मांगों पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, 'मोरया तो जनता ही बुलाती है।' अब मैं एक बात की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आर टी ई में 30 हजार बच्चों की शिक्षा पर संकट मंडराया हुआ है। उनको अधिकार है। आठवीं के बाद, क्या कर रहे हो मंत्री जी? आपने आठवीं के बाद बंद कर दिया और प्राइवेट स्कूलों का रास्ता दिखा दिया। आज उनका अधिकार है बारहवीं की शिक्षा तक। आप बच्चों का भविष्य खराब नहीं करें। उन बच्चों के भविष्य, उनके परिवार के लोगों के सामने जो मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, आप उनके ऊपर ध्यान देंगे, मैं यही बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापतिः हो गई ना सारी बातें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): एक बात और है। अभी तो मेरा टाइम पडा है। हम सब लोग चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे केन्द्र के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, हम सबका एक सपना रहता है, हम सबकी एक इच्छा रहती है कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियां पढ़ाओ। हम बेटियां कैसे पढ़ायेंगे? मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूं कि हमारी बच्चियां स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारी बच्चियों के लिए स्कूलों में टायलेट्स नहीं हैं। आज हालात बहुत खराब हैं। आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप तो क्या ध्यान देंगे, आपसे तो मैं निवेदन कर रहा हूं। आपको बता रहा हूं। लेकिन आप तो स्कूलें बंद कर रहे हैं। आप लड़कियों की स्कूलें बंद कर रहे हैं।

कल बाबूसिंह जी बोल रहे थे कि जोधपुर के अन्दर 450 बच्चियों की स्कूल को बॉयज में मर्ज कर दिया गया। बॉयज स्कूल के अन्दर कैसे पढ़ायेंगे हमारी बच्चियों को? यह क्यों मर्ज कर दिया? बच्चियों की शिक्षा के ऊपर हम सबको बैठकर चिंतन करना चाहिए। आज सबसे बड़ा हमारा जो काम है वह अपनी बच्चियों को पढ़ाने का है। हमारी बच्चियां पढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे जायेगा। आज हम सब इस बात का संकल्प लें कि आने वाले समय में हम बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे।

अंत में निवेदन करना चाहता हूं, छोड़ दीजिये इसको कि तुमने क्या किया और हमने क्या किया। यह तुम, हम की बातें छोड़ दीजिये। बोलना सीखो बोलना, जिंदा व्यक्ति बोलता है, जिंदा व्यक्ति सोचता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो वह बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है इसलिए जिंदे हो जाओ। जनता की आवाज बनकर आओ। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। जनता की आवाज बनकर के हौंसले के साथ प्रदेश के विकास की बात करो। जो कमियां हैं,

उन कमियों को सदन के अन्दर आप उठाने का काम करें। यही बात कहना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लादु लाल पितलिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बुडानिया साहब, गुस्से में पहली बार देखा है आपको। आज क्या वजह है? कोई झगड़ा करके आये हो क्या? इस तरह पहली बार देखा है आपको।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): भैरूंनाथ भगवान की जय, खजूराय श्याम की जय, बाढ़या की माता जी की जय।

माननीय सभापति महोदय, प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा की मांग संख्या 20, 21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लेवल प्रथम की भर्ती में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय का बहुत-बहुत आभार।

माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल 86 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 133 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों, जहां भवनों का अभाव एवं जिन भवनों में मरम्मत की आवश्यकता है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं मरम्मत योग्य भवन के प्रस्ताव मंगवाकर राशि स्वीकृत करने की मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक सुवाना की राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायडा, टीला का खेड़ा, लापलिया खेड़ा, बलाई खेड़ा, रूपपुरा, गाडरी बस्ती, सालमपुरा, मंडप्या, जोतसिंह जी का खेड़ा, डूंगारड़ा, गाडरी खेड़ा, तग़डिया तथा रायपुर ब्लॉक की राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलामली, लक्खा होली, जित्ती, बिकाणी, बोरड़ा खेड़ा, गूजरों का खेड़ा, सहाड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयसिंह पुरा को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्टैंड नहीं है।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारी मात्रा में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। इससे अध्ययन में बाधा आ रही है तथा आये दिन स्कूलों के सामने धरने, प्रदर्शन होते हैं। स्कूलों के ताले लगाये जाते हैं। माननीय, आपके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की मांग करता हूं।

आज आधुनिक तकनीकी का जमाना है। इस कारण तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरे विधान सभा के प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर लैब एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राशि स्वीकृत करने की मांग करता है।

माननीय, विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्राथमिक स्कूलों में आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में पानी, बिजली और शौचालय पर अलग से बजट देने की मांग करता हूं। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल 270 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से प्राथमिक विद्यालयों में 54 केन्द्र संचालित हैं, शेष 216 केन्द्रों को विद्यालयों में स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे राजकीय विद्यालयों का नामांकन बढ़ सके।

माननीय, विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी है। परंतु कई प्राथमिक विद्यालयों के मैदान पर अतिक्रमण हो रखे हैं। आपके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं बजट देकर खेल मैदानों की दशा सुधारने की मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चतुर्थ श्रेणी के पद भारी संख्या में रिक्त हैं।

श्री अध्यक्षः वहीं जाकर के बात करें। इतनी दूर से इशारे नहीं। आप वहां पधारो या बुला लो।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय, सरकार को इन पदों को भरने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्षः मैं तो साफ कहता हूं। आप वहां पधारो या बुला लो।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में आज भी कई प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है।

spp/rtm/04.03.2025/19.50/4f

जिससे आवारा जानवर और कई असामाजिक तत्व विद्यालयों की सम्पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विद्यालयों में चारदीवारी बनाने के लिये बजट घोषणा की मांग करता हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में उच्च शिक्षा के तहत उपखण्ड रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में बालिका शिक्षा में, उच्च शिक्षा में ड्रॉप-आउट रेट कम करना तथा क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना तथा पूर्व में संचालित राजकीय महाविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षा साहित्य विषय खोले जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्षः समाप्त करिये।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा पर विशेष बल दिया गया है तथा इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विविध उपलब्ध किये गये हैं। हमारा प्राचीन ज्ञान संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। अतः संस्कृत भाषा का अध्ययन कर विकास के नये द्वार खोलने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुये स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत विषय खोलने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के साथ-साथ खेलों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, ग्यारह मिनट हो गये।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): राजकीय महाविद्यालय रायपुर के खेल मैदान का विकास होना बहुत जरूरी है जिससे विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास की उचित व्यवस्था प्रकल्पित हो सके, इसके लिए राजकीय महाविद्यालय रायपुर के खेल मैदान को विकसित कर विभिन्न खेलों के कोर्ट तैयार करने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्षः हो गया। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ राजकीय महाविद्यालय रायपुर में लाइब्रेरी का अभाव है। जिसे पूरा करने के लिए... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक घंटी बजाने का कोई अर्थ होता है। घंटी बजाने का कोई अर्थ होता है कि नहीं? बिराजो। दो मिनट पहले बजाता हूँ वाइंड-अप करने के लिये। एक मिनट पहले बजाता हूं वाइंड-अप करो। बोलते जायेंगे तो फिर आसन तो कुछ करें ही नहीं। बिराजो। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2025-26 अनुदान की मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद, आभार। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए किए गए प्रबन्ध के लिये मैं तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रबन्ध किये हैं। प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी भागों को समाहित करके राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करने का काम किया है। नए विद्यालय उनके भवन विद्यालय क्रमोन्नत विद्यालय में नया संकाय खोलना, उच्च शिक्षा में नया महाविद्यालय खोलना, नये संकाय खोलना, तकनीकी शिक्षा में नया ट्रेड खोलना, विद्यालयों में नया भवन निर्माण, विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना, खेल मैदान का विकास, नया स्टेडियम निर्माण ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इनका बजट ज्यादा है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): स्पोर्ट्स ट्रैक, संस्कृत शिक्षा में विद्यालय क्रमोन्नत, कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में आधुनिक डाइनिंग हॉल निर्माण, ओपन जिम निर्माण, युवा साथी केंद्रों की स्थापना, 1000 खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम के लिए प्रशिक्षण के रूप में लगाना सहित सभी प्रकार के प्रबंध से शिक्षा विभाग को सौगात मिलेगी।

मैं यहाँ वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष जी और पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान् वासुदेव देवनानी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान के शिक्षा विभाग को एक सूत्र में जोड़कर एक क्लिक पर विभाग की सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। शिक्षा विभाग में राजस्थान प्रदेश में किये गए नवाचार से आज प्रदेश को नई दिशा

और दशा मिली है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब शिक्षा विभाग की कुछ मांगें रखना चाहूंगा जिसमें सबसे प्रथम मांग प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा यानी राजस्थानी में दिए जाने का प्रबंध होना चाहिए। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, इनकी सराहना करोगे तो एक-आध स्कूल ज्यादा मिल जाएगा, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं वो नहीं, जो सत्य था वो कहा है। कोई गलत नहीं कहा। मातृभाषा यानी राजस्थानी में दिए जाने का प्रबंध होना चाहिए, ताकि छोटा बच्चा अपनी भाषा में ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी कृपा हो जावे तो महाविद्यालय, विद्यालय सब कुछ मिल जाएगा। आपकी मेहरबानी, नजरें इनायत हो जाए। बस इतना ही हमारा निवेदन है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): जल्दी सीख सकते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप में से कोई नहीं बोला। ये भायल साहब अकेले बोले हैं अध्यक्षजी के लिये। हकीकत आप जानते हो ना?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राजस्थान पहला प्रदेश था जो हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पाया था और शिक्षा मंत्रियों के पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष आप बने थे, आपको याद है कि नहीं है? आप बोलो थे कि नहीं?

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय मंत्रीजी, बिराजें। आप दोनों मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भायल साहब बोल गए तो संसदीय मंत्री बोल रहे हैं। सुबह से नहीं बोले आप एक शब्द भी।

श्री अध्यक्षः नहीं, मुझे ध्यान है, माननीय सदस्य मुझे ध्यान है जिस दिन ये बोलना शुरू करेंगे वो तो निहाल हो जाएंगे।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): प्रबन्ध होना चाहिए ताकि छोटा बच्चा अपनी भाषा में जल्दी सीख सकता है। देश के कई राज्यों में ये प्रबंध है तो अपने प्रदेश में भी होना चाहिए और उस स्तर की कक्षाओं में भी राजस्थानी विषय को सभी विद्यालयों में अंग्रेजी की तरह अनिवार्य किया जावे। शिक्षा विभाग में नामांकन के आधार पर अध्यापक होने चाहिए और अधिशेष समायोजन के नाम से जो व्यवस्था चलाई जा रही है, उसको दुरुस्त किया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी शिक्षा में अध्यापकों की कमी है, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो रेगिस्तान हैं, वहाँ जो पूर्व सरकार द्वारा सबको वहाँ जितने भी अध्यापक लगे हुए थे, 50% से ज्यादा वहाँ अध्यापकों की कमी है। इसमें पूर्ति करने के लिए माननीय मंत्री को निवेदन करूँगा कि बाड़मेर रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान में शिक्षक बहुत कम संख्या में हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लगाने की कृपा करावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की ट्रांसफर होनी चाहिए। वर्षों से एक ही स्थान पर है। प्रबोधक का प्रमोशन और उनके नाम परिवर्तन करके अध्यापक करने के साथ इनको भी योग्यता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में समायोजन किया जाए तो विषय अध्यापकों के काफी पद बढ़ सकते हैं। मेरे क्षेत्र में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों के 50% से अधिक पद रिक्त हैं और लेक्चरर भी कई विद्यालयों में नहीं हैं। नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद ही स्वीकृत नहीं, जो 2023 में पूर्व सरकार द्वारा क्रमोन्नत किया गया था, उसमें आज दिन तक पद ही सृजित नहीं किये गये। इस प्रकार की कम से कम 19 स्कूलें हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन की कमी है। संस्कृत शिक्षा में विद्यालय क्रमोन्नत के साथ नया पद स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। राजकीय संस्कृत विद्यालय फौज की ढाणी, सिणधरी, नाकोड़ा में क्रमोन्नत करके 12 वीं तक किया जावे। कटारी संस्कृत विद्यालय में सामाजिक विषय वरिष्ठ अध्यापक के पद स्वीकृत किये जावें। सिवाना क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय विज्ञान का खोलने और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बालिका विद्यालय खोला जावे।

jyg/rtm/04.03.25/20.00/4g

समायोजन में जो विद्यालय बंद हुए हैं, उनको वापस शुरू भी किया जाये। सिवाना के सिणधरी उप खण्ड के होडू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कन्या महाविद्यालय और पादरू उप तहसील मुख्यालय पर नवीन महाविद्यालय खोला जावे। क्षेत्र में समायोजन करके जो विद्यालयों का एकीकरण किया है उनके भवन खाली पड़े हैं, उनमें से कई विद्यालयों को वापस खोलने की मांग आ रही है। इसका ब्लॉक स्तर पर सर्वे करवाकर उनको वापस शुरू किया जाये। समदड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषि विश्वविद्यालय की खाली पड़ी जमीन करीब 90 बीघा है, वहां जोधपुर से नजदीक अगर कृषि महाविद्यालय खोला जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के कृषि महाविद्यालय का फायदा मिल सकता है। समदड़ी में कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पुराने विद्यालय भवन में ही निर्माण की मांग जो शहर के बीचोंबीच है, सिणधरी महाविद्यालय में फर्नीचर का बजट सभी महाविद्यालय एकल व्यवस्था के साथ मात्र एक ही कार्मिक के भरोसे चल रहे हैं। रिक्त पद भरने का प्रबंध किया जाना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों में रिक्त पद अधिक हैं, बड़े-बड़े सिटी में एक ही विषय के एक से अधिक व्याख्याता नियुक्त हैं] जिनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजकर ग्रामीण बालकों को भी राहत प्रदान की जाये। सभी महाविद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, चारदीवारी और शौचालय निर्माण के साथ मूलभूत आवश्यकता वाली सभी मांगों की पूर्ति की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवाना के महाविद्यालयों में नामकरण उस क्षेत्र के महापुरुषों, शिक्षाविद्, शासक, प्रसिद्ध देवी-देवताओं आदि के नाम से किये जाने की मांग, क्षेत्र के 5 महाविद्यालयों के नामकरण की मांग मेरे द्वारा की जा चुकी है, उसको जल्द पूरा किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खाली पद भरने के साथ-साथ पद विहीन विद्यालयों में पद स्वीकृत भी किये जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व जन प्रतिनिधि अपने बालकों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ावें, ऐसी नीति बनायी जानी चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। निजी स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है, इसके लिए भी एक नीति बनानी चाहिए ताकि ध्यान रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए गांव और ढाणी तक स्कूल पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे जी, गांव गरीब और किसान तक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तक बिना भेदभाव एक साथ में 5-5 हजार स्कूलों को क्रमोन्नत करके राजस्थान को तोहफा दिया था। अभी कह रहे थे, बुडानियाजी और रोहित जी, आप कह रहे हो कि आज खाली हैं, एक साल में सारे पद खाली हो गये? शौचालय नहीं है, यह आपकी पांच साल की नीति...

श्री अध्यक्षः अब आप विराजो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया था, इसलिए आप उधर बैठे हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिक्षा के साथ में हर विभाग को बिना भेदभाव, आपको ध्यान होगा, आज भी हर विधान सभा क्षेत्र में कार्य किये हैं, शिक्षा से लगाकर हर चीज को, मैं तो जानता हूं कि मैं अकेला बाड़मेर-जैसलमेर से था, एक धेला भी देने का कार्य नहीं किया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइण्डअप करें। माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आदरणीय जूली जी, इसके लिए शकुन महसूस कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में नीचे से काम होता है, सबको साथ लेकर चलने का काम होता है, चाहे शिक्षा हो, पानी हो। धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्षः आज की बहस समाप्त हो, माननीय मंत्री अपना जवाब दें, मैंने परम्परा भी देखी और व्यवस्था भी देखी, सबसे पहले व्यक्ति, बालक स्कूल में जाता है, उसके बाद उच्च शिक्षा में जाता है और पहले भी स्कूल शिक्षा का जवाब का भाषण पहले आता है, उसके बाद उच्च शिक्षा का है। अतः मैं पुकार रहा हूं माननीय मदन दिलावर। ...(व्यवधान)... अब बार-बार नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये ज्ञान तो हमें प्राप्त ही नहीं था, आज ही प्राप्त हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप लेने की कोशिश करोगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब उस पर आचरण करोगे।

माननीय मंत्रीजी, बोलो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 20 और 21 ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बात और है। आज ये इतने प्रसन्न क्यों हैं, इतने खुश क्यों हैं? गैलरी में कौन बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय, मेरा सबसे आग्रह है, सबसे ज्यादा तो बोलना औरों को चाहिए माननीय संसदीय मंत्री को सबसे कम बोलना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20 और 21 पर लगभग 373 तो कट मोशन प्राप्त हुए हैं और लगभग 33 माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। सबने अपने सार्थक सुझाव दिये हैं, जो सुझाव दिये सार्थक हैं, उनको हम अंगीकार करने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े, कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, लेकिन इसके साथ-साथ, शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी हों और शिक्षा में भी संस्कार का समायोजन होगा, समावेश होगा तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के चार चाँद लग जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्रीमान् भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहले जो बजट पेश किया था, इस बजट से पहले उससे 6.28 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ संस्कार अच्छे इंसान बनाती है, नागरिक बनाती है। अच्छा नागरिक होता है तो समाज अच्छा होता है, इसलिए स्वामी विवेकानन्दजी ने भी कहा था कि शिक्षा ध्येय मनुष्य का सर्वागींण विकास करना है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक, परम श्रद्धेय गुरुजी ने कहा था, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। शिक्षा में संस्कार होना बहुत आवश्यक है लेकिन संस्कार कहां से आयेंगे, संस्कार कहीं बिकते तो नहीं हैं, दुकान पर मिलते तो नहीं हैं, संस्कारों के लिए या तो परिवार है या फिर विद्यालय है। परिवार में मां-बाप हैं, बड़े भाई-बहन हैं, विद्यालय में हमारे गुरुजन हैं। बच्चों के सामने मां-बाप को कैसा व्यवहार करना चाहिए और विद्यालय में हमारे गुरुजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि जनता पूरी निगाह रखती है कि हमारे जो पढ़ाने वाले है अध्यापक, उनकी दृष्टि कैसी है, कैसा पहनावा है, कैसा व्यवहार है, कैसा चाल-चलन है और इसको देखकर ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए मैं कई बार सभी पूज्य गुरुजनों से निवेदन करता हूं कि हमको बच्चों के सामने आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वो हमको देखकर कुछ संस्कार ग्रहण कर सके। इसी प्रकार से मां-बाप को भी रहना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक से अधिक बच्चे पढ़ें, कोई अनपढ़ न रहे इसलिए हमने घर-घर जाकर बच्चों का नामांकन किया, प्रवेश उत्सव मनाया और इसके लिए हमने एप का निर्माण किया, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं और कहीं यदि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो उसके कारण से उसका पता चल जाये। यही नहीं हमने अपार आईडी को भी शामिल किया है, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छी तरह से पूरी दक्षता के साथ प्रवेश

उत्सव मना सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं, वो सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि समय-समय पर उनका सम्मान भी हो, तो साथ में उनके जो अधिकार हैं, प्रमोशन होने के वो भी उनको मिले इसीलिए माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब मैंने शिक्षा विभाग सँभाला तो सबसे पहले मैंने सीट पर बैठते ही एक ही बात कही कि सभी संवर्गों की डीपीसी होनी चाहिए। उसी के कारण से या उस कथन के आधार पर हमारे अधिकारियों ने डीपीसी कार्य प्रारम्भ किया और थर्ड ग्रेड को छोड़कर हमने लगभग सभी डीपीसी कर ली है।

MLS/RTM/04.03.2025/20:10/4h

मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 25 हजार हमारे जो अधिकारी, कर्मचारी थे, उनकी हमने डीपीसी की है। हमने प्रिंसिपल से अधिकारी भी बनाये हैं, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल भी बनाये हैं, सैकंड ग्रेड से व्याख्याता भी बनाये हैं। इस प्रकार से मंत्रालयिक कर्मचारियों की भी हमने की, यानी सारी की सारी डीपीसी हमने की हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले वाली सरकार ने पांच सालों तक सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों का गला घोंटकर रखा, उनको अपमानित करके रखा, प्रमोशंस नहीं किये, जिसके कारण से वे कुण्ठित थे। डीपीसी नहीं की, इसके कारण से प्रमोशंस नहीं हुए और वे लगातार मांग करते रहे, लेकिन उन्हें सुना नहीं। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों का कि पांच साल तक वे कहते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि डीपीसी को न्यायालय में जान-बूझकर उलझाते रहे।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और हमने यह कोशिश की कि छोटी-मोटी जो बीच में अड़चनें आ रही हैं, माननीय न्यायालय से निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को माना और डीपीसी करने की छूट दी। उसके कारण से हम 25 हजार लोगों की डीपीसी कर पाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ पदोन्नतियां कीं, उनमें कुछ गड़बड़ियां भी थीं, अनियमितताएं भी थीं। सगे-सम्बन्धियों को और चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। उनकी भी हम जांच करवाकर दोषियों को नहीं बख्शेंगे।

जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं,
वो समुद्र पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम डीपीसी कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थीं। उनका मैं पहले जवाब दे देता हूं। अध्यापक जो हैं, उनको बीएलओ लगाया जाता है, यह सच है बीएलओ लगाया जाता है, बीएलओ तो लगेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनरी चुनाव के लिए अलग से नहीं आ सकती है, लेकिन मैं चुनाव में लगे जो अधिकारी हैं, जिला कलक्टर्स हैं, एसडीएम्स हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि बीएलओ वहीं का लगाएं, जहां वह कार्यरत है, वहीं बीएलओ को लगाएं। कई बार सिफारिश के आधार पर सौ

किलोमीटर दूर से लाकर बीएलओ लगा देते हैं। वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो बीएलओ लगता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं कि आधे दिन तो उसे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और आधे दिन बीएलओ का काम करना पड़ेगा, लेकिन जिसे सौ किलोमीटर दूर से उठाकर लाएंगे, वह कैसे काम कर सकता है? इससे बच्चों की पढ़ाई सफर करती है। मैं राजस्थान के सभी जिला कलक्टर्स से, चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से बीएलओ न लगाएं।

दूसरा निवेदन यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी हो, किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हमारे यहां से उठा लेते हैं। जिला कलक्टर ऑर्डर कर देते हैं और वहां से कर्मचारी को उठा लेते हैं। हमने कहा कि यदि आपको आवश्यकता है तो हमारे अधिकारियों से बात कीजिये, हमसे बात कीजिये। कितने कर्मचारी चाहिये, हम आपको देंगे, लेकिन कहीं बाड़मेर से, कहीं जैसलमेर से, कहीं झालावाड़ से, कहीं बारां से उठाकर ले आते हैं, वह ठीक नहीं है। जहां आपको काम है, उसी मुख्यालय से आप कर्मचारी लेंगे तो ठीक रहेगा। यह भी मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इस प्रकार का काम करें।

आज नरेन्द्र जी बुडानिया साहब बहुत बातें कह रहे थे, ''हमने नीतियां बनायी हैं''। हां, आपने नीतियां बनायी हैं, बहुत अच्छी नीतियां बनायी होंगी। उन नीतियों का फल क्या रहा? राजस्थान में उप चुनाव हुए तो 7 में से 1 सीट आयी और दिल्ली में जीरो। यह इनकी नीतियों का फल है, इसलिए इन नीतियों का कोई अर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य रोहित बौहरा जी कह रहे थे कि शौचालय नहीं हैं। हां, यह सच है, जब हमने सम्भाला तो 784 शौचालय नहीं थे विद्यालयों में। हमने 2024-25 में 425 शौचालय बना दिये हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में लगभग सारे शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। बहनों को कहीं भी कैसे भी नहीं जाना पड़े, उसका हमारा प्रयास रहेगा।

एक बात और कही, हरिमोहन जी ने कहा कि स्कूल क्रमोन्नत नहीं किये। अब ये पढ़ते-लिखते नहीं तो मैं क्या करूं, ये जानकारी नहीं रखते तो क्या करूं? माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया था, वह लगभग सारे के सारे विद्यालयों के आदेश हमने जारी कर दिये हैं, पर इनको जानकारी नहीं है। कोई जानकारी करना भी नहीं चाहते। इन्होंने यह भी कहा कि जन सहभागिता का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, उसको लगा नहीं रहे हैं। अब ये पता नहीं बिना पढ़े कहां से उठकर आ जाते हैं, क्या समझकर आते हैं, क्या बोलते हैं, इनको यही पता नहीं रहता, 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है इसमें और उसके बदले में जो इनका अंश होता है, टोटल जोड़ते हैं हम लोग तो 41.05 करोड़ के कार्य हमने स्वीकृत कर दिये हैं, इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि जन सहभागिता में जो पैसा है, वह देते नहीं हैं। ये बिलकुल गलत बात कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं की और भर्ती परीक्षा ही नहीं की तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टाफिंग पैटर्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं, हमने एक कोशिश की है कि सभी विद्यालयों में सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाले शिक्षक रहें और छात्रों के अनुपात में हमारे टीचर्स

रहें, सब्जेक्ट के भी रहें और संख्या के आधार पर भी रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कृपा आपकी हुई थी। आप ही यह सिखाकर हमें गये थे। उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही जो ये कह रहे हैं न कि पद नहीं भर रहे हैं, हमने अभी तक 12-13 हजार पद भर दिये हैं। ये तो पद सृजित भी नहीं करके गये थे। इन्होंने इतने विद्यालय खोले, लेकिन पद ही सृजित नहीं किये, भरने की तो बात छोड़ो।

अब हम पद भी सृजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह कोशिश करती है कि यदि विद्यालय खोलना है तो उसके साथ-साथ पद भी सृजित करते हैं और पद भरने की कार्यवाही भी आगे करेंगे, इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि पद नहीं भरे जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीपीसी से हमने काफी पद भर दिये हैं और हम डायरेक्ट भी इन पदों को भरेंगे। इनके कार्यकाल में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती करने का इन्होंने असत्य प्रयास किया और जाकर क्या किया इन्होंने, न्यायालय में अटका दिया या पेपर आउट हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर आउट हो ही गये न। पेपर इन्होंने बेचे और करोड़ों रुपये कमाये। इन्होंने पेपर बेचे और करोड़ों रुपये कमाये। यह धन्धा बना दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने अध्यापकों की भर्ती करने के लिए, कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए, जो उनको भर्ती करना चाहिये था, वह तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी जेबें तो भर गईं, भण्डार तो भर गये और राजस्थान का युवा लुट गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह आरोप सरासर गलत है।

श्री अध्यक्ष: आरोप तो लगते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह आरोप गलत है कि आप अपनी जेब भर रहे थे। यह चीज गलत है। आप आरोप लगाओ, पर ऐसे नहीं, पर्सनल नहीं। आप आरोप लगा रहे हो तो आप जांच करा दो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं लिया किसी का।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हां, हम जांच कराएंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी पार्टी का नाम लिया न कांग्रेस का। कांग्रेस का नाम ले रहे हैं ये। सीधा नाम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नाम लिया होगा तो मैं देख लूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कांग्रेस के लोगों ने, सीधा नाम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पार्टी के तो नाम, भाजपा और कांग्रेस नाम तो आएंगे न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, अध्यक्ष जी, देखो, यह गलत परिपाटी है।

श्री अध्यक्ष: आप भी भाजपा का नाम लेते हैं, आप भी भाजपा सरकार का नाम लेते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, कभी नहीं कहा मैंने। इस प्रकार से नहीं कहा। अध्यक्ष जी, फिर गलत परिपाटी आप डाल रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। नो, नो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, ...(व्यवधान)... 16 जून, 2022 को कुल 5546 पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गयी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये ऐसा कैसे कहेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप भी बोलते हैं। मैंने दिन भर के भाषण सुने हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, इस प्रकार से हम कभी नहीं कहते हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 25 सितम्बर, 2022 को किया गया था। अन्तरिम चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। दस्तावेज सत्यापन 16 नवम्बर, 2022 को हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी... ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सरकारों पर, पार्टी पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस की सरकार कहेंगे, किसकी सरकार कहेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, क्या आरोप लगा रहे हैं ये? ये क्या आरोप लगा रहे हैं? ...(व्यवधान)... ये साबित करें। डेढ़ साल से सरकार में बैठे हैं। क्या माल मारने को बैठे हैं बीजेपी वाले? ये लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): शारीरिक शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का अन्तिम परिणाम 31 मई 2023 को जारी हुआ। मई 2023 में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होते ही एसओजी को फर्जी दस्तावेज ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या आप लोग माल मार रहे हो। आप लोग पैसा कमा रहे हो? आज आप भी धन्धा करते हो क्या पैसा कमाने का? ये बीजेपी ने धन्धा कर रखा है पैसा कमाने का। ...(व्यवधान)... सारे पैसे जनता के आप लूट रहे हो। ...(व्यवधान)... भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे लूट रही है। ...(व्यवधान)... नोट करो मेरा भी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के पैसे लूट रही है। ...(व्यवधान)... करो नोट। और आप लोग खा रहे हैं सारे मिलकर। एक-एक लोग खा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जनवरी 2025 को शिक्षा विभाग द्वारा 134 शारीरिक शिक्षकों को फर्जी डिग्री/दस्तावेज मामले में बर्खास्त किया गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में आओगे तो मैं बरदाश्त नहीं करूंगा। बीच में नहीं, अपनी सीटों पर। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात हुई?

MKD/RTM/04.03.2025/20.20/4j

खुद ये लोग +++ हैं (..व्यवधान..)

श्री अध्यक्ष: दोनों पक्ष जाएं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक पैसा खाने लग रहे हैं, +++ भी पैसे खा रहा है क्या? (..व्यवधान..) इनका +++ पैसे खा रहा है क्या? ये सारे लोग पैसे खा-खाकर छोड़ दे लोगों को (..व्यवधान..) ये बीजेपी पैसे खा-खाकर ही बन रही है। ये गलत परिपाटी मत डलवाओ, फिर कह रहा हूं.. (..व्यवधान..)।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसओजी के पास 1259 अभ्यर्थियों की सूची है, जिनकी डिग्री से लेकर नियुक्ति संदेह के घेरे में है और इन अभ्यर्थियों का डाटा मिस मैच पाया है, 161 अभ्यर्थियों में से 132 ने आवेदन के समय जिस यूनिवर्सिटी की अंकतालिका लगाई, कार्यग्रहण के दौरान अंकतालिका और यूनिवर्सिटी के नाम अलग पाए गए। 1039 परीक्षार्थी ने आवेदन भरते समय और फिर दस्तावेज सत्यापन के दौरान पेश की गई जानकारियों में भारी असमानताएं पाई गईं, जैसे अंकलातिका, रोल नम्बर, यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नम्बर, डिग्री और पास करने के वर्ष में असमानता पाई गई। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास एक ही वर्ष में तीन-तीन अलग-अलग विषयों की फर्जी डिग्री मिली है। जिसका उपयोग उसने अलग-अलग भर्तियों में किया था। जांच में जो खुलासा हुआ, उसके अनुसार चयनित हुए अधिकांश अभ्यर्थियों के पास विवादित 18 विश्वविद्यालयों की डिग्री इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका है, जो कि सन्देह के घेरे में है।

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाएं, नो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है और इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको विलोपित किया जाता है, आरोप बाय नेम हो, बाय पार्टी का नाम हो, इन्होंने पार्टी का नाम लिया। सदन अच्छा भला चल रहा है, सारे लोग उपस्थित हैं, सुबह से सुन रहे हैं, अब जब अन्त होने लगा, कल एडजॉर्न होनी है, उस वक्त एक साधारण सी बात है, यह अपनी तरफ से जो भी आरोप घड़े, लेकिन यह कहना कि इन्होंने अपनी जेबें भर लीं और भर ली, यह संसदीय परम्पराओं में नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसको कृपया विलोपित करवा दें। सदन अच्छा भला चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं तो उसको विलोपित कराने में कोई बात खराब हो रही है। मंत्री महोदय, अपनी बात रख रहे हैं,सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया।

श्री अध्यक्ष: दिन भर में इधर से भी बोलते रहे, उधर से भी बोलते रहे, यह चीजें हमेशा रही हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नहीं, कोई आरोप नहीं लगाता है। आपने यह बना दिया कि कोई आरोप नहीं लगा रहा है।

श्री अध्यक्ष: व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, जो सदन का सदस्य नहीं है। वह नहीं लेंगे, वह यदि होगा, किसी का नाम होगा तो मैं विलोपित करूंगा। पार्टी तो होगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तो फिर मैंने भी जो बोला, वह सारा रिकॉर्ड पर रहना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): (..व्यवधान..) जेबें भरीं, (..व्यवधान..) पैसों का आरोप लगा रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) फिर मैंने जो बोला वह भी रिकॉर्ड पर रहना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कर दें फैसला (..व्यवधान..)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह गलत परम्परा डाल रहे हो। अध्यक्ष जी, यह गलत परम्पराएं मत शुरू करवाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) कल सुभाष गर्ग ने आरोप लगा दिया तब तो विशेषाधिकार ले आये। (..व्यवधान..) तब आपको कौन-सी दिक्कत हो गई थी।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको देखूंगा, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): हम आरोप लगाएंगे, वे भी आरोप लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीट पर जाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) कल को, वे खुद भ्रष्टाचारी हैं, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रस्ताव लेकर आते हो और यहां नाजायज बातें करते हो आप लोग।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा एक आग्रह है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आग्रह गलत हो रहा है आपका, संसदीय मंत्री महोदय, यह परिपाटी गलत मत डालिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): (..व्यवधान..) आप मेरा आग्रह सुनिये। आप सुनिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन यह है, हमारा आशय जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है। हमारे मंत्री जी का आशय किसी व्यक्ति, मेरी बात सुन लो पहले। (..व्यवधान..) एक मिनट, आप प्लीज। मेरी बात सुनो तो बताऊं ना (..व्यवधान..) ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय, सीट पर जाएं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति विशेष, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके ऊपर आरोप नहीं है। राजनैतिक दलों पर आरोप लगते रहते हैं, हम भी लगाते रहते हैं, आप भी लगाते हो। यह तो कोई, सुन लो मेरी बात पूरी, आप बीच में मत बोला। फिर आपकी बात हमको बता देना। जो है, ठीक हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इनको समझाओ, इनको व्यवस्था समझाओ, थोड़ा।

एक मिनट, मैं मेरी बात पूरी कर दूं, फिर आप जरूर बताना। मेरी बात पूरी कर दूं, पहले

मेरी बात पूरी होने दो। नहीं, हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं। मैं आपसे जूली साहब, मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं, क्या मैं मेरी बात पूरी कर दूं। फिर आप बता देना।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि व्यक्ति विशेष जो इस सदन का सदस्य नहीं, उस पर आरोप नहीं लग सकते, लेकिन राजनैतिक दलों पर आरोप लगते रहते हैं और राजनैतिक दलों पर आरोप कभी नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी लगा रहे हो। आप भी आरोप लगा रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, लगा रहा हूं। (..व्यवधान..) मैं वो ही कह रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): देखो, बात इन्होंने कही है, पारीक साहब ने।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान) वही कह रहा हूं, आपस में आरोप लगेंगे या जूते ही चलेंगे। (..व्यवधान..) अब जो बात हो रही है ना, वो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वो आपको भी नहीं करेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप लोगों को नहीं करेगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वो आपको भी नहीं करेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सत्ता के अन्दर बैठकर जिस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हो.....।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप अध्यक्ष की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। (..व्यवधान..) कोई भी अध्यक्ष की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, वह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): (..व्यवधान..) हमारा अधिकार है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) आप खुद चैलेंज करते हो आसन की व्यवस्था को। (..व्यवधान..) आप आसन की बात कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कल ही आपने व्यवस्था दी है, अधिकारी पर आरोप लगाया, आपने विलोपित किया। अधिकारी विशेष पर आरोप लगाया और आपने विलोपित किया, पार्टी विशेष पर आरोप लगा रहे हो, हम कह रहे हैं, विलोपित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: (..व्यवधान..) आरोप विलोपित नहीं किया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): (..व्यवधान..) अधिकारी पर आरोप लगाया, बाय नेम नहीं लगा, फिर भी आपने (..व्यवधान..) कल भी विलोपित किया।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किलें भी पीछे हट जाती हैं, यदि साहस का पुलिंदा हो, मंजिलें भी पास आ जाती हैं, यदि उम्मीदें जिन्दा हो।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजो। मैं नई परम्परा नहीं डाल रहा हूं। मैं भी 20 साल से सदस्य हूं, मैं देखता आया हूं। यह हमेशा किसी व्यक्ति पर जो सदन में सदस्य नहीं है, उस पर कोई आरोप होता है तो उसका नाम और आरोप वो विलोपित होता है। जो सदन में है, सरकार है, पार्टियां हैं, उस पर लगते हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किलें भी पीछे हट जाती हैं,

अगर साहस का पुलिंदा हो, मंजिलें भी पास आ जाती है, यदि उम्मीदें जिन्दा हों।

श्री अध्यक्षः (..व्यवधान..) अब इन पर लगाओगे विलोपित नहीं करूंगा। आप इन पर भी लगा देना, आप जब बोलना, इन पर भी लगा देना। इन पर भी दिन भर लगे हैं, आप भी लगा देना, जब आपका नम्बर आये आप भी लगाना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी, बहुत बड़े मंत्री हैं और इनको इतना छोटा आरोप नहीं लगाना चाहिए, जेबें तो बहुत छोटी होती हैं, इन्होंने तो बहुत ज्यादा भरा है।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): चलो, मैंने छोटा आरोप लगाया है, इसलिए वापस लेता हूं मेरे शब्दों को। छोटा आरोप लगाया है, नहीं तो अब बड़ा लगा दूंगा। मैं छोटे आरोप को वापस लेता हूं। यह छोटा आरोप लगा, इसको वापस ले रहा हूं। यह छोटा आरोप लगा, इसको वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार में रीट परीक्षाओं का हाल तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस वर्ष हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशानुसार और नियमित मॉनिटरिंग के कारण हमने हाल ही में दिनांक 27, 28 फरवरी, 2025 को रीट परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है। जिसमें लगभग 15 लाख 44 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिसमें लगभग 13 लाख 77 हजार ने परीक्षा दी, कुल 89.17 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रदेश में किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही शान्तिपूर्ण और गोपनीय तरीके से परीक्षा हुई है।

मैं समझता हूं इस परीक्षा में कुछ लोगों ने व्यवधान करने का प्रयत्न किया था, कुछ हमारे शिक्षकों ने एक-दो अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरवा ली थी, उनको मैंने निलम्बित कर दिया, क्योंकि इस प्रकार का काम, इस प्रकार का कृत्य हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं आपको जानकारी दूं कि प्री-डीएलएड परीक्षा 2024 हमने करवाई है। जिस प्रकार प्री-डीएलएड परीक्षा आयोजित करने हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को अधिकृत किया गया था। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय जो एक पेपर होता था, उसको हिन्दी में भी छपवाते थे, अंग्रेजी में भी छपवाते थे। हमने सभी आशार्थियों से (..व्यवधान..) कन्सर्न लिया कि आप परीक्षा अंग्रेजी में देना चाहते हो या हिन्दी में देना चाहते हो, 97 परसेंट लोगों ने हिन्दी की बात की, तो हमने 97 के लिए एक ही भाषा में पेपर छपवाया यानी हिन्दी में और 3 परसेंट के लिए अंग्रेजी में छपवाया। उसका लाभ यह हुआ कि राजस्थान सरकार को 36

लाख रुपये की बचत हुई।

साथ ही साथ, कागज की भी कम खपत हुई तथा पर्यावरण का भी संरक्षण हुआ। पहली बार रिकॉर्ड 16 दिवस में परीक्षा परिणाम हमने जारी कर दिया, (..व्यवधान..) जो हो सकता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया कि 450 विद्यालय बन्द किये हैं, हमने 450 विद्यालय बन्द नहीं किये हैं, 450 विद्यालयों में से 369 विद्यालय ऐसे थे, जिनमें एक भी छात्र नहीं था। ये 450 विद्यालय बन्द करने की बात कर रहे हैं। ये बिलकुल गलत बात है, बिलकुल गलत बात है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इन 450 में से 369 यानी 369 विद्यालय ऐसे थे, जिसमें एक भी छात्र नहीं था, यानी शून्य नामांकन था। 81 विद्यालय एक ही परिसर अथवा 100 मीटर की परिधि में संचालित हो रहे थे। एक ही परिसर में दो-दो विद्यालय संचालित हो रहे थे। उनको हमने एक कर दिया तो क्या बुरा किया। हमको टीचर्स एक्स्ट्रा मिल गये हैं, भवन पर्याप्त मिल गया है और इसमें हमने किया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहले भी इन्होंने बहुत सारे जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय किये हैं।

Bhs/Rtm/04.03.25/20.30/4k

उसमें कोएजुकेशन दी जा रही थी तो वहां जो बालिका विद्यालय था उनको भी हमने एक कर दिया तो कोएजुकेशन हो गयी क्योंकि एक में कुछ विषय थे, साइंस थी, एक में आर्ट्स था, तो बालिकाओं को भी आर्ट्स भी पढ़ने का अवसर मिल गया तो साइंस भी पढ़ने का अवसर मिल गया। यह हमने छात्रों के हित में किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार स्थानान्तरण नीति की बात करते हैं। स्थानान्तरण की नीति बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट्स से राय ले रहे हैं और एक्सपर्ट्स से राय लेने के बाद जो सुझाव आयेंगे उनके आधार पर हमारी स्थानान्तरण नीति बनेगी। जहां तक थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं कि वहां बाड़मेर बैठे हैं, जैसलमेर बैठे हैं, गंगानगर बैठे हैं, दस-दस साल हो गये तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर में ये ट्रांसफर करके इनको क्यों नहीं लाये? इनके शासन काल में इन्होंने उनके ट्रांसफर क्यों नहीं किये? जानबूझ कर इन्होंने ट्रांसफर नहीं किये और अब 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' वाली बात हमारे सामने कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हम अंग्रेजी स्कूल बन्द करने जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल तो हमने पहले ही चालू कर रखे थे। अंग्रेजी स्कूल तो पहले ही चालू कर रखे थे। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय के नाम पर हमारे पहले ही विद्यालय चल रहे थे। अंग्रेजी में हम पहले ही पढ़ा रहे थे और माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का

नाटक किया है। इन्होंने नाटक ही नहीं किया बल्कि इन्होंने बालिकाओं का स्कूल छुड़वा दिया है और हम लोगों ने जो विद्यालय बनाये हैं वो आप देख रहे हैं इतने बढ़िया प्रकार के विद्यालय बनाये, उसके बाद जाकर के हमने स्कूल प्रारम्भ किये हैं। न तो आपने विद्यालय दिये हैं, न आपने शिक्षक दिये हैं, न आपने भवन दिया है, ये ऐसे विद्यालय चल रहे थे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्षः इस किताब में जो कुछ नियम होगा, उस पर विचार करूंगा।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी एक योजना लाये हैं, जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, यानी बेटी के जन्म लेते ही एक लाख रुपये का संकल्प पत्र उस परिवार को देते हैं और ढाई हजार रुपये उस परिवार को देते हैं। जब वो सारे टीके लगवा लेते हैं वह एक साल की हो जाती है तो ढाई हजार रुपये फिर देते हैं, और वह एडमिशन लेती है तो चार हजार रुपये देते हैं और जब दसवीं पास कर लेती है तो पच्चीस हजार रुपये देते हैं और जब इक्कीस साल की हो जाती है या ग्रेजुएशन कर लेती है तब उसको कुल पचास हजार यानी एक लाख रुपये देते हैं। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। अधिकांश जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उनमें वहीं निवास की व्यवस्था है, वहीं बच्चियां रहती हैं, वहीं पढ़ती हैं और हमने कोशिश की है कि सभी अध्यापक और वार्डन वहीं रहे और जो वार्डन वहां नहीं रहेंगे, जो शिक्षक नहीं रहेंगे हम उनको बीच में ही कार्यमुक्त कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहां यह नियम है कि चार साल वो रह जाते हैं तो जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं, वो चार साल पूरे नहीं होंगे तो फिर वह जिले में ट्रांसफर नहीं करा पायेंगे और जहां मूल पद पर होगा वहां उनको जाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी सम्भागों पर बालिका सैनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की है और सभी सम्भाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे, ताकि बालिकाएं पढ़ करके और सेना में भर्ती हो सके और यह प्रयास हमारा रहेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः इस किताब में नियमों के अनुसार मैं करूंगा। इसमें यदि होगा तो जरूर करूंगा।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, 23 रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चलायेंगे। बच्चियों को आत्मरक्षा करने के लिए हम ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ऐसे कहने से नहीं, इसमें होगा तो करूंगा। मैं वादा करता हूं। इसमें होगा तो मैं करूंगा न असंसदीय। इसका भावार्थ होगा तो भी करूंगा। आये तो सही। आप भी पढ़े-लिखे हैं आपने भी पढ़ी है किताब। आप मेरे को पेज नम्बर बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा। इसमें पेज नम्बर बता दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): बालिका सुरक्षा की दृष्टि से जीरो टोलरेंस है हमारी

पॉलिसी माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बालिकाओं की शिक्षा की पूरी चिन्ता करते हैं और इसीलिये आपको ध्यान होगा चित्तौड़ जिले में जब एक शिक्षक और शिक्षिका अश्लीलता कर रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः इसमें ऐसा कोई भी शब्द होगा जो असंसदीय होगा, उसे मैं विलोपित करूंगा। अब अपनी-अपनी सीटों पर पधारें। इस किताब के अनुसार चलूंगा और किताब में यदि ऐसा शब्द हुआ जो विलोपित किये जाने योग्य होगा तो विलोपित करूंगा। इस किताब के अनुसार किताब में मुझे पेज बता दो, वाक्य बता दो, पैरा बता दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपनी बात कही है, मेरी बात भी रिकार्ड पर आयी है मैंने भी बी.जे.पी. पर आरोप लगाये हैं। अगर हमारे वाले आपने एक्सपंज किये तो ये भी एक्सपंज होंगे और अगर मंत्री का आप रखते हो तो हमारा भी रखें।

श्री अध्यक्षः मैं इस किताब के अनुसार चलूंगा। किताब में यदि ऐसा कोई शब्द हुआ विलोपित जैसा, मैं जरूर करूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने भी बी.जे.पी. पर आरोप लगाये हैं।

श्री अध्यक्षः लगाओ। आप भी लगाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बी.जे.पी. तो ज्यादा खा रही है साहब, लूट-लूट कर घर भर रही है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

बेटी को शिक्षा का वरदान मिले,
उसके हर सपने को ऊंची उड़ान मिले।
शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित बेटी से,
राष्ट्र और समाज की प्रगति को नये आयाम मिले।।

और इसीलिये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलायी हैं। हमारे लिये बालिकाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में अश्लील हरकतें न हों इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। चित्तौड़ में आपने सुना होगा, एक शिक्षक और शिक्षिका ने हरकतें की तो हमने उनको निलम्बित नहीं किया, उनको बर्खास्त कर दिया और इसी प्रकार से रोहट क्षेत्र में इस प्रकार की घटना आयी है, एक व्याख्याता ने, जो वहां की प्रयोगशाला सहायक होंगी, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो मैंने उसको भी बर्खास्त करने के लिए, विधि सम्मत कार्यवाही करके बर्खास्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्यस्तरीय समान परीक्षा का काम किया। पहले क्या था कि परीक्षाएं जिलों में होती थीं। जिलों में होती थीं तो सब जिलों के अलग-अलग पेपर बनते थे। बहुत सारे अध्यापकों को लगाया जाता था। बहुत सारा धन खर्च होता था। बच्चों

की पढ़ाई में व्यवधान आता था। अबकी बार हमने प्रदेश स्तर से ही पेपर बनाये, उसके कारण से एक जगह ही पेपर छपे, खर्चा कम आया और हमारी दो प्रतिशत मानव शक्ति लगी और बहुत कम पैसा लगा यानी राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया बचा करके हमने इस परीक्षा को सफल बनाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग अस्सी लाख के आस-पास बच्चे हैं। हमने सब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है कि कोई भी बच्चा अस्वस्थ न रहे, क्योंकि कई बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं कई बार उनको बीमारी का पता नहीं चलता है तो हमने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर जिस प्रकार की बीमारियों का हमको पता चला उन बच्चों की बीमारी का इलाज कराने के लिए चिकित्सा विभाग और हम, यानी शिक्षा विभाग मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि उनकी, सबकी बीमारी का इलाज हो। चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। बड़ी बीमारी होती है तो यदि बड़े हॉस्पिटल भी ले जाकर उसका इलाज कराना पड़े तो हम इलाज कराते हैं इसलिये मैं कह सकता हूं कि यह बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसको हमने किया है और यह बहुत कम दिनों में किया है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहली बार था, जिस प्रकार से अध्ययनरत बच्चों की चिन्ता की गयी। पहले कभी किसी ने चिन्ता नहीं की और हमने उनमें से लगभग 75 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है और मैं समझता हूं कि गरीब का बच्चा अब अस्वस्थ नहीं रहेगा। मैं जानता हूं कि जब बच्चा अस्वस्थ रहता है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। इसलिये वो ठीक पढ़ाई करे और इसलिये स्वस्थ रहना जरूरी है इसलिये स्वस्थ रखने के लिए हम उनके सभी प्रकार के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके बताये हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं कि अबकी बार हमने उच्च माध्यमिक कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया तो पहले क्या था अलग-अलग विषय के रिजल्ट अलग-अलग आते थे, यानी अब आर्ट्स का रिजल्ट आ गया, फिर साइंस का आयेगा, फिर वाणिज्य का आयेगा। अबकी बार हमने तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया है और उसको व्यक्तिशः डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया है।

Kas/rtm/04.03.2025/20.40/4I

यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि प्रायोगिक परीक्षाओं में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, तो जिस स्कूल में वो जाते हैं, उसके प्रिंसिपल उनका बहुत स्वागत करते हैं और वो एग्जामिनर भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा स्वागत-सत्कार हो, माला पहनाए, ढोल धमाका हो और हो सके तो अच्छी गिफ्ट भी दे, अच्छे होटल में भी रुकवाये। हमने अबकी बार आदेश जारी कर दिये कि किसी भी प्रकार का स्वागत-सत्कार यदि एग्जामिनर का होगा, तो ठीक नहीं होगा। जो स्वागत करवायेगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और जो स्वागत करेगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

अभी तक हमारे पास कोई बहुत ज्यादा शिकायतें ऐसी नहीं आई हैं, दो शिकायतें हमको जरूर मिली हैं, उन शिकायतों की हम जांच करवा रहे हैं। अगर वो शिकायतें वाजिब होंगी, तो हम उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करेंगे। हम किसी भी कीमत इस प्रकार के लोगों को बख्शेंगे नहीं। यह पुरानी परम्परा थी, पता नहीं कब से हो रही है।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी बच्चों को लगता है कि मेरे कम नंबर आये हैं और परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहते हैं, तो विद्यार्थी फिर उसमें ऑन लाइन आवेदन करते हैं तो री-टोटलिंग होती है। हमने अबकी बार कोशिश की है कि गणित में री-टोटलिंग तो हो ही, उसके अलावा री-चैकिंग भी हो, यानी इसमें कहीं कम नंबर तो नहीं दिये गये हैं। यह पहली बार राजस्थान में प्रयास हो रहा है, ताकि बच्चे को यह नहीं लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। यह सच है कि कई बार अन्याय हो जाता है। मैंने यह भी सुना है, यह भी देखा है कि कहीं उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई मिलीं, कहीं छात्रों ने ही कॉपियां जांचीं। इससे निपटने के लिये हम री-टोटलिंग के साथ-साथ री-चैकिंग को भी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ले रहे हैं, अगर यह सफल रहा तो हम आगे इसको पूरी तरह से लागू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश यह भी की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हमारा प्रश्न पत्र बनता है, उसके दो-तीन खंड होते हैं कि इतने अंक का यह खंड रहेगा, इतने अंक का यह खंड रहेगा। अब पेपर एक व्यक्ति नहीं बनायेगा, अब एक पेपर को भी जितने खंड होंगे, उतने व्यक्ति बनायेंगे और फिर इसको एक किया जायेगा, ताकि पेपर आसानी से आउट न हो, यदि आउट भी हो तो उसका एक ही अंश हो। यह हम नवाचार करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह सफल होगा तो विद्यार्थियों के लिये भी अच्छा होगा और जो नकल करने वाले हैं, पेपर आउट करने वाले हैं, उनसे भी हमको निजात मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिये विभिन्न स्तर की बैठकें कर ली हैं और समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमने रीट परीक्षा की थी, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, चूंकि पहले यह गड़बड़ियां होती रहती थीं। जानबूझ के करते थे या पेपर बेचते थे, वह अलग विषय है, लेकिन अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, हमने पूरे इंतजाम चाक-चौबंद कर दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब से निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण होने लगा है, मेरी मोटी-मोटी जानकारी के अनुसार यह था कि कभी तो सितम्बर में पुस्तकें वितरित होती हैं, कभी अक्टूबर में होती हैं और कभी-कभी तो जनवरी तक भी चल जाती हैं। अबकी बार यह पहला वर्ष था जिसमें हमने 5 जुलाई को राजस्थान के सभी बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें दे दीं। यह शिक्षा विभाग की उपलब्धि है और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ हमने आपसे ही सीखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी इस पीढ़ी को राह दिखाये,
स्वर्णिम भारत की शीतल चाँदनी अब यथार्थ में जगमगाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सारी जानकारी है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा, यानी वाटिका या साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं नर्सरी, उसके बाद कक्षा एक व कक्षा दो। इस पढ़ाई के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि लोकल भाषा या मातृ भाषा में हो। लोकल भाषाएं बहुत सारी हैं, हमने कई जिलों के इनके शब्द कोष तैयार कर लिये हैं, कुछ बाकी हैं, उनके भी शब्द कोष तैयार कर रहे हैं और किताबें लिखी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि इस वर्ष के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मातृ भाषा या लोकल भाषा में पुस्तकें तैयार कर लेंगे और उन बच्चों को संभला देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएमई विद्या चैनल। प्रदेश में टेलीविजन पर पांच पीएमई विद्या चैनल संचालित हैं। डीडी टीवी पर 12 डैडीकेटेड चैनल हैं। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण सामग्री का मार्च, 2024 से 24 घंटे प्रसारण किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिये कैरियर मार्ग-दर्शन हेतु कार्य पुस्तिका, प्रशिक्षकों के लिये समग्र प्रशिक्षण मॉडल विधिवत किये गये हैं। हमारी सरकार के द्वारा इस वर्ष कक्षा 8 तक की कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तकें भी निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, वो दिव्यांगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जो 100 प्रतिशत मूकबधिर हैं या जो 100 प्रतिशत दृष्टि बाधित हैं, ऐसे सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी या अध्यापकों को वहां लगाया जायेगा जहां वो चाहते हैं। चाहे उनके घर के पास ही विद्यालय क्यों न हो, वहीं लगाया जायेगा, लेकिन दूर-दराज नहीं भेजा जायेगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मंत्री बनने के बाद कुछ लोग मेरे पास स्थानांतरण के लिये आये। उनमें से एक दृष्टि बाधित बंधू भी आये। उन्होंने कहा कि साहब, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दूर हूं, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने पूछा कि आप कहां हो, उसने लगभग 300 किलोमीटर दूरी बताई। मैंने पूछा भोजन कौन बनाता है, कैसे रहते हो, तो उसके आंसू आ गये। मैंने कहा कि अब आपको वहीं लगायेंगे, जहां आप चाहेंगे। मैंने पिछली विधान सभा में ही घोषणा की थी कि जो 100 प्रतिशत दिव्यांग लोग हैं, उनको वहां लगायेंगे, जहां वो चाहते हैं और अधिकांश ऐसे लोगों को मैंने लगा दिया है, बाकी बचे हैं, उनको भी लगा देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिये पत्रावलियां पड़ी रहती हैं। यानी अधिकारी चाहे तो आगे भेजे और नहीं चाहे तो नहीं भेजे। कई बार तो जिला शिक्षा अधिकारी वहां से पत्रावली ही नहीं भेजता। हमने यह तय कर दिया है कि पत्रावली कितने दिन में कहां आयेगी और कितने दिन में निस्तारण हो जायेगा, या तो ना या हां। उस पत्रावली का तय समय में हम निस्तारण करेंगे, यह भी हमने तय कर दिया है और उसकी गाइड लाइंस भी बना रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सबको यह जानकारी है कि कई लोग भैरू जी की पूजा करने के नाम पर, बाबा जी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर या

गिरजाघर जाने के नाम पर स्कूल छोड़ जाते हैं। कोई तो कहता है कि मैं भैरू जी की पूजा पांच बार करता हूं, कोई कहता है कि चार बार करता हूं, कई बार कहता है पांच बार नमाज पढ़ता हूं। हमने कहा कि स्कूल समय में कोई भी न तो भैरू जी की पूजा करने जायेगा, न बालाजी की पूजा करने जायेगा, न नमाज पढ़ने जायेगा, न गिरजाघर में जायेगा। स्कूल समय में कोई भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल पढ़ाना ही पड़ेगा, यह भी हमने आदेश जारी कर दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और हमारा जो पहले परीक्षा परिणाम रहता था, उससे बेहतर परीक्षा परिणाम रहा। आपको जानकर यह खुशी होगी कि सरकारी स्कूल की एक बालिका, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दी थी, उसने 600 में से 598 नंबर प्राप्त किये हैं और राजस्थान को टोप किया है, यानी 99.67 अंक प्राप्त कर के राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये जो कहते रहते हैं ना कि निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में वैसी पढ़ाई होती है, होती होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं ये लगातार निजी स्कूलों को बदनाम करते रहते हैं। मैंने जब आंकड़ा निकाला तो 97 प्रतिशत ऐसे निजी विद्यालय हैं, जिनकी फीस 15 हजार रुपये से कम होती है, 97 प्रतिशत विद्यालय।

Msk/rtm/04.03.25/2050/4m

3 परसेंट ऐसे विद्यालय हैं, 3 में से भी 1.2 या 3 परसेंट ऐसे हैं, जिनकी 25 हजार तक होती है, शेष उससे ऊपर होती है। हम सब उसको आधार बनाकर शिक्षा विभाग के विद्यालयों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं यह नहीं कहता कि अच्छी शिक्षा नहीं देते होंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं कि अच्छे पढ़ाने वाले ट्रेंड शिक्षक, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में हैं, वे निजी विद्यालयों में नहीं हैं, उनसे अच्छी शिक्षा राजस्थान सरकार के विद्यालय देते हैं, यह आपसे कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): ये बही निकाल कर डरा रहे हो क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है। अब की बार क्या हुआ? ...(व्यवधान)... क्यों डर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान रखना।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जिम्मा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): लाल रंग की लाये हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपकी वह लाल डायरी नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण की एजुकेशन भी होती है। अब की बार आपने पढ़ा होगा कि बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा के बीच में तापमान 55 डिग्री हो गया था। फलौदी का टैम्प्रेचर 53 डिग्री हो गया था। हम यह सब

लोगों के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए इस धरती का तापमान कम हो, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको निर्देश दिये कि तापमान कम करना है तो निष्कर्ष एक ही निकला कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको निर्देश दिये कि सात करोड़ पौधे लगाने हैं। मुझे आपसे यह कहते हुए बहुत खुशी भी है, मुझे राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों के ऊपर गर्व भी है कि सबने मिलकर 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा दिये, जो पेड़ बनेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पानी कहां है?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि 'एक पेड़ मा के नाम' हमने उसकी अक्षरशः: पालना की। हमने बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी कहा कि जो पेड़ लगायेगा, उसको सत्रांक नंबर होते हैं, सत्रांक में उसको नंबर भी देंगे। हमने वह भी प्रारंभ कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेड़ की कीमत तो मां अमृता देवी ही बता सकती थी कि उसकी कीमत क्या है? जब फिरंगियों का राज था, तब मां अमृता देवी के खेजड़ली गांव में उस समय के शासकों ने पेड़ काटने का ऑर्डर दिया। कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आ गये। उनके कई सारे कारिंदे थे। जब मां अमृता देवी को पता चला तो वह दो बेटियों के साथ उस पेड़ पर लिपट गयीं और जब गांव वालों को पता चला तो अधिकांश गांव वाले उन पेड़ों पर लिपट गये, लेकिन उन हत्यारों ने छोड़ा नहीं और उन सबको मार डाला, लेकिन जीते-जी मां अमृता देवी पेड़ को नहीं कटने दिया। मां अमृता देवी पेड़ की कीमत जानती थी कि एक पेड़ कितने लोगों को जिन्दा रखता है? एक पेड़ उसके जीवनकाल में चार से पांच करोड़ रुपये की ऑक्सीजन देता है, एक पेड़ एक साल में तीस लाख की ऑक्सीजन देता है, एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और एक पेड़ ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिन्दा रहते हैं। जब कोरोना काल आया था तो सब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है? ऑक्सीजन की कीमत इतनी थी कि हमको हैलीकॉप्टर और हवाई जहाजों से जाकर बाहर से ऑक्सीजन लानी पड़ी। इसलिए हमको पेड़ की कीमत को समझना पड़ेगा। पेड़ भारत माता के श्रृंगार हैं, धरती माता के श्रृंगार हैं। यह धरती माता हमारा मल-मूत्र भी सहती है, हमें सब कुछ देती है। जब पानी की जरूरत पड़ती है तो हम बड़े-बड़े छेद करके पीने एवं सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। जब मां हमारे लिए इतना कष्ट सहती है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस भारत माता के लिए कुछ करें। हम सब लोगों को इस भारत माता को श्रृंगारित करने के लिए लगातार पेड़ लगाते रहना चाहिए। ऐसा मेरा आप सब लोगों आग्रह भी है और हम सब बच्चों को यह निवेदन भी करते हैं।

इस बार शिक्षा विभाग और सब विभाग मिलकर यह कोशिश करेंगे कि 10 करोड़ पौधे लगायें। वे पौधे सुरक्षित रहें, इसलिए जहां 200 पौधे लगाये हैं, वहां पर हमने नरेगा से एक कर्मचारी रख दिया है, ताकि जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी, उसको पानी भी पिलायेगा और उसकी रक्षा भी करेगा, चाहे मानव से रक्षा हो, चाहे पशुओं से रक्षा हो। सबसे रक्षा करने की

जिम्मेदारी उसकी होगी। पहले जितने प्रतिशत पेड़ जिन्दा रहते थे, उससे अधिक पेड़ जिन्दा रहेंगे, ऐसा प्रयास हमारा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिथीन हमारी दुश्मन है। लोगों ने समझ लिया है कि हमारी मित्र है, पर यह दुश्मन है। जब पॉलिथीन का यूज करके कहीं फेंक देते हैं, लोग जलाते हैं तो मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। नाली में चली जाती है तो नाली अवरूद्ध हो जाती है। अवरूद्ध होने के बाद उसकी गंदगी रोड पर आती है और गंदगी पर मक्खी-मच्छर बैठते हैं, वे घरों में जाते हैं, रोटी पर बैठते हैं और फिर हम उसको खाते हैं, तो बीमार होते हैं। यहां जहां ज्यादा गंदगी होती है तो कॉर्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है। कॉर्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन जहां ज्यादा होता है, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी और कॉर्बन डाईऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन कॉर्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इधर मोनो ऑक्साइड गैस का निर्माण, इधर मीथेन गैस है। मीथेन गैस और ये सारी गैसें मिलकर जब वायुमण्डल में घूमती हैं तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती हैं। जब श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में आती हैं तो हमको बीमार करती हैं। मैं डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बताऊं तो हिन्दुस्तान में डेढ़ करोड़ लोग इसके कारण से मरते हैं, गंदगी और पॉलिथीन की वजह से। मैंने पोप्यूलेशन के हिसाब से निकाला तो साढ़े सात लाख लोग हर साल राजस्थान में पॉलिथीन की वजह से और गंदगी की वजह से मरते हैं। इसलिए हमको इनको बचाना है। उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे मां-बाप भी हो सकते हैं, हमारी पत्नी भी हो सकती है, पत्नियों के पति भी हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले का आदमी भी हो सकता है, हमारे गांव का आदमी भी हो सकता है, हमारे शहर का आदमी भी हो सकता है। हमारे देश-प्रदेश का आदमी हो सकता है। इसलिए हमारे प्रदेश और देश के लोगों को बचाने के लिए हमको पॉलिथीन से दूरी बनानी पड़ेगी। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने डिस्पोजल आइटम का उपयोग न हो, इसलिए घोषणा की है कि अब हम आगे से बर्तन भण्डार बनायेंगे। उन्होंने एक हजार पंचायतों में बर्तन भण्डार बनाने की घोषणा की है, इसको धीरे-धीरे हम सब ग्राम पंचायतों में ले जायेंगे और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय भी बर्तन खरीदने केलिए अपने एमएलए कोष का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। ताकि जो डिस्पोजल आइटम हैं, उनमें हम बड़े खुश होते हैं। ये तो डिस्पोजल आइटम हैं, फेंक देते हैं, मांजना नहीं पड़ता, संभालना नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एक लेयर होती है, वह लेयर पॉलिथीन की होती है। जब गर्म पेय या गर्म खाद्य सामग्री उसके सम्पर्क में आती है तो उसके पार्टिकल्स खाते समय या पीते समय हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो कि कैंसर की बीमारी करते हैं। हमको कैंसर से भी लोगों को बचाना है। तो हम सबको करना पड़ेगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप शिक्षा से चिकित्सा मंत्री बन गये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है। आधार मशीनों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा,

उनको कई शिकायतें मिली होंगी तो उन्होंने बताया कि ऑपरेटर द्वारा फर्जी दस्तावेजों का नामांकन और फर्जी सूचनाएं दर्ज करके पाया गया..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं माननीय सदस्यों के लिए क्या भोजन की व्यवस्था कर लूं? लगता है, लंबा चलेगा, यह लग रहा है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों का कितना दुरुपयोग हुआ?

श्री अध्यक्ष: आपका लगभग कितनी देर का है, बाकी तो आप स्वतंत्र हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आधा घंटा।

श्री अध्यक्ष: और आपका? आप बतायें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बतायें। आधा घंटा। दोनों आधा-आधा घंटे बोलने वाले हैं। बाकी आप देखे लें, करनी है तो करें। पांच-सात मिनट ज्यादा ऊपर हो सकते हैं। क्योंकि नियम यही है कि यदि 9 बजे बाद सदन चलता है तो भोजन की व्यवस्था अपने यहां से होती है। आप लोग कहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, कोई नहीं करेगा, सब घर जाकर करेंगे। कन्क्लूड करायें। मंत्री जी फोरेस्ट पर भी बोल रहे हैं, खाद्य आपूर्ति पर भी बोल रहे हैं, पंचायती राज में बोल रहे हैं, चिकित्सा पर भी बोल रहे हैं, शिक्षा पर बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): यह पर्यावरण शिक्षा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसको कन्क्लूड करवायें, इतना नहीं होता। एक घंटा हो गया, सब लोग जायेंगे, मजाक बन रहा है।

mdp/rtm/04.03.25/2100/4n

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है कि इतना लम्बा भाषण सुनने के पश्चात भोजन करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो सुन नहीं रहा हूं, अपना मोबाइल खाली कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों का कितना दुरुपयोग हुआ है, उसकी जानकारी मैं दे देता हूं। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के नाम पर लगभग 590 आधार मशीनें ...(व्यवधान)... ली और आधार मशीनों का जो कांट्रेक्ट दिया, वह अलग-अलग ब्लॉक में दिया। जब अलग-अलग ब्लॉक में दिया तो दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये उस आधार मशीन से लिये उस ठेकेदार ने और उसने करोड़ों रुपये कमाए। लेकिन आपको सुनकर दुख होगा कि आधार कार्ड की मशीनें पश्चिमी बंगाल में पहुंच गयीं। दूसरे प्रदेशों में पहुंच गयीं। बांग्लादेश तक पहुंच गयीं और उससे रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन गये, बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बन गये, पश्चिमी बंगाल के लोगों के आधार कार्ड बन गये। उसके कारण से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया, ...(व्यवधान)... लेकिन कांग्रेस ने उसकी कोई चिंता नहीं की। आधार मशीनों से..

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): ये जिस डिपार्टमेंट का है, उसको करने दो। उसके भरोसे छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आधार मशीनें हमारी संस्था की...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार थोड़े- ही सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)... पहली बार है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आधार मशीनों से देश की सुरक्षा को खतरा हुआ, लेकिन इन्होंने चिंता नहीं की। ...(व्यवधान)... भारत सरकार लगातार चेताती रही कि इसका नुकसान हो रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे उच्च शिक्षा पर।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): नोटिस दिया ...(व्यवधान)... उन सभी मशीनों को ब्लॉक किया और हमने फर्म पर एफ.आई.आर. दर्ज की। अभी-भी 131 मशीनें जमा नहीं हुई हैं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी, सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, आधा सेकण्ड, माननीय मंत्री जी, विषय ये है कि माननीय मंत्री जी को अपनी योग्यता का प्रदर्शन सदन के समक्ष तो करना ही करना है, लेकिन तीसरी आंख और बैठी हैं। तीसरी आंख देख रही है, तो घर में तो कम से कम थोड़ा-सा जोश आयेगा, इसलिए पूरा प्रदर्शन करना है आज। पूरी छूट है आपको। आज आपको 100 में से 100 नंबर यदि घर में नहीं मिले तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इनका बॉयकाट किया है। हम इसलिए ही आकर बैठे हैं कि इनकी श्रीमती जी को ऐसा नहीं लगे हैं कि हम बॉयकाट कर रहे हैं इनके पतिदेव का, इसलिए हम बैठे है यहां पर। लेकिन आप भी दया करो, महाराज, बख्शो।

श्री अध्यक्ष: आप लोग बैठे हैं, इसके लिए धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.टी.ई., पिछले सरकार के कार्यकाल में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के बिलों को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भी उनका पूरा भुगतान नहीं किया। पूरा भुगतान नहीं किया, इसके कारण से बहुत परेशान रहे। आपको बता दूं कि 2018-19 के भी 8 करोड़ 97 लाख 38 हजार 540 रुपये बाकी हैं। 2019-20 के भी 7 करोड़ 98 लाख 86 हजार 908 बाकी, जो स्कूलों में हम सरकार की तरफ से बच्चे भेजते हैं, उनके हैं आर.टी.ई. के।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह भी फर्जीवाड़ा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 2020-21 के भी ...(व्यवधान)... 5 करोड़ 41 लाख 4 हजार 400 बाकी।

श्री अध्यक्ष: माननीय, बैठिए, व्यवधान नहीं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 2021-22 के भी 8 करोड़ 85 लाख 94 हजार 31,

2022-23 के भी 28 करोड़ 16 लाख 27 हजार 819 और 2023-24 के 521 करोड़ 27 लाख 58694 बाकी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। इन्होंने आपको सुना है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हमने आने के बाद में 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इनके चक्कर में तो उनके स्कूल बंद हो जाते। बहुत परेशान थे। आज भी गालियां देते हैं इनको कि हमारा पैसा रोक कर रखा था। वे यह कह रहे हैं कि भला करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने हमारा भुगतान कर दिया। थोड़ा और बाकी जरूर है, ...(व्यवधान)... वह भी हम तुरंत देंगे, लेकिन इनकी तरह इस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय, बैठ जाओ। व्यवधान करोगे और देर होगी। आप तो बैठिए। माननीय सदस्य, बीच-बीच में नहीं। कल आप भी बोलेंगे तो फिर मेरे को मत कहना।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, हल्ला मत कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म घोटाला कैसे हुआ? मदरसा बोर्ड में बच्चे थे कितने, 1 लाख 30 हजार, ड्रेस कितने बच्चों की खरीदी, 2.08 लाख बच्चों की। बच्चे तो 1 लाख 30 हजार ही थे, ड्रेस खरीदी इन्होंने 2.08 लाख की, डबल, क्यों खरीदी? क्या आशय था इनका? इतना बड़ा घोटाला। दो ड्रेस देते हैं। 5 करोड़ का घोटाला किया है। शाला दर्पण पर इतने विद्यार्थियों की संख्या स्पष्ट होने के बावजूद भी। शाला दर्पण पर मदरसों में कितने बच्चे हैं, उन सबकी संख्या दर्ज थी, सारा कुछ था, उसके बावजूद भी आंखों में मिर्ची झोंक कर राजस्थान सरकार के साथ इतनी धोखाधड़ी की है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य के 3 हजार 699 मदरसों के 2 लाख 7 हजार 242 बच्चों के लिए 29 अगस्त, 2023 को दो सेट प्रति बच्चे के हिसाब से यूनिफॉर्म खरीदने का आर्डर दिया गया था। नियम के तहत एक बच्चे को एक सत्र में दो यूनिफॉर्म दी जाती है। शाला दर्पण रिकॉर्ड के अनुसार 2023-24 के दौरान मदरसों में 1 लाख 30 हजार बच्चे दर्ज थे, जबकि इन्होंने 2 लाख की खरीदी।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही मिड-डे-मील में हुआ है। मैं कहूं मदरसों, मिड-डे-मील में जाने पर इसमें भी करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ होगा। हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे और ये जांच कमेटी बैठने से जो निष्कर्ष आयेगा, पाई-पाई वसूल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आजकल पाई-पाई मिलता है क्या? रुपये-रुपये तो सुना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम भी आपके साथ हैं, कीजिए। यहां भाषण सभी करते हैं, करता कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): पाई-पाई वसूल करेंगे, पाई-पाई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये पांचवीं बार उठे हैं। अब नहीं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान एवं प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान सरकार के साथ 14 हजार 500 करोड़ से

अधिक राशि के 250 से अधिक एम.ओ.यू. किये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा विभाग के साथ किये गये एम.ओ.यू. को धरातल पर लाने के लिए पुरजोर कार्यवाही की जा रही है। इसके कारण से भवन बनेंगे, हमारे यहां क्लासरुम बनेंगे, लैबोरेट्रीज बनेगी। ये सारा कुछ होगा तो शिक्षा का स्तर और अच्छा सुधरेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सब लोगों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एम.ओ.यू. किये।

केवल सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने एम.ओ.यू. किये हैं। पहली बार हुआ है कि इन्होंने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एम.ओ.यू. किये हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल चलता है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से जब पांच साल उनकी सरकार थी तो बहुत कम पैसे उसमें आये, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक लगभग 500 करोड़ से अधिक का सहयोग प्राप्त हो चुका है। भामाशाहों, दानदाताओं, कंपनियों द्वारा शिक्षा विभाग में पारदर्शी एवं त्वरित रूप से विभाग को सहयोग कर सके, इस हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल की स्थापना की थी, जिससे अब तक लगभग 500 करोड़ से अधिक का सहयोग प्राप्त हो चुका है।

Ans/rtm 21.10 4o 04.03.2025

पोर्टल के माध्यम से ना केवल राशि बल्कि सम्पूर्ण विद्यालय निर्माण मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन सुगम एवं सरल। शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए भामाशाह, दानदाताओं और कम्पनियों अधिकतम सहयोग लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है।

भामाशाह को प्रोत्साहित करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा भामाशाहों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किये गये, जिसके कारण पोर्टल् पर दानदाताओं की उपस्थिति कम रही और गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 61 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। अब यह भाजपा पार्टी की सरकार आई है तब से अब तक 110 करोड़ रूपये का आर्थिक सहयोग शिक्षा विभाग को मिला है।

हिन्दुस्तान स्काउट व गाइड्स। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से स्थापित हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड्स संगठन जिसको राजस्थान में मान्यता, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए किये गये प्रयासों से वर्ष 2015 में मिली, यह संगठन गत सरकार में पक्षपात व अवहेलना का शिकार रहा, इस संगठन का उद्देश्य सम्पूर्ण प्रदेश में गतिविधियां आयोजित करवाकर छात्र-छात्राओं में राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा कर उनका शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास करना था। ...(व्यवधान)... हां निपटा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सबको ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत गंभीर मामला है। मिड-डे-मील कार्यक्रम में हमने विशेष पहल की ताकि मिड-डे-मील ठीक मिले, अच्छा भोजन बच्चों को मिले। इसलिए हम उसमें माताओं, बहनों को उस दिन उसमें अतिथि बनाते

हैं, ताकि वह भोजन भी चखती हैं और पता भी चल जाता है कि बच्चों को कैसा भोजन मिल रहा है। हमने उसमें श्रीकृष्ण भोग योजना भी शामिल की है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर बच्चों को भोजन कराना चाहता है तो खुद के ख़र्चे से अच्छा भोजन करा सकता है। कुछ लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को, शिक्षा विभाग को इसका लाभ हो रहा है। मिड-डे-मील में आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कितनी अनियमितताएं हुई हैं। महामारी के दौरान राजस्थान में मिड-डे-मील योजना में खाना पकाने की लागत के बराबर का खाना पकाने की सामग्री दालें, तेल, मसालें वितरीत करने का निर्णय लिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि इसका इतना पैसा सीधे बच्चों के या उनके अभिभावकों के खातों में ट्रांसफर कर दो, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया और कहा कि हम सामग्री देंगे। तो सामग्री देंगे तो सामग्री गई कहां? इन्होंने कहा कि जितने बच्चे थे सबको पहुंचा दी, लगभग 59 लाख 81 हजार बच्चे थे उसमें से इन्होंने 66 लाख 22 हजार बच्चों को कोम्बो पैक वितरित करना दर्शाया गया। बच्चे कितने थे 59 लाख 81 हजार और बांटे कितनो को 66 लाख 22 हजार को। जब कोरोना काल था। मैं कहूं कि राशन की दुकान पर खाद्य सुरक्षा का अनाज मिलता है उसमें लगभग 60-70 परसेंट लोग अनाज लेने नहीं आये कोरोना के कारण और यहां इन्होंने 59 लाख 81 हजार बच्चों में से 66 लाख 22 हजार को वितरित कर दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा घोटाला हो गया। कौन खा गया इस पैसे को, इसको देखना पड़ेगा। यही नहीं, मैं यह भी कह रहा हूं कि इनको जब सामान खरीदना था तो इन्होंने टेंडर जारी किये होंगे, नेफेड भी इसमें आया और कई कम्पनियां भी आई, नेफेड को बाहर कर दिया, जबकि भारत सरकार का था। नियम कानून सबके दस्तावेज थे उसके पास, फिर भी उसको बाहर कर दिया। फिर कॉनफैड को दिया, कॉनफैड ने फिर एक कम्पनी को दिया फिर उसने तीसरी कम्पनी को दिया और तीसरी कम्पनी का मालिक कौन था, मैं यहां नहीं बताना चाहता, नहीं तो यह हल्ला करेंगे। उसे कौन खा गया। उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। मेरा अनुमान है लगभग 100 करोड़ रुपये का घोटाला है। मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी ने सीधा-सीधा कहा है कि इसमें 1705 करोड़ रुपये का घोटाला है। यह जांच है, यह सीएजजी की जांच है, मेरी नहीं है। हमने डिपार्टमेंटली जांच भी कराई थी, लेकिन उस समय के अधिकारियों को दबाव बनाकर वह जांच गलत लिखाई गई, इसलिए उस जांच को निरस्त करता हूं और अब अलग टीम बनाऊंगा, टीम बनाकर जांच कराऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यह 1705 करोड़ रुपये जो खाये हैं उनको नाकों से निकलवाएंगे। राजस्थान सरकार का 1705 करोड़ रुपया किसी भी कीमत पर खाने वालों को नहीं छोड़ेगे। आप जानते हैं कौन लोग हो सकते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी किसी को मिर्ची लग सकती है ...(व्यवधान)... किसी को मिर्ची लग सकती है।

श्री अध्यक्षः आपका पूरा समय होने जा रहा है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): बस हो गया, थोड़ा सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी कितना कष्ट होता था और हमको भी कितना कष्ट होता है कि राष्ट्रीय महापुरुषों के

बारे में इन्होंने क्या-क्या पढ़ाया। महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया। अकबर जो मीना बाजार लगाता था, +++ था, आक्रांता था ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): उत्तेजना पैदा कर रहे हो आप, अच्छा भला चल रहा है ...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): लुटेरा था, उसको महान बताया। यह हमारे देश का अपमान था। महापुरुषों का अपमान था। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, इसे विलोपित करें, यह क्या तरीका है। ...(व्यवधान)... उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हो? जानबूझकर कर रहे हो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अकबर आपका क्या लगता है ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिन्दुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों से छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: समय पूरा हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): पूरा हो गया, यह तो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अकबर क्या लगता है, औरंगजेब क्या लगता है आपका ...(व्यवधान)... पाठ्यपुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया, जो पूर्णतया अनुचित था।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अपना करेक्टर साबित कर रहे हो कि मेरा ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मेरा करेक्टर बहुत अच्छा है, आपके करेक्टर की चिंता करो।

श्री अध्यक्ष: कोई घोषणाएं हो तो कर दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक है या कार्मिक हैं सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी। यानी एक ही श्रेणी के, जैसे संस्कृत के विद्यालय हैं तो उनका अलग कलर रहेगा, मीडिल स्कूल हैं तो उनका अलग कलर रहेगा, सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं तो अलग कलर रहेगा, हम ऐसी कोशिश करेंगे। अतेक अतीत की प्रेरणा, भविष्य का संकल्प, ज्ञान का वह सच्चा संधान, विकसित राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में शिक्षा बने सबसे बड़ा अभियान।

एकता से ऊर्जा आती है और ऊर्जा से उत्कर्ष,

उत्कर्ष से शक्ति आती है और शक्ति से प्रगति,
प्रगति से परिवर्तन आता है और परिवर्तन से नवनिर्माण
नवनिर्माण से संकल्प आता है और संकल्प से सिद्धि
और यही हमारा ध्येय है।

श्री अध्यक्ष: मैं समझाता हूं, स्कूल शिक्षा पूरी हो गई। अब मांग।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20 व मांग संख्या 21 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रारम्भिक पूरी हुई कि माध्यमिक भी पूरी हुई। दोनों पूरी हो गई। अब उच्च शिक्षा। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा कटौती प्रस्ताव, मांग संख्या 22 पर आपने बहुत कम समय बोलने के लिए दिया...

श्री अध्यक्ष: कम नहीं दिया, आप बोल सकते हो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में लक्ष्यबद्ध और प्रतिबद्ध विद्वानों से लफ्ज प्रतिष्ठ इस सदन में अनुदान मांग पर बोलते हुए मुझे आज अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि एक गरीब, किसान, मजदूर का बेटा, उस गांव व ढ़ाणी में बसने वाले गरीब, किसान और मजदूर की चिंता हमेशा रहती है।

VPS-RTM-04.03.2025-21.20-4p

इसलिए इस बात पर मुझे यह लगता है कि यह विपक्ष भी हमारा साथ देगा और उन गरीब, मजदूर, किसानों के हित में जरूर उनकी सलाह इस सदन को देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): विपक्ष में तो एक जना ही बैठा है। क्या सलाह देगा?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): लेकिन विपक्ष के सदस्य सदन में कम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद इनको उस गरीब, किसान और मजदूर की चिंता नहीं है। उनके बच्चों की चिंता नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, पूरा रिप्रजेंटेशन है। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, सरदार के लिए कहते हैं न लोगबाग, सरदार के लिए लोग क्या कहते हैं? सरदार जा रहा है, ऐसा नहीं कहते। यह कहते हैं कि यह फौजें कहां जा रही हैं? यह फौजें हैं पूरी की पूरी, आप चिंता मत करो। आप बोलो। मैं आपका पूरा सुनकर जाऊंगा। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): वैरी गुड। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ऐसा था कि यह बोल सकते हैं। एक सेकण्ड। पहले प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की, यह लगभग 500 अरब रुपये की मांगें हैं और इनकी जो है, वह केवल मेरे को

लगता है कि लगभग 25 अरब रुपये की है, तो इसलिए मैंने थोड़ा समय के लिए कहा है, बाकी आप बोल सकते हैं, इनको आजादी है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इनकी मांग छोटी है। यह इनके साथ पक्षपात हो रहा है। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। आप सभी का धन्यवाद। आपको समय ज्यादा लग जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया, हो गया। आपकी बात आ गयी। आप बैठिये, हो गया। पारीक साहब की हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है, उसके लिए मैं काफी हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं पर वह, उस संसदीय मंत्री ने हजार रुपये पास करवाये थे, उसके लिए भी पूरा ही पढ़ा था तो इनको भी पूरा पढ़ने दो।

श्री अध्यक्ष: चलिये, पूरा पढ़ें। मेरी ओर से पूरी अनुमति है। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): शिक्षा मंत्री आप भी रहे हो। डिफरेंस आपको मालूम है। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान मांगों पर अपनी बात को रखने से पूर्व मैं भारत के पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं-

'क्या हार में, क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला,
यह भी सही वो भी सही
वरदान नहीं मांगूंगा
हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा।
रार नई ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूं,
गीत नया गाता हूं।
गीत नया गाता हूं।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसी कविता से प्रेरणा लेते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधान मंत्रीजी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने के लिए राज्य में यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान के लिए कार्य योजना बनाकर सरकार के गठन के प्रथम दिवस से ही कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया।

हम विकसित राजस्थान एवं विकसित भारत के निर्माण तक हार नहीं मानेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयासों से विकसित समृद्ध भारत के सपने को साकार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से आज मांग संख्या 22- उच्च शिक्षा के 183 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से नवीन महाविद्यालय के 27 प्रस्ताव, नवीन संकाय के 19, यू.जी. से पी.जी. में क्रमोन्नयन के 16, नवीन विषय के 20, भूमि आवंटन तथा कक्षा-कक्ष एवं चारदीवारी निर्माण के 18, ऑडिटोरियम एवं खेल मैदान के 6, रिक्त पदों को भरने के 45, विश्वविद्यालय संबंधी 14, अन्य विषयों के 23 प्रस्ताव आये हैं।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): घोषणा करो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): करेंगे।

श्री अध्यक्ष: इंतजार करो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपके किये काम, जिनको मैं कोई बंद नहीं करूंगा। जिनमें त्रुटि रही है, उसको सही तरीके से हम व्यवस्थित करेंगे। सभी प्राप्त 183 कटौती प्रस्तावों के उत्तर सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दिये जाएंगे।

माननीय अध्यक्षजी, अब मैं सर्वप्रथम हमारे सभी सम्मानित विद्वान सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, शेरगढ़, पिलानी, सादुलशहर, शाहपुरा, आहोर, बामनवास, राजसमन्द, केशोरायपाटन, मनोहर थाना, टोडाभीम, बांदीकुई, मकराना, बीकानेर पश्चिम, बून्दी, माण्डलगढ़, सांचौर, पाली, शाहपुरा, भीनमाल, खण्डेला, रायसिंहनगर, फलौदी, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, निवाई, किशनगढ़, केकड़ी, नोहर, महुवा, पीपल्दा, वल्लभनगर, राजाखेड़ा, बाड़मेर, तारानगर, सहाडा से और अन्य जो भी सदस्य आज यहां पर बोले, इस मांग की चर्चा पर आज उन्होंने विधान सभा में भाग लिया, उसको लेकर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास, अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए सुझाव एवं सुधार के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव एवं समस्याएं बताई हैं। इन विषयों पर मैं आगे अपनी बात रखूंगा।

इन सभी माननीय सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विश्वास दिलवाता हूं कि हमारी सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेगी।

राजस्थान की उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और पिछले एक वर्ष में हमने इस दिशा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मैथिलीशरण जी गुप्त की कविता की कुछ पंक्तियों का यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि-

'जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

अर्थात् शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें देशभक्ति,

नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण की भावना भी होनी चाहिए ।

मैथिलीशरण जी की इस कविता के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह माना की शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का मूल आधार हैं।

यही कारण है कि हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू कर रही है जिसके महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे।

इससे प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसे समान अवसर मिलेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच आधारभूत स्तंभ पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर आधारित है, जिसमें मातृ भाषा में शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया हैं।

प्रदेश में आज कुल 3210 महाविद्यालय हैं जिनमें से सामान्य शिक्षा के 569, राजकीय महाविद्यालय 19, राजकीय विधि महाविद्यालय 43, राजकीय कृषि महाविद्यालय 43 और निजी शिक्षण संस्थान के जो महाविद्यालय है वह 1615 और 02 स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एवं 06 निजी सहभागिता महाविद्यालय स्थापित हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 956 है। इन महाविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में सामान्य शिक्षा में प्रदेश में 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं जो कि राजस्थान की उच्च शिक्षा के लिए एक गर्व का विषय है।

मानव संसाधन मंत्रालय के ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की नवीनतम रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में देश का औसत सकल नामांकन अनुपात 28.4 है।

मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 28.6 है जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हमारा उद्देश्य है कि वर्ष 2035 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत तक प्राप्त कर लिया जाये।

राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले एक वर्ष में हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में नए महाविद्यालयों की स्थापना की है, प्रदेश में सत्र 2024-25 में 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें 20 सहशिक्षा एवं 4 कृषि महाविद्यालय है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, हम सभी यह मानते हैं कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है और इसी सोच के साथ हमने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

महिलाओं की शिक्षा को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है और इसी उद्देश्य से हमने गत वर्ष 13 नए कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किए हैं और वर्तमान बजट में भी 12 कन्या महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित किया है ताकि हमारी बेटियां निर्भय होकर अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी।

शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना भी होना चाहिए।

ssy/rtm/04.03.2025/21.30/4q

इसे ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में और संकायों की शुरुआत की है, जिसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें, भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकें। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 43 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 33 नवीन विषयों में अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया है।

हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पारंपरिक विषयों के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा मिले, जिससे हमारे छात्र ना केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सक्षम बन सकें। इसके लिए हमने 33 जिला मुख्यालयों पर 33 महाविद्यालयों में बीबीए पाठ्यक्रम तथा कंप्यूटर साइंस के विषय प्रारंभ कर दिये हैं। 7 संभाग मुख्यालयों पर 7 महाविद्यालयों में बीसीए कोर्स भी प्रारंभ कर दिये गये हैं। रोजगार परक शिक्षा की ओर अग्रसर प्रदेश सरकार द्वारा 7 संभाग मुख्यालयों पर 7 महाविद्यालयों में एमबीए एवं एमसीए कोर्स प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी कर दी है एवं एआईसीटीई की अनुमति प्राप्त होते ही यह कोर्स भी प्रारंभ हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को अब उच्च शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिटल शिक्षा की ओर भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। चरणबद्ध रूप से महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, आईसीटी लैब के माध्यम से ई-लर्निंग की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी का लाभ मिल सकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें 16 सह शिक्षा महाविद्यालय और 12 कन्या महाविद्यालय एवं 3 कृषि महाविद्यालय, इस प्रकार 31 नवीन महाविद्यालय खोले जाने के लिए प्रस्तावित किये हैं। साथ ही 5 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने एवं 4 महाविद्यालयों में नये संकाय, 5 महाविद्यालयों में नवीन विषय खोलने की घोषणा की है। आधारभूत संरचना विकास के लिए 6 महाविद्यालयों के भवन निर्माण, मरम्मत कार्य और राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के ऑडिटोरियम निर्माण की भी घोषणा की है। आपके अजमेर में की है।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा विभाग के लिए बजट प्रस्तावों के लिए आपके एवं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आभार ज्ञापित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता उसकी इमारत और सुविधाओं के साथ-साथ उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता से उनकी गुणवत्ता निर्धारित

होती है। सरकार ने महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को और गतिशील बनाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉलेज शिक्षा विभाग में लगभग 2600 शिक्षकों के पद रिक्त है जिनके विरुद्ध लगभग 2500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में चल रही है और RPSC में प्रक्रियाधीन 1,936 पदों की भर्ती प्रक्रिया में से 11 विषयों के 397 अभ्यर्थियों की सूची विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 07 विषयों के 32 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि कॉलेज शिक्षा विभाग को प्राप्त सहायक आचार्य के शेष 365 चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से हिन्दी विषय के 195 सहायक आचार्यों की काउन्सलिंग करके आज नियुक्ति के आदेश हो गये हैं।

अंग्रेजी, भूगर्भ विज्ञान, पेन्टिंग विषय के सहायक आचार्य के पदों पर काउन्सलिंग करके नियुक्ति के आदेश एक महीने में कर दिये जायेंगे। सहायक आचार्य भर्ती के लिए RPSC द्वारा 2025 में सहायक आचार्य के 574 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। इस पर आगामी कार्यवाही RPSC के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही RPSC द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष के 247 रिक्त पदों को भरने हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 25.02.2025 को एवं पीटीआई के 247 पदो के लिए 30.01.2025 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। RPSC से इन भर्तियों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए त्वरित गति से प्रयास किये जा रहे है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ सहायक के 80 एवं शीघ्र लिपिक के 16 रिक्त पदों को भरने हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। सहायक कर्मचारी के 863 रिक्त पदों, कनिष्ठ सहायक के 258 रिक्त पदों व वाहन चालक 05 रिक्त पदों की अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शिक्षको के 1597 पद रिक्त हैं, इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूजीसी के मापदंड एवं राज्य सरकार के नियमानुसार रोस्टर की प्रक्रिया पूर्ण करके भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की वजह से विद्यार्थियों के अध्ययन में कोई बाधा नहीं आए, उसके लिए विद्या सम्बल योजना के तहत शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 132 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। यह कार्य शीघ्र पूर्ण करवा लिया जायेगा एवं अस्थायी भवनों में संचालित महाविद्यालयों को स्थायी भवन में संचालित करा दिया जायेगा। दिनाक 12 जनवरी, 2025 को प्रदेश के 51 महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों तथा 01 महाविद्यालय के पुनर्निर्मित भवन का लोकार्पण किया जा चुका हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, 50 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों के लिए कुल 259.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। इन भवनों का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। आशा है कि निकट भविष्य में शीघ्र इन भवनों का लोकार्पण करके इनमें महाविद्यालय प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके और सदन के माध्यम से मैं सभी भामाशाहों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होने प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया हैं। इन भामाशाहों द्वारा प्रदेश के 03 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिनमें श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय, नोहर का निर्माण करवाने के लिए श्री केशव कुमार बिहानी का, शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय, धौरीमन्ना, बाडमेर का निर्माण करवाने के लिए श्री उदयराज गांधी का तथा राजकीय सदूदेवी पारख कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ का निर्माण करवाने के लिए श्री जतन पारख का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। कई वर्षों से लंबित आरवीआरईएस व्याख्याताओं को सीएएस के अन्तर्गत 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 61 शिक्षकों को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को चयनित वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान एवं पे बैण्ड 4 प्रदान किये जाने बाबत पात्र शिक्षकों को सीएएस का लाभ स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शीघ्र प्रदान किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, विगत भाजपा सरकार द्वारा आरईएस शिक्षकों को यूजीसी पदनाम सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य प्रदान कर दिये गये थे परन्तु आरवीआरईएस शिक्षको को यह पदनाम नहीं दिये गये थे, हमारी सरकार गठन के पश्चात् यह पदनाम स्वीकृत करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी, यह कार्यवाही अब अंतिम चरण में है। आशा है कि शीघ्र ही आरवीआरईएस शिक्षको को यूजीसी पदनाम सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य हो जायेगें।

विभाग के कार्मिकों की सुविधा के लिए कार्यों को विक्रेन्द्रीकृत करने की दृष्टि से चाइल्ड केयर लीव, पीएचडी अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, उच्च अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दक्षता हेतु किये जाने वाले ओरियेन्टेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि कार्यो की अनुमति हेतु राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक निदेशकों को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिटस पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर उनकी अपार आईडी बनाई गई है।

spp/rtm/04.03.2025/21.40/5a

साथ ही, परीक्षा परिणामों को डीजी लोकर पर अपलोड किया गया है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों को स्वयं पोर्टल अर्थात् स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाई यंग एंड एस्पाइरिंग मांइन्ड्स पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से क्रेडिट प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

इससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने का अवसर मिलेगा।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एवं श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लोकार्पण हो चुका है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिफ्ट हो चुका है तथा श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय नवीन परिसर में निकट भविष्य में शिफ्ट हो जायेगा।

नवीन सरकार के गठन पश्चात् से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने तथा छात्र-छात्राओं में उत्साहवर्धन करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को समय पर उपाधियां मिल सकें।

हमारी सरकार के गठन के बाद अभी तक लगभग 12 लाख 83 हजार से अधिक उपाधियां एवं 1280 पदक प्रदान किये गये हैं।

भारतीय पारम्परिक ज्ञान की समृद्ध विरासत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मार्गदर्शक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पारम्परिक भारतीय ज्ञान एवं प्रणाली के संवर्द्धन पर बल दिया है।

इसके संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु भारतीय ज्ञान परम्परा संबंधी कोर्सेज को सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने हेतु विश्वविद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है।

सभी विश्वविद्यालय कुल अर्थात् परिवार ही होते हैं। इसके लिये उच्चतम गुरू को हमारे पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों में भी कुलगुरु के रूप में ही संबोधित किया गया है।

हमारी सरकार द्वारा पिछले बजट में गुरू शिष्य की परम्परा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया था।

इसी की पालना में दी राजस्थान यूनिवर्सिटीज् लॉ एमेन्डमेन्ट बिल, 2025 विधान सभा में पुरःस्थापित कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि यह बिल सदन में इसी सत्र में पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, नीट और आईआईटी के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के द्वारा निराशा एवं अन्य कारणों से आत्महत्या करने के प्रकरण ध्यान में आने पर हम सभी का मन उद्वेलित और दुःखी होता है।

हमारी डबल इंजन की सरकार सदैव छात्रों के शैक्षणिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति सचेत एवं सजग रहती है।

इसी क्रम में कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अंगीकार करते हुए विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

इसी अनुक्रम में कोचिंग संस्थानों पर सक्षम वैधानिक नियंत्रण हेतु विधेयक दी राजस्थान कोचिंग सेन्टर कन्ट्रोल एण्ड रेगुलेशन बिल, 2025 प्रक्रियाधीन है।

यह विधेयक कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता, शुल्क नियंत्रण, छात्रों के अधिकारों और अनुशासन को नियमित करने में सहायक होगा।

जहां एक ओर हम सरकारी महाविद्यालयों को सशक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य वित्तपोषित एवं निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पारदर्शी रूप से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें तो एक आदर्श स्थिति होती है।

परन्तु प्रदेश के राज्य वित्तपोषित एवं निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होती है तो कष्ट होता है।

विश्वविद्यालय युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण करने का केन्द्र होता है। निर्माण की पाठशाला की जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तो शासन के साथ साथ समाज को भी पीडा होती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार शिकायतें प्राप्त होने पर विश्वविद्यालयों के अधिनियम के अनुसार जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करती है।

हमारा प्रयास है कि सभी विश्वविद्यालय गुणात्मक एवं पारदर्शी शिक्षा प्रदान करें और राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने में अपना योगदान प्रदान करें।

देश के विकास में युवा पीढ़ी की सशक्त हिस्सेदारी के प्रयासों में युवा पीढ़ी को नशामुक्त बनाने हेतु विभाग द्वारा महाविद्यालयों में ''नयी किरणः नशा मुक्ति अभियान' संचालित किया जा रहा है जिसमें माह फरवरी, 2025 तक 13,510 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

साथ ही, प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को नशामुक्ति ई-शपथ का कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक एक लाख 13 हजार 113 विद्यार्थी शपथ ले चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार युवा शक्ति को देश के महापुरुषों से प्रेरणा मिले इसी उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालयों में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व व कृतित्व पर दिवेर विजय स्मृति कार्यक्रम आयोजित किये गये।

साथ ही सुशासन की प्रतीक एवं आदर्श नारी के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रतिस्थापित न्यायप्रिय पुण्य श्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष को भी

विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से उत्साहपूर्वक महाविद्यालयों में मनाया गया।

प्रकृति, पशु पक्षी, मानव जीवन तथा राष्ट्र से प्रेमपूर्ण अवधारणा की जीवन्तता के दृष्टिगत राज्य के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ''एक पेड़ मां के नाम'' थीम के अनुसार पौधारोपण, पक्षियों हेतु परिण्डे की व्यवस्था, दान भावना के प्रोत्साहन हेतु दान उत्सव, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन, स्वच्छता ही सेवा तथा हर घर तिंरगा अभियान जैसे कार्यक्रमों को साकार रूप प्रदान किया गया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों के गुणवत्ता मानकों में अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2024 में 45 राजकीय महाविद्यालयों में नैक प्रत्यायन ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

विभाग के सतत प्रयत्नों से नैक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन महाविद्यालयों में भी प्रत्यायन कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार, शोध, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए कुल 330 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ है।

बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान योजना के अर्न्तगत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 100 करोड जेण्डर समावेशन और समानता पहल योजना में बांसवाडा, प्रतापगढ़, जैसलमेर और करौली जिलों में स्थित महाविद्यालयों के लिए 40 करोड़

और विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को मजबूत करने के लिए महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाडा एवं एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर के लिए 60 करोड़ तथा 26 राजकीय महाविद्यालयों के लिए 130 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने छात्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं को और प्रभावी बनाया है।

हमने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रवृत्ति का वितरण समय पर और पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिससे किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा को बीच में न छोड़ना पड़े।

इस वर्ष लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है और आगामी वर्षों में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा।

हम यह मानते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर छात्र को बिना किसी वित्तीय बाधा के मिलना चाहिए और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हमने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ उन छात्रों को मिले जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, विगत सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉरलशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ की और विदेश में पढ़ने के लिए 500 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया था, जिसकी यह बार-बार बात कहते हैं। इन्होंने योजना

शुरू की, उसके बारे में बता रहा हूं।

श्री अध्यक्षः अभी तो आप सुनो, यह भी सुन लेंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इन्होंने 2021-22 में केवल 73 विद्यार्थियों को केवल 5 करोड़ 30 लाख रुपये दिये, जिसकी यह बात कर रहे हैं।

इसी प्रकार 2022-23 में 172 विद्यार्थियों को 63 करोड 19 लाख का भुगतान किया गया। वर्ष 2023-24 में कुल 447 विद्यार्थियों का चयन हुआ जिसमें से केवल 102 विद्यार्थियों का चयन हमारी सरकार के गठन होने के पश्चात् हमने किया है। इन विद्यार्थियों को 160 करोड़ 69 लाख का भुगतान हुआ है, जिसको हमने स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशी संस्थाओं में अध्ययन हेतु 300 विद्यार्थी एवं देश के संस्थानों में 200 विद्यार्थियों के लिये विगत योजनाओं की कमियों को दूर कर जरूरतमंद एवं गरीब विद्यार्थियों के लिये दिशा-निर्देशों के साथ प्रारंभ की है।

jyg/rtm/04.03.25/21.50/5b

जिससे वो गांव और ढाणी में रहने वाला बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले सके। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): उन बच्चों की फीस तो जमा करवा दो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं कि आपने नहीं करायी है, हमने करायी है। मैं आपका जवाब दे रहा हूं कि आपने कितनी दी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विराजो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमने कितनी दे दी, वो बता रहा हूं। वर्ष 2024-25 के लिए 126 विद्यार्थियों को विदेश में और 57 विद्यार्थियों को देश के संस्थानों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है। ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ...(व्यवधान)... जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 285 विद्यार्थियों को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ...(व्यवधान)...

आप फिर स्कूटी योजना की बात कर रहे हो, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत 20,105 स्कूटियों का वितरण किया जा चुका है। साथी योजनांतर्गत विभागों से सम्बन्धित स्कूटियों की संख्या सत्र 2023 के लिए 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गयी है। जिसमें वर्ष 2025 की घोषणा में बढ़ाकर 35 हजार कर दी गयी है। पुराने अकादमिक सत्र की बकाया स्कूटियां शीघ्र ही वितरित करने के लिए नियम वित्त विभाग की राय के अनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काली बाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में सभी वर्गों के अंतर्गत, अभी आप कह रहे थे, माननीय सदस्य, कि ओबीसी के लिए इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं आपको इसी की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस योजना में सभी वर्गों के अंतर्गत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा

वरीयतानुसार स्कूटी दी जाती है। जिसके अंतर्गत ओबीसी वर्ग की छात्राएं भी लाभांवित होती हैं। वर्ष 2021-22 में सामान्य वर्ग से चयनित 1,690 छात्राओं में से 1,059 ओबीसी वर्ग की छात्राएं थीं। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में चयनित 2,775 में से 1,666 ओबीसी वर्ग की छात्राएं थीं। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में चयनित 4,162 में से 2,706 ओबीसी वर्ग की छात्राएं थीं। इसलिए हम ओबीसी के भी, किसी भी जाति के लिए ऐसा नहीं करते, सभी जातियों को वरीयता के अनुसार दिया जाता है। इस प्रकार काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में ओबीसी छात्राओं को भी लाभ मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जाग्रत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि के देखते हुए बजट 2025-26 में प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और इसे सशक्त किये बिना समाज का समग्र विकास सम्भव नहीं है। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा को न केवल सुलभ बनाने का कार्य किया बल्कि इसे उच्च गुणवत्ता और नवाचारों के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि उच्च शिक्षा का हर पहलू, चाहे वह नये महाविद्यालयों की स्थापना हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, छात्रवृत्ति का वितरण हो या शोध या नवाचार को बढ़ावा देना हो, सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किया जाये। हमने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने की दिशा में जो कदम उठाये हैं वो निश्चित रूप से राज्य को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाई तक ले जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य केवल महाविद्यालय खोलना नहीं बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना जहां शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और राजस्थान देश में शिक्षा का अग्रणी राज्य बने, यही हमारा संकल्प है और यही हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं समापन की ओर बढ़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि-

सपनों को सच और ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं अंतः प्रेरणा, केवल बल नहीं, अंतर्बल की जरूरत होती है, क्योंकि जन्नत ना मन्नत से मिलती है और ना ही मन्नत से वह पैदा की जाती है, वो मेहनत से पैदा की जाती है। हमारी सरकार मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगी और प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कवि महोदय जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा-

'जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है,
हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है,
अभी तो नापी मुट्ठी भर जमीन है,

अभी तो सारा आसमान बाकी है।'

जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले मांग रख दो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 22 को पारित किया जाये।

बधाई एवं आभार

भारतीय क्रिकेट टीम की चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमी फाइनल में जीत पर बधाई

श्री अध्यक्षः माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बढ़िया बातें सुनने के बाद एक बढ़िया बात मैं भी आपको बता रहा हूं।

आज चैम्पियंस ट्रॉफी में सेमी फाइनल में अपनी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। सभी माननीय सदस्यों को सदन की ओर से भारतीय टीम को बहुत-बहुत बधाई आपकी ओर से देता हूं।

...(व्यवधान)...

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 218,82,20,69,000/- (दो सौ अठारह अरब बयासी करोड़ बीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 288,30,94,49,000/- (दो सौ अठासी अरब तीस करोड़ चौरानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,85,55,45,000/- (पच्चीस अरब पचासी करोड़ पचपन लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक ...(व्यवधान)... मैं कल की तरह चैक कर रहा था।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 05 मार्च 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.58 बजे, बुधवार, दिनांक 05 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

अनुदान की मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

1. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अधिकांश स्कूलों में विगत कई वर्षों से संधारण कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में छात्र-छात्राओं के अनुपात में भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

3. विधान सभा क्षेत्र आहोर के मालगढ़, देवगढ़-छापरिया में प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

4. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-बिरौदा (महवा), नौगॉव (महवा), राजकीय प्राथमिक विद्यालय-रूद का नागला (महवा) एवं मौसमपुर पट्टी को क्रमोन्नत करने तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चूरखेड़ा में पेयजल की व्यवस्था एवं चारदीवारी का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

5. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने एवं शौचालय का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

6. ब्यावर जिले में विगत सरकार द्वारा बन्द किए गए सभी प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्राथमिक स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्राथमिक स्कूलों के भवनों की जर्जर हालत को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्राथमिक स्कूलों में खेल मैदान के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के भौतिक विकास के लिए खेल योजनाएं बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

12. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण छात्रों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

13. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पूर्व में बन्द हुए प्राथमिक विद्यालयों को पुनः संचालित करने, प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने तथा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भनोखर को महात्मा गांधी विद्यालय से पृथक करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बालिका विद्यालय खोलने, ग्राम पंचायत मुख्यालय- सिणेर, सैला, भूका भगत सिंह एवं खेज़डिपाली में नवीन बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नवीन राजस्व गांव, ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं पूर्व में समायोजित किए गए विद्यालय पुनः शुरू करने, सिवाना बीईईओ के अधीन-जेतमाल नगर, सिणधरी बीईईओ के अधीन-गोगाजी धोरा भाटा (समायोजित विद्यालय) एवं रावत नगर, कांजी, सेवालियों की ढाणी-कांजी, कपूरडीनाड़ी भाटा, धांधलों की ढाणी दांखा, किशनोणी राजपूतों की ढाणी–सिणधरी चारणान, एवाड़ी, कमठाई को पुनः शुरू करने एवं नवीन विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा अन्य प्रदेशों की भाँति स्थानीय राजस्थानी भाषा में दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में वर्ष 2008 से पदस्थापित प्रबोधक, उच्च स्तर के विद्यालयों में योग्यताधारी प्रबोधकों के पदस्थापन एवं पदनाम-समायोजन अध्यापक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन के आधार पर अध्यापकों का पदस्थापन करने के पश्चात् अधिशेष अध्यापकों को कमी वाले विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

19. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

20. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन राजकीय प्राथमिक एवं नवीन राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

22. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक भौतिक सुविधाओं से युक्त अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, पेयजल स्रोत, खेल मैदान, शौचालय एवं चारदीवारी आदि प्रमुख निर्माण कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

24. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय-गुगाजी की ढाणी, डालाना जोहड़, कानाका वाली ढाणी, छतरी की ढाणी, फगेडियों की ढाणी, वार्ड नं. 6 नवलगढ़ एवं वार्ड नं.20 मुकुन्दगढ़ को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

25. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में से जर्जर हालत वाले विद्यालयों की मरम्मत एवं नए कमरे तथा शौचालय निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में बजट घोषणा 2024-25 में स्वीकृत 50 नए विद्यालयों में से पूर्व में निर्मित भवनों में ग्राम शाहीपुरा, ग्राम पंचायत गुढा, ग्राम तीखाबड़ा, मंगल पंचायत व पुराना गांव अजेता में बंद पड़े विद्यालयों को पुन: खोलने के संबंध चर्चा के लिए।

27. प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए स्थानान्तरण नीति बनाकर क्रियान्वित करने के संबंध चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

28. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र भीम में नवीन राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, काछबली (भीम) एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रतनाखेड़ा (कालागुमान), चक कालागुन (ताल) व कुलता का खेड़ा (स्वादडी) में खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.1)

30. प्रदेश में पुरातन गुरूकुल व्यवस्था को स्थापित करने में निष्फलता के कारण जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

31. विधान सभा क्षेत्र आहोर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-पचानवा, भागली पुरोहितान मालपुरा, मंडला, बालिका पाचोटा में कक्षा-कक्ष की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

32. विधान सभा क्षेत्र आहोर के नोसरा बागरा में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्थित पीपरला की ढाणी, रातानाड़ा, कुण्डली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र आहोर में वर्षा के समय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छत से पानी के टपकने तथा कक्षा-कक्षों के जर्जर स्थिति में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

35. किशनगंज-शाहाबाद में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत नए भवन एवं जर्जर भवनों की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

36. प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में प्रतिबन्धित जिलों के शिक्षकों के स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 6-डी प्रक्रिया के तहत प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित करने के संबंध चर्चा के लिए।

39. प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया से शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार करवाए जाने अथवा आवश्यकतानुसार नवीन भवन निर्माण करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)

41. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भोमियों की ढाणी (ग्राम पंचायत भूण्डेल), करणीनाडा (ग्राम पंचायत भूण्डेल) एवं खिंचियों की ढाणी (ग्राम पंचायत नोखा चांदावता) में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
44. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में विगत 8 वर्षों से बन्द पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय-दधवाड़ी को पुन: प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

45. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जमाबंदी पर आधारित भूमि की पैमाईश करवाकर बॉउण्ड्रीवाल बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
46. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के अलनिया ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मूलभूत एवं भौतिक सुविधाओं से वंचित विद्यालयों में विकास कार्य करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
49. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालयों में नवीन कक्षों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त कमरों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

50. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा(आबू) के प्राथमिक विद्यालयों में नए कक्षा-कक्ष बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
51. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा(आबू) में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)</u>

52. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चूरखेड़ा में पेयजल की व्यवस्था एवं क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
53. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूंद का नगला (महवा) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
54. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नौगांव (महवा) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

55. जोधपुर शहर में बालक एवं बालिकाओं के पाँच विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. जोधपुर शहर में स्कूलों के समायोजन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

57. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में स्कूलों को क्रमोन्नत करने तथा भवनरहित स्कूलों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के प्राथमिक विद्यालयों में अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति तथा विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

59. विधान सभा क्षेत्र बगरू के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

60. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में नवीन विद्यालय खोलने, महात्मा गांधी विद्यालय में स्टाफ उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में शिक्षक नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

61. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गाडरी खेड़ा (442810) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

62. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में मर्ज की गई स्कूलों को खोलने तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

63. प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण पर वर्षों से लगाए हुए प्रतिबंध को समाप्त कर स्थानान्तरण प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में भवनहीन अथवा जर्जर भवन वाले विद्यालयों को चिन्हित कर नवीन भवन/कक्षा-कक्ष बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

66. विधान सभा क्षेत्र बयाना के नागला जाटवान ग्राम पंचायत सालाबाद में पुन: राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र बयाना के प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र बयाना में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के लिए डिजिटल साधनों, स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर शिक्षा और इन्टरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)</u>

71. प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा एक ही निदेशक के अधीन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. प्रदेश में कक्षा एक में नामांकन कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)</u>

75. प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, 2009 के द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात में अध्यापकों की उपलब्धता, खेल मैदान, पर्याप्त कक्षा-कक्ष, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, पुस्तकालय, पेयजल सुविधाएँ तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालक-बालिकाओं के लिए निर्बाध पहुँच आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रावधान वर्ष 2010 से लागू होने के 15 वर्षों बाद भी प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कानून को लागू किए जाने के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा घुमन्तु एवं विमुक्त, सांसी, कंजर, रहवासी जाति के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील योजना के तहत छात्र-छात्राओं को भोजन कराए जाने के बावजूद ड्रापआऊट की समस्या के लगातार बने रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अधिकांश प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय किराए के भवनों में संचालित होने, जीण-शीर्ण, जर्जर एवं असुरक्षित होने के कारण प्रारम्भिक कक्षाओं के प्रवेशित बालक-बालिकाओं का आकर्षण विद्यालय की ओर न होने तथा उनमें शिक्षा के प्रति उदासीन भावना विकसित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने से शिक्षण की व्यवस्था गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने के कारण 5वीं से 8वीं कक्षा तक

के बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान भी भली-भांति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

80. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजस्व ग्राम खीचीवाला एवं जांदवा में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करवाने, ग्राम ठठावता मेघवाल मोहल्ला में बंद किए गए राजकीय विद्यालय को पुनः शुरू करवाने, राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों को ध्वस्त कर नवीन भवन निर्माण करवाने, विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक लगवाने तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

81. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मर्ज की गई प्राथमिक स्कूलों को पुनः शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।
82. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नवीन प्राथमिक स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
83. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्रिशुल को पुनः खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

84. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हूरड़ा में मर्ज कर बन्द कर दी गई प्राईमरी स्कूलों को पुनः डिमर्ज कर चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।
85. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हूरड़ा के ग्राम अर्जुनपुरा (ग्राम पंचायत बोरेला) ग्राम जालकी का बाड़ीया (ग्राम पंचायत रामपुरा) में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

86. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

87. प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियोंके लिए हैप्पीनेस करिकुलम (खुशी का पाठ्यक्रम) जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।
88. प्रदेश के प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को देश व प्रदेश के वीरतापूर्ण इतिहास गौरव और महापुरूषों की जीवनी पर शिक्षण के संबंध में चर्चा के लिए।
89. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के शिक्षकविहीन विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के अनुपात में कम शिक्षकों की संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
90. प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पौष्टिक व संतुलित आहार दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु वेद और योगा पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)

92. विधान सभा क्षेत्र नोहर के वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नए प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

93. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम के राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में राजकीय विद्यालयों के नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं जीर्ण-शीर्ण कक्षों के मरम्मत व पुन: निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय शुरू किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में उच्च प्राथमिक बोर्ड की स्थापना करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)

98. विधान सभा क्षेत्र नोहर में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र नोहर में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमरों व चारदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदश में जनवरी, 2024 के पश्चात् बंद किए गए राजकीय विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने वाले प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष मील (वि.सं.179)

101. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदयपुरा में नवीन विद्यालय भवन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

102. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में मूक-बधिर एवं मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

103. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाडलवास में नए कक्षा-कक्ष के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-ढाणी रावतान, मोड़की में नए कक्षा-कक्ष के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बंधा की पपुरना में नए कक्षा-कक्ष के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।
106. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय-ढाणी पीरूका-खरखड़ा में नए कक्षा-कक्ष के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

107. विधान सभा क्षेत्र मकराना में नव सृजित ग्राम पंचायत कोरोली (मकराना) में उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
108. विधान सभा क्षेत्र मकराना में बन्द की गई स्कूलों को पुनः चालू करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
109. विधान सभा क्षेत्र मकराना के स्कूलों में नए भवन बनवाने, स्कूलों में नए शौचालय बनाने, पुराने भवनों की मरम्मत कराने तथा स्कूलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

110. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लक्ष्मीपुरा (बरोदा) में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खोलने, अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने, विद्यालयों के खेल मैदान एवं विद्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन करने तथा विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाली कार्मिक का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

111. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में बच्चों के अनुपात से अधिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ताराचन्द (वि.सं.73)</u>

112. विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।
113. श्रीडूंगरगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
114. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

115. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बंद पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय भटिण्डा को पुनः भटिण्डा ग्राम में प्रारम्भ/संचालित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
116. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बंद पड़े राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार कर पुनः संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण, शुद्ध पेयजल, चारदीवारी, शौचालयों हेतु व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य करवाने, खेल मैदानों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हटवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक लगाने, खेल मैदान तैयार करने, योगाभ्यास, प्रार्थना सभा करवाने एवं विद्यार्थियों को दूध पावडर के बजाय ताजा डेयरी का दूध पिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)

120. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के विद्यालयों में दिव्यांग सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु आगामी शिक्षक भर्तियों में विशेष शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत ग्राम मांडियाई खुर्द में धोलिया भाकर के पास नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजकीय विशेष आवासीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के मरम्मतीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं.106)

125. प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हेल्पर का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नवीन प्राथमिक विद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

128. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समसा द्वारा स्कूलों में विद्यालय भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

129. प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिशुओं के लिए प्ले-ग्राउण्ड एवं क्रैच खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

133. प्रदेश में लिटरेसी एवं न्यूमरेसी गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं भवनों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में स्मार्ट कक्षा-कक्षों का निर्माण एवं आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक द्वारा शिक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. प्रदेश में विद्यालयों की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बाल वाटिका प्रारम्भ नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)</u>

138. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल(जयपुर) में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)</u>

139. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय प्राथमिक विद्यालय-चूना भट्टा गोटन, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जारोड़ा खुर्द के भवनविहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की बजट स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम जड़ाऊ कलां, कलरू, नेतड़िया व कात्यासनी में नवीन विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पिथास, चौहान नगर, लांछ की ढाणी में नवीन विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)

142. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)

143. प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा स्तर से ही संस्कृत भाषा, वैदिक गणित और राजस्थान के गौरवशाली महापुरूषों की कथाओं को समाविष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा स्तर से ही खेल प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें निखारने के लिए खेल विभाग के साथ संयुक्त कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के एकीकरण कार्य को विशेष प्राथमिकता से सम्पादित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

146. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के मर्ज हुए विद्यालय-बोटड़ा व अन्य को डीमर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में घुमन्तु परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में पंचायत या संकुल स्तर पर एबीएल रिसोर्स सेंटर अर्थात् गतिविधि आधारित शिक्षण संदर्भ केन्द्र को प्रभावी ढंग से विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

150. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के लिए उल्लेखित बिन्दुओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रभावी योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं.120)

151. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामबिलास (वि.सं.135)

152. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के प्राथमिक विद्यालयों के क्रमोन्नयन एवं भूमि व भवनविहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

153. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल व्यवस्था तथा बिजली का कनेक्शन जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
154. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जर्जर भवनों की मरम्मत करने एवं शौचालय निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
155. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
156. प्रदेश में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
157. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के रामपुरा में मेघवाल बस्ती में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

158. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, शौचालय एवं पेयजल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
159. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
160. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम लाडाबास में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं ग्राम रघुनाथपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
161. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भवादिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
162. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के खुनखुना स्टेशन में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

163. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय-सुनारोंवालों, खेजरोली को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
164. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय-कुमावतों की ढाणी राडावास को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
165. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय-ढाणी रेडान पीपलोद को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
166. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय-ढाणी खुडालिया को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय-भर्तृहरि मोड़ विलान्दरपुर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)</u>

168. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक 5-एलएनपी में दो कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

169. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैरादड़ा, तहसील रैणी (अलवर) के जर्जर भवन का पुन: निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेडोली,तहसील रैणी (अलवर) में चार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

171. प्रदेश में प्रबोधकों की अध्यापकों के समान नियमित डीपीसी की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में लिपिक और सहायक कर्मचारी के पद सृजित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. प्रदेश में अध्यापकों से गैर-शैक्षणिक कार्य कराए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

अनुदानों की मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से **100 रुपया** कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

1. विधान सभा क्षेत्र बांरा-अटरू के अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिये खेल-कूद मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र बांरा-अटरू में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कंवरलाल (वि.स.26)

3. विधान सभा क्षेत्र अन्ता के माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं चार दीवारी निर्माण के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

4. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांथा में विज्ञान एवं कृषि संकाय, पावटा में गणित एवं विज्ञान संकाय, जटवाडा में गणित संकाय तथा रौत हडिया में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावरा, महवा (टीकाराम पालीवाल), ऊकरूप, रौतहडिया, खेडला गदाली, सलेम्पुर थाना, बाडा बुर्जुग, खेड़ला बुजुर्ग, तालचिडी, बहडखों, दुल्हापुरा, टूडियाना, कमालपुर, बरीतकी, मालीपुरा तालचिडी एवं पावटा में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

6. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में बालक- बालिकाओं के अलग-अलग शौचालय निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

7. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरूपा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय में ई-लाइब्रेरी खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी माध्यम में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदानों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)

13. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में शिक्षकों का अलग केडर बनाकर नई भर्ती कर पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

14. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डयोढाना (कठूमर) तथा मोकलटेडी (लक्ष्मणगढ़) को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

15. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम पंचायत मुख्यालय केलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलवाड़ा में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के देवडा, सरीयादे नगर, रबाटीपों का थाटा, अन्नपूर्णा नगर, मांगी एवं लोहिड़ा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति के अनुसार पद स्वीकृत कर पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. बाड़मेर एवं बालोतरा जिलों में माध्यमिक शिक्षा में गणित/अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं प्राचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैला, देवन्दी, सिठोर, चाडो की ढाणी, ईटपापा, दान्तेरीपार, खेजडिपाली, गोलीपाभापलान, कांखी, लोहिडा एवं रबारीयों की ढाणी सहित कई विद्यालयों में भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय (बालक-बालिका), खेल मैदान तथा भौतिक सुविधाऍं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोकलसर, सिणरे एवं भूका भगत सिंह में विज्ञान संकाय खोलने के साथ इन विद्यालयों के कला संकाय में राजस्थानी विषय शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

21. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

22. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित माध्यमिक स्तर के समस्त राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार विभिन्न संवर्ग के नवीन पद स्वीकृत कर अतिशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उचित मापदण्डानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि आदि नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित माध्यमिक स्तर के समस्त राजकीय विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

27. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ विद्यालयों में कक्षा-कक्ष भवन जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति एवं आवश्यकतानुसार नये कक्षा-कक्ष बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

28. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कमरों एवं शौचालय निर्माण व जर्जर कमरों व भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, करजूना को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पद तत्काल स्वीकृत कर नियुक्ति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारोठ (भीम) व मदारिया (देवगढ़) में नवीन विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
32. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में एक केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूरीभडाज में विज्ञान संकाय खुलवाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फोजावाली अंग्रेजी माध्यम को हिन्दी माध्यम में करने तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नागडीवास को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तथा भवरानी शंखवाली, सांकरणा एवं बागरा में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
35. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बागरा सियाणा में 10000 से अधिक आबादी होने के उपरान्त भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में ओपन जिम नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
36. विधान सभा क्षेत्र आहोर में उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलडी, बुडतरा, मिठडी, गोविन्दला, बेदाना-कला एवं रसियावास खुर्द को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
37. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थांवला, मेडा उपरला, कंवला, ओडवाडा, सनवाडा, सांडन, देलदरी, बोकडा, चुण्डा सराणा, शंखवाली,मालगढ, किशनगढ़ में कक्षा-कक्ष की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
38. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छत मरम्मत एवं कक्षा-कक्ष मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

39. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

40. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्वार/नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
41. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षकों सहित विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।
42. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में नई भर्ती प्रक्रिया के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
43. विधान सभा क्षेत्र भादरा के अधिकांश विद्यालयों में आवश्यकतानुसार विज्ञान, कृषि एवं वाणिज्य संकाय खोलने एवं कला संकाय में अतिरिक्त विषय स्वीकृत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
44. विधान सभा क्षेत्र भादरा के अनेक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर लेब एवं कम्प्यूटर की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>**श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)**</u>

45. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खींवसर में हिन्दी साहित्य एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूण में भूगोल, गृह विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान अतिरिक्त विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)**</u>

46. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैनणी में विज्ञान एवं गणित संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, असावरी, माणकपुर, पांचौडी, बिरलोकास, गुढा भगवानदास, नागडी, रोलाचांदावता एवं हरसोलाव में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मून्दियाड एवं शहीद सुरेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शंखवास एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरनाला में कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
49. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)**</u>

50. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), कैथून में विषयवार नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
51. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लाडपुर ग्राम पंचायत जाखोड़ा को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रायपुरा को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित केडर स्ट्रेंथ से रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम (वि.सं.175)

54. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू के माध्यमिक स्कूलों में कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू के ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

57. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रौती-हडिया में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जटवाडा में गणित संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पावटा में गणित एवं विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

60. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद भरने तथा नये कमरों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

61. केलवाड़ा के उच्च माध्यमिक विधालय के जर्जर भवन में 10 कक्षा-कक्षों के निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

62. विधान सभा क्षेत्र बगरू के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

63. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा महात्मा गांधी विद्यालय में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

64. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेडी का अमराणा (483087) को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
65. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठिकरिया (483081) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
66. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सतपुडा (224179) में नवीन वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

67. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने एवं विद्यालयों के भवन बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

68. झालावाड़ जिले के खानपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारोला तारज, पनवाड, सूमर, हरिगढ़, बाघेर, जोलपा और गाडवाडा में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
69. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
70. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारोला व पनवाड में कृषि विज्ञान संकाय खोलने एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारोला में अंग्रेजी व्याख्याता का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
71. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अपर्याप्त कक्षा-कक्ष वाले विद्यालयों को चिन्हित कर नवीन कक्षा-कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

72. विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
73. विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
74. विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बयाना एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामचरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपवास में एन.सी.सी. ईकाई खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
75. विधान सभा क्षेत्र बयाना के कंजोली, घुरेटी, बंगसपुरा, नगला झामरा, घाटा, गुर्जर बलाई एवं लखनपुर के राजकीय विद्यालयों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र बयाना के पी.एम. श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानसुजापुर में कृषि संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

77. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के क्रमोन्नत विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने पर विद्यार्थियों से कार्य करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

80. प्रदेश में विद्यालय परिसर में बीड़ी, सिगरेट व गुटका खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के विद्यालयों में सुरक्षा व सुचारू रूप से अध्ययन हेतु कैमरा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

82. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवीन गुलाबबाडी में हिन्दी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य के पदों को स्वीकृत कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित राजाकोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबबाडी में स्ववित्त पोषण योजना के तहत चलाये जा रहे विषय को सरकार द्वारा पूर्णकालीन नियमित विषयों के रूप में राज्य वित्त पोषण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माखुपुरा एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबबाडी में कृषि संकाय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणीपुरा एवं भगवानगंज व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाडगंज में विज्ञान संकाय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगंज एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर में कलां संकाय में चित्रकला एवं संगीत कला विषयों को जौड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

85. प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को भी शाला गणवेश का कपड़ा नि:शुल्क दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. प्रदेश के निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से अधिक शुल्क एवं मनमानी फीस वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं. 91)

87. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत करने, जर्जर भवनों को ध्वस्त कर नवीन भवन का निर्माण करने, रिक्त पदों पर शिक्षकों का पदस्थापन करने तथा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, दाउदसर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

88. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
89. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
90. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डेरू, शेखपुरा भोपुर एवं पदमपुरा के विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
91. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
92. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

93. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपाहेलीकलां में कृषि संकाय खोलकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राहत प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

94. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय (पिंक टॉयलेट) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
96. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा- कक्षों व जर्जर हो चुके भवनों का निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
97. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

98. प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक बालिका मॉडल स्कूल की स्थापना (जो निजी विद्यालय के समान सर्व सुविधा युक्त हो) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

100. विधान सभा क्षेत्र नोहर में मापदंड अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र नोहर के वंचित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदानों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

102. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम की राजकीय बालक-बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीनाथ घाटी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नं; 15, जस्सुसर गेट बीकानेर को एकीकृत नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में विद्या-समीक्षा केन्द्र मुख्यालय शुरू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं जीर्ण-शीर्ण कक्षों की मरम्मत व पुनः निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

105. प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

107. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द में महात्मा गांधी इंगलिश मिडीयम में मर्ज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को पृथक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की ग्राम पंचायत बरसनी, पाटन, शम्भुगढ़, अंटाली एवं आसीन्द में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

109. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, नवीन संकाय खोलने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

110. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांवट तथा चौमूं पुरोहितान में कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

111. विधान सभा क्षेत्र खण्ड़ेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाखनी में नवीन विद्यालय भवन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र खण्ड़ेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आभावास, लांपुवा एवं जाजोद में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं.165)</u>

113. विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकाय विषयों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विधालयों को क्रमोन्नत करने तथा सभी महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

114. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लसड़ावन, केली एवं बाड़ी, तहसील-निम्बाहेड़ा में कृषि विज्ञान अतिरिक्त संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाई ब्लॉक-निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौडगढ़ में अतिरिक्त संकाय (कला) विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बाहेड़ा, में विज्ञान संकाय में अतिरिक्त गणित विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पंचायत समिति छोटी सादड़ी के तीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय- (1) छोटीसादड़ी (2) रम्भावली (3) बम्बोरी में अतिरिक्त संकाय कृषि विज्ञान खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

118. विधान सभा क्षेत्र मकराना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जाने एवं कम्प्यूटर अनुदेशक लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत लोरोली में एक भी विद्यालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश में उर्दू विषय को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद सृजित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

122. प्रदेश के राजकीय महात्मा गांधी (अंग्रेजी) विद्यालयों में विषयानुसार पद सृजित कर शिक्षकों का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

123. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाडलवास को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

124. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माधोगढ़ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तातीजा में विज्ञान संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीकृष्णनगर-बडाऊ का भवन पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो जाने से नये भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पीएमश्री शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पपुरना में संस्कृत संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माधोगढ़ के खेल मैदान को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोजकुमार (सुजानगढ) (वि.स.112)

128. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम रूपेली तहसील बीदासर में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं होने से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. शैलेश सिंह (वि.सं.164)

129. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांतरूक-कुम्हेर में विज्ञान संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पला, सैंत, पपरेरा एवं सोनगांव में नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पूंठ एवं सुपावस को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

131. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के क्षतिग्रस्त विद्यालयों में भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

132. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के जनजाति क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता, प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर के पद स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ताराचन्द (वि.सं.73)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आडसर एवं श्रीडूंगरगढ़ में विज्ञान संकाय व संस्कृत विषय शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के श्री डूंगरगढ़ के ब्लॉक मुख्यालय पर विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ताराचन्द (वि.सं.73)</u>

136. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुनरासर एवं श्रीडूंगरगढ़ में पुस्तकालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

137. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मीलपुरा, गोविन्दपुरा, दीपपुरा, बडी का वास, शिवकुण्डा, कुशलपुरा, जैसल्या तथा लालवास को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

138. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय (संकाय) खोलने एवं व्याख्याताओं के पदस्थापन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े प्रधानाचार्यो/उप प्रधानाचार्य /ऐच्छिक विषयों के व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों, गैर शैक्षणिक स्टाफ यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इत्यादि के अतिशीघ्र पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया मीठापुर, रणसीगांव, भटिण्डा, डांगियावास, रियां, भावी, खेजड़ला में कृषि संकाय/विज्ञान संकाय खोलने एवं ऐच्छिक विषयों के व्याख्याताओं के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों यथा खारिया मीठापुर, भावीं, बोरूंदा, खेजड़ला, रियां रणसीगांव, बिसलपुर, पालासनी, डांगियावास में पी.एम.श्री विद्यालय घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर उपखण्ड मुख्यालय पर मॉडल स्कूल (श्री विवेकानन्द मॉडल स्कूल) (सीबीएसई कोर्स अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

143. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संकायों को खोलने के लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के दिव्यांग सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु व्याख्याता विशेष शिक्षा सहित विशेष शिक्षकों के नवीन पदों के सृजन व स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर क्रमोन्नयन से वंचित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

146. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों को सुचारू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं.106)</u>

148. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों का जीर्णोद्वार एवं कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

150. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के आर.ए.सी. में हायर सैकेण्ड्री स्कूल का भवन बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

151. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित विद्यालयों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. भरतपुर के रेलवे स्कूल एवं महाराजसर के स्कूल में खेल मैदानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. राजकीय सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, जाटोली रथभान एवं फुलवारा में विज्ञान व भूगोल विषय के संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के सभी विद्यालयों में शैक्षिक एवं पी.टी.आई. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अर्न्तगत विद्यालयों में काउन्सलर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरलाल सहारण (वि.स.191)

156. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आसलखेडी, खींवासर व जसरासर में नवीन विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खासोली, चलकोई, कोटवादताल, घण्टेल एवं देपालसर में नवीन कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

158. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के विद्यालयों में पर्याप्त बजट की उपलब्धता व कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ पीने का पानी, शौचालय और पुस्तकालय आदि सुविधाओं को सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

161. प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और STEM (साईन्स, टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग और मैथमैटिक्स) शिक्षा को व्यापक रूप से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय एवं खेल सुविधाओं के निर्माण व विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

163. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल (जयपुर) में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

164. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चून्दिया व ईन्दावड में अतिरिक्त कृषि संकाय खोलने तथा गगराना व पुंदलू में अतिरिक्त विज्ञान संकाय तथा घापरीखुर्द में अतिरिक्त कलां संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गगराना, कुरडाया, कलक तथा माईदंड कलां में आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लास रूम निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रोहिसी, जावली तथा भूरियासनी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल डांगी (वि.सं.21)

167. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के राजकीय विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)

168. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलनसर में कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सजनाणियों की ढाणी में उच्च माध्यमिक की कालांश शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में पंचायत मुख्यालय पर विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

172. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में प्रदेश और राष्ट्र के गौरवशाली महापुरूषों की जीवनियां समाविष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों में कथा श्रवण एवं कथन की कला विकसित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

174. प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय एकीकरण कार्य एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नीतिगत निर्णय विशेष प्राथमिकता से लिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं का चयन कर इनके नियमित प्रशिक्षण एवं अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खेल विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. देवभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण के लिए जोधपुर संभाग के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के कला संकाय में संस्कृत विषय की उपलब्धता को 50 प्रतिशत विद्यालय तक ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

177. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के विद्यालयों में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होने वाली सीएसजी की ग्रांट 25 प्रतिशत के स्थान पर 75

प्रतिशत आवंटित किए जाने की आवश्यकता व बजट जुलाई माह में ही विद्यालयों को आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

178. प्रदेश के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए वेडिंग व इंसीनरेटर मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. प्रदेश के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभावी पुस्तकालय कक्ष एवं भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़ी पुस्तकों के संग्रह की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

180. प्रदेश के भविष्य को देखते हुए एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने से प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में (बीसीआई) बैसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. प्रदेश के उच्च माध्यमिक शिक्षा में प्रभावी एवं प्रेरणादाई कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को अन्य विभागों की तरह उच्च पद पर पदौन्नति देने की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं.120)

182. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मुख्यालय रेवदर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन कृषि संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामबिलास (वि.सं.135)

184. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के जिला मुख्यालय पर जिला संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोले जाने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, स्मार्ट क्लास विहीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास खोले जाने, लालसोट के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब खोले जाने व नवीन संकाय स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (113)

185. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी), चान्दगोढी में कक्षा-कक्ष निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्यन से कक्षा-कक्ष का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ के खेल मैदान के लिए भूमि स्वीकृत करने एवं छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण कक्षा-कक्षों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साखू, रामपुरा, बीराण व चान्दगोठी में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

190. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, शौचालय एवं पेयजल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गिरधारीपुरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढिगाल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

194. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लोबडावास को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोनाकासर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शक्तपुरा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिभान्दरपुर में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाथन में कला संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)</u>

199. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सादुलशहर में तीन कक्षा-कक्षों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

200. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़ के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिनान, तहसील रेणी (अलवर) में गणित विषय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैरेर, तहसील रैणी (अलवर) में कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र राजगढ-लक्ष्मणगढ़ की ग्राम बूचपुरी, तहसील रैणी (अलवर) में बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोठडी गुरू, तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)

205. प्रदेश में शिक्षकों को 7,14,21,28 एवं 32 वर्ष पर चयनित वेतनमान दिये जाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करने एवं स्थाई स्थानान्तरण नीति लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. प्रदेश में वर्ष 2024 में जारी आरपीएससी विज्ञप्ति में टीएसपी क्षेत्र हेतु उर्दू टीचर के पद बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. प्रदेश में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, कम्प्यूटर अनुदेशक का पदनाम कम्प्यूटर शिक्षक करने, प्रयोगशाला सहायकों को 1997 से अध्यापक मानते हुए समस्त लाभ दिए जाने, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य के व्याख्याता के पद सृजित करने तथा सभी नवसृजित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3

अनुदान की मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

1. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने के साथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पॉलिटीकल साईंस और अन्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. आहोर मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भवरानी, चांदराई, बागरा हरजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भवरानी, चांदराई, हरजी, गुडाबालोतान में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

5. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय अम्बेडकर महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने, 10 कक्षा-कक्षों का नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत कराने, महाविद्यालय की चार दीवारी का निर्माण कराने एवं राजकीय महाविद्यालय मण्डावर में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

6. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के उपखण्ड छीपाबड़ौद में कन्या महाविद्यालय खोलने एवं हरनावदा शाहजी में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

7. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में सभी संकाय विषय खोलने, राजकीय बालिका महाविद्यालय ब्यावर एवं राजकीय बड़ाखेड़ा महाविद्यालय को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नगरपालिका मांढ़ण में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) के नये विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

11. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की नगरपालिका बर्डोद के राजकीय कन्या महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)(वि.सं.112)

13. प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त पड़े शारीरिक शिक्षकों के पदों के कारण खेल व्यवस्था प्रभावित होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

14. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की ग्राम पंचायत मुख्यालय खोह (कठूमर) में महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

15. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहाबाद उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के महाविद्यालय वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय सिवाना, कन्या महाविद्यालय सिवाना, कन्या महाविद्यालय समदड़ी, महाविद्यालय समदड़ी, महाविद्यालय सिणधरी, कन्या महाविद्यालय चाड़ो की ढ़ाणी में रिक्त पदों को भरने एवं कन्या महाविद्यालय समदड़ी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय होड्डु (सिणधरी) एवं राजकीय महाविद्यालय पादरू की स्थापना हेतु स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सभी राजकीय महाविद्यालयों में विकास समिति गठित कर उसमें स्थानीय विधायक प्रतिनिधि को मनोनीत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कन्या महाविद्यालय सिवाना, कन्या महाविद्यालय समदड़ी, कन्या महाविद्यालय चाड़ों की ढाणी, महाविद्यालय सिणधरी एवं महाविद्यालय समदड़ी आदि का नामकरण महापुरूष, स्वतन्त्रता सेनानी, वीरयोद्धा, क्षेत्र के शासक, समाज सुधारक, प्रसिद्ध देवस्थान आदि के नाम से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

21. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय में कम्प्यूटर, संस्कृत संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

22. जिला बाड़मेर में संचालित महाविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधायुक्त कम्प्यूटरीकृत लाइब्रेरी, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, खेल मैदान, पुस्तकालय कक्ष एवं शौचालय आदि निर्माण कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश में संचालित निजी महाविद्यालयों में डिग्री एवं डिप्लोमा के नाम पर छात्र-छात्राओं से मनमर्जी शुल्क वसूली की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित समस्त महाविद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चौहटन में विज्ञान संकाय स्वीकृत कर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान आदि नवीन विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

27. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नवलगढ़ शहर, जाखल एवं बसावा में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

28. राजकीय महाविद्यालय बून्दी और तालेड़ा में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने एवं प्रतिनियुक्ति पर गये प्राध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बून्दी की ग्राम पंचायत डावी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

30. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालय भीम में स्नातकोत्तर के लिए भूगोल विषय प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालय भीम व देवगढ़ में एन.सी.सी. केडेट खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ में वाणिज्य व विज्ञान संकाय व भीम में राजनीति विज्ञान संकाय प्रारम्भ करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजकीय पाना देवी मोरिजावाला कन्या महाविद्यालय में एमए प्रथम वर्ष में भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र आहोर के महाविद्यालय में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिन्दी में स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

35. किशनगंज-शाहाबाद के महाविद्यालयों में नए विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

36. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय की चारदीवारी का निर्माण कार्य स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय में आचार्य/सहायक आचार्य सहित विभिन्न कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय, भादरा में वाणिज्य संकाय(कॉमर्स) स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय भादरा हेतु परिवहन व्यवस्था प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

41. राजकीय महाविद्यालय खींवसर में विज्ञान संकाय स्वीकृत करने एवं एनसीसी विंग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पांचौड़ी व हरसोलाव में नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

43. कोटा के राजकीय महाविद्यालयों में अल्प आय वर्ग/लघु सीमांत/बटायेदार किसानों/खेतीहर श्रमिक परिवारों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. कोटा के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

45. कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय की चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाकर कम कम आठ फीट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. कोटा के राजकीय महाविद्यालयों में सेालर सिस्टम पेनल लगाने एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की समयबद्ध देखभाल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. कोटा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जाकर लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं.175)

48. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में वर्ष 2014-15 में स्वीकृत सरकारी कॉलेज हेतु भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राजकीय महाविद्यालय पिण्डवाड़ा में नवीन संकाय भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

50. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के राजकीय महाविद्यालय, मण्डावर में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय अम्बेडकर महाविद्यालय में 10 कक्षा-कक्षों का नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. राजकीय अम्बेडकर महाविद्यालय, महवा की चारदीवारी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

53. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के चार सरकारी महाविद्यालयों में एन.सी.सी. विंग प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के सभी कॉलेजों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

55. राजकीय महाविद्यालय बगरू को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बगरू के महल रोड़, जगतपुरा में महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. राजकीय महाविद्यालय बगरू में ''विज्ञान संकाय'' एवं ''कला वर्ग'' में ''संस्कतृ'' विषय की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (वि.सं.183)

58. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना की उच्च शिक्षण संस्थानों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

59. पिलानी में नवीन महाविद्यालय खोलने, महाविद्यालयों में स्थाई स्टाफ उपलब्ध कराने एवं नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

60. चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यलय में विद्यार्थियों की संख्या 6,000 से अधिक होने के कारण साईंस व कॉमर्स कॉलेज अलग से खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

61. महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में स्नातक स्तर पर कला संकाय में लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, दर्शन शास्त्र, संगीत एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित व वाणिज्य संकाय में व्यावसायिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विषयों को प्रारंभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में संस्कृत विषय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. राजकीय विधि महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ को RAJ-CES सोसाइटी से हटाकर नियमित राजकीय विधि महाविद्यालय में परिवर्तित कराने एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बी.एड हेतु नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

65. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु बजट आंवटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

66. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. झालावाड़ सहित राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अस्थायी संविदा व्याख्याताओं को स्थायी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. राजकीय स्नातक महाविद्यालय खानुपर को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राजकीय विधि महाविद्यालय झालावाड़ में सीटें बढ़ाये जाने, मास्टर पाठ्यक्रम खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

70. प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में संगीत विषय में संगीत प्राध्यापकों की नियुक्ति व तबला वादकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्थाई प्राध्यापकों एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. बयाना स्थित देवनारायण कन्या महाविद्यालय में स्थाई सेक्शन बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

73. प्रदेश में विद्या संबल योजना के शिक्षकों को लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में विद्या संबल योजना में कार्यरत शिक्षकों को मासिक वेतन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राजकीय कन्या महाविद्यालय पदमपुर (श्रीगंगानगर) में विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. केसरीसिंहपुर (श्रीगंगानगर) में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. ज्ञान ज्योति महाविद्यालय श्रीकरणपुर का सरकारीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

78. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये जाने हेतु नियामक आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में फर्जी डिग्रियां बांटने वाले निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की मान्यता को तुरन्त समाप्त कर दोषियों को कठोर सजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को सख्ती से तत्काल लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में महर्षि दयानन्द शोधपीठ, संस्कृत विभाग व वैदिक वांग्मय विभाग में निदेशक या वैदिक विद्वानों की नियुक्ति किये जाने के साथ ही रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों को आवश्यक रूप से शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. अजमेर दक्षिण में स्थित ब्रिटिश कालीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के भवन एवं ऑडीटोरियम हॉल की मरम्मत हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)</u>

83. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की नगर पालिका छापर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाने, राजलदेसर राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने एवं रतनगढ़ एवं राजलदेसर महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

84. राजकीय महाविद्यालय मकराना में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. राजकीय महाविद्यालय मकराना के लिए भूमि आवंटन पर कोर्ट स्टे को खारीज करवाने एवं भवन निर्माण करवाने के लिए बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. राजकीय महाविद्यालय मकराना में विषयानुसार स्टॉफ (व्याख्याता) का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. मकराना महाविद्यालय में गृह विज्ञान व कम्प्यूटर विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

88. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड नादौती में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम की चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गुढाचन्द्रजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

92. जिला मुख्यालय भीलवाड़ा पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

93. जिला मुख्यालय भीलवाड़ा पर माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय या आर.आई.टी. में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. जिला मुख्यालय भीलवाड़ा पर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में रिसर्च व अन्य के लिए आधुनिक सुविधायुक्त लाइब्रेरी व कम्प्यूटर लैब निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर सेठ मुरलीधर मानसिंहका कन्या महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में एमबीए, बीसीए, एमसीए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)</u>

97. प्रदेश में राजमेस के द्वारा लगाए गए व्याख्याताओं को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)</u>

98. श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर में विभिन्न स्वपोषित संकायों को राजकीय संकायों में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, राजकीय महाविद्यालय पल्लू व श्री गौरीशकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर में विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

101. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम के राजकीय महाविद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक संसाधनों की पूर्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

102. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम के राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में स्थित राजकीय महाविद्यालय गंगाशहर एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर के रिक्त पदों पर व्याख्याता और अन्य स्टॉफ के स्थायी पदस्थापन/नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में खेल शिक्षा विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में राजकीय कन्या महाविद्यालय मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर हेतु भूमि का आवंटन एवं विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष मील (वि.सं.179)

106. बाबा विशम्भरदास राजकीय बालिका महाविद्यालय होद को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

107. स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में कृषि संकाय शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में स्व-वित्तपोषित योजना के तहत खोले गये एम.ए. अर्थशास्त्र संकाय को राजकीय मद में बदलने, राजकीय कन्या महाविद्यालय बबाई में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. राजकीय कन्या महाविद्यालय बबाई को राजसेस श्रेणी से राजकीय श्रेणी में परिवर्तित किये जाने एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय में एन.सी.सी. शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय में रिक्त चल रहे शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)

111. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय तथा कन्या महाविद्यालय सांडवा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सुजानगढ़ एवं सांडवा (तहसील बीदासर) में राजसेस में चल रहे महाविद्यालयों में संविदाकर्मी व्याख्याताओं के स्थान पर स्थायी व्याख्याता लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शैलेश सिंह (वि.सं.164)</u>

113. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय महाविद्यालय परिसर में स्थित खेल मैदान के उन्नयन एवं विकास हेतु स्पोर्टस कॉम्पलेक्स निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय महाविद्यालय, डीग में राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, लोक प्रशासन एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

115. नवीन राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी, नवीन कन्या महाविद्यालय, जहाजपुर, महाविद्यालय जहाजपुर में रिक्त पदों को भरने तथा इन महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर की चारदीवारी के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

116. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में स्थित राजकीय महाविद्यालय गढ़ी में स्थायी पदों की स्वीकृति एवं इसके भवन निर्माण में हुई कथित अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ताराचन्द (वि.सं.73)</u>

117. श्री डूंगरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में नये विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

119. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय बालिका महाविद्यालय के लिये भूमि आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय महाविद्यालय जालसू में विज्ञान संकाय खुलवाने एवं ग्राम पंचायत खोरा बीसल में नवीन महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

121. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बिलाड़ा में रिक्त पड़े शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक पदों यथा प्रध्यानाचार्यों, प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर/व्याख्याताओं के पदों पर शीघ्र पदस्थापन करवाने एवं कक्षा-कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं ऑडिटोरियम हॉल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित बोरून्दा उपतहसील/ग्राम पंचायत एवं कापरड़ा उपतहसील/ग्राम पंचायत मुख्यालय डांगियावास में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन कर पदस्थापन करने तथा भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उपखण्ड मुख्यालय पीपाड़शहर में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत वाणिज्य/विज्ञान संकाय का संचालन सरकार को अपने अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपाड़शहर एवं राजकीय महाविद्यालय पीपाड़शहर में प्रध्यानाचार्यों, व्याख्याताओं, सहायक आचार्यों एवं गैर-शैक्षणिक स्टॉफ के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष, पी.टी.आई., सहायक कर्मचारियों की भर्ती कर पदस्थापन के साथ ही राजमेस योजना से परिवर्तित कर राजकीय स्तर पर संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल)(वि.सं.108)</u>

126. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के राजकीय कन्या महाविद्यालय मथानियां में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के राजकीय पी.जी. महाविद्यालय का नामकरण शहीद गोरख राम 'वीर चक्र' के नाम से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के राजकीय पी.जी. महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)</u>

129. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में नवीन विषय एवं संकाय प्रारम्भ करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गुढ़ाकटला, गुढ़लिया, बड़ियाल कलां में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राजकीय महाविद्यालय का नामकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में विगत में आगरा रोड़ पर खोले गये कॉलेज को पृथक से 10 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत होने के उपरान्त अभी तक कोई कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

134. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय का सरकारीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

135. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता की आड़ में कुलपतियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. भरतपुर जिले के महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में हो रही वित्तीय अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

140. प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम और वर्चुअल लैब आदि सुविधाओं के विकास पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय एवं किरण माहेश्वरी महाविद्यालय में नवीन संकाय, नवीन विषय और अधिस्नातक कक्षाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द में कला संकाय में राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं भूगोल व विज्ञान संकाय में रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय में व्यावसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम. विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही समग्र अधिनियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

144. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल (जयपुर) में बन रहे किशनपोल गर्ल्स महाविद्यालय को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

145. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय महाविद्यालय मेड़तासिटी में स्नातकोत्तर (पी.जी.) हेतु हिन्दी, इतिहास, समाज शास्त्र (कला वर्ग) तथा वनस्पति शास्त्र (विज्ञान संकाय) व व्यावसायिक प्रशासन (वाणिज्य वर्ग) विषय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय महाविद्यालय मेड़तासिटी में ऑडिटोरियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल डांगी (वि.सं.21)

147. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में स्थित महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने एवं इनमें नवीन संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)

148. विधान सभा क्षेत्र फलौदी की ग्राम पंचायत जांम्बा में महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

149. प्रदेश की उच्च शिक्षा में ललित कलाओं के प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण हेतु ललित कलाओं के विषयों की उपलब्धता 50 प्रतिशत महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए। `

150. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए मानसिक तनाव एवं अवसाद से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार और सह-शैक्षणिक गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

151. प्रदेश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय गौरव के जीवन्मुक्त महापुरुषों के जीवन चरित्रों का समावेश और तद्विषयक कथा-कथन प्रशिक्षण/अभ्यास/कार्यशालाओं के आयोजन की समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. प्रदेश के उच्च शिक्षा केन्द्रों में संस्कृत विषय/संकाय/शोध-केन्द्र/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण/ प्रयोगशालाओं की उपलब्धता बढ़ाने के विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

154. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के श्री प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में गणित के स्वीकृत पद को किसी अन्यत्र महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के श्री प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा के भवन की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा के श्री प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषयों के संचालन व प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित अध्ययन केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रभावी अध्यापन व्यवस्था के लिए इफेक्टिव मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

159. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालय आबूरोड़ व राजकीय महाविद्यालय रेवदर में प्राध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामबिलास (वि.सं.135)</u>

161. विधान सभा क्षेत्र लालसोट की ग्राम समेल ग्राम पंचायत होदायली पंचायत समिति लालसोट में नवीन राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)(वि.सं.113)</u>

162. प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के गांव-सांखू, चान्दगोठी, रामपुरा, हमीरवास में नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ एवं राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)(वि.सं.113)</u>

165. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय महाविद्यालय-राजगढ़ में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

166. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन व भवन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय महाविद्यालय खाटू खुर्द में भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय छोटी खाटू में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय छोटी खाटू में भवन, खेल मैदान, पुस्तकालय, लैब एवं आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

170. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय महाविद्यालय राडावास में स्नात्तक स्तर पर इतिहास संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के मनोहरपुर में सह-शिक्षा का नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में पी.जी. स्तर पर भूगोल संकाय (विषय) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय महाविद्यालय राडावास में स्नात्तक स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के खेजरोली में सह-शिक्षा का नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

175. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय महाविद्यालय लालगढ़ में समाजशास्त्र विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय महाविद्यालय हिन्दुमलकोट में पंजाबी विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय महाविद्यालय हिन्दुमलकोट में स्थाई शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)

179. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय रैणी एवं कन्या महाविद्यालय राजगढ़ को राजसेस के दर्जे से राजकीय मद से संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में कम्प्यूटर एवं सैन्य विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में सभागार का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के कन्या राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ की चारदीवारी निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रूपये का बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)

183. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय महाविद्यालय ईटावा में तीन शिक्षकों को तीन साल पूर्व कोटा जिले से अन्यत्र डेपूटेशन पर लगाने से उत्पन्न स्थिति एवं राजकीय महाविद्यालय ईटावा में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।